जनादेश की गारंटी

सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सभा सभा के प्रथम चरण के मतदान से एक दिन पहले चुनावी मशीन की विसनीयता के बारे में यही कहा। एडीआर और अन्य की तरफ से जारी जनहित याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए ईलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर संदेह जताने को सही नहीं बताया। इस पर फैसला अभी आना है। पर इन टिप्पणियों से ईवीएम पर न्यायालय के रु ख का पता चलता है। स्वदेश निर्मिंत ईवीएम मशीन से चुनाव बीसवीं सदी के नौवें दशक से ही कराया जा रहा है। इसके पहले, 1982 में केरल की परवूर विधानसभा उपचुनाव में उसे कुछ बूथों पर आजमाया गया था। इसकी खामियों को दुरु स्त कर इसे प्रयोग-सक्षम बनाया गया। ईवीएम के जरिए यूपीए ने दो आम चुनाव जीते हैं और केंद्र में उनकी दो सरकारें बनी हैं। इसके पहले एनडीए की भी सरकार बनी है। विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव ईवीएम से ही हुए हैं। इसके बावजूद हारे हुए दल या गठबंधन हर आम चुनाव के वक्त ईवीएम को हटाने या उसे वीवीपीएटी से लैस करने की मांग चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक करते रहे हैं। आयोग की तरफ से हर चुनाव के पहले उनके समक्ष ईवीएम के फूलप्रूफ डेमो के जरिए चिंताओं के निराकरण के बावजूद सवाल उठाते रहना एक रस्मी कवायद है। उनका आरोप होता है कि इसमें डाले गए वोट भाजपा को मिलते हैं। पहले के कुछ उदाहरण इसकी तस्दीक भी करते थे पर यह तो मशीनी गड़बड़ी हो सकती थी। अब तो इसमें पर्याप्त सुधार किया गया है। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने चार करोड़ टेस्टेड डेटा पर अपना भरोसा जताया है। यह सही भी है। ऐसा नहीं होता तो यूपीए ही लगातार जीतता होता या एनडीए का राज बदस्तूर रहता। दलों को चुनावों में इतना पैसा और पसीना नहीं बहाना पड़ता। ईवीएम अपने आका को तश्तरी में नतीजे परोस देती। न्यायालय ने रस्मी याचियों से स्पष्ट कर दिया है कि बैलेट पेपर और बक्से की झीना-झपटी वाले प्रतिगामी चुनावी दौर में भारत जैसे 'महादेश को नहीं लौटाया जा सकता। यह जर्मनी नहीं है। अलबत्ता, इस मसले पर फिर उंगली न उठे इस लिहाजन हर वोट का हिसाब रखने के लिए ईवीएम को वीवीपीएटी के साथ जोडऩे पर विचार किया जा सकता है। अंतिम परिणाम में देरी के बावजूद। चुनाव बिल्कुल शुद्ध-पवित्र तरीके से होना चाहिए ताकि उसके जनादेश की 'गारंटी हो। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी में अवाम का मत है।

जनता निर्णय लेगी

ताजा सर्वेक्षण बताते हैं कि इस बार के आम चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और विकास प्रमुख मुद्दे के रूप में हावी रहने वाले हैं। ये मुद्दे मतदाताओं के लिए अपना सांसद चुनने में काम में आएंगे। पिछले पांच साल में देश की हालत में कितना सुधार हुआ और जनता के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता की बेहतरी के लिए कितनी जिम्मेदारी से कार्य किए, यह भी मतदाताओं पर असर डालेगा। इसी तरह 2019 में एनडीए सरकार ने किन घोषणाओं या वादों को पूरा किया और कौन-सी घोषणाएं एनडीए की केंद्र और राज्यों में उसकी सरकारें पूरा करने में नाकाम रहीं, इस बार के आम चुनाव में जनता द्वारा उन सारे मुद्दों पर गौर करके मतदान करने की बात ताजा सर्वेक्षण में सामने आई है। ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा लोगों के लिए सबसे अहम रहने वाला है। तमाम ऐसे लोगों की राय है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है क्योंकि गैर-बराबरी बढ़ी है। वहीं पर सर्वेक्षण में महिलाओं को रोजगार के अवसर कम होने की शिकायत भी है। बेरोजगारी के अलावा महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है। रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ोतरी से भी आम लोगों में खासी नाराजगी है खासकर गरीब, ग्रामीण और मजदूरी करके परिवार पालने वाले मजदूरों में। निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग की भी महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है। उज्ज्वला और मुफ्त राशन योजना से भारत का निम्न वर्ग राहत महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि भाजपा के नये चुनाव घोषणापत्र में गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को अगले पांच साल और बढ़ा दिया गया है। निश्चित ही इसका असर चुनाव परिणाम में दिखाई देगा क्योंकि 2019 में निम्न और माध्यम वर्ग ने केंद्र की मुफ्त राशन योजना को पसंद किया था। आयुष्मान योजना को विस्तार देते हुए गरीबों के अलावा सत्तर साल के बुजुगरे को भी इसका लाभ देने की बात जरूर नई है, इससे करोड़ों बुजुगरे को फायदा मिलेगा। इसी तरह पिछले पांच सालों में विकास की अहमियत को 48 प्रतिशत जनता ने स्वीकार किया। सबसे दिलचस्प राय भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में देखने को मिली। महज 8 प्रतिशत लोगों ने भ्रष्टाचार को तवज्जो दी यानी 92 प्रतिशत लोगों ने भ्रष्टाचार को कोई खास तवज्जो ही नहीं दी, जबकि दस साल पहले भ्रष्टाचार सबसे गंभीर मुद्दा हुआ करता था। उस समय देश में बेरोजगारी की दर 5 प्रतिशत के आसपास थी, लेकिन अब यह 6.8 प्रतिशत के आसपास है। पिछले चुनाव में बेरोजगारी को लेकर लोग इतने आक्रामक नहीं थे जितने आज हैं।

भ्रमजाल में खुद भी फंसिए और दूसरों को भी फंसाईये...

आरती कुमारी

चुनावी माहौल : सजने लगी चुनाव की मंडी, फ्रेंचाइजी लेने वालों को माननीय बनवाने की सौ फीसदी गारंटी आइए,आइए साहेबान! एक बार हमारी तरफ भी नजर फरमाऐं। सब कुछ आपके लिए ही तो सजा रखा है। भारी डिस्काउंट, गिफ्ट आइटम। सब कुछ तो है। एक बार हमारी तरफ आकर तो देखें। वादा रहा। निराश नहीं करेंगे। क्या कहा, गारंटी! जी, फुल गारंटी। कोई टेंशन नहीं। शिकायत मिले तो सौ फीसदी रिटर्न। अरे भाई! उधर मत जाओ। धोखेबाज हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मौके के यार हैं। अभी दिख रहे हैं। काम निकलते ही अपना मजमा समेट ऐसे निकल जायेंगे, जैसे कभी यहां थे ही नहीं। इनका एक ठिकाना हो तो आपको बताएं। जितने आप और हम कपड़े नहीं बदलते,उससे ज्यादा तो ये ठिकाने बदल लेते हैं। क्या कहा? ये जुबान के सच्चे हैं। भाई साहब, आप कौन से युग में जी रहे हैं। ये त्रेता के सत्यवादी हरिश्चन्द्र थोड़े ही हैं, जो जुबान के पक्के हो। ये तो कलियुग के मिथ्यावादी हरिश्चंद्र हैं। कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। भूल गए पिछली बार आपसे इन्होंने क्या कहा था। बड़ी जल्दी भूल गए आप तो। ये वही है जो दही के नाम पर आपको कपास थमा गए थे। आप भी सोच रहे होंगे कि गाड़ी कौनसी पटरी पर चढ़ गई है। सब्र रखें। सब बताते हैं। आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। ये इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है। हर क्षण इसका नया ड्राइवर और नया स्टेशन है। हां यात्री पुराने ज्यादा और नए कम हैं। चुनावी बाजार की शुरुआत हो चुकी है। वोट जुटाने वाले प्रमुख ' होलसेल व्यापारी' बाजार में गाजे बाजे के साथ अपना मजमा लगा चुके हैं। सीजन को देखते हुए कारिंदों की फौज वक्त के साथ दो-दो हाथ करने को तैयार हैं। बाजार की मांग अनुसार रोज कुरतों और फटकों के रंग बदले जा रहे हैं। सीजन का फायदा उठाने वाले वोट के होलसेल व्यापारियों ने जगह जगह अपने बंदे छोड़ दिए हैं। जो जैसे तैसे वोटरनुमा उपभोक्ताओं को लुभा अपनी ओर खींचने के जोड़ तोड़ के प्रयास में हैं। बिना लाग लपेट कहने का सीधा भाव यह है कि फिलहाल राजनेताओं का सीजन चल रहा है? आए दिन किसी ना किसी को अपना फटका पहनाकर अधिक से अधिक संख्या में भावी ' माननीय' रूपी फ्रेंचाइजर बनाए जा रहे हैं। ' आगामी समय में आपको ही आशीर्वाद मिलेगा ' यह जुमला लगातार उन्हें सादर भेंट स्वरूप मिल रहा है। एक ही क्षेत्र रूपी बाजार की फ्रेंचाइजी लेने वाले बीसों छोटे व्यापारी वोट रूपी सिक्योरिटी भरने को लालायित खड़े हैं। इसी का फायदा यह कहकर उठाया जा रहा है, वोट एकत्रीकरण में जिस व्यापारी की मार्केटिंग स्ट्रेजी स्ट्रॉन्ग रही, आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। इसलिए बिना कुछ विचारे मैदान में लगे रहो। कोई हतोत्साहित होकर मैदान छोड़ दूसरे पाले में न चला जाए, इसका भी डायरेक्टर टीम विशेष ध्यान रख रही है। बीच बीच में ग्लुकोन-डी या मिक्स फ्रूट जूस के रूप में यह कहना उनमें और जोश भर रहा है कि आप ही सबसे आगे चल रहे हो। हाईकमान के पास आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है। बस जोश में होश रखिए, इस बार आपका ही राजयोग का योग है।

' माननीय' बनवाने का सौ फीसदी आश्वासन : होलसेल व्यापारियों के 'जुबानी माल' को भोले भाले मतदाताओं तक हर हाल में पहुंचाया जाना इनका प्रथम लक्ष्य है। सत्ता की फ्रेंचाइजी लेने वाले ' भावी माननीय' भी कमतर नहीं हैं। वे भी गांव-गांव और गली-मोहल्लों में अपने-अपने रिटेलर खड़े कर रहे हैं?। ये सभी रिटेलर एक ही कंपनी के 'जुबानी माल' का प्रचार कम और अपने होलसेल व्यापारी का अधिक गुणगान ज्यादा कर रहे हैं। समय के अनुरूप चलने के लिए यदि फिजिकली आमने-सामने प्रचार रूपी भ्रमजाल नहीं फेल पा रहा तो सोशल मीडिया का सहारा लेने में भी ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कई बार तो रिटेलर अपनी ही कंपनी के दूसरे होलसेल व्यापारी की पुरानी कंपनी में रहते हुए किए गए वायदों और खाई गई कसमों का पुराना चिट्ठा खोलने में भी कंजूसी नहीं बरत रहे। एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने 'आका' के सामने ' बाहुबली का दिखावा इनके खेल को और ज्यादा निखार रहा है।

प्रचार तंत्र में कोई नहीं पीछे : ऐसा नहीं है कि चुनावी बाजार में उत्पादों की कमी है। बाजार विभिन्न रंगों के लेबल लगे उत्पादों से भरा पड़ा है। सीजन में सभी प्रोडक्ट निकालने हैं। नफा नुकसान आंकलन करने का अभी किसी के पास समय नहीं है। अभी तो साम दाम दण्ड भेद की नीति से सभी प्रोडक्ट को बाजार में उतारना जरूरी है। पैकिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। दिवारें पुतवानी शुरू कर दी गई है। जगह जगह लगे फ्लेक्स प्रोडक्ट लगातर आंखों के सामने है। कंपनी पुरानी है तो फ्रेंचाइजी लेने वालों की लंबी कतारें है। यहां कंपनी के ही नियम कायदे हैं। ऐसी स्थिति में फ्रेंचाइजर कोई ना नुकर कर प्रोडक्ट को बाजार में बेचने को तैयार खड़े हैं। हां नए व्यापारियों के समक्ष सबसे बड़ी चिंता फ्रेंचाइजी वितरण की है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें फ्रेंचाइजी लेने वालो की एकबार सारी शर्ते माननी पड़ रही है। मौके के अनुसार गधों को भी बाप समान दर्जा देना पड़ रहा है।

किसे मिलेगा रसगुल्ला, सब बाद की बात : चुनावी बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचने में कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा? इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं। कौनसा प्रोडक्ट कामयाब रहेगा या फुस्स रहेगा। गारंटी मिलेगी या नहीं। इसका किसी के पास जवाब नहीं। फिलहाल होलसेल व्यापारी, फ्रेंचाईजर, रिटेलर सब प्रोडक्ट के गुणगान में लगे हैं। भ्रमजाल कामयाब हो यही सबका लक्ष्य है। कंपनी होलसेल व्यापारी का सीजन के बाद क्या रवैया होगा। प्रोडक्ट बिक गया तो फ्रेंचाइजी लेने वालों को क्या लाभ मिलेगा। क्या उन्हें आशीर्वाद मिलेगा या फिर अगले सीजन की बाट जोहनी पड़ेगी। या उन्हें फिर दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने को मजबूर होना पड़ेगा।, ये सब तो आने वाले आगामी छोटे सीजन के समय ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों की जरूरतों के हिसाब से माल बेचने वाली कंपनियों का बाजार भले ही उठान पर ना हो, राजनीतिक पार्टियों का बाजार सातवें आसामन पर है।

मार्केटिंग के लिए फील्ड में उतरे एजेंट : चोला समाजसेवा का, नजर बत्ती पर वैसे तो आप मार्केट में किसी प्रोडेक्ट बेचने वाली कंपनी की ड्रिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो आपको तय मुनाफा ही मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिन कंपनियों का सीजन चल रहा है अगर इनकी स्थाई ड्रिस्ट्रीब्यूटरशिप एक बार मिल जाए तो बस अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सुखपूर्ण जीवन तय है। इन कंपनियों से जुड़ने के लिए समाजसेवा का चोगा सर्वाधिक उपयोगी है। इससे इंट्री सीधी हो रही है। सभी की नजर ' मछली की आंख" की तरह 'लाल बत्ती' पर है। एक बार मिल जाए तो बात बन जाए। फिर उन्हें पांच साल तक न तो रिटेलर चाहिए और न ही उपभोक्ता...?

पृथ्वी से ही जीवन है

गिरीश्वर मिश्र

पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, भूमि आदि विभिन्न नामों से जाने जाने वाली सता को हजारों साल से माता कहा जाता रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में माताभूमिः पुत्रोहं पृथिव्याः का उद्घोष मिलता है। माता के रूप में पृथ्वी जाने कब से मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि सभी जीवित प्राणियों यानी अपने आश्रितों का निर्व्याज भरण-पोषण करती आ रही है। माता का स्वभाव है कि वह स्वयं कष्ट सह कर भी अपना सारा प्रेम शिशुओं के ऊपर उड़ेलती रहती है क्योंकि वह अपनी संततियों को अपने अस्तित्व से अलग नहीं रखती। वे उसी के अभिन्न अवयव या अंश होते हैं । वैसे भी सारी दुनिया में जो कुछ भी स्थित है वह ईश्वर का आवास हैः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत । इसलिए उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता । तभी भारत के आदमी ने सोचा कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ़ बसता नहीं है । वह प्राण शक्ति है और वह उसी की बदौलत जीता है । हमारी भाषा, विचार और शरीर-रचना सब पर इस भूमि का अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी प्राणियों के लिए आश्रय ही नहीं है वरन उसी से ही जीवन संभव हो पाता है। हम सब पृथ्वी के तत्वों से निर्मित होते हैं। मिट्टी की सबसे विलक्षण शक्ति उसकी उर्वरा क्षमता में निहित है। इस जीवनी शक्ति के चलते रूखे-सूखे बीज का रूपांतरण होता है, अंकुरित होकर वह बीज हरी-भरी घास, अन्न की लहलहाती फसल, नाना प्रकार के चित्ताकर्षक सुगंधित पुष्प, भाँति-भाँति के सुस्वादु रसीले फल वाले, औषधीय और अन्य क़िस्म के वृक्ष-वनस्पतियाँ आदि जानें क्या-क्या बन जाता है। धरती के नीचे प्रवाहित जल हमारे जीवन का स्रोत है। उसके क्रोड़ में विभिन्न धातुएँ-कोयला, सोना, चाँदी, लोहा, हीरा, मोती हैं, ऊर्जा का स्रोत पेट्रोल है। क्या कुछ नहीं है उसमें। बहुत से पदार्थ ऐसे भी हैं जो रत्नगर्भा पृथ्वी ने अपने भीतर छिपा रखे हैं और हमें उनका ज्ञान नहीं है। ऐसी पृथ्वी जड़ नहीं है और हमें अपने अस्तित्व को उसके हिस्से के रूप में देखना चाहिए। हमारा पृथ्वी से सम्बन्ध एक समग्र रचना या अंगी के अंग के रूप समझना चाहिए। पृथ्वी को देवता माना गया। पृथ्वी रक्षणीय और वंदनीय हो गयी। भूमि को माता का दर्जा मिला। परंतु आज की स्थिति भिन्न है। अब वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों में जलवायु - परिवर्तन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ग्लेशियरों के बहुत बड़े पैमाने पर पिघलने की घटना से प्राकृतिक संतुलन ख़तरे में पड़ रहा है । हम सब प्रकृति और मनुष्य अलग-अलग देखने लगे हैं। प्रकृति का संसाधन वाला रूप बड़ा आकर्षक लगता है। विगत वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हादसों में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है किंतु मनुष्य अपने सीमित स्वार्थों के चलते बाज नहीं आता। उसे यह विस्मृत हो जाता है कि प्रकृति विकल्पहीन है।उसे खोने का ख़तरा हमें कहीं का न रखेगा। यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों में बाढ़, लू, सूखा और तूफ़ान जैसी चरम स्थितियों का कई कई बार सामना करना पड़ा है। भारत के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका का असर हुआ था। दुबई में हुई ताजा वर्षा और बाढ़ अभूतपूर्व है। विकास को लेकर चिंतन में 'टिकाऊ विकास' के लक्ष्यों को पहचानना सराहनीय कदम था। पर उद्घोषणा को कार्यस्तर पर लागू करने तक की अब तक की यात्रा आगे नहीं बढ़ पा रही है। जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों के विनाश और जैव विविधता के ह्रास का ख़तरा बढ़ रहा है। सभी देश पर्यावरण की रक्षा के लिए ज़रूरी मानकों, मानदंडों और पाबंदियों को स्वीकार न करके छूट लेने की फ़िराक़ में हैं। ग्रीनगैस के उत्सर्जन को लेकर आज जो हालात हैं उसमें यह स्थिति ख़ास तौर पर दिख रही है। अब पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि अनियंत्रित होती जा रही है। विडम्बना यह भी है कि इस वैश्विक पैमाने पर आ रही विपत्ति का नुक़सान अक्सर कम विकसित देशों को ही भुगतना पड़ता है। अनुमान है कि विश्व को 2.5 से 2.9 सेल्सियस तापमान से गुजरना होगा। मौसम में होने वाले इस तरह के क्रांतिक बदलाव के भयानक परिणाम हो सकते हैं। आज प्रौद्योगिकी का जिस तेज़ी से विकास हो रहा है वह प्रकृति की संभावनाओं को कुंठित और करने वाला साबित हो रहा है । खेती में में रासायनिक खाद और कीटनाशकों आदि के विविध रूप विष की तरह मानव शरीर में पहुँच कर अनेक रोगों को जन्म दे रहे हैं। यही हाल आणविक ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ी समस्याओं का भी है। वृक्षों आदि विभिन्न वनस्पतियों, मनुष्य और अन्य जीव जंतु सभी परस्पर निर्भर हैं। ये सभी एक दूसरे के लिए पूरक की तरह सक्रिय हो कर काम करते हैं। परंतु मनुष्य प्रकृति से लेता तो है पर उसे देने की बात याद नहीं रहती है। हाँ, कई लोगों को मन में यह भ्रम ज़रूर है कि प्रकृति असमाप्य है, कभी ख़त्म न होगी। हम प्रकृति को जड़ या निर्जीव मान कर मनोवांछित तरीक़े से इच्छानुसार उसके शोषण और दोहन में शामिल हो जाते हैं। यह हमारे स्वभाव का हिस्सा बनता जाता है। हम असंवेदनशील और असहिष्णु हो कर हिंसक बनते जाते हैं। पृथ्वी से मिलने वाले प्रसाद का सेवन श्रेयस्कर होता है न कि लोभवश अंधाधुंध शोषण। पृथ्वी की अकूत सम्पदा में बहुत कुछ यदि पुनर्नवीकरण करने लायक़ (रिन्यूएबिल) होता है तो बहुत कुछ उपयोग के साथ क्रमशः ख़त्म होता जाता है। परंतु यह सब देख हम पृथ्वी को एक संसाधन मान बैठते हैं जिसका शोषण करने लगते हैं। पृथ्वी को उपभोग्य और उसके सभी पक्षों का उपभोग करते रहना हम अपना हक़ सा मान बैठे है। इस उपभोग के अनियंत्रित होने से जीवन की पारिस्थितिकी ख़तरे में पड़ने लगी है क्योंकि सब कुछ परस्पर सम्बंधित है। खेती-बारी, काम-धंधा, सुख-स्वास्थ और सामाजिक-आर्थिक उन्नति से जुड़ी सारी गतिविधियाँ धरती पर ही टिकी हैं। आधुनिक आदमी की सोच में मनुष्य ने पृथ्वी को जड़ मान अपने को अलग कर उस सम्पदा का स्वामी मान बैठा। उसे जीवन को संचालित करने के लिए 'विकास' का एक नया मंत्र मिला गया जिसका आशय निरंतर आगे बढ़ना है और दुनिया के सारे संसाधनों का उपयोग करना है। दुनिया, जगत या पृथ्वी हमारे लिए साधन हैं जिनका मन मर्ज़ी से उपयोग करना है। मनुष्य सब कुछ का केंद्र बन गया और उसके स्वार्थ की सिद्धि को प्रमुख मान लिया गया। पृथ्वी के सभी संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू हुआ। अनियंत्रित विकास के चलते एक ओर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति कम होने लगी तो दूसरी ओर कूड़ा-कचरा का ढेर लगाने लगा। जो जितना विकसित हुआ उसने उतने ही ज़्यादा कूड़ा पैदा किया। देखते-देखते राजधानी दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में कूड़े के कई पहाड़ खड़े हो गए जिनका निस्तारण असंभव सी परियोजना हो गयी। मातृभूमि का एक भौतिक आधार है पर वह सांस्कृतिक संकल्पना है। भौतिक विस्तार के क्षेत्र का घट-बढ होता रहा है। मातृभूमि राष्ट्रीय संस्कृति का मुख्य अंश रहा है। सुजलां , सुफलां, मलयजशीतलां मातरं, बंदे मातरम् का आवाहन हमें कर्म और त्याग के साथ 'मातृदेवो भव' के संकल्प की ओर अग्रसर करता है। भारत भूमि ऐसी 'पुण्यभूमि' के रूप में याद की गई है जहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। मातृभूमि की वंदना राष्ट्रीय संस्कृति का मुख्य भाग रहा है। यह राष्ट्रीय आस्था का विषय है। धरती के साथ हिंसा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। पृथ्वी को जन की धात्री कहा है। उपेक्षा की जगह जागरूक हो कर पृथ्वी की सेवा-सुश्रूषा अपेक्षित है। भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। एकांगी भौतिक विकास के परिणाम जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से घातक हैं। मातृभूमि के संवर्धन में ही सबकी वृद्धि है। मतभेद, प्रतिस्पर्धा और हिंसा के फलस्वरूप मातृभूमि की हानि और सामान्य जन जीवन की भी हानि होती है। दोनों परस्पर निर्भर हैं। हर तरह की विविधता को परे करते हुए मातृभूमि सभी का ख़्याल रखती है।

मेष राशिः आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाएंगे। घर-वार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है, उनके धन में वृद्धि होने की संभावना है। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैय्या करियर में आपको बेहतरी दिलायेगा।

वृष राशिः आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आप स्वस्थ्य बने रहेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। आपको शिक्षकों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। आज आपकी बातों का लोगों पर प्रभाव दिखेगा। साथ ही वो आपसे जुडऩे की कोशिश भी करेंगे।

मिथुन राशिःआज आपको आर्थिक रूप से अपने रिश्तेदारों से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाये रखने के लिए आपको टहलना चाहिए। इससे आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। आज सकारात्मक सोच आपको कार्यों में सफलता दिलाएगा। परिवार के साथ किसी टूर का प्लान बनायेंगे। आज लेनदेन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरुरत है।

कर्क राशिः आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको थोड़ा आलस महसूस होगा, जिससे काम में मन कम ही लगेगा। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ायेंगे । जो छात्र फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें आज कुछ नया डिजाईन करने को मिल सकता है, उनकी मेहनत रंग लाएगी। दांपत्य रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होने की संभावना है।

सिंह राशिः आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। कोई नया काम करने के लिए सोचेंगे।

कन्या राशिः आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे।जीवनसाथी के साथ डिनर का प्रोग्राम बनेगा। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।

तुला राशिः आज का दिन आपके शानदार रहने वाला है। आज कारोबारियों को धन लाभ होने की उम्मीद है। ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी, आप अपने सारे रुके हुए काम पूरा करने में सफल होंगे। आज जीवनसाथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे। आज किसी वजह से दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल जाएगा। कोई जरूरी चीज आज आप कहीं रखकर भूल सकते हैं। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए।

वृश्चिक राशिः आज आप माता-पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। जीवनसाथी से आपको खुशखबरी मिलेगी, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बन रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। आज आप कामकाज में बहुत बिजी हो सकते हैं। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।

धनु राशिः आज आप कोई जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। दांपत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएगी, साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। कार्यक्षमता के बल पर आपको आगे बढऩे के कई मौके मिलेंगे। नींद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। करियर में सफलता सुनिश्चित होगी।

मकर राशिः आज आपको बच्चो से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन मे आगे बढऩे के मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति जरूर होगी। नए व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा।

कुंभ राशिः आज घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आर्ट्र्स स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूराःपूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जायेगी। वर्क आउट शुरू करने से आप चुस्तःदुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।

मीन राशिः आज जीवनसाथी के सहयोग से कोई काम पूरा हो जायेगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन जल्द ही सब ठीक भी हो जायेंगा। टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी काम में सफलता मिलेगी। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे।

पहले चरण के मतदान में मध्यप्रदेश की तासीर क्या!

जयराम शुक्ल

लोकसभा चुनाव, मध्यप्रदेश में पहले चरण के महासमर में मौसमी लू-लपट के साथ वोटों की छीन-झपट का जोर चरम पर है। पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाईगर रिजर्व में सियारों की हुआ-हुआ, चिड़ियों की चहचहाहट और बाघों की दहाड़ पर मैदानी इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं की तू-तू मैं-मैं और नेताओं की हुंकार भारी पड़ रही है। विन्ध्य की दो सीटों सीधी, शहडोल और महाकोशल की चार सीटों मंडला, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, बालाघाट लोकसभा सीटों के लिए आज मत पड़ रहे हैं। यह इलाका कभी 'ग्रेट गोड़वाना' का हिस्सा रहा। मुगलों से भिडऩे वाली वीरांगना रानी दुर्गावती से लेकर अंग्रेजों से मोर्चा लेने वाले संग्राम शाह- रघुनाथ शाह के पराक्रम की गाथाएं अभी भी लोगों की जुबान पर हैं। एक तरह से चुनाव के इस पहले चरण का नियंता विशाल वनवासी वर्ग है जिसे रिझाने के लिए भाजपा के पास मोटे पैकेज हैं तो कांग्रेस के पास भावनात्मक और सामाजिक मुद्दे। छिन्दवाड़ा में छीना-झपटी..! इस चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें छिंदवाड़ा पर देश की निगाहें टिकी हैं। कमलनाथ का सबकुछ दांव लगा है। बेटे नकुल नाथ चुनाव मैदान में हैं। बड़ा सवाल यह है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का पर्याय बना रहेगा यह इस बार निजाम बदलेगा। भाजपा ने विवेक साहू बंटी पर दांव खेला है। केन्द्रीय नेतृत्व और रणनीतिकार हर कदम पर इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस बार न इन्हें संसाधन की कोई कमी और मनोबल तो जामसांवली के मंदिर के शिखर तक। पर चर्चा के केन्द्र में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ हैं, न नकुलनाथ और न बंटी। बाघ जब बूढ़ा हो जाता है तो जंगल के वन्यजीव उसकी अवहेलना करने लगते हैं। न उसकी गुर्राहट काम आती और जंगल के राजा होने का रसूख। कमलनाथ के साथ कुछ ऐसा ही ही। एक एक करके सभी विश्वसनीय साथ छोड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चोट अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह ने दी। कांग्रेस की टिकट पर पच्चीस हजार मतों से जीतने वाले कमलेश गोड़वाना के शाही वंशज हैं। उनका टूटना दांए हाथ के कट जाने जैसा है। नकुलनाथ के पिछले चुनाव में अमरवाड़ा ने 22 हजार की लीड न दी होती तो जीतना ही मुश्किल था। छिन्दवाड़ा शहर में भी विपरीत हवा है। सबसे पुराने साथी दीपक सक्सेना और महापौर विक्रम अहाके ने बगावत करके छिन्दवाड़ा की मांद को भाजपा के लिए सुभेद्य बना दिया है। विधानसभा में जिस छिन्दवाड़ा जिले की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती हों उसके हर विधानसभा में नेताओं कार्यकर्ताओं की पतझड़ है। यहां वनवासी वोटों का प्रतिशत 35 से ऊपर है। तामिया के भारिया वनवासी हैं तो मैदानी इलाके में गोंड। अबतक कांग्रेस का साथ देते आ रहे थे इस बार जन-मन में क्या है..? कोई समझ नहीं पा रहा। बालाघाट में कंकर का बंकर! छिन्दवाड़ा की जोड़ीदार सीट है बालाघाट। मध्यप्रदेश में नक्सलियों का बड़ा ठिकाना। खौफ इतना कि एक बार नक्सलियों ने दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के मंत्री लिखीराम कांवरे को कुल्हाड़ियों से काट डाला था। हिना कांवरे यहीं से कांग्रेस विधायक हैं। बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। नक्सलियों का यह एक कॉरीडोर भी है। लगभग 38 प्रतिशत वनवासी बाहुल्य यह लोकसभा क्षेत्र पिछले छह बार से भाजपा के कब्जे में है। लेकिन विधानसभा में भाजपा एक बार भी क्लीनस्वीप नहीं कर पाई। पारंपरिक वनवासी भाजपा की ओर झुकें हैं। नक्सली सत्ता के खिलाफ रहते हैं सो इनका जहां असर होगा वे भाजपा के खिलाफ ही अपना फरमान देंगें। इस बार एक बड़ा फैक्टर हैं कंकर मुंजारे। कभी ये फायर ब्रांड विधायक हुआ करते थे। एक बार निर्दलीय तो एक बार सपा से। ये बालाघाट से एक बार सांसद भी रहे चुके हैं। इस बार बसपा से प्रत्याशी हैं। पिछड़े लोधी वर्ग से आते हैं जो कि यहां की प्रभावी जमात है, जन-धन-बल तीनों से। पिछली बार बसपा को यहां से 6.5 प्रतिशत वोट मिले थे। इतने प्रतिशत वोटों की घट-बढ़ सारे समीकरण बिगाड़ देती है। कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक हैं और कांग्रेस के लिए जी जान से जुटी हैं। जाति से बिंधी राजनीति को साधने के लिए भाजपा ने यहां से भारती पारधी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वार को।नक्सली आतंक एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा सरकार ने उसपर काबू पाया है। वनवासियों ने अति गरीबों के लिए भाजपा की जन-मन योजना असर दिखा रही है। भाजपा के पुराने स्टालवार्ट ढाल सिंह बिसेन, गौरीशंकर बिसेन और दादा देशमुख क्या कर रहे हैं, खबरें कुछ भी बयान नहीं करतीं पर अब इतना माद्दा भी नहीं बचा कि टिकट कटने के बाद सहानुभूति के जरिए पार्टी का कुछ बिगाड़ सकें। गोंगपा भी कभी एक बड़ा कारक रहा करती थी लेकिन अब तितर-बितर है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल उसके साथ है.. और इस चुनाव में उन्नीस के मुकाबले बीस ही रहने वाला। मंडला का मन डोला..! मंडला से अबतक जो खबरें आ रही हैं वो भाजपा की पेशानी पर बल डालने वाली हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते छठवीं बार जीत के इरादे से मैदान पर हैं। उन्हें कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम से खासी टक्कर मिल रही है। फग्गन केन्द्र में बरसों से मंत्री रहे हैं तो ओंकार पिछले तीन बार से अच्छे खासे मतों से विधायकी जीत रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मंडला का रुख कांग्रेस के पक्ष में रहा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

केजरीवाल का स्वास्थ्य
राजनीति का विषय

अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य राजनीति का विषय बन गया है। इससे राजनीति की इस स्तर तक गिरावट स्पष्ट है जहां राजनीतिक लाभ के लिए जीवन को दांव पर लगाया जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में प्रशासन और जन-कल्याण को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यहां यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति उभर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित घटनायें इस प्रवृत्ति का उदाहरण हैं। यहां स्वास्थ्य संकट एक प्रकार से 'नायकत्व' का प्रतीक बन गया है और स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने के बजाय यह संकुचित राजनीतिक विमर्श विकसित करने के काम आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय-ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल जानबूझ कर उच्च शर्करा वाला भोजन ले रहे हैं ताकि अपनी जमानत का आधार तैयार कर सकें। लेकिन केजरीवाल की सहयोगी आतिशी ने इसे खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि जेल में बंद मुख्यमंत्री को आवश्यक इंसुलिन तथा घर में बने खाने से वंचित करने के लिए एक षडयंत्र किया गया है जिससे उनका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। दोनों दावे एकदम विपरीत होने के बावजूद स्वास्थ्य संकट का राजनीतीकरण रेखांकित करते हैं। सत्ता की राजनीति में जहां नैतिकता को पीछे छोड़ दिया जाता है, अब मानव जीवन की पवित्रता की भी अनदेखी होने लगी है। ऐसे में किसी व्यक्ति की बेहतरी के बजाय संकुचित लाभ के लिए उसके संकटों का लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा विमर्श न केवल राजनीतिक विमर्श की निष्ठा पर, बल्कि प्रशासन से जुड़े लोगों की नैतिकता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। ईडी ने जोर दिया है कि केजरीवाल जानबूझ कर अपने स्वास्थ्य से छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि उसका कानूनी लाभ उठाया जा सके। इससे पता चलता है कि कोई राजनेता अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए किस सीमा तक गिर सकता है। इससे वह संस्कृति रेखांकित होती है जहां लोगों के व्यक्तिगत संघर्षों को राजनीतिक लाभ के लिए हथियार बना दिया जाता है। इसके उलट, केजरीवाल का जीवन संकट में डालने के आतिशी के आरोपों से बेलगाम राजनीतिक लफ्फाजी के खतरनाक परिणाम रेखांकित होते हैं। यदि बिना किसी प्रमाण के हत्या के प्रयास के आरोप लगाए जाते हैं तो इससे न केवल अविश्वास के बीज उगते हैं, बल्कि ऐसे जघन्य अपराधों की गंभीरता भी कम होती है।

मुख्य रूप से 'केजरीवाल प्रकरण' राजनीति का गहरा संकट रेखांकित करता है जहां मानव गरिमा पर राजनीतिक सुविधा को वरीयता मिलती है। सत्ता और प्रभाव की अथक खोज में अक्सर निहित स्वार्थों की बलिवेदी पर मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य बलिदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार संवेदना और गरिमा की कमी न केवल लोकतंत्र का ढांचा कमजोर करती है, बल्कि नागरिकों के मूलाधिकारों व स्वतंत्रताओं को भी खतरे में डालती है। मामले में सच और झूठ पर ज्यादा गौर किए बिना सभी लोगों की तरह केजरीवाल को भी सर्वोत्तम इलाज मिलना चाहिए, भले ही यह बीमारी स्वयं उनके द्वारा पैदा की गई हो। राजनीति के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए राजनेताओं को अपनी प्राथमिकतायें पुन: निर्धारित कर उनमें सद्भावना, निष्ठा तथा जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यक्तियों के कल्याण को कभी 'राजनीतिक दांवपेंच' का आधार नहीं बनने देना चाहिए। राजनेताओं को हर नागरिक की गरिमा व बेहतरी के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए, भले ही उसका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। 'केजरीवाल प्रकरण' मानवता को कुचल कर राजनीति करने के जोखिम की ओर संकेत करता है।

सूकी की सुरक्षा पर संकट

आंग सान सूकी की सुरक्षा पर ऐसे समय संकट मंडरा रहा है, जब म्यांमार में सैनिक शासक पराजय की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार पूरे घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

म्यांमार में लोकतांत्रिक चुनाव से निर्वाचित आंग सान सूकी के जेल में बंद होने या अपने ही घर में नजरबंद होने के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है। आंग सान सूकी की सुरक्षा पर ऐसे समय संकट मंडरा रहा है, जब म्यांमार में सैनिक शासक पराजय की कगार पर पहुंच गए हैं। न्यूज़ वेबसाइट 'द इरावडी' ने 'नैपीटा व यंगून में विश्वस्त सूत्रों' का संदर्भ देते हुए कहा है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रतीक 78 वर्षीय आंग सान सूकी तथा देश की लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के जेल में बंद 72 वर्षीय राष्ट्रपति विन मिंट जेल में बंद हैं। इनको 1 फरवरी, 2021 में हुए सैनिक विद्रोह के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। वेबसाइट की उच्च स्तरीय विश्वसनीयता को देखते हुए यह बात वास्तव में सही हो सकती है। इस संबंध में उसके द्वारा दी गई खबर को भी विश्वसनीय माना जा रहा है। लेकिन 16 अप्रैल की दोपहर के बाद से स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जब सरकार-समर्थक मीडिया ने कहा कि दोनों को नए ठिकाने पर ले जाया गया है।

इसके बाद सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जा मिन तुन ने वीओए व बीबीसी की बर्मा सेवाओं को बताया कि 'मौसम के बहुत अधिक गरम होने के कारण न केवल डा आंग सान सूकी और यू विन मिंट, बल्कि कुछ अन्य वृद्ध बंदियों की आवश्यक देखभाल की जा रही है।' लेकिन उसने यह नहीं बताया कि क्या सूकी को एक नए स्थान पर ले जाया गया है। जब मीडिया संगठनों ने ज्यादा सूचनाओं के लिए उन पर दबाव डाला तब भी उन्होंने कोई विस्तृत विवरण नहीं दिए। इस बात के कोई फोटोग्राफिक या अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं जिनमें उनको 'हाउस अरेस्ट' में ले जाने का विवरण मिलता हो। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय स्रोत तथा खबरिया एजेंसियां उनके हाउस अरेस्ट के बारे में खबरें प्रसारित करते रहे।

लेकिन यह सच नहीं है। आंग सान सूकी के बेटे किम एरिस ने एक ब्रेकफास्ट इंटरव्यू के दौरान 'स्काई न्यूज़' के के बर्टले को बताया, 'वे हाउस अरेस्ट की बात करते हैं। लेकिन सूकी के पास केवल एक घर है और वे वहां नहीं हैं।' सैनिक शासक तथा उनके प्रवक्ता के रूप में काम करने वाली खबरिया एजेंसियों की अत्यधिक अविश्वसनीयता को देखते हुए यह भ्रम बना रहने की संभावना है। शायद दोनों जानबूझ कर इस बारे में भ्रम बने रहने देना चाहते हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो सवाल उठता है कि इस कृत्य के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? इसका सर्वाधिक उपयुक्त जवाब यह छवि बनाना हो सकता है कि सैनिक शासक उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अचानक क्यों बताया जा रहा है? कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि आंग सान सूकी जेल में बहुत बीमार हैं और सैनिक शासक उनको आवश्यक चिकित्सकीय सहायता नहीं दे रहे हैं। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सैनिक शासक सूकी की जेल में हत्या करवा कर यह दावा कर सकते हैं कि उनकी मौत वृद्धावस्था या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से हो गई है।

जो भी हो, वर्तमान प्रकरण से स्पष्ट है कि जनरल यह छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि सुश्री सूकी के साथ कोई अवांछित घटना हो जाती है तो वे उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इसका एक और कारण सैनिक शासकों के बीच व्याप्त मतभेद हैं। ये मतभेद बढ़ रहे हैं और सैनिक शासकों का एक वर्ग सुश्री सूकी के साथ समझौता कर देश में व्याप्त गृह युद्ध समाप्त करवाना चाहता है। सैनिक शासक गृह युद्ध में लगातार पराजित हो रहे हैं और वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। म्यांमार सेना का असली नाम टटमाडा के बजाय सिट-टैट है और वह निकट भविष्य में ही पराजित होने वाली है। विपक्षी 'थ्री ब्रदरहुड एलायंस' द्वारा 27 अक्टूबर, 2023 से छेड़े वर्तमान युद्ध में सरकारी सेनायें एक के बाद दूसरी पराजयों का सामना कर रही हैं। इस युद्ध को 'आपरेशन 1027' का नाम दिया गया है। सैनिक शासकों की नवीनतम पराजय 11 अप्रैल, 2024 को म्यावाडी को खो देना है जो एक महत्वपूर्ण सीमान्त कस्बा है। करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी-केएनएलए व करेन नेशनल आर्मी के हाथों हुई यह पराजय सैनिक शासकों की सर्वाधिक अपमानजनक पराजय है, जबकि पराजयों का सिलसिला एलायंस के वर्तमान आपरेशन के बाद से ही शुरू हो गया था। म्यावाडी म्यांमार के पूर्वी सिरे पर थाईलैंड की सीमा के निकट प्रमुख व्यापार केन्द्र है। यहां से होकर गुजरने वाला कुल आयात और निर्यात 2023 में 1 बिलियन डालर था। इसे दक्षिण-पूर्व आशियान देशों के लिए म्यांमार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है।

बताया जाता है कि म्यांमार के सैनिक शासक एक जवाबी युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी यह तय नहीं है कि इसकी शुरुआत होगी। यह भी देखना होगा कि यदि ऐसा कोई जवाबी युद्ध शुरू हो जाता है तो भी वह किस सीमा तक सफल होगा। लेकिन यदि यह सफल हो जाता है तो भी आशंका है कि क्या सिट-टैट शहर पर फिर कब्जा करने के बाद इसका कब्जा अपने पास बनाए रखने में सफल होगा। लेकिन इन सबके बावजूद केवल यह एक युद्ध व्यापक रूप से चल रहे गृह युद्ध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकेगा। वर्तमान समय में म्यांमार के सैनिक शासक एक व्यापक जन-विद्रोह का सामना कर रहे हैं। अपने मौजूदा चरण में गृह युद्ध पूरी तरह विद्रोही सैनिक एलायंस के पक्ष में है। इस एलायंस में उत्तरी शान राज्य के कोकांग विशेष क्षेत्र में सक्रिय म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी-एमएनडीएए की प्रमुख भूमिका है। म्यांमार के सैनिक शासक के खिलाफ एलायंस में शान राज्य में सक्रिया टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी-टीएनएलए तथा देश के पश्चिमी भाग में राखीन राज्य में सक्रिय अराकान आर्मी-एए भी शामिल हैं। म्यांमार में सैनिक शासक के खिलाफ जन-विद्रोह में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय मुक्ति सेनाओं के बीच निकट समन्वय स्थापित है। म्यांमार की अपदस्थ लोकतांत्रिक सरकार ने एक निर्वासित सरकार बनाई है तथा उसकी सशस्त्र शाखा भी सैनिक शासन के खिलाफ जन-विद्रोह व विभिन्न सैनिक गतिविधियों में समन्वय बनाने का प्रमुख काम कर रही है। विपक्षी सरकार की सैनिक शाखा पीपुल्स डिफेंस फोर्स-पीडीएफ म्यांमार के सैनिक शासन के खिलाफ सक्रिय अनेक नस्ली सेनाओं के साथ ही केएनएलए व केएलए के साथ समन्वय बना रही है।

म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ चल रहे व्यापक व तेज गृह युद्ध की स्थितियों पर गौर करें तो अनेक चीजें स्पष्ट होती हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वर्तमान समय में एए ने देश के पूरे राखीन राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। 1 अप्रैल तक उसने सैनिक शासकों द्वारा संचालित सेना सिट-टैट के 170 शिविरों और चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही उसने सरकारी सेना के अनेक बड़े अड्डों, बटालियन मुख्यालयों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं पर भी कब्जा कर लिया है। अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से अराकान आर्मी-एए ने 15 जनवरी, 2024 को पलेटवा के महत्वपूर्ण कस्बे पर कब्जा कर लिया था। यहां चीन एक बंदरगाह तथा 1,600 हेक्टर क्षेत्र में फैले विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास कर रहा था।

एए के कब्जे के बाद अब चीन की इन परियोजनाओं का निर्माण असंभव हो गया है। चीन प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से म्यांमार में लोकतांत्रिक सत्ता का तख्ता उलटने तथा आंग सान सूकी की गिरफ्तारी के बाद से ही म्यांमार के सैनिक शासक का समर्थन कर रहा है और देश के विशाल भूभाग पर अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कब्जा करना चाहता है। चीन की इस विशाल परियोजना को गहरा धक्का देने के साथ ही अराकान आर्मी सितवे पर भारी दबाव डाल रही है। सितवे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। एए ने पहले इस महत्वपूर्ण कस्बे के आसपास बसे छोटे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया और सड़कों तथा जलमार्गों के माध्यम से सितवे तक पहुंच को काट दिया है। म्यांमार में जारी गृह युद्ध को देखते हुए भारत ने अप्रैल, 2024 की शुरुआत में ही यंगून से अपने कौंसुलेट कर्मचारियों को हटा दिया था।

पहले यह सोचा जाता था कि अपरिहार्य होने के बावजूद म्यांमार के सैनिक शासन का पतन होने में लंबा समय लगेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि म्यांमार सैनिक शासन का पतन अनुमानित समय के बहुत पहले ही हो जाएगा। भारत ने हमेशा म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार तथा वहां लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रतीक आंग सान सूकी का समर्थन किया है। ऐसे में भारत सरकार की स्वाभाविक रूप से म्यांमार में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर नजर है।

प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक

डॉ सुशील द्विवेदी
(लेखक, पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी और इसके पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का प्रतीक है। पहला पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन ने की जिसमें लगभग दो करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में हिस्सा लिया था.तब से हर साल पृथ्वी दिवस का आयोजन एक विशेष थीम के साथ 22 अप्रैल को होता आ रहा है इस वर्ष 2024 की थीम, गृह बनाम प्लास्टिक है। इस थीम, के साथ अर्थ दिवस मनाने का उद्देश्य मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पिछले वर्षों मैं पृथ्वी दिवस की थीम के रूप मैं जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर प्रजातियों की रक्षा और वृक्षारोपण के लाभों तक कई पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल किया जा चुका है। इस वर्ष की थीम, गृह बनाम प्लास्टिक, इसलिए और भी प्रासांगिक है क्योंकि प्लास्टिक पर 2024 के अंत तक एक ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि हेतु दुनिया के देशों की सहमति होने की उम्मीद है।प्लास्टिक को लेकर ब्रिटेन सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों ने 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का आह्वान किया है ।

धरती पर आज इन्सान प्लास्टिक से बुरी तरह घिर चुका है वह प्लास्टिक खा रहा है , पी रहा है और पहन भी रहा है जहां इसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया, पर साथ ही यह अपने साथ अनेको समस्याएं भी साथ लाया। उन्हीं में से एक इसके प्रदूषण की समस्या है। दुनिया के सामने यह समस्या कोई नयी नहीं है, काफी समय से हम इसके बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आज हम हर साल करीब 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा फैला रहे हैं, जो कि सम्पूर्ण मानव जाति के भार के बराबर है। आज दुनिया भर के लिए अब प्लास्टिक एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ की चोटियों तक इंसान ने प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों से ग्रह को पाट दिया है अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको प्लास्टिक की कई सारी चीज़ें नज़र आएंगी. ऐसी ही चीज़ों के बारीक़ टुकड़े जब बहुत छोटे आकार में टूट जाते हैं तो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है. *आमतौर पर पाँच मिलीमीटर से छोटे टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं. कुछ टुकड़े इससे भी छोटे होते हैं, जिन्हें नैनो स्केल में ही मापा जा सकता है. उन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। ये प्लास्टिक के बारीक-महीन कण, हर उस चीज में पहुंच रहे हैं जो हम खाते हैं और जिसमें हम सांस लेते हैं. ऐसा अनुमान है कि इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक व्यक्ति औसतन हर साल 50 हजार से ज़्यादा प्लास्टिक कणों का उपभोग करता है, और अगर इसमें सांसों के जरिए हमारे भीतर पहुंचने वाले कणों को भी शामिल कर लिया जाए, तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। जब कभी हम यात्रा कर रहे हों या ऐसी जगह हो, जहां साफ पानी न मिल पाए, वहां हमारी कोशिश रहती है कि बोलतबंद पानी मिल जाए। हम यह मानते हैं कि इस पानी में गंदगी नहीं होंगी. लेकिन इस पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के असंख्य महीन कण हो सकते हैं। आज धरती पर धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति कम से कम 5 ग्राम अर्थात एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के भार जितना प्लास्टिक पानी से , खाने से या माइक्रोप्लास्टिक युक्त हवा से अपने शरीर मैं ले रहा है। पीने का साफ़ पानी हम सभी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। आईआईटी पटना के एक शोध में बारिश के पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक कण मिले थे. इसी तरह एक अन्य शोध में पाया गया कि भारत में ताज़ा पानी की नदियों और झीलों तक में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। इनमें फ़ाइबर, छोटे टुकड़े और फ़ोम शामिल हैं। इस शोध के मुताबिक, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और शहरी इलाक़ों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट जैसे कई कारणों से ये हालात बने हैं। माइक्रो प्लास्टिक पानी के अलावा यह उस जमीन में भी बहुतायत में पाए जाने लगे हैं, जहां खेती होती है।

अमेरिका में साल 2022 में एक पड़ताल की गई थी. इसके मुताबिक़, सीवर की जिस गाद को वहां फसलों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक होने के कारण 80 हज़ार वर्ग किलोमीटर खेती योग्य जमीन दूषित हो गई थी। इस गाद में माइक्रोप्लास्टिक्स के अलावा, कुछ ऐसे केमिकल भी थे, जो कभी विघटित नहीं होते यानी उसी अवस्था में बने रहते हैं.वहीं, ब्रिटेन में कार्डिफ़ यूनिवर्सिटी ने पाया था कि यूरोप में हर साल खेती वाली जमीन में खरबों माइक्रोप्लास्टिक कण मिल रहे हैं जो हर निवाले के साथ लोगों के शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं, जिनमें बाक़ियों की तुलना में माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा होता है.दरअसल, *कुछ शोध बताते हैं कि जड़ों वाली सब्ज़ियों में माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा पाए जाते हैं. यानी पत्ते वाली सब्जियों में कम माइक्रोप्लास्टिक होंगे, जबकि मूली और गाजर जैसी सब्ज़ियों में ज्यादा देखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में शरीर में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की पहचान की है, संभावना है कि इंसान वर्षों से प्लास्टिक के छोटे कण को खा रहे हैं, पी रहे हैं या सांस के जरिए शरीर में ले रहे हैं। हालांकि मनुष्यों पर स्वास्थ्य अध्ययन अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, कुछ जानवरों में विषाक्तता चिंताओं को पुष्ट करती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड द्वारा किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक केमिकल्स अगली दो पीढ़ियों में मेटाबॉलिक डिजीज का कारण बन सकते हैं।माइक्रोप्लास्टिक के ख़तरों को लेकर अभी सीमित शोध सामने आए हैं. कुछ शोध ऐसे भी हैं कि ये हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियों (हारमोन पैदा करने वाली ग्रंथियों) के काम में समस्या पैदा करती हैं. हो सकता है भविष्य में पता चले कि माइक्रोप्लास्टिक बहुत गंभीर नुक़सान कर सकते हैं, इसलिए अभी से सजग रहने की ज़रूरत है। हर दिन ऐसे नए अध्ययन सामने आ रहे हैं जिनमें इनके इंसानों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ते दुष्प्रभाव उजागर हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए उपलब्ध विज्ञान और समाधानों के मद्देनज़र, देशों की सरकारों, कम्पनियों और अन्य हितधारकों से, इस संकट को सुलझाने के लिए कार्रवाई की गति और दायरा बढ़ाने होंगे. आज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने या प्लास्टिक के विकल्प के रूप मैं अन्य प्रकृति हितैषी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की जरूरत है इस पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी और प्लास्टिक के 100 साल पुराने रिश्ते को अलविदा कहने के बारे मैं गंभीरता से विचार करके कदम उठाना होगा।

पृथ्वी दिवस पर आप छोटे छोटे काम करके पृथ्वी को बचाने में जैसे महत्पूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े के थैले का उपयोग करें और पुन: प्रयोज्य पानी की बोतल लें। ऊर्जा को बचाने का काम करें। इसके लिए जरूरी है बत्तियां बंद करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें। जब आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हों। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रुरी हैं, इसलिए पानी बचाएं इसके लिए आप कम समय तक शॉवर लें और नल को बंद कर दें। साथ ही न पौधे लगाएं और पेड़ों की रक्षा करें बल्कि तीज त्योहार जन्मदिन शादी की वर्षगांठ व अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर हरे भरे पौधे लोगों को भेंट मैं दें।

आप की बात

यात्री सुविधा

रेलवे ने मनपसंद सीट पाने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है ताकि हवाईजहाज और सिनेमा की तरह रेलयात्री भी अपनी सीट बुक करवा सकें। लेकिन हर ट्रेन में सीमित सामान्य बोगियों के कारण इस श्रेणी के यात्रियों को बहुत ही कष्टमय यात्रा करनी पड़ती है। कम दूरी की बात छोड़ें किन्तु लम्बी दूरी की यात्रा तो और भी अधिक दिक्कत भरी हो जाती है। सामान्य बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती तब बैठकर सुकून से यात्रा करना तो उनके लिए दूभर सपना बन जाता है। अत्याधुनिक और सुविधाजनक ट्रेनें बेशक रेलवे चलाये किन्तु सामान्य श्रेणी के यात्रियों के बारे में भी सोचे ताकि उनकी दुखभरी यात्रा में थोड़ा सुकून आ सके। हालांकि, आधुनिक रेलें हमारे विकास की प्रतीक हैं परन्तु विकास का लाभ सबको मिलना चाहिए, फिर चाहे वह कम पैसे खर्च करने वाला सामान्य यात्री ही क्यों न हो। रेलें आम जनता की यात्रा का आज भी प्रमुख साधन हैं। अत: तुलनात्मक रूप से अमीरों की तुलना में गरीब व सामान्य रेल यात्रियों को कम से कम मानवीय ढंग से यात्रा करने का अवसर मिलना चाहिए। गरीबों की यात्रा को विशिष्ट सेवायें प्राप्त करने वाले अमीरों से प्राप्त धनराशि या माल भाड़े की आमदनी से फाइनेंस करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह सरकार का दायित्व भी है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

फर्जी मतदाता

निर्वाचन आयोग ने हैदराबाद जिले की मतदाता सूची से 5.41 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। इस जिले में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का कारण उनकी मौत होना, निवास बदलना और दो बार नाम दर्ज होना है। इस प्रकार यह सारे के सारे मतदाता फर्जी थे। जब घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया गया तब पता चला कि यह सब तो डमी है। हैदराबाद की इस घटना से देश भर में फर्जी मतदाताओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। अब आज निर्वाचन पद्धति में एक-एक वोट महत्वपूर्ण है। ऐसे में पांच लाख से अधिक फर्जी मतदाता किसी भी हारने वाले उम्मीदवार को जिता सकते हैं और जीते हुए उम्मीदवार को हरा सकते हैं। हैदराबाद के इस प्रकरण को देखते हुए अब समय आ गया है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया जाए और जो ऐसा नहीं करें उन्हें मतदान से वंचित रखने का सख्त नियम बनाया जाए। देश में लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के लिए समान मतदान सूची बनाना तथा उसे सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके साथ ही जनता को फर्जी मतदाताओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

उपभोक्ताओं से ठगी

दुनिया भर के आम नागरिक बढ़ती महंगाई की मार सह रहे हैं। ऐसे में अनेक देशों के खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं ने ठकी की नई तरकीब निकाली है। ग्राहकों से बढ़े दाम लेने के बदले पुरानी कीमत पर डब्बाबंद चीजें दी जाती हैं, मगर उनका वजन कम कर दिया जाता है। इससे ग्राहकों को लगता है कि कीमत नहीं बढ़ी है, मगर उसे ये समझने में काफी समय लगता है के सामान का वजन कम कर उससे ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं। फ्रांस ने इसे लेकर सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। वहां के वित्तमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से ऐसे मामलों के बारे में दुकानदारों को स्पष्ट रूप से अपने ग्राहकों को बताना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उत्पादों के वास्तविक मूल्य विकास को समझना चाहिए। ऐसा ही नियम इस समय भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं वाले देश में भी बनना चाहिए। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में उपभोक्ता आंदोलन कमजोर रहा है। इसके साथ ही ऐसी स्वतंत्र एजेंसियों की बहुत कमी है जो अपनी आय के लिए विज्ञापनों पर निर्भर न हों तथा विभिन्न उत्पादों के निर्माण में आने वाले खर्च, उपभोक्ता से लिए जाने वाले मूल्य तथा उत्पादों की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन कर जागरूकता फैलाएं।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

सराहनीय कदम

विद्युत कंपनी द्वारा नई तकनीक के जरिए विद्युत लाइन में फाल्ट की जानकारी तत्काल मोबाइल पर मिल जाएगी। यह सराहनीय कदम है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते सभी तरह के कामकाज में चमत्कारी सुधार व सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राइवेट सेक्टर तो इनको हाथों हाथ अपना रहा है। मगर शासकीय कार्यालय इस बारे में कोई उत्सुकता व तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। इसका एक कारण रिश्वतखोरी भी है। जब उपभोक्ताओं का सारा काम ऑनलाइन होने लगेगा तो भ्रष्ट तत्वों को मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बातचीत व लोक व्यवहार में भी शासकीय कर्मचारियों में एक प्रकार का सूपेरियारिटी कंपलेक्स है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के सभी विभागों के कर्मचारी जिस सम्मान व नम्रता से उपभोक्ताओं से व्यवहार करते हैं वह अनुकरणीय व अभिनंदनीय है। हालांकि, सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं । सभी शासकीय विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को शीघ्रता से अपनाना और व्यर्थ की औपचारिकताओं को खत्म करना चाहिए। यह सराहनीय कदम होगा।

–**विभूति बुपक्या**, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुभाषित *तुम्हारे लक्ष्यके अलावा जिसपर भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है।* ❐ *स्वामी विवेकानन्द*

बुजुर्गोंके हितमें कदम

बढ़ती उम्रके साथ बीमारियोंका दायरा भी बढ़ने लगता है और इलाजका खर्च बढ़नेसे वरिष्ठ नागरिकोंको काफी परेशानीका सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितिमें स्वास्थ्य बीमा बड़ा सम्बल होता है क्योंकि इलाज और अस्पतालोंके अन्य खर्चे इतने बढ़ गये हैं कि सामान्य व्यक्तिके लिए इनका निर्वहन करना दुष्कर हो गया है। इस सम्बन्धमें भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने राहतकारी कदम उठाया है, जो स्वागतयोग्य है। एक अप्रैल २०२४ से इरडा ने कुछ नीतिगत परिवर्तन किया है, जो प्रभावी भी हो गया है। अब स्वास्थ्य बीमा पालिसी खरीदनेके लिए अधिकतम उम्रकी सीमा समाप्त कर दी गयी है। पहले ६५ वर्षकी आयु तक ही नयी बीमा पालिसी खरीदनेकी अनुमति थी। अब ६५ वर्षसे अधिक उम्रके लोग भी अपना स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं। निजी बीमा कम्पनियां ऐसे लोगोंका बीमा करने से मना नहीं कर सकेगी। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इरडा ने यह भी कहा है कि बीमाकर्त्ताओंको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आयु समूहोंके लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करे। इरडा का यह बड़ा नीतिगत निर्णय है। इसका उद्देश्य वरिष्ठजनोंको राहत पहुंचाना और एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना तथा बीमा प्रदाता कम्पनियोंको अपने उत्पादकी पेशकशमें विविधता लानेके लिए प्रोत्साहित करना है। एक बड़ी समस्या बीमा दावेके भुगतानसे सम्बन्धित है, जिसमें प्राय: अड़चनें आती हैं। इसे सरल और आसान बनानेके लिए व्यवस्था की गयी है कि सभी बीमारियोंका दावा भुगतान पांच वर्ष बाद हर हालमें देना होगा। साठ माह तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज जारी रहनेके बाद किसी भी बहानेसे बुजुर्गोंके क्लेमको बीमा कम्पनियां खारिज नहीं कर सकती हैं। इरडा ने दावोंके भुगतानके सम्बन्धमें बीमा कम्पनियोंकी हीलाहवाली और बहानेबाजीपर अंकुश लगाकर उपभोक्ताओंके हितमें बड़ा कदम उठाया है। पहले से घोषित बीमारीका कवरेज अब तीन सालके बाद ही मिलने लगेगा जबकि पहले इसकी सीमा चार वर्ष थी। इरडा ने जो राहतकारी कदम उठाया है, उससे बड़ी संख्यामें वरिष्ठ जन लाभान्वित होंगे। इरडा की बीमा कम्पनियोंकी सेवाओंपर सतत नजर रखनेकी भी आवश्यकता है।

दालकी बढ़ी कीमतें चिन्तनीय

आजके दौरमें महंगी देशके समक्ष सबसे बड़ी समस्या है, जिसपर अंकुश लगानेके लिए केन्द्र सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। विशेषकर दैनिक उपयोगकी खाद्य पदार्थोंकी कीमतोंमें वृद्धि आमजनकी परेशानी बढ़ानेवाली है। जलवायु परिवर्तनके कारण मौसमकी अनिश्चिततासे भी दुश्वारियां बढ़ी हैं क्योंकि इसका दुष्प्रभाव फसलोंपर पड़ा है जिससे उत्पादनमें कमी आयी है। इन दिनों दालकी कीमतोंमें लगातार वृद्धि विशेष चर्चामें है। सरकार की लाख कोशिशोंके बावजूद पिछले कई महीनोंसे दालकी कीमतोंमें बढ़ोत्तरी जारी है। मुख्य रूपसे अरहर दालकी कीमतोंमें तेजी से जहां सरकार चिन्तित है, वहीं आम लोगोंकी दिक्कतें बढ़ी हैं। सरकार ने अब कीमतोंपर लगाम लगानेके लिए सभी कम्पनियोंसे दाल की आपूर्ति तेज करनेको कहा है। दालकी जमाखोरी करने वाले व्यापारियोंके खिलाफ सख्त काररवाई करनेकी चेतावनी भी दी है। इसका कितना प्रभाव जमाखोरोंपर पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही बतायगा। सरकारकी ओर से दालके आयातको सुगम बनानेका प्रयास किया रहा है। इस दिशामें साल २०२५ के मार्च तक अरहर, उड़द और मसूर दालके आयातको शुल्कमुक्त किया जाना सरकारका सार्थक कदम है। पिछले तीन माहमें अरहर दालके थोक दाममें २० रुपये प्रति किलो तक बढ़ोत्तरीके चलते खुदरा बाजारमें इसकी कीमत १६० रुपये प्रति किलो तक पहुंच गयी है जो मध्यम और गरीब लोगोंकी थालीसे दूर होनेकी स्थिति है। दालकी कीमतोंका बेलगाम होनेका मुख्य कारण है कि विदेशोंमें जमाखोरी कर रही भारतीय कम्पनियां अन्य देशोंसे अरहर दालकी खरीदारी तो कर रही हैं लेकिन उसे भारत नहीं ला रही हैं। ऐसी कम्पनियोंके विरुद्ध सख्त रुख अपनानेकी जरूरत है जिससे मांगके सापेक्ष आपूर्तिका तालमेल बना रहे। सरकारको इसपर विशेष निगरानी रखनेकी आवश्यकता है।

लोक संवाद

प्रशासनिक कुशलतापर वोट

महोदय,- हार-जीत चुनावी अंग है। मतदाता किस आधारपर वोट करते हैं यह कहना जटिल काम है। धर्म भाषा और संस्कृतिकी विविधता लिए सबसे बड़े लोकतंत्रकी विशेषताएं है। भाजपा ओर कांग्रेस एक-दूसरेपर हमलावर है। भाजपा मोदीकी गारंटीपर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेसके पास न्याय पत्र ही लोकसभा चुनावका बड़ा हथियार है। राजस्थानमें कांग्रेस दस सालोंमें चुनाव हार रही है। मोदीका फैक्टर काम कर रहा है। कांग्रेसके दिग्गज नेताओंने भाजपाका रुख किया है। राहुलने सीधा निशाना मोदीपर साधा है एलेक्ट्रोरल बॉण्डपर मोदीको घेरा है। आखिर क्या चाहते हैं मतदाता। एक्जिट पॉल और सारे अनुमान मटदाताके समक्ष धरेके धरे रह जाते हैं। एक बार मतदाता निर्णय करता है तो उसके किल्लेको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। मतदाता एक ही पार्टीको वोट करते आ रहे हैं। उस समय घोषणा-पत्रको नहीं देखा जाता है। ऐसे लाखों मतदाता है जिनका निशान दिमागमें है और उसीको वोट करते है। चुनावमें प्रचार-प्रसारके दौरान अपने चहते नेताओंको सुनना पसंद करते हैं। इंडी गठबंधन और एनडीए अपने-अपने समीकरण और गणित लगा रही है। देशमें कोई भी गम्भीर मुद्दे होते हुए कांग्रेसको नकारना कांग्रेसकी विफलताका मुख्य कारण कानून व्यवस्था तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारका अपराधबोधसे लोग ग्रसित है। भाजपाकी विदेश नीतिमें बदलाव भारतकी साखमें वृद्धि हुई है। मोदीने न्यायपत्रको विभाजनकारी बताया, क्योंकि कांग्रेसका न्यायपत्रपर जनताकी विचारधारा निर्भर करती है। राजनीतिक दल वोटरोंको हल्केमें नहीं लेना चाहिए। बूथपर मन बदलनेवाले वोटर गणितमें फेरफार कर सकते हैं। देशकी सुरक्षा आतंकवाद धार्मिक स्वतंत्रता महंगी और विदेश नीति जैसे मुद्दे खास फैक्टर है। इनको आधार बनाकर वोट किया जाता है। अनुशासनकी कमीसे सीधा असर मतदानपर पड़ता है। इसलिए नेताओंकी कथनी और करनी समान होनी चाहिए। विकासके नारेको गम्भीरतासे लिया है। मोदीके विकासमें २५ सौ किमी हाइवे बनाये गये। बिना भेदभाव राशन मुहैया कराया गया। आशा विश्वास और मोदीकी त्रिवेणी मोदीकी गारंटीसे चुनाव लड़नेकी इस धारणापर आगे बढ़ रहा है। **-कांतिलाल मांडोत, सूरत।**

लोकसभा चुनावकी तस्वीर

इस समय लोकसभा चुनावको लेकर कई तरहके मत हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे प्रबल मत यह है कि भाजपा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें अपने सहयोगी दलोंके साथ तीसरी बार भारी बहुमतसे सरकारमें लौट रही है। दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि भाजपा चुनाव हार रही है और वह २०० सीटोंसे नीचे चली जायगी।

❐ **अवधेश कुमार**

सबसे प्रबल मत यह है कि भाजपाके ३७० और सहयोगी दलोंके साथ चार सौ सीटें मिलनेकी भी भविष्यवाणी हो रही है। विपक्ष भाजपाकी आलोचना करती है, नरेन्द्र मोदीपर सीधे प्रहार भी करती है, परन्तु अपने समर्थकों और भाजपा विरोधियोंके अन्दर भी विश्वास नहीं दिला पाती कि वाकई वह भाजपासे सत्ता छीननेकी स्थितिमें चुनाव लड़ रहे हैं। इण्डी गठबंधनकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेससे नेताओंके छोड़कर जानेका कायम सिलसिला इस बातका प्रमाण है कि पार्टीके अन्दर कैसी निराशा और हताशाका सामूहिक मनोविज्ञान व्याप्त है। इसमें आम मतदाता और विश्लेषक स्वीकार नहीं कर सकते कि वाकई विपक्षी दल भाजपा और राजगको सशक्त चुनौती देनेकी स्थितिमें है। तो फिर इस चुनावका सच क्या हो सकता है। आखिर ४ जूनका परिणाम क्या तस्वीर पेश कर सकता है। इस चुनावकी एक विडंबना और है। भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकोंका एक वर्ग स्वयं निराशाजनक बातें करता है। इनमें ऐसे लोगोंकी संख्या बड़ी है जिनमें उत्साह या आशावादका भाव न के बराबर मिलता है। वे बताते हैं कि जैसी दिल्लीमें या बाहर हवा दिखती है धरातलपर वैसी स्थिति नहीं है। जब उनसे प्रश्न करें कि धरातलकी स्थिति क्या है तो सबके उत्तरमें कुछ सामान बातें समाहित होती हैं, गलत उम्मीदवारके कारण लोगोंके अन्दर गुस्सा या निराशा है, गठबंधनको सीट देनेके कारण अपने लोगोंके अन्दर निराशा है, गठबंधनने ऐसे उम्मीदवार खड़े किये हैं जिनका बचाव करना या जिनके लिए काम करना भाजपा कार्यकर्ताओंके लिए कठिन हो गया है। कुछ लोग अनेक क्षेत्रोंमें जातीय समीकरणकी समस्याका उल्लेख भी करते हैं। एक समूह यह कहता है कि आम कार्यकर्ताओं और नेताओंकी सरकारमें उपेक्षा हुई है, उनको महत्व नहीं मिला है और अब लोगोंका धैर्य चुक रहा है। यहांतक कि जिस तरहके लोगोंको पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा या टिकट दिया गया है उनसे भी लोग असहमति व्यक्त करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकोंके साथ विपक्षकी बातोंको मिला दिया जाय तो निष्कर्ष यही आयगा कि भले भाजपा चार सौ पारका नारा दे लेकिन यह हवाहवाई ही है। किन्तु क्या यही २०२४ लोकसभा चुनावकी वास्तविक स्थिति है।

प्रधान मंत्रीने २०४७ तक भारतको विकसित देश बनाने और अगले पांच वर्षोमें विश्वकी तीसरी अर्थव्यवस्था बननेका जो नारा दिया है वह लोगोंके दिलोंको छू रहा है। विपक्षकी आलोचनाके विपरीत नरेन्द्र मोदीकी विकास संबंधी नीति तथा समाजके हर वर्गके आत्मनिर्भर और विकसित होनेके लिए दिये गये कार्यक्रमोंने बड़े वर्गके बीच सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह पहली बार है जब भारतके बाहर भारत विरोधी आतंकवादी दनादन मारे जा रहे हैं और दुनियाके प्रमुख देशोंके विरोधके बावजूद ऐसा हो रहा है अन्यथा पूर्वकी सरकारें उनके समक्ष किंकर्तव्यविमूढ़ रहती थी।

यह बात सही है कि अनेक राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदिको शामिल किया जा सकता है वहां पार्टीके अन्दर कई जगह उम्मीदवारोंको लेकर विरोध है। कुछ उपयुक्त लोगोंको टिकट न मिलना तथा ऐसे सांसदोंको फिरसे उतारना जिनको लेकर कार्यकर्ता नाराजगी प्रकट करते रहे हैं विरोधका एक बड़ा कारण है। साथी दलोंने भी भाजपाके लिए समस्याएं पैदा की है। इन सबमें विस्तारसे जाना संभव नहीं, परन्तु कुछ संकेत दिये जा सकते हैं। उदाहरणके लिए बिहारमें लोजपाने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो परिवारवादका साक्षात प्रमाण है और भाजपाके लोगोंके लिए इनका बचाव करना कठिन है। कुछ साथी दलोंने सक्षमताकी जगह व्यक्तिगत संबंध और परिवारको टिकट देनेमें प्रमुखता दिया। बिहारके जमुईमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं प्रचारके लिये गये और वहां भाजपाके लोगोंने पूरी ताकत लगायी। इसका असर भी हुआ। बावजूद यह प्रश्न किया जा रहा है कि किसी नेताके बहनोई या २६ सालकी एक लड़कीको, जिसके पिता साथी दलमें नेता हैं उनको हम अपना नेता या प्रतिनिधि मानकर कैसे काम करें। स्वर्गीय रामविलास पासवानकी राजनीति परिवारके इर्द-गिर्द सिमटी रही। जद-यूकी ओरसे भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं, जिन्हें भाजपा और राजगके परम्परागत कार्यकर्ता और समर्थक स्वीकार नहीं कर रहे। भाजपाके भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारेमें नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमपर उन्हें थोप दिया गया है। झारखंडमें भी बाहरसे लाकर टिकट देने और ऐसे उम्मीदवारको खड़ा करने, जिनको भाजपा पहले नकार चुकी हो समस्या पैदा कर रही है।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ४ जूनका परिणाम भी इसीके अनुरूप आयगा। यह सही है कि यदि भाजपा और राजगमें उम्मीदवारोंके चयनमें ज्यादा सतर्कता बरती जाती, स्थानीय नेतृत्वके चॉइसकी सही तरीकेसे जांच होती तो स्थिति पूरी तरह वैसी ही उत्साहप्रद होती जैसी चाहिए। बावजूद देशव्यापी व्याप्त अंतर्धारा क्या है। दस वर्षोंकी नरेन्द्र मोदी सरकारका प्रदर्शन, प्रधान मंत्रीकी स्वयंकी छवि, वर्षोंतक संघटन परिवार द्वारा हिन्दू समाजके बीच किये गये सकारात्मक कार्य, २२ जनवरीको रामलालकी प्राण-प्रतिष्ठा, विरोधियों द्वारा हिंदुत्वको लेकर उपेक्षा या प्रहारका व्यवहार तथा अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानोंका वोट लेनेके लिए विपक्षी दलोंकी प्रतिस्पर्धा भाजपाके पक्षमें ऐसा आधार बनाती है जिसका कोई विकल्प नहीं। भाजपाके समर्थकोंमें एक बड़ा वर्ग विचारधाराके कारण जुड़ाव रखता है और पिछले कुछ वर्षोंके कार्योंके कारण हिन्दुओंके अन्दर हिन्दुत्व एवं भारतीय राष्ट्रभावकी चेतना प्रबल हुई है। वह बहस करते हैं कि आखिर भाजपा नहीं होती तो क्या अयोध्यामें राम मंदिर बनता और ऐसी प्राण-प्रतिष्ठा होती। वे धारा ३७० से लेकर समान नागरिक संहिता, तीन तलाक कानून, नागरिकता संशोधन कानून आदिकी चर्चा करते हैं। नागरिकता संशोधन कानूनका तो इण्डी गठबंधनके ज्यादातर दलोंने विरोध किया है। उन्हें लगता है कि घातक अल्पसंख्यकवादपर यदि किसी पार्टीकी सरकार द्वारा नियंत्रण लगा है तो भाजपा ही है। उत्तर प्रदेशमें योगी आदित्यनाथ सरकारके प्रभावोंके कारण जिन माफियाओंपर सरकारें उनके समुदायके कारण हाथ डालनेसे बचतीं थी वे मटियामेट हुए हैं, सड़कोंपर नमाज पढ़ना बंद हुआ है। देशके कई राज्योंने बादमें इसका अनुसरण किया। स्वाभाविक ही उन्हें लगता है कि आनेवाले समयमें कोई पार्टी यदि इन सबपर काम कर सकती है तो वह भाजपा ही है। दूसरी ओर सामाजिक न्याय एवं विकासको प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी सरकारने जिस तरहसे व्यावहारिक रूप दिया है उसका बड़ा आकर्षण समाजके हर वर्गमें है। पहले नेता बाबा साहब अंबेडकरका नाम लेते थे जबकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें उनसे जुड़े पांच प्रमुख स्थलोंका ऐसा विकास किया गया जिसकी कल्पना नहीं थी और उन्हें एक बड़े तीर्थ और पर्यटन स्थलमें बदलनेकी कोशिश हुई। दलित और आदिवासियोंके बीच आप जायंगे तो नरेन्द्र मोदीका समर्थनका एक बड़ा वर्ग खड़ा मिलेगा। प्रधान मंत्रीने २०४७ तक भारतको विकसित देश बनाने और अगले पांच वर्षोंमें विश्वकी तीसरी अर्थव्यवस्था बननेका जो नारा दिया है वह भी लोगोंके दिलोंको छू रहा है। विपक्षकी आलोचनाके विपरीत नरेन्द्र मोदीकी विकास संबंधी नीति तथा समाजके हर वर्गके आत्मनिर्भर और विकसित होनेके लिए दिये गये कार्यक्रमोंने सामान्य गरीबों महिलाओं किसने उद्योगपतियों, व्यापारियों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियोंके बड़े वर्गके बीच सकारात्मक प्रभाव डाला है। इन सबको लगता है कि तुलनात्मक रूपमें भाजपा और नरेन्द्र मोदी सरकार ही सही है। यह पहली बार है जब भारतके बाहर भारत विरोधी आतंकवादी दनादन मारे जा रहे हैं और दुनियाके प्रमुख देशोंके विरोधके बावजूद ऐसा हो रहा है। यद्यपि सरकार इसे नकारती है परन्तु आम लोगोंको लगता है कि यह सब नरेन्द्र मोदी सरकारके कारण ही हो रहा है अन्यथा पूर्वकी सरकारें उनके समक्ष किंकर्तव्यविमूढ़ रहती थी। स्वयं विपक्षने ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिनसे लोगोंके सामने इसमें ही चयन करनेका विकल्प है कि आपको प्रधान मंत्रीके रूपमें नरेन्द्र मोदी चाहिए या नहीं। ऐसी स्थितिमें मतदाता किस ओर जायंगे इसकी कल्पना ज्यादा कठिन नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्य में प्रधान मंत्रीकी रोड शोमें उमड़ी भीड़ बता रही है कि किस तरह पिछले दस वर्षोंमें भारतीय जनमानसकी सोच और व्यवहारमें बदलाव आया है।

भ्रष्टाचारपर प्रहारसे जनता खुश

नरेन्द्र मोदीके प्रधानमंत्रित्व कालमें ईडीने भ्रष्टचारियोंकी भ्रष्ट कमाई २२०० करोड़ रुपये जब्त किये हैं। मोदीने खासकर कांग्रेसको भी लपेटेमें लेकर कहा है कि कांग्रेसी कालमें सिर्फ ३५ लाख रुपये ही ईडीने जब्त किये थे।

❐ **विष्णुगुप्त**

प्रधान मंत्री मोदीने कहा है कि वे अपने विरोधियोंको बदलेकी भावनासे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडीकी काररवाई नहीं करा रहे हैं, राजनीतिज्ञ तो गिनती मात्रके हैं परन्तु असली निशानेपर तो भ्रष्ट अफसर, अपराधी और तस्कर हैं। राजनीतिज्ञ तो सिर्फ तीन प्रतिशत ही है, शेष ९७ प्रतिशत तो भ्रष्ट अधिकारी, कारपोरेट घराने, अपराधी और तस्कर ईडीके निशानेपर हैं, आतंकवादी संघटन और उसके संरक्षकोंकी भी ईडीने गर्दन नापी है। जब मोदीने ये आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं तब ईडी विरोधियोंसे जवाबकी अपेक्षा होती है। कांग्रेसीराजमें ईडी खामोश क्यो थी, सिर्फ ३५ लाखकी संपत्ति ही क्यों जब्त की थी, भ्रष्टाचारियोंको बचानेके लिए ईडीके हाथ-पैर बांधे गये थे। लेकिन ईडी विरोधी जवाब देनेके लायक ही नहीं हैं। ईडी विरोधी मोदीकी इस अवधारणाके खिलाफ जवाब क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए कि मोदीके कथन, मोदीके आंकड़े सच हैं। आज ईडीकी भ्रष्टाचार विरोधी काररवाइयोंसे न केवल राजनीतिज्ञ, बल्कि अन्य बड़ी-बड़ी हस्तियां भी जेलोंमें हैं और हर जगह यह डर फैला है कि कहीं कोई शिकायत हो गयी तो फिर ईडी गर्दन नाप देगी। भ्रष्टचारके खिलाफ लडाईके लिए ईडीका डर जरूरी है।

ईडीको बदनाम करनेके लिए कैसी-कैसी अफवाहें उड़ती हैं, देशसे लेकर विदेशोंतक ईडीके खिलाफ किस प्रकारकी प्रक्रियाएं चलती हैं, यह सब भी स्पष्ट है। ईडीकी काररवाईके खिलाफ अमेरिकाने झूठ आधारित आलोचनाएं की, जर्मनीने आलोचनाएं की, इतना ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट संघ भी कूद पड़ा। कहनेका अर्थ यह है कि देशके अन्दर ईडीके खिलाफ जो अफवाहें शुरू की गयी थी उन अफवाहोंके साथ अमेरिका, जर्मनी और सयुंक्त राष्ट संघ जुड़ गये। भारतको लोकतंत्र कायम रखनेके लिए और नेताओंपर भ्रष्टाचारके मामले चलानेपर नसीहतें दी गयी। यह देखनेकी कोशिश नहीं हुई है कि भारतका लोकतंत्र गतिमान है, लोकतंत्रपर कोई आंच नहीं है, लोकतंत्रको सुरक्षित रखनेके लिए न्यायपालिकाकी स्वतंत्रता बहुत ही प्रशंसनीय है, न्यायपालिका तो कार्यपालिकाके वर्चस्वसे बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडीकी काररवाई कोई अराजक और गैर-कानूनी काररवाई नहीं है। ईडीकी काररवाईका न्यायिक परीक्षण होता है, न्यापालिका ईडीकी सभी काररवाईयोंका आकलन करती है, सुबूत देखती है, भ्रष्टाचारकी परिस्थितियां देखती हैं। इसके उपरांत ही भ्रष्टाचारियोंके आरोपियोंको रिमांड देती है या फिर जेल भेजती है। ईडीकी प्रशंसा इस बातकी भी होनी चाहिए कि जटिल न्यायिक व्यवस्थाके बावजूद उसने भ्रष्टाचारियोंको गर्दन नापनेमें कोई कसर नहीं छोड़ती है, भ्रष्टाचारके सुबूत जुटाती है और भ्रष्टाचारकी कड़ियोंको जोड़नेमें सावधानी भी बरतती है।

ईडीको कमजोर करनेकी राजनीति और साजिशें भी चलती रहती हैं। क्या यह सही नहीं है कि ईडीके अधिकारको लेकर भ्रष्टाचार विरोधियोंकी एकजुटता चरमपर रहती है। अरविन्द केजरीवालको जेल भेजा गया तब ईडीके अधिकारोंपर प्रश्न उठाये गये और ईडीके अधिकारको चुनौती दी गयी, झारखंडके पूर्व मुख्य मंत्री हेमंत सोरेनको जब भ्रष्टाचारके आरोपमें जेल भेजा गया तब भी ईडीके अधिकारको लेकर प्रश्न खड़े किये गये और न्यायपालिकामें चुनौती दी गयी। सुप्रीम कोर्टने परीक्षणके बाद साफ तौरपर ईडीकी काररवाइयोंको कानून और संविधानके अनुरूप पाया था। सुप्रीम कोर्टकी बैंचने न्यायिक परीक्षणके बाद फैसला दिया था कि पीएमएलएकी धारा ५,१५,१७,४५,५० को वैध करार दिया था, इन धाराओंमें संबंधित व्यक्तिकी गिरफ्तारी, उसकी संपत्तिको सर्च करने, छापेमारी करने और उसकी संपत्तिको अटैच करनेका अधिकार है। दिल्ली होईकोर्टने भी ऐसे प्रश्नों और ऐसी साजिशोंको बेनकाब कर दिया। अरविन्द केजरीवालकी चुनौतीपर दिल्ली हाईकोर्टने साफ कर दिया किया कि ईडीके पास अधिकार है, वह भ्रष्टाचारके खिलाफ काररवाई कर सकती है, मुख्य मंत्री पदपर बैठे व्यक्तिको भ्रष्टाचार करनेका अधिकार नहीं है, वह अपनी गिरफ्तारीसे बच नहीं सकता है, मुख्य मंत्री भी आम नागरिक की तरह ही है। अरविन्द केजरीवाल और हेमंत सोरेनकी गिरफ्तारीसे पूर्व भी बार-बार ऐसे प्रश्न सुप्रीम कोर्टमें उठाये गये हैं और ईडीकी काररवाईको बाधित करनेकी कोशिश हुई है।

भ्रष्ट नेता बहुत ही चालाक और धूर्त होते हैं। वे अपना बचाव करनेके लिए तमाम हथकण्डे अपनते हैं, क्योंकि उनके पास धन बल होता है, अपने समर्थक बलको लेकर अंहकारमें होते हैं, महंगे वकीलोंके माध्यमसे न्यायपालिकाको प्रभावित करनेकी कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थक बलपर राजनीतिक बचावकी कोशिश चरमपर होती है। लालू इसके उदाहरण हैं। उनके पास समर्थक बल है। इसलिए उनका पूरा परिवार बचा हुआ है। सीबीआईकी जांचका कोर्टमें परीक्षण हुआ, लालू दोषी ठहराये गये, अब फिर रेलवे कांडमें ईडीके निशानेपर लालू और उनका परिवार है। परन्तु लालूका परिवार ईडीपर राजनीतिक आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि नरेन्द्र मोदी बदलेकी भावनासे उन लोगोंपर काररवाई करा रहे हैं। अरविन्द केजरीवाल राजनीतिकी गन्दगी दूर करनेके लिए आये थे, कहते थे कि वे राजनीतिको बदल देंगे, भ्रष्टचार समाप्त कर देंगे, भ्रष्टचारियोंकी गर्दन नाप देंगे, शिला दीक्षितसे लेकर सोनिया गांधीके भ्रष्टचारपर प्रश्न खड़ा करनेवाले केजरीवाल सत्तामें आनेके साथ ही खामोशी धारण कर ली। नैतिकता और शुचिताकी बात करनेवाले केजरीवाल शराब बेचने लगे, दिल्लीके नागरिकोंको शराबमें डूबाने लगे, गली-गलीमें शराबकी दुकानें खोलवा दी और शराब घोटाला भी कर दिया। अब केजरीवालका आरोप है कि नरेन्द्र मोदी लोकतंत्रको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए बिना सुबूत उन्हें जेलमें डाला गया है। लेकिन न्यायिक परीक्षणमें अरविन्द केजरीवालको राहत नहीं मिलनेका आधार यह कहता है कि ईडीके पास पक्के सुबूत हैं। नेशनल हेराल्ड मामलेमें स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी फंसे हैं। एक कोर्टने ईडीको नेशनल हेराल्डकी संपत्तियोंको जब्त करनेका आदेश दिया है। शराब घोटालेका नया अपडेट यह है कि ईडीके बाद सीबीआई भी प्रवेश कर गयी है। सीबीआईने तेलागंनाके पूर्व मुख्य मंत्री चन्द्रशेखर रावकी बेटी के.कविताकी पोल खोल कर रख दी है, दिल्लीके एक आलीशान होटलमें शराबके घोटालेबाजोंसे कविताकी बैठक हुई थी।

ईडीके खिलाफ भ्रष्टाचारियोंकी ऐसी गिरोहबंदी चिंताजनक है। भ्रष्टाचारके कारण आम आदमीकी संभावनाएं मरती हैं। अब बड़े भ्रष्टाचारी अपनी गर्दन नपनेके डरसे परेशान हैं। ईडी जैसी सभी जांच एजेंसियोंका डर बना रहना चाहिए। प्रशंसाकी बात यह है कि नरेन्द्र मोदीकी सरकार सिर्फ ईडी ही नहीं, बल्कि सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियोंको रोकती नहीं है, उन्हें विषहीन नहीं बनाती हैं। जांच एजेसियोंकी भ्रष्टचार विरोधी काररवाइयोंसे आतंकवाद और तस्करीपर भी रोक लगा है, देशकी सुरक्षा भी चाक-चौबंद हुई है। जब धनपर ही बुलडोजर चल जायेगा तो फिर देशद्रोही आतंकवादी कैसे अपनी सक्रियता सुनिश्चित कर सकते हैं। जनता सब जानती है, यही कारण है कि भ्रष्टाचारियोंकी गोलबंदीके बावजूद जनता ईडीकी काररवाइयोंपर खुशी जाहिर करती है।

आत्मबोध

मनुष्य जन्म

❐ **बाबा हरदेव**

मनुष्यका जन्म मिलना सुनहरा अवसरके रूपमें है। इस जन्ममें मनुष्य अपनी पहचान बना सकता है। सत्यको जानकर अपनी आत्माका उद्धार कर सकता है। यह आत्मा जन्मों-जन्मोंसे आवागमनके चक्करमें पड़ी हुई है और बार-बार इसको शरीर धारण करना पड़ता है। चौरासी लाख योनियां बतायी गयी हैं तो शरीरके आवागमनके सिलसिलेका अंत आखिर कब होगा। अंत होना, इस आवागमनके बंधनसे निजात पाना, इसीको मोक्ष कहते हैं और यह अवसर होता है जब मनुष्य जन्म हमें मिलता है। यदि इस जन्मको भी हमने हाथोंसे गंवा दिया तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा कि सुनहरा अवसर मिला, हीरे जैसा जन्म मिला, लेकिन इसकी कौड़ीके भाव बना दिया। जब हमने सत्यकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, जब हम सत्यके इच्छुक नहीं बने, जब हमने ब्रह्मज्ञानियोंका संग नहीं किया और इस तरहसे मंजिले मकसूदकी हमने प्राप्ति नहीं की तो हमसे बड़ा मंदभागा और कौन होगा। अकसर लोग कहत हैं इसकी बुरी किस्मत है, ये मंदभागा है क्यों। क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इसके पास झोंपडी है, एक पक्का मकानतक नहीं है। इस तरहसे ये खुशकिस्मती और बदकिस्मतीके हमने सांसारिक पैमाने बनाये हैं, लेकिन यदि सही मायनेमें देखा जाय तो उससे बड़ा कोई बदकिस्मत नहीं होता, जो यह अमोलक जन्म पाकर भी अपनी मंजिलको नहीं प्राप्त कर पाता। इस हीरे जैसे जन्मको पाकर भी जो केवल सांसारिक खेल खेलता रहे, सांसारिक प्रवृत्तियोंसे युक्त रहे, हिंसाके दौर चलता रहे, नफरत करता रहे वह होता है सबसे मंदभागा। वह नहीं कि जिसके पास दौलत नहीं या शोहरत नहीं या मकान नहीं। कबीर जी कितने खुशकिस्मत थे, मेहनत, मुशक्कत करते थे, कपड़ा बुननेका काम करते थे, लेकिन उनसे बड़ा खुशकिस्मत और कौन होगा, क्योंकि उन्होंने वह दौलत पा ली, उन्होंने वह सरमाया प्राप्त कर लिया, जिसकी तुलनामें दुनियावी सारे सिलसिले धूमिल हो जाते हैं। उन्होंने जो पाया वह लोकतक सीमित नहीं है, इसकी कीमत परलोकमें भी है। वो कमाई वह करते हैं, प्राप्त वह करते हैं, उनके हिस्सेमें वह आता है तो इसी तरहसे हमारे हिस्सेमें भी यह सब कुछ आये हमारे हिस्सेमें भी ये अवस्था आये, हमारे हिस्सेमें भी ये जागना आ जाय, हमारे हिस्सेमें भी ये परम तत्वकी प्राप्ति आ जाय। ये मंजिले मकसूद ही असली पहचान है, ये हर एकके हिस्सेमें आ जाय। यह इनसानी जन्म मिला, यह मौका मिला ताकि हर कोई अपना जन्म संवार सके, जब इनसानी जन्म दे दिया गया तो हर किसीके लिए संभावना बन गयी कि वह अपना उद्धार कर सकता है, वह अपना कल्याण कर सकता है। जरूरत है तो बस अपने अन्दर उस भावनाको लानेकी जिससे ये मंजिले मकसूद हमें मिल जाय।

जागरूकतासे बच सकता है लाखों जीवन

❐ **भारत डोगरा**

दुनिया और देश दोनों स्तरपर दुर्घटनाएं लोगोंके दुख-दर्दका एक बहुत बड़ा कारण हैं, फिर चाहे यह सड़क दुर्घटनाएं हों, अग्निकांड हों या अन्य दुर्घटनाएं। दूसरी ओर अनेक अध्ययन यह भी बता रहे हैं कि यदि सही नियोजन एवं पूरी प्रतिबद्धतासे प्रयास किये जायं तो दुर्घटनाओंकी संख्याको काफी तेजीसे कम किया जा सकता है। हालमें प्रकाशित एक पुस्तक वाय एक्सीडेंट्स आर रेयरली एक्सीडेंटलने अधिकांश लोगोंके जीवनके इस अनुभवको अनेक तथ्यों और प्रमाणोंके साथ प्रस्तुत किया है। इस पुस्तकका शीर्षक ही बहुत कुछ कह जाता है- कम दुर्घटनाएं ही दुर्घटनावश होती हैं। यानी जिसे हम किस्मतका खेल मान बैठे हैं उन दुर्घटनाओंमेंसे अधिकांशपर वास्तवमें मनुष्यका नियंत्रण होता है और हम समय रहते काररवाई करें तो बहुमूल्य मानव जीवन एवं संपत्तिकी क्षति रोकी जा सकती है। इस पुस्तकके लेखकों मार्क गरस्टीन एवं माइकेल एल्सबर्गका कहना है कि बेहतर नियोजन, मेहनत एवं जोखिमके प्रति चौकन्ने बने रहनेसे दुर्घटनाओं एवं उनके दुष्परिणामोंको बहुत कम किया जा सकता है। इस पुस्तकमें दिये गये अनेक उदाहरणोंका आकलन भी यही बताता है कि जहां आरंभिक चेतावनियोंपर ध्यान न देकर सुरक्षाको ताकपर रखा गया वहां गम्भीर दुर्घटनाएं हुईं, जबकि जहां आरम्भमें सुरक्षापर ध्यान दिया गया वहां दुर्घटनाओंको टाला जा सका। दुख-दर्द कम करनेका एक बड़ा जरिया है दुर्घटनाओंकी सम्भावनाओंको कम करना। इसके साथ दुर्घटना हो जानेपर जीवन रक्षाकी सम्भावनाको मजबूत करना भी जरूरी है। इन दो उपायोंसे प्रतिवर्ष लाखों जीवन बचाये जा सकते हैं और इससे कहीं अधिक लोगोंको बहुत कष्टदायक रूपसे घायल होने, दीर्घकालीन शारीरिक-मानसिक क्षति तथा अपंगतासे बचाया जा सकता है।

गम्भीर दुर्घटनासे प्रभावित व्यक्ति ही क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, उनके परिवारके सदस्यों एवं अन्य नजदीकी व्यक्तियोंको भी इस दुर्घटनाके कई प्रतिकूल असर भुगतने पड़ते हैं। गहरे दुख-दर्द एवं सदमेके अतिरिक्त इन विभिन्न व्यक्तियोंको प्राय: गम्भीर आर्थिक संकट भी झेलना पड़ता है। दुर्घटनाओं संबंधी समग्र जानकारी अभी किसी एक स्थानपर उपलब्धतक नहीं है। सबसे अधिक चर्चामें सड़क दुर्घटनाएं हैं। इसके अतिरिक्त यातायातकी दुर्घटनाएं लें तो रेल दुर्घटनाएं, नाव दुर्घटनाएं एवं वायुयान दुर्घटनाएं हैं। अंतिम श्रेणीको छोड़ दें तो शेष सभी दुर्घटनाओंके उपलब्ध आंकड़े वास्तविकतासे कम हैं। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकोंकी रक्षापर विशेष ध्यान दें, क्योंकि दुर्घटनाओंमें सबसे अधिक मौतें इन्हींकी होती हैं। सड़क दुर्घटनाओंमें घायल व्यक्तियोंका जीवन बचानेके लिए पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि इस दौरान उचित प्राथमिक इलाज देकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तिको अस्पताल पहुंचा दिया जाय तो लगभग ५० प्रतिशत जीवन बच सकते हैं। परन्तु इसके लिए बहुत कम सुविधाएं देशमें उपलब्ध हैं। यातायातके बाद दूसरे नंबरपर कार्यस्थलपर होनेवाली दुर्घटनाएं हैं।

इनकी संख्याको कम बनानेके प्रयास प्राय: होते हैं। कार्यस्थल यानी उद्योगों, खदानों, खेत-खलिहान, प्लांटेशन, निर्माण कार्यों, सफाई कार्य आदिमें होनेवाली बहुत दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतोंके सरकारी आंकड़े वास्तविकतासे कहीं कम हैं। आवासमें होनेवाली दुर्घटनाएं सबसे उपेक्षित हैं। इनमें प्रति दुर्घटना चाहे कम क्षति हो परन्तु इन दुर्घटनाओंकी कुल संख्या बहुत अधिक है। चौथे नंबरपर सभी तरहके शिक्षण-प्रशिक्षण स्थानोंमें होनेवाली दुर्घटनाएं हैं। पांचवें स्थानपर ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो विशेषकर भीड़वाले स्थानोंपर तीर्थस्थानों, मेलों, उत्सवों, सम्मेलनों एवं पर्यटन स्थलोंपर होती हैं।

अंतमें उन दुर्घटनाओंकी हमें एक अलग श्रेणी बनानी चाहिए जिनका असर बहुत दूर-दूरतक जा सकता है एवं देरतक बना रहता है। इस श्रेणीमें जहरीली गैसके रिसावसे जुड़ी दुर्घटनाओं एवं परमाणु ऊर्जा संयंत्रोंकी दुर्घटनाओंको रखा जा सकता है जिनपर विशेष ध्यान देने एवं उच्च स्तरकी विशिष्ट तकनीकी उपलब्ध करनेकी जरूरत है। इन सभी दुर्घटनाओंके बारेमें समग्र विश्वसनीय जानकारी एक स्थानपर उपलब्ध होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जानकारीके आधारपर ही दुर्घटनाओं एवं उनकी जानलेवा क्षमता कम करनेके लिए उचित प्रबंधन एवं नियोजन हो सकता है। हालांकि विभिन्न तरहकी दुर्घटनाओंसे बचावके लिए अलग-अलग तरहके प्रयास जरूरी हैं, परन्तु कुछ सामान्य महत्वके कदम ऐसे हैं जो सब तरहकी दुर्घटनाओंकी क्षति कम करनेके लिए महत्वपूर्ण हैं। जीवनके सभी क्षेत्रोंमें जरूरी सावधानियों एवं सुरक्षाके नियमोंको अपनानेकी जागरूकताको बढ़ाना ऐसा ही एक कार्य है। दुर्घटनासे घायल जहां भी हो जो भी हों, उन्हें तुरन्त जरूरी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना एवं सही तौर-तरीकोंसे अस्पतालोंमें पहुंचाना एक अन्य महत्वपूर्ण जरूरत है।

सामान्य एवं विशिष्ट सब तरहकी दुर्घटनाओं संबंधी जिम्मेदारियोंको आगे बढ़ानेके लिए एक केन्द्रीय दुर्घटना प्राधिकरणकी जरूरत है जहां एक स्थानपर सभी तरहकी दुर्घटनाओं संबंधी प्रबंधन नियोजन, अध्ययन एवं अनुसंधान समग्र रूपसे हो सके। इसके कार्यालय राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरपर होने चाहिए तथा साथ ही पंचायतोंमें दुर्घटनाओं संबंधी जागरूकता बढ़ानेके कार्यको महत्व मिलना चाहिए। इसके साथ दुर्घटनाओं एवं उनकी जानलेवा क्षमताको कम करनेके कार्यको विभिन्न स्तरोंपर जन-भागीदारीसे एक व्यापक जन-अभियानका रूप देना चाहिए।

संपादकीय

“ हम जीवन और एक-दूसरे की देखभाल करने के लिए पृथ्वी पर हैं।
-जिया बास्टिडा, मैक्सिकन जलवायु कार्यकर्ता

आम चुनाव के लिए सियासी पारा तो पहले ही चढ़ गया था, अब 2019 की तुलना में कुछ जगहों पर हुए कम मतदान पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को बूथ तक लाने के प्रयास करें और मतदाता भी अपने वोट की ताकत को समझकर लोकतंत्र को मजबूत करें।

जागरूक हों मतदाता

पहले और सबसे बड़े चरण में 21 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने की सात चरणों वाली मतदान प्रक्रिया का पहला पड़ाव पार हो गया है। आम चुनाव के लिए सियासी पारा तो पहले ही ऊपर चढ़ गया था, मगर 2019 की तुलना में कुछ जगहों पर हुए कम मतदान पर चर्चाओं और दावों का दौर एक बार फिर गर्म है। पिछली बार की तरह बिहार में सबसे कम वोट पड़े, तो नगालैंड के छह जिलों में तो राजनीतिक वजहों से एक वोट तक नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर समेत कई जिलों में मतदान प्रतिशत का गिरना सभी दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी वजह गेहूं की कटाई, सहालग, बेतहाशा गर्मी व मतदाताओं की उदासीनता बताई जा रही हैं। दरअसल, उम्मीद से ज्यादा मतदान होने पर अमूमन यह माना जाता है कि मतदाता बदलाव के लिए एकजुट हो रहे हैं, दूसरी ओर, वोटिंग अपेक्षा से कम रहने पर मतदाताओं की उदासीनता की वजह पूरे राजनीतिक वर्ग से असंतोष को माना जाता है। वजहें जो भी रही हों, कम वोटिंग उन 75 सीटों पर लड़ाई को जरूर दिलचस्प बना सकती है, जहां 2019 के चुनावों में कांटे की टक्कर यानी हार-जीत का फर्क 20 हजार वोटों से कम रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश भर में कम वोटिंग हुई। इसलिए, एक ही चरण के चुनाव से देश में मतदाताओं के ट्रेंड के बारे में अनुमान लगाना भी सही नहीं होगा। हां, युवाओं की उदासीनता जरूर निराश करती है। पहली बार वोट देने का अधिकार पाए युवाओं में केवल 38 फीसदी ने 2024 के चुनावों के लिए बतौर मतदाता पंजीकरण करवाया है। इस मामले में बिहार (17 फीसदी) तो सबसे पीछे है, राजनीतिक तौर पर जागरूक माने जाने वाले महाराष्ट्र (22 फीसदी) की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कम मतदान से किसे फायदा पहुंचेगा और किसे नुकसान, यह तो बाद की बात है, फिलहाल तो

सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे मतदाताओं को बूथ तक लाने और मतदान के प्रति जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाएं, क्योंकि यह तय है कि नजदीकी मुकाबलों में जो दल अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में कामयाब रहेंगे, वे ज्यादा लाभ में रहेंगे। मतदाताओं को भी समझना होगा कि नागरिक के तौर पर मतदान उनकी एक जिम्मेदारी और वोट उनकी ताकत है, जिसके जरिये वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। पूरे पांच साल बाद मतदाताओं को यह मौका मिलता है, इसलिए अपने वोट का उपयोग करने के साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

तपती धरती को राहत मिले...

आज हमारी पृथ्वी के सामने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का भयावह संकट है। इससे निपटने के लिए प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार को प्रोत्साहन देना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार के बीच तालमेल से हम एक हरित और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

वीर सिंह

वर्ष 1970 से प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन पृथ्वी को बचाने और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सबसे आवश्यक जिन दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है, वे हैं प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार। जबकि ये दोनों परस्पर जुड़े प्राकृतिक और सामाजिक समाधान जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह पर जीवन को अक्षुण्ण रखने के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को जीवन-ऊर्जा में रूपांतरित करने की नैसर्गिक घटना है और शाकाहार प्राकृतिक दोहन को नियंत्रित करने की मानव की मौलिक प्रकृति-प्रदत्त जीवन शैली। इन्हें प्रोत्साहित किए बिना हमारे जीवित ग्रह को बचा पाना संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसके माध्यम से हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। यह नैसर्गिक क्रिया न केवल वनस्पति के साम्राज्य को बनाए रखती है, वरन हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। ग्लूकोज पृथ्वी के समस्त जीव रूपों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। वास्तव में यह सौर ऊर्जा ही है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैव-रसायन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसी से हमारा ग्रह एक जिंदा ग्रह बना है।

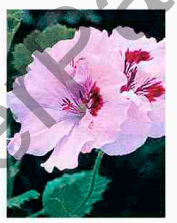

वर्तमान में हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के ऐसे कुचक्र में फंसी है, जिससे अगर यह बाहर न निकली, तो इसका भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी को इस दुश्चक्र से मुक्त करने के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति है प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम क्षमता तक अभिवृद्धि। जलवायु परिवर्तन की केंद्रीय संचालक है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण और जीवाश्म ईंधनों के दहन जैसी मानव गतिविधियों ने इस नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया है, जिससे

वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में खतरनाक वृद्धि हुई है तथा ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ा है। इससे निपटने के लिए हमें न केवल बचे हुए वनों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करनी चाहिए, वरन वनीकरण और पुनर्वनीकरण प्रयासों को भी बढ़ावा देना चाहिए। हरित आवरण का विस्तार करके हम प्रकाश संश्लेषण के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखा जा सकता है।

इसके साथ-साथ शाकाहार को अपनाना पृथ्वी की जीवटता में और प्राण फूंकने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पशुधन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है, जो वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 14.5 प्रतिशत है। पशुओं के सघन औद्योगिक पालन से न केवल भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस मीथेन उत्पन्न होती है, बल्कि इसके लिए व्यापक भूमि, पानी और चारा की भी आवश्यकता होती है, जिससे वनों की कटाई और जैव विविधता के क्षरण को बढ़ावा मिलता है।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में मांस उद्योग एक बड़ा स्रोत है। इसके विपरीत पौधों पर आधारित आहार में कार्बन पदचिह्न काफी कम होता है। शाकाहार खान-पान की एक शैली ही नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जिसे अपनाकर हम प्रकाश संश्लेषण के निकटस्थ, अर्थात सूर्य की शक्ति के सबसे निकट, जीवन यापन कर प्रकृति के सिद्धांतों का अनुपालन कर सकते हैं। वैसे भी जीवन विकास के क्रम में अपनी आकृति-प्रकृति, एनाटॉमी, शारीरिक कार्यिकी, अपने स्वभाव और अपनी चेतना से मानव एक शाकाहारी प्राणी है। शाकाहार को अपनाकर हम पृथ्वी की पारिस्थितिकी सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। वैसे भी वनस्पति-आधारित आहार कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिनमें मोटापा और कई तरह के कैंसर के खतरों से बचाव सम्मिलित हैं।

प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार के बीच तालमेल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए पौधों की शक्ति का उपयोग करने के उनके साझा लक्ष्य में स्पष्ट है। संपूर्ण मानवता द्वारा शाकाहार अपनाने और प्रकाश संश्लेषण को चरम तक ले जाने वाली प्राथमिकताओं का समर्थन कर हम प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं और एक हरित और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अपेक्षित नियंत्रण करने के साथ-साथ प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार पर्यावरण के लिए कई सह-लाभ प्रदान करते हैं। शाकाहारी भोजन पैदा करने के लिए मांस-प्रधान आहार की तुलना में काफी कम पानी और भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण के उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं। जैसे, जिस भूमि क्षेत्र में 100 क्विंटल शाकाहारी भोजन पैदा होता है, उतने क्षेत्र में केवल 10 क्विंटल मांस ही पैदा होगा। शाकाहार खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन का अवशोषण होता है, जबकि मांस उत्पादन में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।

इस तरह शाकाहार पर निर्भर रहकर मानव अपने अधिकांश प्राकृतिक वनों को बचाते हुए मिट्टी, जल और जैव विविधता का संरक्षण कर सकता है, लुप्तप्राय जीवों के अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण को त्वरित कर पृथ्वी को उसकी सुंदरता, स्वास्थ्य, जीवटता और वैभव लौटा सकता है तथा अपने लिए आशाओं और प्रसन्नताओं से भरा भविष्य पैदा कर सकता है। शाकाहार के दर्शनशास्त्र को जीवन का मूलभूत तत्व बनाकर हम सभी के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाली एक न्यायसंगत और टिकाऊ खाद्य प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा लोगों को अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य हेतु शाकाहार पर निर्भर बनाने और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर ठोस नीति तैयार होनी चाहिए। पृथ्वी पर जीवन को अक्षुण्ण रखने वाली प्राकृतिक प्रणालियों का पोषण और सुरक्षा हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है।

-प्रोफेसर एमेरिटस, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

जीवन धारा

स्वामी रामतीर्थ

काम, लोभ और क्रोध के कारण मनुष्य निराशा का अनुभव करता है और उसका निष्फल अहं काम, लोभ और क्रोध से ही तृप्ति की खोज करता है। इस प्रकार हमारी चेतना निराशा के दुश्चक्र में फंस कर रह जाती है।

पतन का कारण है हमारी स्वार्थपरता

स्वार्थपरता मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जब किन्हीं कारणों से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं, तभी स्वार्थपरता अस्तित्व में आती है। साथ ही, जो मनुष्य मानव-स्वभाव के वास्तविक स्वरूप से अनजान होता है, उसमें भी इस प्रवृत्ति का जन्म होता है। जन्म-जन्मांतर के विकास क्रम में हमारे भीतर नाना प्रकार के जो संस्कार एकत्रित होते जाते हैं, उनसे मानवीय चेतना आच्छादित हो जाती है। ये संस्कार ही इच्छाओं के रूप में प्रकट होते हैं और इन इच्छाओं के द्वारा हमारी चेतना और ज्ञान का दायरा सिमटता चला जाता है। स्वार्थपरता का दायरा इच्छाओं के दायरे के समान ही होता है। तरह-तरह की इच्छाओं के अवरोध के कारण अपने यथार्थ स्वरूप की अभिव्यक्ति आत्मा के लिए असंभव हो जाती है। इससे हमारा जीवन अपने तक ही केंद्रित और सीमित हो जाता है। इसके लिए हम इच्छानुकूल वस्तुओं की खोज करते रहते हैं, जो सब की सब परिवर्तनशील और क्षणभंगुर होती हैं। किंतु ऐसी नाशवान वस्तुओं द्वारा वास्तविक तृप्ति होना असंभव है। इस प्रकार असंतोष का एक सामान्य भाव सदैव बना रहता है और इसी के साथ सभी प्रकार की चिंताएं भी उत्पन्न होती रहती हैं।

मनुष्य का निष्फल अहंकार जितने मुख्य रूपों में व्यक्त होता है, उनमें काम, लोभ और क्रोध मुख्य हैं। काम, लोभ के समान ही है। केवल इसके तृप्त होने की विधि भिन्न है। काम स्थूल शरीर के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। लोभ हृदय की अशांति की एक अवस्था है और वह अधिकार व सत्ता की लिप्सा से पैदा होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिकार और शक्ति की खोज की जाती है। इस प्रयत्न में मनुष्य आंशिक रूप से ही सफल हो पाता है और उसका यह आंशिक संतोष इच्छा की अग्नि को शांत करने के बजाय और बढ़ाता जाता है। इस कारण लोभ के लिए अपने सम्मुख स्थित विशाल क्षेत्र पर विजय पाना असंभव होता है और वह मनुष्य को लगातार असंतुष्ट बनाए रखता है। इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध इच्छाओं के खंडित होने से उत्पन्न होता है। उसका लक्ष्य होता है, इच्छाओं के तृप्त होने के मार्ग की बाधाओं को दूर करना।

इस प्रकार काम, लोभ और क्रोध की प्रवृत्तियों के द्वारा ही मनुष्य निराशा का अनुभव करता है और उसका निष्फल अहं काम, लोभ और क्रोध के द्वारा ही अधिक तृप्ति के साधनों की खोज करता है। इस प्रकार हमारी आत्मा की चेतना असीम निराशा के दुश्चक्र में फंस कर रह जाती है। काम, लोभ या क्रोध की पूर्ति न होने से निराशा उत्पन्न होती है। इन तीनों पतनकारी प्रवृत्तियों का विस्तार स्वार्थपरता के साथ ही होता है। इसलिए स्वार्थपरता ही वास्तव में हमारी समस्त निराशा और चिंताओं का मूल कारण है। पर इस प्रयत्न में वह अपने आपको ही पराजित करती है। वह इच्छाओं के द्वारा अपनी तृप्ति करना चाहती है। लेकिन परिणाम में उसे एक असंतोष ही मिलता है।

इच्छाओं का त्याग ही सुख...

सूत्र

स्वार्थपरता का अनिवार्य परिणाम असंतोष और निराशा ही है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए सुख की समस्या का एकमात्र उपाय इच्छाओं का त्याग है। बाहरी दमन के कारण इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, वे सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही जड़ से मिटाई जा सकती हैं।

दूसरा पहलू

सुबह खाया जानेवाला हल्का खाना शरीर और मस्तिष्क को दिन भर ऊर्जा मुहैया कराता रहता है।

नाश्ता न करने जैसा है अस्वास्थ्यकर नाश्ता

अनेक अभिभावक जानते हैं कि सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चों के लिए नाश्ता करना आवश्यक है। काम पर जाने से पहले अनेक युवा भी नाश्ता करने से कतराते हैं, जबकि सुबह खाया जानेवाला हल्का खाना शरीर और मस्तिष्क को दिन भर ऊर्जा मुहैया कराता रहता है। अपने नए अध्ययन में हमने यह जानने की कोशिश की है कि सुबह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करने, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह चीज खा लेने और सुबह कुछ न खाने का शरीर पर क्या असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की परियोजना के तहत हमने ऑस्ट्रेलिया के पांच हाई स्कूलों के 13-14 वर्षों के कुल 648 छात्रों को अपने अध्ययन में शामिल किया। ये सभी विज्ञान के छात्र थे और निजी स्कूलों में पढ़ते थे। हमने उनसे पूछा कि वे सप्ताह में कितने दिन नाश्ते में फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रोटीन, साबुत अनाज आदि लेते हैं। वे सप्ताह में कब-कब चीनी वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रसंस्कृत मांस, फास्ट फूड, नुकसानदेह बेकरी उत्पाद आदि नाश्ते में लेते हैं। हम जानना चाहते थे कि कितने आत्मविश्वास से वे स्कूल का काम करते हैं, विज्ञान विषय को कितना महत्व देते हैं और सीखने के प्रति उनमें कितनी ललक है? हमने पाया कि जिन छात्रों ने सुबह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता किया था, कक्षाओं में वे पढ़ाई के प्रति ज्यादा प्रेरित थे और उनकी उपलब्धियां भी अधिक थीं। कक्षा की जांच परीक्षा में भी उन्हें ज्यादा नंबर मिले। जबकि बिना नाश्ता किए स्कूल आने वाले छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगन और एकाग्रता कम पाई गई। पर अध्ययन का सबसे हैरान करने वाली बात थी कि अस्वास्थ्यकर नाश्ता करने वाले छात्रों की एकाग्रता का स्तर भी बिना नाश्ता किए स्कूल आने वाले सहपाठियों की तरह ही था। इसका मतलब यह है कि सुबह अस्वास्थ्यकर नाश्ता करना नाश्ता न करने जैसा ही नुकसानदेह है। हालांकि यह पता लगाना अभी शेष है कि ऐसा क्यों है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अस्वास्थ्यकर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा शरीर और मस्तिष्क को उस तरह चालित नहीं कर पाती, जो पढ़ने और सीखने के लिए जरूरी है। अध्ययन में शामिल सभी छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली गई थी, लेकिन इस पर व्यापक अध्ययन होना अभी बाकी है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बच्चों के स्वास्थ्यकर नाश्ता करने या न करने में क्या संबंध है। *(कन्वर्सेशन से)*

-साथ में एमा बर्न्स, जोएल पीयरसन, केड्को सीपी बोस्टविक और रोजर कैनेट।

एंड्रयू जे मार्टिन

हमने अपने अध्ययन में पाया कि जिन छात्रों ने सुबह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता किया था, कक्षाओं में वे पढ़ाई के प्रति ज्यादा प्रेरित थे और उनकी उपलब्धियां भी अधिक थीं।

अस्वास्थ्यकर नाश्ता करने वाले और बिना नाश्ता किए स्कूल आने वाले छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगन और एकाग्रता समान रुप से कम पाई गई।

आंकड़े

मोबाइल फोन निर्यात

पिछले एक दशक में मोबाइल फोन के निर्यात में हमारे देश ने शानदार कामयाबी हासिल की है और अब छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।

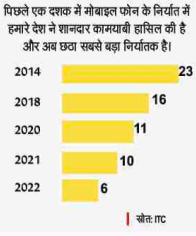

स्रोत: ITC

सुपात्र को ज्ञान देने से वह ज्ञान फलीभूत हो उठता है, जबकि कुपात्र को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता।

सुपात्र को ही ज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

रामकृष्ण परमहंस को संसार का कोई भी सुख और वैभव आकर्षित नहीं कर पाता था। उनके भीतर किसी प्रकार की लालसा नहीं थी। वह कभी किसी वस्तु का अभाव महसूस नहीं करते थे, किंतु अपनी अस्वस्थता के दिनों में अवश्य दुखी हो गए थे। वह उपासना के दौरान अपने कष्टों को देवी मां के समक्ष प्रकट करते थे।

एक बार वह बड़े करुण होकर देवी मां से बोले, मां, तूने संसार में इतनी बुराइयों को बनाया ही क्यों? जीवों में भी तूने ज्ञानी की जगह अज्ञानी ही ज्यादा बनाए। अगर तुमने ज्ञानी लोग ज्यादा बनाए होते, तो इस संसार की यह दशा कदापि नहीं होती।

अपनी शारीरिक अक्षमता और संसार की आत्मिक दुर्बलता उन्हें और विचलित करती थी। वह संसार का कल्याण करना चाहते थे। वह अपने भक्तों में भी सदैव सुपात्रों की तलाश में रहा करते थे।

एक दिन किसी ने पूछा, भक्त तो सभी भक्त हैं, उनमें सुपात्रों की तलाश क्यों?

उन्होंने कहा, सुपात्र को ज्ञान देने से वह ज्ञान फलीभूत हो उठता है, जबकि कुपात्र को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। अज्ञानी और कुपात्र तो उस फूटे ढोल के समान हैं, जिसे रात दिन बजाने पर भी ताल नहीं निकल सकती, संगीत नहीं उभर सकता।

आज का इतिहास

पृथ्वी दिवस मनाकर धरा को बचाने के संकल्प का दिन

पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरुकता बढ.ाने के लक्ष्य के साथ 22 अप्रैल के दिन 'पृथ्वी दिवस' यानि' अर्थ डे' मनाने की शुरुआत की गई थी।

वर्ष 1970 में शुरु की गई इस परंपरा को दुनिया ने खुले दिल से अपनाया और आज लगभग पूरी दुनिया में प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस के मौके पर धरा की धानी चूनर को बनाए रखने और हर तरह के जीव-जंतुओं को पृथ्वी पर उनके हिस्से का स्थान और अधिकार देने का संकल्प लिया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस दिन का खास मुकाम है। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश सेवा के लिए भारतीय सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दिया था।

अपराधों के दुश्चक्र में नाबालिग

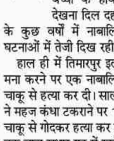

नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध को कम करने के लिए सही सजा का प्रावधान हो, ताकि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके।

दीपिका शर्मा | समाज

जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और बैट-बॉल जैसी चीजें शोभा देती हैं, उस उम्र के बच्चों के हाथों में चाकू-छुरे जैसी चीजें देखना दिल दहला देने वाली घटना है। हाल के कुछ वर्षों में नाबालिग बच्चों द्वारा अपराध की घटनाओं में तेजी दिख रही है।

हाल ही में तिमारपुर इलाके में महज माचिस देने से मना करने पर एक नाबालिग ने 21 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी। साल भर पहले भी उसी नाबालिग ने महज कंधा टकराने पर 16 साल के एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। उसके बाद कुछ समय तक बाल सुधार गृह में रहने के बाद वह बाहर आ गया। वहीं 2023 के अंत में दक्षिण पूर्वी जिले के बदरपुर इलाके में तीन नाबालिगों ने किशोरी दोस्त के साथ गैंगरेप किया और वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये घटनाएं आपराधिक मामलों में नाबालिगों की

संलिप्तता की बानगी हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों की मानें, तो वर्ष 2022 में देश में नाबालिगों द्वारा कुल 30,555 अपराध किए गए, जिनमें झपटमारी, लूटपाट, वाहन चोरी, घरों में चोरी, ठगी की वारदातें और यहां तक कि दुष्कर्म के मामले भी शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ किए गए अपराधों में 3,545 नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनमें से 345 मामले जबरन शादी के इरादे से महिलाओं के अपहरण से संबंधित मामले पाए गए। नाबालिगों द्वारा अपराध के मामले में देश की राजधानी 2,340 से अधिक मामलों के साथ छठे स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर महाराष्ट्र(4,406), फिर मध्य प्रदेश (3,795) और राजस्थान (3,063) हैं।

नाबालिगों द्वारा अपराध के मामलों में इजाफे का क्या कारण है? क्या इन सबके पीछे का कारण दोषपूर्ण परवरिश व सामाजिक माहौल में बदलाव है या नई तकनीकी दुनिया। फरवरी 2024 में बिहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें मरने से पहले इंसान को तड़पता हुआ देखने के लिए तीन नाबालिग लड़कों ने कैब ड्राइवर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा कि किसी की भी रुह कांप जाए। एक ने ड्राइवर के गले में फंदा डाला, तो दूसरे ने ड्राइवर के गले में कील घोंप दी। इसके बाद वे रस्सी से ड्राइवर का गला तब तक कसते रहे, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस के सामने उन्होंने कबूला कि उसकी जान निकलते देखने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। उन्होंने यह भी कबूला कि कत्ल करने का यह तरीका उन्होंने यूट्यूब से सीखा और उस ड्राइवर से उनकी न तो जान-पहचान थी और न ही कोई दुश्मनी। पुलिस के लिए भी ऐसी विकृत मानसिकता चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि ऐसे संगीन अपराधों में भी नाबालिगों को कड़ी सजा देने का प्रावधान नहीं है। उन्हें बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है या उनकी काउंसिलिंग करा कर ही घर भेज दिया जाता है, जिस कारण कई बार बड़े-बड़े अपराधी उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें अपराध के दलदल में फंसा देते हैं। बालमन को पैसों का मोह, मौज-मस्ती तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। अपराध से जुड़ी फिल्मों और वेब सीरीज का भी बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और उनमें आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देता है। बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं। यदि इनका भविष्य संवर गया, तो देश का विकास मुमकिन है और यदि इसी गति से नाबालिगों के अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी होती रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब देश पर माफिया का राज होगा। इसलिए जरूरी है कि नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध को कम करने के लिए सही सजा का प्रावधान हो और ऐसी नीति बनाई जाए कि बच्चों को जुल्म की दुनिया में कदम रखने से रोका जा सके। नाबालिगों को उसके अपराध की प्रकृति के आधार पर सजा का उचित प्रावधान होना चाहिए, ताकि जघन्य अपराधों की तरफ रुख करने से बालमन बचा रहे व कोई उन्हें बहला-फुसलाकर अपराध की राह पर न धकेल सके। सरकार, समाज, माता-पिता, अभिभावकों को बच्चों के बेहतर व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 66 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

सम्पादकीय

राज्य सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग को सहयोग करने की जरूरत

आम चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर हिंसक घटनाओं ने जरूर लोकतंत्र के इस उत्सव को बदरंग करने की कोशिश की, पर अच्छी बात है कि उनसे मतदाताओं और मतदान की प्रक्रिया पर बहुत नकारात्मक असर नहीं देखा गया। मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा की चपेट में है और वहां पहले से चुनाव के विरोध का स्वर उभर रहा था। इसलिए अगर कुछ मतदान केंद्रों पर उपद्रव की घटनाएं हुईं, तो इसकी वजहें समझी जा सकती हैं। वहां चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक मतदान केंद्र के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया। यह भी कोई अनपेक्षित घटना नहीं थी, क्योंकि मतदान से दो दिन पहले ही वहां सुरक्षाबलों ने उनतीस नक्सलियों को मार गिराया था। उस घटना की प्रतिक्रिया में हमले की आशंका पहले से थी। हालांकि वहां भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं हुई।

मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा देखी गई, वह जरूर चिंता पैदा करती है। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में हिंसा की आशंका बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता छोटी-छोटी बातों को लेकर गुत्थमगुत्था होते और हिंसक घटनाएं करते देखे जाते रहे हैं, उसमें इस चुनाव में भी व्यापक हिंसा की आशंका पहले से जताई जा रही है। उसकी शुरुआत कूचबिहार में देखी गई। वहां भाजपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता लोगों को धमकाने और मतदान से रोकने का प्रयास करते रहे। यही आरोप तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए। उपद्रवियों की धर-पकड़ और हिंसा पर काबू पाने के क्रम में की गई तलाशी में कई बम भी बरामद किए गए। जाहिर है, हिंसा की तैयारियां वहां पहले से की गई थीं। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में निर्वाचन आयोग अतिरिक्त रूप से सतर्क रहता है। इसलिए भी कूचबिहार में किसी बड़ी घटना की साजिशों को रोकने में कामयाबी मिल गई। मगर अभी वहां बाकी चरणों के चुनाव होने हैं, जिनमें हिंसा की आशंका बनी हुई है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग का सहयोग करे। यह ठीक है कि राजनीतिक दल अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। मगर इसका लोकतांत्रिक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि प्रतिद्वंद्वी दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले करके उन्हें मतदान से रोका और अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने का प्रयास किया जाए। अगर कोई राजनीतिक दल अपने कामकाज और सैद्धांतिक प्रभाव से मतदाता का विश्वास अर्जित नहीं कर पाता, तो उसे जीत का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। मगर कुछ समय से धनबल और बाहुबल के जरिए चुनाव को अपने पक्ष में करने की अनैतिक कोशिशें बढ़ी हैं।

विश्व पृथ्वी दिवस

बहुत हुआ पृथ्वी का दोहनः अब तो उठो जागो, आंखें खोलो

आज पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण इतनी तीव्र गति से हो रहा है, कि वर्तमान में इसका कोई भी कोना चाहे वह ध्रुव प्रदेश हो या समुद्री तल हो या अंतरिक्ष क्षेत्र सहित सभी जगहों पर मानव ने अपरिमित गंदगी फैला कर पृथ्वी की युगों से अनवरत चली आ रही व्यवस्था में खलल उत्पन्न कर दिया है। अब तो यह स्थिति है कि हमारी पूरी पृथ्वी का ही भविष्य दांव पर लग गया है। पृथ्वी पर इतना ज्यादा मनुष्य ने लालच और शक्ति की चाहत में हर प्रकार से लूट मचाई हुई है। जिसका परिणाम है कि आज पृथ्वी बंजर हो रही है। समुद्र गंदे हो गए हैं। जल थल नभ सभी प्रदूषित हो गए हैं। विश्व का पर्यावरण पूरी तरह से खराब हो चुका है।

सुरेश सिंह बैस

मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसके मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा होता है। पृथ्वी उसके आहार की व्यवस्था अपने वनस्पतियों से करती है। एवं अमृततुल्य शीतल जल अपना हृदय निचोड़ कर देती है। प्रतिपल जीवन के लिए अति आवश्यक प्राणवायु का संजीवनी भी प्रदान करती चली आ रही है। अपने पूरे जीवन भर मनुष्य पृथ्वी से केवल और केवल लेता ही रहता है ।वापस उसे कुछ भी नहीं देता ।आखिर में अंतत: जीवन के अंत में उसी की गोद में ही मृत्यु हो जाने पर चिरनिंद्रा का आश्रय भी पाता है। ऐसी जगत माता पृथ्वी के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को भूलकर मनुष्य छुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर वह अपनी मां के जीवन को ही खत्म करने पर तुल गया है। यह जानते हुए भी कि मां ही नहीं रहेगी तो उस पर हर कार्यों के लिए आश्रित पुत्र यानी मानव का तो नामोनिशान ही नहीं रह जाएगा। उसके दोषों का दुष्परिणाम अन्य जीव जंतु व जानवरों को भी निर्दोष होते हुए भी भुगतना पड़ेगा। यह सब जानते हुए भी मनुष्य पृथ्वी को विनाश के कगार पर धकेले चला जा रहा है।

पृथ्वी पर आज की तारीख में कोई खतरा सबसे ज्यादा है तो वह है स्वयं मनुष्य, इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण तथा कमजोर होती जा रही जीवनदायिनी ओजोन की परतों से है। जो कि कई जगहों पर अब 卐ओजोन होल卐 का रूप ले चुका है। ओजोन की परत के घटने के कुप्रभाव का अंदाज सिर्फ इससे ही लगाया जा सकता है कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सीधे पहुंचकर जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होगी। जीव जंतुओं में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी वहीं वनस्पति जगत में भी विकृतियां पैदा हो जाएंगी। कई शैवाल और प्लैक्टन आदि नष्ट हो जाएंगे। वही अंधाधुंध वनस्पतियों का नाश करना भी मनुष्य नहीं छोड़ रहा है। आज जंगल के जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का संसार दिन ब दिन छोटा होता चला जा रहा है । यह भी पृथ्वी और पर्यावरण के लिए अत्यधिक नुकसानदायक हो रहा है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बीस प्रतिशत से भी कम होने लगी है ।और अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी होती जा रही है। फलत: पृथ्वी का तापमान आसामान्य रूप से काफी गर्म हो रहा है। पृथ्वी के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति को हम ग्रीनहाउस इफेक्ट अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।

ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के ध्रुवों का बर्फ पिघल कर समुद्र स्तर को बढ़ा रहा है । और कई तटीय इलाकों के प्रदेशों को लीलता चला जा रहा है। भू वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कह दिया है कि आगामी पचास वर्षों के अंदर ही भारत के कई तटीय इलाके समुद्र में डूब जाएंगे। साथ ही दुनिया के कई देश उदाहरणार्थ मालदीव्स, श्री लंका , कैरेबियन देश सहित कई छोटे छोटे द्वीप भी समुद्र के अंदर समा जाएंगे। अनेक छोटे छोटे द्वीपों और समुद्र किनारे के देशों को ग्लोबल वार्मिंग जलमग्न कर देगा। इन्हें अगर बचाना है तो हमें मुख्य रूप से वाहनों और कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फोटोकॉपी मशीन, एक्सरे मशीनों के प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगाना होगा। क्योंकि पृथ्वी इन वजहों से भी प्रदूषित हो रही है। इनके द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी की ओजोन परतें कमजोर होती चली जा रही हैं। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए इन ओजोन परतों को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है । सड़कों पर धुआं तथा धूल उड़ाती शोर करती गाड़ियां, प्रतिदिन स्थापित होती फैक्ट्रियां और तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उनके रहने के लिए पृथ्वी के सीने पर सैकड़ों गुना रफ्तार से फैलती कंक्रीट के जंगल ने पृथ्वी को बुरी तरह से घायल कर दिया है ।आज पृथ्वी इन के बोझ से कराह रही है। सिसक रही है ।और ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए सबसे ज्यादा दोषी स्वयं मनुष्य है। मनुष्य ने विकास के नाम पर पृथ्वी के पुराने स्वरूप को ही बदल

डाला है। जीवन उपयोगी वनों को नष्ट कर डाला है। एवं समुद्र में करोड़ों टन कचरा पहुंचाकर परमाणु विस्फोट और नदियों के अमृत रूपी पेयजल के निरंतर प्रदूषित करने की क्रिया ने पृथ्वी को एक बारूदी गोले में तब्दील कर दिया है। तभी तो वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि सन् 2040 से प्रारंभ होकर सन् 2080 तक पृथ्वी पर महाविनाश होना अवश्यंभावी नजर आता है।

पृथ्वी पर विकास के लिए अंधाधुन निर्माण करने के कारण जो हवा ,पानी, ठंड, गर्मी ,खनिज तत्वों के निर्माण हेतु पृथ्वी के गर्भ में जानी चाहिए, वह अब स्थाई निर्माण कार्यों के कारण पृथ्वी से बाहर ही रह जा रही है ।जिससे हो यह रहा है कि पृथ्वी का उपजाऊ तत्व नष्ट होते चला जा रहा है 7वही पानी, हवा ,ठंडी ,गर्मी निर्धारित चक्र में पृथ्वी के अंदर न जाने से भी असामान्यता पैदा हो रही है ।जीवन के लिए आवश्यक वन जिनसे सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए फल फूल ,अन्न, सब्जी ,पहनने के लिए परिधान, मकान बनाने के लिए लकड़ी, खाना पकाने के लिए इंधन, औषधियां आदि अनेक उपहार प्राप्त होते हैं। उनका भी धीरे-धीरे विनाश कर दिया गया है। पहाड़ों के पीठ नंगे कर दिए गए हैं। पृथ्वी का गर्भ काटकर कोयला ,खनिज आदि निकाल लिए गए हैं। फल स्वरुप बड़े पैमाने पर बनजर भूमि, कटाव ,बाढ़ ,सूखा ,भूकंप, प्राकृतिक आपदा का सामना आए दिन करना पड़ रहा है।

हमें अब तो सचेत होना होगा अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। अब तो अनिवार्य रूप से मनुष्य को जागना होगा ।सचेत होना होगा। सतर्क होना होगा। और अपने अनैतिक लोभ और ताकत के प्रदर्शन में हर हाल में अंकुश लगाना होगा। मां पृथ्वी को भी सहनशीलता और स्नेह बहुत प्रिय है ।जब तक परस्पर स्नेह सौजन्य ता का वातावरण बना रहता है। तब तक प्राणी ही नहीं प्रकृति भी स्नेह स्वभाव दिखाती है, और सहयोग करती है! लेकिन स्थिति बदलते ही प्रतिशोध के लिए कमर कस लेती है।

हमारी पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है! वह भी कुपित हो उठी है! वह रणचंडी का रूप धारण कर ले! इसके पहले ही मनुष्य को उसे शांत करने की प्रक्रिया अपनानी ही होगी। यह इस बात पर निर्भर है, कि हम उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। हमारी संवेदना उसे दुष्ट करेगी तभी तो वह हमें समृद्ध और सुविधा संपन्न बनाएगी। इस आदान-प्रदान को निरंतर चलाए रखने की पहली और अंतिम जिम्मेदारी केवल और केवल मनुष्य पर ही है।

विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी ।
विश्वंभर विभ्रति भूमि
रग्निमिन्द्र ऋषभा द्रविणेनो दधातु ।।
(अर्थात संसार का पालन करने वाली पृथ्वी धनधान्य से परिपूर्ण है। आश्रित जगत की क्षुधा मिटाने वाली पृथ्वी से यह कामना है कि वह हमें समृद्धि से ओतप्रोत करें।)

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

संतान पक्ष से आरोग्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें। भाइयों का साथ मिलेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

वृष

विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। परिवार व मित्रों के साथ समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा। शारीरिक कष्ट संभव है।

मिथुन

निवेश शुभ रहेगा। तीर्थयात्रा की योजना बन सकती है। व्ययवृद्धि से तनाव रहेगा। बजट बिगड़ेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। निवेश शुभ रहेगा।

कर्क

जीवनसाथी पर अधिक मेहरबान होंगे। कोर्ट व कचहरी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

सिंह

भागदौड़ रहेगी। बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम न उठाएं। कष्ट, भय, चिंता व तनाव का वातावरण बन सकता है।

कन्या

कार्य पर ध्यान दें। कोई राजकीय बाधा हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी गलत कार्य न करें। विवाद से बचें। काफी समय से अटका हुआ पैसा मिलने का योग है, प्रयास करें। व्यापार में अधिक ध्यान देना पड़ेगा।

तुला

मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। नए संपर्क बन सकते हैं। धनार्जन होगा। तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। मित्रों के साथ बाहर जाने की योजना बनेगी।

वृश्चिक

रोजगार प्राप्ति के योग हैं। परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है। शत्रुता में वृद्धि होगी। अज्ञात भय रहेगा। थकान महसूस होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। यात्रा सफल रहेगी।

धनु

भरपूर प्रयास करें। आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है।

मकर

शारीरिक कष्ट हो सकता है। बेचैनी रहेगी। नई योजना बनेगी। लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं। व्यय होगा। हानि संभव है।

कुंभ

पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है। अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी।

मीन

दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। व्यापार में लाभ होगा। दूर से शोक समाचार मिल सकता है, धैर्य रखें।

आज का इतिहास

22 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- 2002 - पाकिस्तान में पर्ल हत्याकांड की सुनवाई प्रारम्भ की।
- 2004 - उत्तर कोरिया में ट्रेनों की भीषण टक्कर, 3000 हताहत।
- 2005 - बांडुंग (इंडोनेशिया) में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई-अफ़्रीकी सम्मेलन आरम्भ।
- 2008 - भाजपा के महासचिव गोपीनाथ मुण्डे ने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया।
- 2010 - दिल्ली के ज़िला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसपी गर्ग ने वर्ष 1996 में लाजपत नगर बाज़ार में हुए विस्फ़ोट मामले में दोषी छह लोगों में से तीन मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली बट्ट और मिर्जा निशार हुसैन को मौत की सज़ा सुनायी।

2 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति

- 1914 - बी. आर. चोपड़ा - हिन्दी फ़िल्म निर्माता-निर्देशक
- 1916 - कानन देवी - भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फ़िल्म निर्माता। 1932 - स्वामी सच्चिदानंद - जानेमाने आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक, दार्शनिक तथा लेखक हैं।
- 1936 - पी. चंद्रशेखर राव, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में समुद्र के क़ानून के न्यायाधीश हैं।
- 1952 - कमला प्रसाद बिसेसर - भारतीय मूल की कैरेबियन द्वीप त्रिनिनाद एवं टोबैगो की महिला प्रधानमंत्री।
- 1960 - मनोज मुकुंद नरवणे - भारतीय थल सेना के नव नियुक्त सेना प्रमुख हैं।

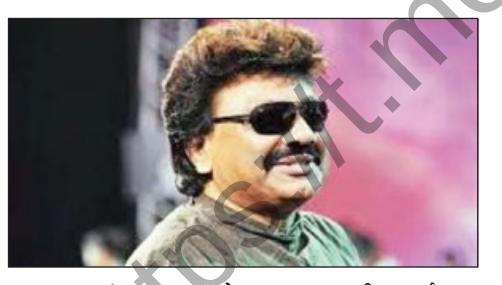

- 1962 - गुरुप्रसाद मोहापात्रा - भारतीय आईएएस अधिकारी थे।
- 1974 - चेतन भगत - मशहूर उपन्यास लेखक।
- 1894 - अम्मू स्वामीनाथन - भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थीं।
- 1851 - सर गंगा राम - प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे।
- 1840 - जेम्स प्रिंसेप - ब्राह्मी लिपि भाषाविद् एवं अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज़ व्यक्ति थे।
- 1760 - अकबर द्वितीय - मुग़ल वंश का 18वाँ बादशाह था।

22 अप्रैल को हुए निधन

- 2021 - श्रवण कुमार राठौर - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे।
- 2013 - लालगुड़ी जयरमण - भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक।
- 2001 - महमूद अली ख़ाँ - भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

विशेष आलेख

नींद का अभाव दिनचर्या और जीवन शैली के लिए घातक

डॉ वीरेन्द्र भाटी मंगल

वर्तमान दौर में बदली जीवन शैली के कारण लोग नींद से दूर होते जा रहे है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव व कार्य की अधिकता के कारण प्राय: लोग नींद से दूर होते जा रहे है, जो घातक है। नींद पूरी न होने की प्रवृति से आज बड़े-बुर्जुगों के साथ युवा भी पीड़ित हो रहे है। परिणाम स्वरूप घातक रोग सामने आ रहे है। एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में नींद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने और तंत्रिका के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। सही नींद स्वस्थ मानसिक स्थिति का भी कारक है। सही व संतुलित नींद मानसिक तनाव को भी कम करती है जिससे मन की उत्तेजना संयमित रहती है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क अपनी गहरी प्रक्रियाओं में लगा रहता है जो स्मृति और अवगति को बढ़ावा देता है। अच्छी नींद लेने वाले व्यक्ति दिनभर अधिक उर्जावान और सक्रिय होते हैं। वे काम में अधिक प्रभावी रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं।

नींद के प्रति लोगों में जनजागृति को लेकर प्रतिवर्ष 16 मार्च को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निद्रा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ नींद के महत्व के बारे में जागरूक करना है और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूक करना है। निंद प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह विशेष रूप से नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक सभी के लिए आवश्यक है। नींद शरीर को आराम देती है, मानसिक तनाव को कम करती है, मनोविकारों को रोकती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा, सही नींद की दिशा में अधिक संज्ञान और संज्ञानात्मक जीवनशैली स्वास्थ्य और कुशलता को बढ़ावा देती है।

नींद का अभाव हमारी दिनचर्या और जीवन को प्रभावित कर सकता है। नींद शारीरिक आराम के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर को विश्राम देती है, मांसपेशियों को आराम प्रदान करती है, और ऊर्जा को फिर से भरती है। इसके अलावा नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सही नींद हमें तनाव और चिंता से राहत दिलाती है, मानसिक तनाव को कम करती है, और हमें एक सकारात्मक मनोवृत्ति प्रदान करती है। नींद सही आने से ही हम दिनभर के कार्यों को संभालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते है। यह हमें जीवन में सक्रिय और प्रभावशाली बनाती है। इसके साथ ही नींद की कमी से हमारी याददाश्त और दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। अच्छी नींद आने से हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। कम नींद से, तनाव और चिंता का सामना करना मुश्किल हो सकता है। नींद की कमी से, हमारी कार्य क्षमता कम हो सकती है, जो काम पर असर डाल सकता है। नींद की कमी से शारीरिक समस्याएं जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

हमारे जीवन में नींद को हमेशा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हम अपने दिनचर्या में पर्याप्त नींद को शामिल कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते है। नींद हमारे शरीर और मन के लिए एक महत्वपूर्ण खुराक है। जिसकी पूर्ति करनी जरूरी है। हमारी संतुलित दिनचर्या के लिए सही नींद का आना बहुत जरूरी है। जब नींद संतुलित नहीं रहती है तो शरीर में कई समस्याओं का कारण बन जाती है, जैसे कि थकावट, चिंता, या मानसिक तनाव आम बात है। इसके लिए नियमित व्यायाम, ध्यान, और संयमित आहार बहुत जरूरी है। इसके अलावा अनियमित नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, इससे मोटापा, मनोविकार, और दिल की बीमारियां बढती है। सही मायने में नींद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरी नींद लेकर ही हम अपने जीवन को स्वस्थ, सक्रिय, और उर्जावान रख सकते है। इसलिए बढती जीवन शैली में नींद के महत्व का हम समझे।

समय पर सही नींद लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने नींद पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें ताजगी और ऊर्जा देने के साथ-साथ हमें दिनभर के कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करती है। जीवन में नींद की अधिकता या कमी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बनती है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, और अन्य अंगों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। सही नींद से, हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। यह हमें तनाव, चिंता, और उदासी के खिलाफ मजबूत बनाता है। नींद से बढ़ी हुई स्मरण शक्ति हमें बेहतर याददाश्त और मनोविज्ञान में मदद करती है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही नींद की आवश्यकता होती है।

कॉन्ग्रेस और कम्युनिस्ट' 'एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं

रामस्वरूप रावतसरे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मलयालम चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न सवालों का खुल कर जवाब दिया। इससे पहले वो तमिल चैनल को इंटरव्यू दे चुके हैं। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस बार दक्षिण भारत क्षेत्रीय भाषाओं पर अधिक है। ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2014 उम्मीद का कालखंड था, लोगों के दिल में भी उम्मीद थी और उनके मन में भी उम्मीद थी कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें ।पीएम मोदी ने कहा, मैं शासन नहीं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। मैं पद पर बैठकर मौज करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं लोगों के लिए एक सामान्य नागरिक से भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में वो विश्वास में पलट गया। जन सामान्य के विश्वास ने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया, मुझे लगा हम सही दिशा में हैं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' का जो मंत्र लेकर चले हैं, उसे हम जमीन पर उतार पाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, भाजपा नहीं लड़ रही है, ये देश की जनता की पहल है। उन्होंने कहा कि देश की जनता, 10 साल के अनुभव के अनुसार निर्णय कर चुकी है। हमने डिजिटल अप्रोच लिया, ह्यूमन इंटरवेंशन को हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने याद किया कि कैसे किसी प्रधानमंत्री (राजीव गाँधी) ने कहा था कि हम एक रुपया भेजते हैं, तो 15 पैसा ही पहुँचता है। पीएम मोदी ने कहा कि 85 पैसा बीच में कोई न कोई पंजा खा ही जाता था, जबकि अब हम 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने मामले दर्ज किए हैं, उनमें से सिर्फ 3 प्रतिशत लोग ही राजनीति से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कोई संस्था बनाई गई है, वो काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए। काम करे, इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक ही नहीं बनता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया कि भाजपा अपर कास्ट की पार्टी है, जबकि सच ये है कि भाजपा में सबसे ज्यादा एससी हैं, सबसे ज्यादा एसटी हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिर नैरेटिव बनाया गया कि भाजपा अर्बन पार्टी है, साथ ही जवाब दिया कि आज भाजपा में ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फिर नैरेटिव बनाया गया कि भाजपा पुराणपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती है। आज दुनिया में डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व भाजपा शासित सरकार कर रही है। ये जो भ्रम फैलाए गए हैं, वो गलत हैं।

https://t.me/Anewspaperabc

हिंदू हारे क्यों और अब हिंदू उत्कर्ष के कारण क्या हैं?

हिन्दुओं ने आत्म मुग्धता के साथ केवल अपने बारे में महानता की बातें कीं लेकिन जो सावरकर और हेडगेवार को जानते हैं वे समझते हैं कि अपनी दुर्बलताओं की और ध्यान दिए बिना शक्ति अर्जन का पथ प्रशस्त करना संभव नहीं होता। वर्तमान हिंदू उदय का काल सनातन हिन्दुओं की वीरता और उनके असीम धैर्य के साथ विश्व में दुर्लभ संघर्ष की अद्भुत निरंतरता बताता है तो उसके साथ ही स्मरण रखना होगा पिछले कई सौ वर्षों में हिन्दू द्वारा हिन्दू से विद्वेष, हिंदू की हिंदू से शत्रुता, असंगठन, शत्रु के साथ अपने स्वार्थ के लिए जा मिलना और सामूहिक शत्रु के विरुद्ध अपने ईर्ष्या भाव खत्म कर संगठित बल से उस शत्रु का हनन करने की भावना का ना होना जिसने हिंदुओं को विदेशी क्षुद्र शक्तियों का दास बनाया। हिन्दुओं ने आत्म मुग्धता के साथ केवल अपने बारे में महानता की बातें कीं लेकिन जो सावरकर और हेडगेवार को जानते हैं वे समझते हैं कि अपनी दुर्बलताओं की और ध्यान दिए बिना शक्ति अर्जन का पथ प्रशस्त करना संभव नहीं होता। ये पांच सौ वर्ष कैसे बीते हमारे ? इन वर्षों में लाखों हिन्दुओं का वध हुआ, उनकी स्त्रियों का अपमान हुआ, बच्चे नर नारी गुलाम बनाकर काबुल और बगदाद के बाजारों में बेचे गए, हमारे मंदिरों का ध्वंस हुआ और उनका अपमान हुआ, हमारे पूर्वजों को डरा धमका कर, संहार के भय से इस्लाम में लाया गया। आज उन मतांतरित हिन्दुओं के वंशज ही आक्रमणकारी विदेशियों की भांति हिन्दू धर्म, एवं आस्था स्थलों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, क्यों ? पांच सौ वर्षों के संघर्ष की निरंतरता के बाद हिन्दुओं के असीम धैर्य के बावजूद उनके प्रति मतांतरित जिहाद-अनुयायियों की शत्रुता काम क्यों नहीं हुयी ? हिन्दू इन विषयों पर सोचना भी नहीं चाहता। स्मृति भ्रंश और विगत के बलिदानों का विस्मरण हमारी बड़ी कमजोरी है। मंदिरों की अपरमित आय उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित रहती है। हिन्दुओं का कौन सा एक भी मंदिर है जो अपने ही रक्तबंधु दलितों के प्रति समता और सच्चे आत्मीयता का भाव जन जन में पैदा करने के लिए दो चढ़ावा खर्च करता होगा? अथवा देश के कोने कोने मं हिन्दुओं को धर्मान्तरित करने वाली शक्तियों के सामने हिन्दू रक्षक और समरसता के यथार्थ प्रहरी भेजने हेतु अपने करोड़ो रुपये के हिन्दू-धर्म-दान का कोई अंश खर्च करता होगा? इन हिन्दू मंदिरों के संचालक एवं धर्म कोष के अधिपति अपनी राजनीतिक अभीप्साओं की पूर्ति के लिए मंदिर कोष कभी सरकारी कार्यों हेतु, कभी आगंतुक राजनीतिक महानुभाव के सरकारी सहायता कोष हेतु, कभी सड़क पानी बिजली के लिए खर्च कर अपने लिए राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा की संभावनाएं ढूंढते हैं। लेकिन अरुणाचल से लेकर अंडमान और लद्दाख तक जो संगठन हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनको कभी दो रुपये की सहायता नहीं देते। हिंदू पर्व केवल लोकाचार-रीति रिवाज और कर्मकांड के पालन द्वारा अपनी क्षुद्र मनोकामनाएं पूरी करवाने का पाखंड नहीं होना चाहिए। हिन्दू क्यों हारा? किन कारणों से आक्रमणकारी जीते? किन कारणों से हमारा संगठन जातियों, धन कुबेरों के स्वार्थों, धार्मिक कुरीतियों और रूढ़िवादिता के कारण छिन्न भिन्न होता रहा? और किन महापुरुषों ने हिन्दू संगठन का बीड़ा उठाया जिस कारण आज सर्वत्र एक हिंदू उत्कर्ष का भाव दिखने लगा है? इन पर विचार किये बिना भारत के नवीन भाग्योदय पर विमर्श अधूरा ही कहा जायेगा।

स्मरण रखिये महाशक्ति संपन्न, विष्णु के अवतार श्री राघव को भी रावण वध से पूर्व भगवती शक्ति का आवाहन कर आशीर्वाद लेना पड़ा था. हमारे अवतारी पुरुष और वीर पराक्रमी गुरु दुष्ट हन्ता, जनसंगठक, मयार्दा रक्षक, प्रजा वत्सल, अत्यंत सौम्य, अक्रोधी, शालीन, भद्र, सबकी सुनने वाले और विनम्र रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जीवन भर जन हित के लिए संघर्ष किया- उनको जीवन में कभी लौकिक सुख नहीं मिला -विलासिता और ऐश्वर्य से कोसों दूर रहे। यदि कृष्ण शक्ति, नीति और पराक्रम के योद्धा पुरुष थे जिनको सुदर्शन चक्र के प्रतापी रूप से जाना गया तो राम मयार्दा भक्षक रावण तथा उसके पुत्रों के वध के बाद उसकी स्वर्णमयी लंका भस्म कर- 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' कहते हुये अयोध्या लौटे-और कृष्ण ने मथुरा वृंदावन से हजारों मील दूर गुजरात में देहोत्सर्ग किया। दोनों ही अवतारी पुरुष शक्ति और पराक्रम के अन्यतम उदाहरण हैं। अर्थात जहाँ आवश्यक हो वहां अरि हनन कर सज्जनों को अभय देना ही हिन्दू सनातन परंपरा का प्राचीनतम सन्देश रहा है। शक्ति का उपार्जन करना, स्वयं को शत्रु से अधिक बलशाली बनाना, पश्चाताप रहित शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना, उसके प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाना, सत्य और धर्म रक्षा के लिए प्रत्येक पग उठाने का साहस रखना ही सनातन नियम है। वर्तमान सन्दर्भों में भारत के आराधकों का विजय पथ पर आरोहण एक नए युग के प्रवर्तन का प्रतीक है। एक ओर यदि हिंदू उत्कर्ष की पुनः प्राप्ति हमारे संघर्ष के अटूट सातत्य का स्वर्णिम अध्याय है तो यह भी सत्य है कि सनातन पथ पर सनातन का नाम लेने वालों ने ही अति दुर्गम कंटक भी बोये, हिन्दू निर्वीर्य दुर्बलताओं का अनुभव भी हुआ, शक्ति अर्जन और जन संगठन में कमियां रहीं। 'तुम विजयी हो गए तो क्या हुआ, पहले यह बताओ मुझको क्या मिला?' इस प्रकार के भाव लेकर सनातन ही सनातन की पराजय का कारण बना। यह इस प्रकार था मानों लंका विजय के बाद हनुमान श्री रघुवीर से पूछें कि अब मुझे कौन सा मंत्रालय मिलेगा? अयोध्या वालों ने तो कोई युद्ध नहीं किया, इसलिए अधिकांश पद, वानर और रीछ जातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इस भाव के विरुद्ध जन संगठन और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि मानने का भाव सनातन की विजय सुनिश्चित करता है। जितना भी यह भाव बढ़ेगा हिंदू उत्कर्ष उतना ही निकट आएगा। - तरुण विजय

45 साल की अदावत से पहले 31 साल तक पक्के दोस्त रहे दोनों देश, ईरान और इजरायल में सीधी जंग हुई तो कौन पड़ेगा भारी?

19 अप्रैल को हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कुल मिलाकर कहें तो मीडिया ईस्ट में तनाव बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इजरायल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोनों आपस में एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों देश कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। हम सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इस बयान से साफ कर दिया था कि वो ईरान से बदला लेंगे कब, कहां और कैसे? इस सवाल का जवाब आज सुबह सवेरे मिल गया। जब खबर आई कि कई दिनों की प्लानिंग के बाद इजरायल ने जुम्मे के दिन ईरान पर हमला कर दिया। आपको याद होगा कि 13 अप्रैल यानी शनिवार के दिन ईरान ने इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन दागे थे। शनिवार यहूदियों के लिए पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन को यहूदि सब्बाथ कहते हैं। अब इजरायल ने भी इस्लाम के पवित्र दिन शुक्रवार को ईरान पर हमला कर दिया। इजरायल ने ईरान पर एयरस्ट्राइक कर उसके इस्फहान शहर को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान की तरफ से इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए गए थे। और उससे भी पहले इजरायल की तरफ से दमिश्वक में इजरायली दूतावास की इमारत को निशाना बनाया गया। हालांकि 19 अप्रैल को हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कुल मिलाकर कहें तो मीडिया ईस्ट में तनाव बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इजरायल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोनों आपस में एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों देश कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। 1948 में इजरायल अस्तित्व में आया। उस वक्त उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1948 में अरब इजरायल वॉर हुआ और फिर 1956 में स्वेज नहर संकट, 1967 में सिक्स डे वॉर, 1973 का युद्ध लेकिन ईरान कभी इन युद्धों में किसी की तरफ से शामिल नहीं हुआ। इस दौरान दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ थे। उसे एक देश के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर रहे थे। जब सभी मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ थे तब ईरान ने ही सबसे पहले इजरायल को मान्यता दी थी। इसके बाद इजरायल ने भारी तादाद में ईरान को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया था। फिर ईरान की तरफ से भी इजरायल को तेल की सप्लाई की जाने लगी। दोनों देशों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि इजरायल और ईरान की खुफिया एजेंसियां टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग भी साथ में किए। ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरूआत हुई। इजरायल के साथ ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी ने अमेरिका और इजरायल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया। मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठने लगे। 1979 में ईरान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बन गया और इसी के साथ इजरायल के साथ ईरान के रास्ते अलग हो गए। दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई। एयर रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर विराम लग गया। आगे चल कर रिश्ते और बिगड़ गए जब ईरान ने इजरायल के विरोधी सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों को हथियार की सप्लाई शुरू कर दी।

26 अप्रैल के बाद अमेठी-रायबरेली के पत्ते खोलेगी कांग्रेस

- अजय कुमार

अमेठी से राहुल तो रायबरेली से प्रियंका वाड्रा होंगी प्रत्याशी!

लखनऊ। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को और अमेठी में 20 मई को पांचवें चरण में होना है। दूसरे चरण और पांचवें चरण के बीच 24 दिनों का अंतराल गांधी परिवार के लिये सियासी रूप से बहुत चौकानें वाला हो सकता है। कयास लगाये जा रहे हैं कि वॉयनाड के मौजूदा और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी वॉयनाड में 26 अप्रैल को मतदान होने के बाद अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। इस बात को हवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी दी है। महाराष्ट्र के नांदेड में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा पीएम ने कहा कि राहुल गांधी पहले अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड गए, अब उन्हें वायनाड से भी हार का डर सता रहा है। पीएम ने कहा, शहजादे अब वायनाड छोड़कर दूसरी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं।वैसे मोदी ने इसी के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा था।

वैसे कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार भी राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। पार्टी की ओर से इस बारे में संकेत भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आगामी 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तब तक दूसरे चरण में वायनाड में मतदान हो चुका होगा, जहां से वह अभी पार्टी प्रत्याशी हैं। पार्टी का मानना है कि अब भी गांधी परिवार को इन परंपरागत सीटों पर अधिक प्रचार की आवश्यकता नहीं है। शायद इसी वजह से अब तक पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते खोलने से परहेज किया है।

उधर, कुछ दिनों पूर्व अखिलेश के साथ प्रेस कांफ्रेस करते हुए राहुल गांधी ने गोलमोल जबाव देकर सस्पेंस बरकरार रखा था। अमेठी से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि यह पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का अधिकार क्षेत्र है और वह इसके फैसले का पालन करेंगे। जबकि भाजपा ने स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है।राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी और कांग्रेस अध्यक्ष मुझ से जो भी करने को कहेंगे, मैं करूंगा। ऐसे फैसले हमारी सीईसी में होते हैं। हाल ही में अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद अमेठी आएंगे और वह धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी से हमें सचेत रहना होगा राहुल सनातन विरोधी पहले से हैं। स्मृति ईरानी 29 अप्रैल को नामांकन करेंगी।

बहरहाल,जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूछा गया कि अमेठी-रायबरेली सीट से कांग्रेस किन्हें उम्मीदवार बनाएगी. इस सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि हम लोग चाहते हैं राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी-रायबरेली से चुनाव लड़ें. ऐसा ही कांग्रेस संगठन भी चाहता है. हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों के संबंध में कांग्रेस चुनाव समिति (सीईसी) तय करेगी.

बता दें कि माना जा रहा है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी और रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. जहां अमेठी से बीजेपी ने फिर से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं रायबरेली सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का एलान नहीं किया है.

उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर आगामी 20 मई को पांचवें चरण में मतदान होना है। आगामी 27 अप्रैल से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस वायनाड के मतदाताओं को मतदान से पहले यह संदेश नहीं देना चाहती है कि राहुल गांधी यह सीट छोड़ सकते हैं। अथवा वायनाड के विकल्प के रूप में अमेठी सीट भी है। इसलिए अभी तक कांग्रेस ने रणनीति के तहत अमेठी से पार्टी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन वह अमेठी में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे।

आखिर कब थमेगी अपने ही युवाओं से खून की होली

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षाबलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जवान नक्सलियों के अड्डे तक पहुंचने के लिए 20 घंटे तक पैदल चले हैं। नक्सलियों के समूह को देखने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की थी। जब बंदूकें शांत हुईं, तो जंगल के फर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। इनमें ललिता, शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़े के शवों की पहचान सबसे पहले की गई। मृतकों में पंद्रह महिलाएं भी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता को केन्द्र और राज्य में भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कम समय में देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस अभियान को गति मिली है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बल कैंप लगाए जा रहे हैं। 19 के बाद इनकी संख्या 250 हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी मदद मिल रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन महीने में 80 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 125 गिरफ्तार हुए हैं और 150 ने आत्मसमर्पण किया है। देश के 10 राज्यों में 70 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखंड जहां 16 जिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित 14 जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नक्सलियों को आशंका थी कि सरकार उनके खिलाफ अभियान तेज करेगी और हुआ भी ऐसा ही। राज्य की नई सरकार ने शान्ति का प्रस्ताव भी सामने रखा था लेकिन नक्सल नेताओं की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षाबलों को बस्तर में फ्री हैण्ड कर दिया गया हैं। ऐसे में पिछले तीन महीनों में नक्सलियों को कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। अब तक जहां माओवादियों के बटालियन स्तर के नेता ही ढेर हुए थे तो इस बार शंकर राव जैसे डिवीजन लेवल का नेता पुलिस के गोली का शिकार हुआ हैं। ऐसे में नक्सली प्रदेश में पूरी तरफ से बैकफुट में हैं। अब लगातार सवाल किये जा रहे हैं कि आखिर

कब तक छत्तीसगढ़ को इस नक्सल दंश से छुटकारा मिल पायेगा और बस्तर में खून की होली थमेगी। सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है कि पिछले एक दशक में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं, मौतों और उनके भौगोलिक प्रसार में काफी कमी आई है। जहाँ वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी वहीं वर्ष 2018 में प्रभावित जिलों की संख्या 60 रह गई है। वर्ष 2009 में जहाँ नक्सलवाद की घटनाओं और इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्रमश 2258 व 1005 थी वहीं वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर क्रमश 833 एवं 240 रह गई। देश के जिन 8 राज्यों के लगभग 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई है उनमें ओडिशा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 तथा बंगाल के 8 जिले शामिल हैं। वर्ष 2015 के बाद से नक्सलियों के 90 प्रतिशत हमले लगभग चार राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हुए हैं।

माओवादियों के थिंक-टैंक और प्रथम पंक्ति के नेता या तो मारे जा चुके हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरूआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड? पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यत कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं।

नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया है। नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है। सरकार नक्सली चरमपंथ से निबटने के लिये बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय शामिल हैं। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है।

सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप नक्सलियों के हौसले कमजोर हुए हैं तथा उनके आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ रही है। विमुद्रीकरण ने भी नक्सलियों को पहुँचने वाली वित्तीय सहायता पर लगाम लगाई है और इसके बाद से अब तक 700 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48877 किमी. सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। इसके तहत कुल 4072 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर पुलिस की दवाब बनाने की सक्रिय कार्रवाई और विकास बहुआयामी योजनाओं से नक्सली समस्या जड़मूल से समाप्त हो सकेगी।

- योगेन्द्र योगी

विश्व के 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने से पहले भारत का जल संकट

भारत में पानी की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि ग्लोबल वा?मग 1.5 डिग्री की सीमा तक पहुंच रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े हुए तापमान और मानसून के पैटर्न में बदलाव से पानी की कमी और बदतर हो गई है, जिससे कृषि और आवश्यकताओं की स्थिरता खतरे में पड़ गई है। तत्काल कार्रवाई आवश्यक है क्योंकि अस्थिर प्रथाओं और बढ़ते शहरीकरण से जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। भारत को इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि यदि पर्याप्त शमन उपाय नहीं किए गए, तो पानी की समस्या बदतर हो जाएगी और तापमान बढ? और वर्षा अनियमित होने से आजीविका और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। 1.5 डिग्री ग्लोबल वा?मग की स्थिति में देश के स्थायी भविष्य के लिए भारत की जल समस्याओं का समाधान आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में हालिया संकट एक भयावह संकेत है कि देश की बदलती जलवायु, अप्रत्याशित मानसून, अत्यधिक तापमान और जल निकायों का कुप्रबंधन इस विशाल देश के लिए गंभीर खतरे हैं।

1000 वर्षों में, भारत ने कृषि, घरेलू खपत और कई अन्य उपयोगों के लिए देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए एक विस्तृत जल प्रणाली विकसित की है। हालांकि, 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ, उन मांगों में नाटकीय रूप से विस्तार हुआ है। कृषि, घरेलू उपभोग और अन्य उद्योगों के क्षेत्र, जो पहले से ही लेन-देन के सूक्ष्म संबंध में थे, काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत की 1.4 अरब की मजबूत आबादी ने सभी क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दिया है, जो स्वाभाविक रूप से जल संसाधनों की घटती उपलब्धता से पूरा हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से अपर्याप्त दूरदर्शिता और योजना के कारण हुआ है और अक्सर इसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों की कमी हो गई है। भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार एक अन्य महत्वपूर्ण कारक मानसून पैटर्न में बदलाव है। मानसून का मौसम पहले कृषि के लिए वरदान था, लेकिन हाल के दिनों में इसमें अप्रत्याशितता बढ़ गई है। रुक-रुक कर भारी वर्षा के साथ लंबे समय तक शुष्क मौसम आम हो गया है, जिससे पारंपरिक खेती के पैटर्न बाधित हो रहे हैं और कृषि उत्पादन कम हो रहा है। यह प्रवृत्ति खाद्य सुरक्षा और लाखों कृषि नौकरियों में बदलाव को खतरे में डालती है।

सबसे गंभीर समस्याओं में से एक को याद रखना आवश्यक है जिसे आगामी चुनावों से पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक में हल नहीं किया जाएगा-बढ़ते मौसम के मिजाज के बीच भारत में जल संसाधनों का कुप्रबंधन। बेंगलुरु में हालिया जल संकट केवल एक छोटी सी चेतावनी थी जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि गंभीर जलवायु-प्रेरित मुद्दों से बचने के लिए भारत की जल सुरक्षा की रक्षा के लिए व्यापक उपाय जल्द ही लागू किए जाने चाहिएं। हालांकि, भारत में पानी की समस्या जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक बहुस्तरीय और जटिल है। यह किसी विशेष मुद्दे तक सीमित नहीं है, जैसे कि तेजी से शहरीकरण, औद्योगिक विकास, कृषि और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा; जलवायु परिवर्तन भी इन और अन्य समस्याओं को बढ़ा देता है। अप्रत्याशित मानसून और बढ़ता तापमान केवल पानी की कमी को बढ़ाता है, जिससे लोगों और अर्थव्यवस्था की कृषि और उद्योग जैसी सबसे बुनियादी जरूरतें कमजोर हो जाती हैं।

बेंगलुरु, जिसे कभी-कभी भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, में गंभीर जल संकट था, जो इस बात को उजागर करता है कि शहरी क्षेत्र पानी की कमी के प्रति कितने संवेदनशील हैं। शहर जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह अस्थिर भूजल निकासी और अपर्याप्त वर्षा जल संग्रहण सुविधाओं पर निर्भर है। यदि पूर्व-निवारक कदम नहीं उठाए गए, तो तापमान बढ? और वर्षा अधिक अनियमित होने के कारण ऐसी स्थितियां अधिक बार और गंभीर होने की संभावना है।

भारत के जल संसाधनों के गलत प्रबंधन के शहरों से परे भी दूरगामी परिणाम हैं। जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत कृषि में कार्यरत है, जो इसे विशेष रूप से असुरक्षित बनाता है। अप्रत्याशित मौसम के साथ, मानसून की बारिश पर निर्भर पारंपरिक खेती के तरीके अब टिकाऊ नहीं रह गए हैं। सूखे, बाढ़ और भूजल स्तर में गिरावट के कारण किसानों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके कारण फसल की विफलता होती है। इसके अलावा, पानी की कमी भारत के औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, जो देश के आर्थिक विस्तार का मुख्य इंजन है। शीतलन, स्वच्छता और विनिर्माण कार्यों के लिए कई व्यवसायों के लिए पानी आवश्यक है। उत्पादन को खतरे में डालने के अलावा, घटती जल आपूर्ति भी इन उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डालती है।

भारत की जल दुविधा का समाधान : भारत की जल दुविधा के लिए मजबूत नीति निर्णय और वैज्ञानिक समझ के संयोजन वाली एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जल संसाधनों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन की सख्त जरूरत है। इसमें कानूनी ढांचे को मजबूत करना, जल-बचत नवाचारों को वित्त पोषित करना और उद्योगों में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना शामिल है। -अंजल प्रकाश

अपनी मुर्गियों को अंडे सेने से पहले मत गिनें

2024 के आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। वह एक पुरानी कहावत, ह्यअपनी मुर्गियों को अंडे सेने से पहले मत गिनें, वर्तमान उम्मीदों पर लागू होनी चाहिए कि विजेता कौन बनेगा? व्यापक सहमति इस बात पर बनती दिख रही है कि न केवल मोदी सत्ता में वापस आएंगे। बल्कि शायद 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ। जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता और गिनती नहीं हो जाती, तब तक हम किसी नतीजे पर यकीन नहीं कर सकते, भले ही अभी हालात किसी खास नतीजे के पक्ष में दिख रहे हों। उसकी वजह यहां है। सबसे पहले, अतीत के विपरीत, हर दूसरे दिन टी.वी. चैनलों पर बहुत सारे जनमत सर्वेक्षण दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ को वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन अन्य को नहीं। वास्तव में, उनके अंतिम सीट अनुमानों में व्यापक समानताएं, अनुमानों पर आश्चर्य होता है कि क्या यहां काम में किसी प्रकार की पुष्टि पूर्वाग्रह नहीं है। यह मानते हुए भी कि संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को बता रहे हैं कि वे वास्तव में मतदान के दिन क्या कर सकते हैं। मतदाता द्वारा ई.वी.एम. बटन दबाने से पहले ही मतदान की प्राथमिकताओं को सीट जीत में बदलने के खतरों को कम कर-के आंका नहीं जा सकता है।

दूसरा, मौसम कार्यालय ने इस वर्ष भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की है। देश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा का प्रतिबद्ध या सीमांत मतदाता घर पर बैठने का फैसला करेगा, या भाजपा के विरोधी को वोट देगा। हम वास्तविक मतदान दिवस तक यह नहीं जान सकते। यह एक असंभव बात है जिस पर सभी पक्षों को विचार करना होगा। (एक तरफ, यह अफसोस की बात है कि लगभग एक अरब मतदाताओं को तेज गर्मी के बीच में ही मतदान केंद्रों की ओर जाना पड़ सकता है)

तीसरा, सर्वेक्षणकत्र्ताओं और कुछ टी.वी. एंकरों के विपरीत, भाजपा ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है जैसे कि चुनाव जीत लिया गया हो। हालांकि वे स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से विश्वास व्यक्त करते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया है। वरना मोदी दिन-रात पसीना नहीं बहा रहे होते। कमजोर राज्यों में कई सहयोगियों और दलबदलुओं की तलाश लगातार जारी है। एक ऐसी पार्टी के रूप में जो मतदाताओं के मूड में बदलाव देखने के लिए कई बार निजी तौर पर मतदान करती है। 400 पार की बयानबाजी परिवार के लिए प्रतिबद्ध वोट हासिल करने का स्पष्ट आह्वान हो सकती है।

राज्यों में कई चरणों में मतदानः चौथा, बड़े राज्यों में मतदान की व्यापक प्रकृति (बहुत कम में एक दिवसीय मतदान होता है) कि पहले चरण में मतदान बाद के चरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डाल सकता है। बाड़ लगाने वाले पहले चरण में संभावित जीत का समर्थन करने का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि जो लोग फिर से (अनुमानित) शुरूआती रुझानों के खिलाफ हैं, वे बाद के चरणों में प्रतिशोध के साथ मतदान कर सकते हैं ताकि उनकी शत्रुता को कार्यालय लेने से रोका जा सके। बहु-चरणीय मतदान में पार्टियों के पास स्वयं गियर बदलने और संदेश देने का विकल्प होता है। 2009 में, कांग्रेस पार्टी के (दिवंगत) वाई.एस. राजशेखर रैड्डी ने पहले चरण में तेलंगाना समर्थक भाषण दिए, जबकि अगले चरण में आक्रामक रूप से एकजुट आंध्र की वकालत की। उन्होंने दोनों चरण जीते। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, जहां एक ही मुद्दे (उदाहरण के लिए सी.ए.ए.) पर अलग-अलग संदेश सुनने के इच्छुक कई निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां अलग-अलग चरणों में संदेश अलग-अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि न केवल अलग-अलग राज्य, बल्कि एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्र इस बार अलग-अलग मतदान कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित आई.टी.आई.सी.एस. परिणामों की संभावना का पता चलता है। (एक तरफ, फिर से, किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या बहु-चरणीय मतदान के साथ भी, चुनावों पर मतदान 6 लंबे हफ्तों तक फैलाया जाना चाहिए)। छठा, सहयोगियों के बीच वोट हस्तांतरण की भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है। जबकि यू.पी. में सपा-कांग्रेस गठबंधन को 2019 में सपा-बसपा गठबंधन की तरह विरोधाभासों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, महाराष्ट्र में एम.वी.ए. को इस बात की वास्तविकता की जांच करनी होगी कि क्या उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व मतदाता कांग्रेस या शरद पवार को वोट देंगे या इसके विपरीत वोट देंगे। सेना और राकांपा में विभाजन से ऐसी मतदाता दुविधाओं को हल करना और अधिक कठिन हो जाएगा। दिल्ली में, भाजपा का डर वास्तव में कांग्रेस और ह्यआपह्न के मतदाताओं को एक साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक बना सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है क्योंकि हर मतदाता जानता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव सिर्फ 10 महीने दूर हैं, और दोनों पार्टियां अलग-अलग कोनों से चुनाव लड़ेंगी। सातवां, न्यायिक कार्रवाई से कुछ राज्यों में फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अदालतें केजरीवाल समेत जेल में बंद ह्यआपह्न के सभी वरिष्ठ नेताओं को रिहा कर दें तो दिल्ली के मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। क्या उस समय सहानुभूति मतदाताओं को प्रभावित करेगी? इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सर्वेक्षणकर्ता गलत हैं। या कि भाजपा इसे उसी तरह खोने जा रही है जैसे 2004 में जनमत सर्वेक्षणों में पसंदीदा घोषित किए जाने के बाद वाजपेयी ने खो दिया था। 1 जून तक इंतजार करना सबसे अच्छा है, जब एग्जिट पोल आएंगे या इससे भी बेहतर, 4 जून तक इंतजार करना होगा। **-आर. जगननाथन**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

नेताओं की घर वापसी का फायदा नहीं उठा पाया अकाली दल बादल

देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के चलते पूरे भारत में चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं, पंजाब भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन पंजाब की सियासी फिजा अप्रत्याशित दिशा में आगे बढ़ रही है पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता अपनी वफादारी बदल कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और उन पार्टियों की उम्मीदें भी बढ़ा रहे हैं। पंजाब की 5 प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा और बसपा ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जिसके नेता इधर-उधर न गए हों।हालांकि दल बदलने का चलन नया नहीं है और नेता लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अब अकाली दल बादल की स्थिति अन्य पार्टियों से कुछ अलग है। 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अकाली दल के कई बड़े नेताओं, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल के महासचिव सुखदेव सिंह ढींडसा, लोकसभा सदस्य रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, रतन सिंह अजनाला और सेवा सिंह सेखवां आदि शामिल थे, ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ब्रह्मपुरा ने अपने सहयोगियों के साथ टकसाली अकाली दल का गठन किया और सुखदेव सिंह ढींडसा ने यूनाइटेड अकाली दल का गठन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा जब पार्टी के 100 साल के इतिहास में पहली बार अकाली दल को केवल 3 सीटें मिलीं। इस हार ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

बाद में शिरोमणि कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने भी सुखबीर सिंह बादल की पार्टी की संप्रभुता को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और घोषणा की कि वह अकाली दल बादल के उम्मीदवार के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी। शिरोमणि अकाली दल ने बीबी जगीर कौर को पार्टी से निलंबित कर दिया। ये सब यहीं नहीं रुका बल्कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अकाली दल से नाता तोड़ लिया और बाद में बड़ी संख्या में दिल्ली कमेटी के सदस्यों ने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया और अकाली दल हाशिए पर चला गया। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इन सब पर काबू पाने की योजना बनाई। श्री अकाल तख्त पर पहुंच कर सिख संगत से माफी मांगी गई। सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल से अलग हुए पूरे नेतृत्व से घर वापसी की अपील की और धीरे-धीरे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और मंजीत सिंह जी.के. समेत कई नेता अकाली दल में शामिल हो गए। बाद में, सुखबीर सिंह बादल यूनाइटेड अकाली दल के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा और बीबी जगीर कौर को फिर से पार्टी में शामिल करने में सफल रहे। इस तरह सुखबीर सिंह बादल एक बार लोकसभा चुनाव से पहले यह संदेश देने में कामयाब रहे और वह अकाली दल को एकजुट करने में लगभग सफल हो गए हैं। हालांकि, जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सुखबीर सिंह बादल के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अकाली दल को एकजुट करने की उनकी मुहिम जोर पकड़ती नजर आ रही है। अकाली नेता सिकंदर सिंह मलूका के बेटे और उनकी आई.ए.एस. पत्नी ने नौकरी छोड़कर अकाली दल को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा दोआबा में अकाली दल का दलित चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक पवन टीनू भी अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे अकाली दल को गहरा झटका लगा। टीनू के साथ जिला जालंधर शहरी के पूर्व अध्यक्ष गुरचरण सिंह चन्नी भी अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। चुनाव के लिए नामांकन भरने में अभी काफी समय है और यह कहना मुश्किल है कि यह सिलसिला कब रुकेगा।

पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर विशेष

पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो प्लास्टिक को कहना होगा ना

सरकारी प्रतिबंधों के बीच एकल उपयोग वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग छूट नहीं रहा है। चोरी छिपे घटिया प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। इसका जीता जगाता उदाहरण नालों-सड़कों से अटा-पटा प्लास्टिक कचरा है। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक

इंगर एंडरसन की माने तो, जिस तरह से हम प्लास्टिक का उत्पादन, उपयोग और निपटान करते हैं, वह पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित ही कर रहा है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है और जलवायु को अस्थिर कर रहा है।

संजय कुमार

1970 में शुरू हुआ, पृथ्वी दिवस आज एक वैश्विक उत्सव बन गया है, जिसमें 193 से अधिक देशों में सालाना एक अरब से अधिक लोग भाग लेते हैं। विकास और बेहतर जीवन की चाहत ने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया है। खासकर पशु-पक्षी-मानव बल्कि हर जीव का स्वास्थ्य खतरे में है, जो एक गंभीर चिंता के रूप में है।

22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। और इस बार पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है, प्लैनेट बनाम प्लास्टिक,जो पारिस्थितिक और मानव स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है, ताकि पृथ्वी बची रहे।

प्लास्टिक से पर्यावरण खतरे में हैं। हमने इसे आज खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। ऐसे में पर्यावरण की तस्वीर धुंधली होती जा रही है। विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, अवैध खनन, निर्माण और विनाशकारी पदार्थों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। कह सकते हैं पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों में तेजी से हो रहे बदलाव ने प्रदूषण शब्द को पैदा कर दिया है।

इसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक प्रकार का अत्यंत धीमा जहर है, जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसे रोग ग्रस्त बना रहा है, बल्कि जीव- जंतुओं, पशु -पक्षियों, पेड़-पौधों और वनस्पतियों को भी नष्ट कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण ही आज विश्व में जीवन खतरे में है। इस की वजह से बहुत से जीव जंतु, पशु-पक्षी, वन्य प्राणी दुनिया से विलुप्त हो गए हैं या कगार पर हैं। यही नहीं प्रदूषण से कैंसर, रक्तचाप, शुगर, दमा, मलेरिया, चर्मरोग, नेत्ररोग जैसी बीमारी से इन्सान संघर्ष कर रहा है। डराने वाली बात कहें तो सारा विश्व भयाक्रांत है। पर्यावरण को प्रदूषित करने में आज के समय में प्लास्टिक की भूमिका अहम् हो गयी है। प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिये एक गंभीर संकट बन गया है और आने वाले समय में यह और भी ज्यादा भयावह होने वाला है। प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पाद छोटे-छोटे टुकड़ो में टूट जाते है तथा मिट्टी और पानी के स्त्रोतो में मिल जाते है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। देखें तो प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण और पृथ्वी के जनजीवन पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। एक गंभीर समस्या और है कि प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्त्रोतो जैसे कि, नदियों, समुद्रो तथा महासागरों में मिल जाता है और जल स्त्रोतों को प्रभावित करता है। इसके अलावा हवा द्वारा उड़ा लिये जाने पर प्लास्टिक के छोटे- छोटे टुकड़े एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिये जाते है और प्लास्टिक के यह टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते है, जो मिट्टी के गुण तथा उर्वरकता को नष्ट कर देता है। यह पेड़-पौधों के वृद्धि को भी प्रभावित करतें हैं। पशुओं द्वारा कचरे में फेका गया खाना खाया जाता है। वह प्लास्टिक बैगों को अपने खाने के साथ खा लेते है, जो उनके आंतो में फंस जाता है, जिससे अंत में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके अंदर कई गंभीर बीमारीयां उत्पन्न कर देता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्लास्टिक प्रदूषण आज विकराल ही नहीं, बल्कि अपने भयावाह काल से गुजर रहा है। जिस प्लास्टिक को हमने विकास से जोड़ा, इंसानी जीवन को बदला। आज वह इन्सान के साथ-साथ धरती के सभी जीव जंतुओं के लिए तबाही का हथियार बना हुआ है। पहले हमने प्लास्टिक को बढ़ावा दिया और आज यह हमारे जीवन में इतना घुल मिल गया है कि इसे निकाल पाना आसान नहीं है। हाँ, धीरे धीरे इसे कम किया जा सकता है, नहीं तो एक वक्त आएगा कि पूरी तरह से यह जीव जंतुओं को निगल जायेगा।

सरकारी प्रतिबंधों के बीच एकल उपयोग वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग छूट नहीं रहा है। चोरी छिपे घटिया प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। इसका जीता जगाता उदाहरण नालों-सड़कों से अटा-पटा प्लास्टिक कचरा है। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन की माने तो, जिस तरह से हम प्लास्टिक का उत्पादन, उपयोग और निपटान करते हैं, वह पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित ही कर रहा है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है और जलवायु को अस्थिर कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है तो, प्लास्टिक के उपयोग को लेकर बाजार में बदलाव की सख्त जरूरत है। इसके पुनः उपयोग, रीसायकल और उत्पादों में विविधता पर ध्यान देना होगा है। प्लास्टिक को ना कहना होगा तभी प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। आंकड़े गवाह हैं कि प्रत्येक वर्ष 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधे को केवल एक बार उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसमें से 10 फीसदी से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि दुनिया भर के देश और कंपनियां मौजूदा तकनीकों का उपयोग करके नीति और बाजार में बदलाव करती हैं, तो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण 80 प्रतिशत तक कम हो सकता है। आंकलन है कि पुनर्चक्रण या रीसाइक्लिंग, यदि पुनर्चक्रण एक अधिक स्थिर और लाभदायक उद्यम बन जाता है, तो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। पुनर्विन्यास और विविधता वैकल्पिक सामग्री जैसे कागज या कूड़े की खाद या कंपोस्टेबल सामग्री से बने उत्पादों के साथ प्लास्टिक रैपर, पाउच और टेकअवे आइटम जैसे उत्पादों के बदले अन्य सामग्रियों को अपनाने से प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। एकल या एक बार उपयोग और छोटी अवधि में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से 10 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक को अभी भी 2040 तक सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसे बिना रीसाइक्लिंग योग्य प्लास्टिक के कचरे के निपटान के लिए डिजाइन और सुरक्षा मानकों को स्थापित करने और लागू करने और माइक्रोप्लास्टिक में बदलने वाले उत्पादों पर लगाम लगाकर हल किया जा सकता है।

ऐसा माना जा रहा है कि, पांच साल की देरी से 2040 तक 80 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है । सवाल उठता है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोके । अपने दैनिक जीवन में अपना कर हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में महात्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। उपयोग ना करके/ अन्य विकल्पो को अपना कर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिये सबसे महात्वपूर्ण कदम यह है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना होगा । हम इनके उपयोग के आदि हो चुके है तथा यह काफी सस्ते भी है, इसलिये हम इनके उपयोग को पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहे हैं । हालांकि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को आसानी से बंद कर सकते है, जिनके इकोफ्रैंडली विकल्प उपलब्ध है। प्लास्टिक बैगों और प्लास्टिक से बने अन्य वस्तुओ का उपयोग नही बंद कर सकते तो कम से कम उन्हे फेंकने से पहले जितनी बार भी हो सके उनका पुनरुपयोग करे।

प्लैनेट बनाम प्लास्टिक विषय के साथ, पृथ्वी दिवस 2024-2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60त्न की कमी, एकल-उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर अमल करें। हमारे प्राकृतिक और शहरी पर्यावरण को खतरे में डालने वाले व्यापक प्रदूषण को कम करने के लिए यह पहल आवश्यक हैं। इसमें शक नहीं कि प्लैनेट बनाम प्लास्टिक विषय पर्यावरण की रक्षा करने और मानव प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने की तात्कालिकता पर जोर देगा। पृथ्वी दिवस के जरिये सकारात्मक पहल को देखा जा सकता है। आमलोगों को साफ-सफ़ाई में भाग लेना, पेड़ लगाना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना और महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों से जुड़ना अहम् है। पृथ्वी दिवस 2024 प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ने और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रभावशाली बदलावों पर जोर देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संधि जैसी पहल का समर्थन करना भी शामिल है। लेकिन इसके लिए आम भागीदारी जरुरी है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर 2024 फोकस है ताकि व्यक्तियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय निकायों तक सभी से अमल का आह्वान है ताकि प्लास्टिक के खतरे से भविष्य सुरक्षित हो।

बात प्लास्टिक प्रदूषण की तो, विश्व भर के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हमे इसके समाधान के लिये कठोर फैसले लेने होंगे, नहीं तो वक्त आएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण को ही निगल जायेगा और इन्सान कुछ नहीं कर पायेगा। तो आइये प्लास्टिक को ना कहें, अपनाने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जीवन को।

(लेखक पर्यावरणविद और प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो , पटना के उप निदेशक हैं)

अध्यात्म

कष्टों में तपकर बने खरा सोना

दंडी स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। वे सत्य के आग्रही थे और अहंकार व पाखंडी से दूर रहते थे। उनका आश्रम मथुरा में था। उसने शिक्षा पाने दूर-दूर से लोग आते थे। उनके शिष्यों में दयानंद भी थे। सभी शिष्यों के मध्य आश्रम के कार्यो का स्पष्ट विभाजन था, किन्तु दयानंद से अधिक काम लिया जाता था। उन्हें भोजन भी कम दिया जाता, जिसमे मात्र गुड़ व भुने हुए चने होते थे।

रात में पढ़ने के लिए प्रकाश की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जाती थी। जबकि दूसरे शिष्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थी।

स्वामी जी के शिष्य दयानंद के प्रति उनके इस व्यवहार से चकित थे और परस्पर बातचीत में इसकी निंदा भी करते थे, किन्तु दयानंद को गुरु की निंदा अच्छी नहीं लगती थी।

वे अन्य शिष्यों को ऐसा करने से रोकते थे और सदैव खुश रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे।

एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी से इसका कारण पूछा, तो वे मौन ही रहे।

अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य शास्त्रार्थ करने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें बहस हेतु एक विषय दे दिया, उन्होंने सारे शिष्यों को एक तरफ और दयानंद को अकेले दूसरी तरफ बैठाया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो सभी शिष्यों पर दयानद भाड़ी पड़े और जीत गए। तब दंडी स्वामी ने शेष शिष्यों से कहा - देखा आप लोगों ने, दयानंद अकेला आपसे लोहा ले सकता है, क्योंकि वह हर काम पूर्ण समर्पण से करता है।

दयानंद खरा सोना है और सोना आग में तपकर ही निखरता है। यही दयानंद आगे चलकर भारत के महँ समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए।

कथासार यह है कि माता-पिता व गुरु के द्वारा सौपें गए कार्य बिना शिकायत व पूर्ण समर्पण से करने पर कार्यकुशलता व ज्ञान की वृद्धि होती है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं ...

दरअसल, सदुपयोग करने के बरक्स आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है। आज फेसबुक और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बहुत कम अवधि के रील बनाने और उसे सोशल मीडिया के किसी मंच पर जारी करने वालों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। कई बार लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे खतरनाक कदम उठाते हैं कि अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। पर खेद की बात यह है कि कई लोग दूसरे लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। जहां बात आस्था की होती है, वहां तर्क का कोई काम नहीं होता। हर धर्म में कई ऐसी बातें हो सकती हैं, जिसे तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। मगर सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक विचित्र नासमझी दिखती है।

विनय कुमार पाठक

इसमें कोई दो मत नहीं कि यह सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के अनेक लाभ हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्मार्टफोन और हर जगह नेटवर्क की उपलब्धता ने सोशल मीडिया से जुड़े रहने को बहुत ही आसान बना दिया है। इसके कारण हम हमेशा अपने मित्रों रिश्तेदारों से आभासी संपर्क में तो रहते ही हैं, अनजान लोगों से भी संपर्क बना लेते हैं। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले से आभासी दुनिया में मित्रता की जा सकती है। हमें अपनी प्रतिभा और अपना शौक भी दुनिया के साथ साझा करने का अवसर सोशल मीडिया के कारण उपलब्ध हो पाता है। यह निश्चित रूप से इसके वे फायदे हैं, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और आजकल के दौर में हम सब इसे देख-समझ और महसूस कर सकते हैं। पर जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। एक ओर इससे कई लाभ हैं और हम सब न सिर्फ अक्सर इसे गिनाते रहते हैं, बल्कि इस दुनिया में इस तरह गुम रहते हैं तो इसके पीछे हमारा तर्क यही होता है कि यह फायदेमंद है। मगर दूसरी ओर इसके नुकसान भी हैं।

हमारे व्यस्त होने में सोशल मीडिया पर मौजूद जिस भी सामग्री की भूमिका हो, हम उसके ऐसे लती हो जाते हैं कि वह एक तरह की जकड़बंदी होती है। मगर इसके समांतर दूसरे स्तर पर देखें तो अश्लील और अर्ध-अश्लील सामग्री से इंटरनेट का संसार अटा पड़ा है। इस जाल में फंसने के बाद इससे निकलना एक बड़ी चुनौती होती है। मगर इससे आगे सामाजिक प्रभाव वाली परिस्थितियां ज्यादा चिंताजनक हैं। कुछ मामलों में भीड़ हिंसा या भीड़ के हाथों हत्या जैसी जघन्य घटना भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण घटी है। इससे हम समझ सकते हैं कि इसके दुष्प्रभावों का स्तर क्या हो सकता है।

कोई भी माध्यम उपयोग करने वाले की नीयत और प्रकृति पर निर्भर करता है। परमाणु शक्ति का प्रयोग विध्वंस के लिए भी किया जा सकता है तो ऊर्जा संयंत्र के लिए भी। एक चाकू का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए भी हो सकता है तो चिकित्सक इसका प्रयोग किसी की जान बचाने के लिए करता है। कहा भी गया है कि विष, जो प्राणों के लिए खतरा होता है, उसे भी विष के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

दरअसल, सदुपयोग करने के बरक्स आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है। आज फेसबुक और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बहुत कम अवधि के रील बनाने और उसे सोशल मीडिया के किसी मंच पर जारी करने वालों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। कई बार लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे खतरनाक कदम उठाते हैं कि अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। पर खेद की बात यह है कि कई लोग दूसरे लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। जहां बात आस्था की होती है,

वहां तर्क का कोई काम नहीं होता। हर धर्म में कई ऐसी बातें हो सकती हैं, जिसे तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। मगर सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक विचित्र नासमझी दिखती है।

सकारात्मक नकारात्मक सोच वाले लोग दूसरे धर्म की कमियों को दिखाने के लिए तरह तरह के वीडियो जारी कर देते हैं। इससे उस संबंधित धर्म के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है, जिस धर्म के विरुद्ध कुछ अशोभनीय लिखा या दिखाया गया है। नतीजतन, प्रतिशोध की भावना से दूसरी ओर से भी जवाब में ऐसे वीडियो जारी किए जाते हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हों।

इस प्रकार एक दुश्चक्र बन जाता है जो एक दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावना को आहत कर समाज में असहिष्णुता फैलाता है। इस तरह के कृत्य अविवेकशील लोगों के द्वारा किए जाते हैं। विवेक से लैस लोगों को चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई प्रतिक्रिया न दें, मगर अफसोस कि कई बार सोचने-समझने वाले लोग भी ऐसे विवादों में सक्रियता से हिस्सा लेते हैं।

इससे इस तरह के विवादों का विस्तार ही होता है। कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध टिप्पणियां की जाती हैं, जिनका समाज के एक वर्ग के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव होता है। इससे सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ता है।

जरूरी है कि इस तरह के बेकार विवादों से बचकर रहा जाए सोशल मीडिया के समाज विरोधी उपयोग करने वालों से। यों कहने को इसका नामकरण सोशल मीडिया के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ यह होना चाहिए कि इन मंचों पर एक नया समाज बने। सवाल है कि समाज का स्वरूप क्या होता है? सहयोग, सद्भाव और संवेदना जैसे तत्त्वों की जो प्रचुरता जमीनी स्तर पर समाज में पाई जाती है, उसका कितना अंश सोशल मीडिया पर बने कथित समाज में वास्तव में दिखता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने दुख या अपनी खुशी सोशल मीडिया पर साझा की, तो उसके प्रति जरूरी संवेदना जताने के लिए सैकड़ों-हजारों लोगों का संदेश आ जाएगा।

मगर वास्तव में जिस तरह किसी के पास होने और उसकी मदद की दरकार होती है, उससे दुख-सुख साझा करके वास्तविक सहयोग प्राप्त करने की जो उम्मीद होती है, वह सोशल मीडिया पर शायद ही कभी पूरी होती है। जबकि जमीनी स्तर के समाज का यही सब जीवन तत्त्व रहा है। जाहिर है, इंटरनेट के आभासी समाज और वास्तविक समाज में यही फर्क है, जो एक स्तर पर सच और कल्पना की दुनिया से परिचित कराता है।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

पुरानी उधारी चुकाने का दबाव रहेगा। मित्रों की छोटी-मोटी बातों को तूल न दें। जीवनसाथी आपसे काफी प्रसन्न रहेगा। मित्रों के लिये उपहार खरीद सकते हैं।

वृषभ

दाम्पत्य सम्बन्धों में प्रेम भाव बढ़ेगा। बच्चों के साथ काफी अच्छा समय बितायेंगे। धर्म-कर्म में आपकी स्वाभाविक रुचि और बढ़ेगी।

मिथुन

आज आपकी दिनचर्या काफी अस्त-व्यस्त रहेगी। घरवालों के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे। फाइनेंस से जुड़े मामलों में हानि हो सकती है।

कर्क

कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। आज आपको फर्जी फोन कॉल्स से सावधान रहना चाहिये। उच्च स्तरीय शोध कार्यों में आप जुड़ सकते हैं।

सिंह

राजनीति से जुड़े लोगों को कठिनाई होगी। महँगी वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं तो बजट का ध्यान रखें। अपयश जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है।

कन्या

आज आप शेयर मार्केट से काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सतर्क रहेंगे। सन्तान को लेकर समस्या दूर होगी।

तुला

आईटी और बैंक से जुड़े लोगों को करियर में अच्छे, नये और उत्तम विकल्प मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी पर भरोसा न करें।

वृश्चिक

परिजनों को लेकर काफी चिन्ता रहेगी। जीवनसाथी से सुझाव लेकर काम करना हितकारी होगा। विरोधी पक्ष आपके प्रति परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

धनु

आज जीवनसाथी आपसे कुछ शिकायत कर सकता है। बीमा सम्बन्धित कारोबार से लाभ मिलेगा। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आलस्य में आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिये।

मकर

आज आपके सभी काम शान्तिपूर्वक पूर्ण होंगे। छात्र करियर को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे। परिवार का खर्च बढ़ सकता है। घर की मरम्मत आदि की योजना बना सकते हैं।

कुंभ

कार्यक्षेत्र में आपके टीमवर्क की प्रशन्सा होगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। शाम को परिवार के साथ कहीं घूमने के लिये जा सकते हैं।

मीन

भौतिक सुख-सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे। मित्रों के साथ बहसबाजी में न पड़ें। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के साथ काम करने से लाभ मिलेगा।

जहां मूर्खों का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती हैं। मूर्ख व्यक्ति की बात पर विश्वास करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। इसलिए यदि लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मूर्खों और चापलूसी करने वालों की बात पर यकीन न कीजिए। मूर्ख और चापलूस, दोनों तरह के व्यक्ति सही सलाह नहीं देते हैं।

चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, सोमवार 22 अप्रैल 2024
www.live7tv.com

बुद्धिहीन उपभोक्तावाद की आसक्ति से नहीं मिलेगी खुशी

अविजित पाठक

हालांकि हम लोग एक भयावह रूप से हिंसाग्रस्त विश्व में जी रहे हैं, वह जिसमें लगातार होने वाले युद्ध, सैन्यीकरण, नए किस्म का अधिनायकवाद, बढ़ती आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और सामाजिक कारणों से बना मानसिक संताप इसका चरित्र बन गया है। और मानो इन सबके बीच खुशी ढूंढ़ना एक अनन्त खोज बन गई है। आधुनिक काल में, हमें गुणा-भाग वाली सूक्ष्मता से प्यार हो गया कि तुर्रा यह कि खुशी जैसे उच्च गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिष्ठ अनुभव को भी हमने नापने-तोलने की चीज बना डाला है। हर साल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास उपाय नेटवर्क एक सूची जारी कर, विभिन्न मुल्कों का पदानुक्रम तय करता है जो उसके हिसाब से मापने लायक खुशी सूचकांक पर आधारित हैझ इस निर्धारण में सकल घरेलू उत्पाद, आयु दीर्घता, राजकीय कामकाज दक्षता, स्वतंत्रता, सामाजिक संबल (परोपकारी व्यवहार) को गिना जाता है। जहां फिनलैंड पिछले सालों की भांति सबसे खुश देश है वहीं विश्व खुशी रिपोर्ट-2024 में भारत का स्थान 143 देशों में 126वां है। खैर, मैं इस किस्म की रिपोर्ट के गुण-दोषों को पूरी तरह खारिज भी नहीं करता। बेशक, एक उचित मात्रा में सामाजिक सुरक्षा, राज्य द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक भलाई नीतियां, अच्छी मेडिकल सुविधाएं, रोजगार उपलब्धता, संवाद की मौजूदगी वाला समाज और राजनीतिक स्वतंत्रता रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ हद तक संतोष पैदा करते हैं। तथापि, यहां यह अहसास भी उतना ही जरूरी है कि शुद्ध खुशी जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि उल्लास के हमारे सबसे बढ़िया लम्हे और संतोष भी कुछ हद तक आशंका से जुड़े होते हैं, मसलन, जो कुछ हमारे पास है उसे खोने का डर, चाहे यह भौतिक संपदा, शरीर की तंदुरुस्ती हो या फिर प्रियजनों का साथ छूटने का भय। ताजिंदगी हम सम्पूर्ण खुशी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह हाथ नहीं आती। कोई हैरानी नहीं कि हमारे इस काल में जीवन जीने का ढंग सिखाने वाले, प्रेरणास्पद भाषणकर्ता और आध्यात्मिक बाबाओं की कोई कमी नहीं, जो बारम्बार हमें एक खास तकनीक पर चलने की सीख देते हैं, मसलन, समाधि अभ्यास, श्वास साधक व्यायाम, सचेतन होना इत्यादि -खुश व सफल होने के मकसद हेतु। लेकिन फिर, यह समझना चाहिए कि खुशी की प्राप्ति कैप्सूल खाने जैसा एक त्वरित उपाय नहीं है, जिसकी खुराक किसी स्व-सहायता पुस्तक या आश्रम अथवा मठ के विशेष सत्रों में भाग लेकर मिले। तथ्य तो यह है कि यदि सच में हम एक आडम्बरहीन, शांतिपूर्ण और संतोष से परिपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें स्व और दुनिया अथवा राजनीति और अध्यात्म के बीच पुल बनाना होगा। उदाहरणार्थ, जरा सोच कर देखिए, जो व्यक्ति भूख, कुपोषण और सिर पर छत न होने से बेहाल है उसको संचेतना सिखाने की बेवकूफी (बुरे अनुभवों से बने संताप या अस्थिर भविष्य की आशंका को नजरअंदाज कर वर्तमान में जीने की समर्था बनाए)। या फिर उस मानसिक हिंसा के बारे में सोचिए जो एक बेरोजगार युवा के मानस पर चोट करती है, जब नौकरी पाने में कंपनी दर कंपनी से अस्वीकृति झेलनी पड़े, तिस पर आप उसे सबसे अधिक बिकने वाली स्व-सहायता किताब मैं ठीक हूं- आप ठीक हैं जैसी कोई पुस्तक पढ़ने को कहें ताकि अच्छा और सकारात्मक महसूस का भ्रम पाले। यह ठीक उतना ही बेवकूफाना है जब किसी बेघर को या जो पहले से झुग्गी में रह रहा है, उसे न्यूनतम साधनों में जीवन जीने का प्रवचन दिया जाए। राजनीतिक व आर्थिक असमानता की नींव को बदले बिना हम अ गैर-बराबर व शोषण करने वाली दुनिया को बदलकर संतोष की ओर नहीं बढ़ सकते।

इसी प्रकार जैसा कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 बताती है कि भारतीय युवाओं में 83 प्रतिशत बेरोजगार हैं या जब द राइज ऑफ बिलिनियर्स राज नामक शोध-पत्र कहे कि भारत के चोटी के 1 फीसदी अमीरों के हाथ में 40 प्रतिशत आम लोगों के बराबर सरमाया है, तो एक आम भारतीय को महसूस हो रहे संताप, भय और आशंका का अंदाजा लगाना कठिन नहीं। भले ही हमारे पास हजारों की संख्या में बाबा, गुरु और स्व-सहायता सिखाने वाले हों, जो मोक्ष प्राप्ति की जुगत के तौर हमें नाना किस्मों की घुट्टी पिलाते हैं, तथापि अलफ सच्चाई है कि हमारा देश नाखुश मुल्क है। संभवतः हमारे समाज में राजनीतिक-आर्थिक पुनर्संरचना किए बिना हम वैसा सामाजिक परिवेश नहीं बना सकते, जो यथेष्ट संतोष से परिपूर्ण लोगों की तरक्की अनुकूल हो।

ऐसा नहीं है कि मुझे अर्थपूर्ण, सतत और करुणामय जीवन के लिए आत्मविश्लेषण या अंदरूनी शांति के महत्व से इंकार है। जहां उचित मात्रा में आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे रोजमर्रा के जीवन को कुछ आरामदायक बनाती है वहीं हम एक अधिक अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण वजूद की ओर नहीं बढ़ सकते, जिसके बिना मैं जीवन को धर्मनिष्ठ नहीं कह सकता। उदाहरणार्थ, यह धर्मनिष्ठा जीवन जीने के ढंग में, गैर-उपभोक्तावाद अवस्था की कला विकसित करने के बारे में हैं। भोजन, आवास, जीवन-पुष्ट शिक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता और विरक्ति न बनाने वाले काम जैसी मूलभूत जरूरतों को लालच के वायरस के मोहपाश में जा फंसने से अलहदा कर पहचानना होगाझ वह लालच जिसका बाजार-चालित समाज ने सामान्यीकरण कर दिया है।

हां, उस समाज में कभी खुशी नहीं हो सकती जो नवउदारवादी बाजार द्वारा उत्पादित नित नए फैशनों या नई वस्तुओं के प्रति बुद्धिहीन उपभोक्तावाद या निरंतर बढ़ती आसक्ति के सिद्धांत को मान्यता दे। लालसा की यह प्रवृत्ति शांति और धीरज को भंग करती है । इसकी बजाय व्यक्ति में ईर्ष्या, अशांति और पीछे छूट जाने का भयंकर डर बनाती है। इसी प्रकार, दूसरों से जुड़े रहने वाले स्व को विकसित करने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैझ वह स्व जिसे दिखने में साधारण से कामों में भी बहुत आनंद मिलता होझ जैसे कि दोस्तों से बिना स्वार्थ मिलना या पहाड़ी इलाके में सैर और प्रकृति की अनंतता की झलकी का अनुभव करना। यह बेशक साधारण लगे लेकिन फिर भी सर्जनात्मकता के अतिरेक से लबरेज होती है, वह जो हमें निरंतर ललचाने और बहकाने वाली बाजारीकरण संस्कृति से उपजी मिथकीय सफलता या अति उत्तम और खुशी वाली जिंदगी की मरीचिका से पीछे भागने की लालसा से मुक्त रहने में मददगार होती है।

जीवन की धर्मनिष्ठा को जरूरत है हमारे अस्तित्व में अंतर्निहित उदासी को अंगीकार करने के साहस की। यह सब कुछ हमारे बस में नहीं को स्वीकार करने जैसा है। जो कुछ हम थामकर रखना चाहते हैं वह चलायमान और अस्थाई है। बिना पूर्व सूचना घटित अकल्पनीय दुर्घटनाएं और शोकाकुल प्रसंग हमारे अस्तित्व को झिंझोड़ सकते हैं, मौत की सच्चाई से कोई नहीं बच सकताझ जो कि हमारे फुलाए अहम की व्यर्थता की अंतिम परिणति है। संभवतः यह अहसास, हमें कटु बनाने की बजाय, आंसुओं से भरे इस लौकिक अस्तित्व से गुजरने में समर्थ बनाता है।

आपदा को आमंत्रण

युक्त अरब अमीरात और खाड़ी के कुछ अन्य देशों में अचानक आई भारी व असामान्य बारिश ने इंसान को तमाम सबक दिए हैं। जिन देशों को अपनी समृद्धि व संपन्नता का दंभ था, वहां आई मूसलाधार बारिश ने सारी आधुनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। दुनिया का सबसे ज्यादा आधुनिक व चहल-पहल वाला दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराजकता का शिकार हो गया। सैकड़ों उड़ाने रद्द हो गईं। दुनिया के चोटी के हवाई अड्डों में शामिल जिस दुबई एयरपोर्ट में पिछले साल आठ करोड़ यात्रियों की आमद थी, एक मूसलाधार बारिश से उसकी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थीं। इस दौरान ओमान में 19 लोगों की मौत के अलावा अन्य देशों में भी लोगों के हताहत होने की आशंका है। बताते हैं कि अभी भी कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 75 साल बाद रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में डूबे वाहन और बारह लेन वाले हाईवे पर लगा जाम बता रहा है कि कुदरत की माया के आगे मानव का विकास अभी भी बौना ही है। फिर मध्यपूर्व के रेगिस्तानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का होना निश्चित ही अचरज की बात है। अचानक आई इस बारिश और बाढ़ को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कहा जा रहा है। लेकिन वहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह घटना विशुद्ध रूप से प्रकृति से मानवीय छेड़छाड़ का नतीजा है। आलोचक इस असामान्य बारिश को क्लाउड सीडिंग का नतीजा बता रहे हैं। दरअसल, कृत्रिम तरीके से बारिश कराने की कोशिश को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जिसमें बादल में बारिश के बीज बोने के लिये कृत्रिम तरीके से प्रयास किये जाते हैं। ऐसे कुछ प्रयास यूएई में किये जा रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार व सोमवार को यूएई में क्लाउड सीडिंग की योजना बनायी गई थी और मंगलवार को भयावह बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। आशंका जतायी जा रही है कि क्या कृत्रिम बारिश के प्रयासों के चलते यह स्थिति पैदा हुई है? बहरहाल, आने वाले वक्त के अध्ययन हमें बताएंगे कि इस आपदा के आने में क्लाउड सीडिंग की कितनी भूमिका थी। वैसे दुनिया के तमाम देशों में संकट के समय क्लाउड सीडिंग कराने के मामले सामने आते रहते हैं। किन्हीं देशों में सामरिक तो कहीं कृषि उद्देश्यों के लिये कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते बदले हालात में यह संकट गहरा हो जाता है। उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बारिश का सहारा तब लिया जाता है, जब हवा की नमी की कमी के चलते बारिश नहीं हो पाती। भारत में साठ के दशक में कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया गया था।

कई आशंकाओं से भरा खतरनाक रास्ता!

पंकज चतुर्वेदी

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में सड़क हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। 15 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। चूंकि माहौल चुनाव का है सो प्रधानमंत्री से लेकर विधायक तक सक्रिय हो गये। कुछ कार्रवाई होती भी दिख रही है। जो बस सड़क पर चल रही थी, उसका अनफिट होने के कारण एक महीने पहले भी 15 हजार का चालान हुआ था। सब जानते थे कि बस चलाने वाला शराब पिए है और उसकी ड्राइविंग बेलगाम थी, इसके बावजूद बस सड़क पर चलती रही। अभी इस दुर्घटना के बाद सड़कों पर बसों की जांच और चालान की औपचारिकता चल ही रही थी कि यमुनानगर में स्कूली बच्चों से भरा एक तिपहिया पलट गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। सात बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। जो वाहन महज तीन सवारी के लिए परमिट प्राप्त है, उसमें 12 से अधिक बच्चे भरे थे। सड़क पर चलने के लिए नाकाबिल वाहन, क्षमता से अधिक बच्चे, बेतहाशा गति, अकुशल चालकझ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाने ले जाने में लिप्त वाहनों के मामले में सारे देश की यही एक-सी तस्वीर है।

दिल्ली के वजीराबाद पुल पर लुडलो केसल स्कूल की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 28 बच्चों की मौत के बाद सन् 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बसों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार स्कूल बस पीले कलर की होनी चाहिए। इसके साथ ही उस पर स्कूल बस जरूर लिखा होना चाहिए। बस में फर्स्ट-एड बॉक्स होना जरूरी है और बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही बस में आग बुझाने वाला यंत्र भी लगा होना चाहिए। स्कूल बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। यही नहीं, दरवाजों पर ताले लगे हों और बस में एक अटेंडेंट भी हो। सबसे बड़ी बात कि अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यह निर्देश दिल्ली में ही हवा-हवाई हैं।

और अब तो स्कूल पहुंचने की राह में बड़ा खतरा ओमनी वैन हैं जिसमें अतिरिक्त सीटें लगा कर क्षमता से दोगुने नहीं तीन गुणा अधिक बच्चे बैठना, उनकी अंधाधुंध स्पीड और सबसे अधिक उसके चालकों का संदिग्ध व्यवहार नए किस्म का खतरा है। देश में आए रोज बच्चों के यौन शोषण में ऐसे वाहन चालकों की संलिप्तता सामने आती है। बसों के मामलों में तो स्कूल को जिम्मेदार बना दिया जा सकता है लेकिन वैन में ओवर लोडिंग, दुर्व्यवहार और दुर्घटना होने पर स्कूल हाथ झटक कर अलग हो जाते हैं। बीते कुछ सालों में बैटरी चालित रिक्शा स्कूल की राह का एक खतरनाक साथी बना है। इसमें बेशुमार संख्या में बच्चों को भरना, प्रतिबंधित या तेज गति के वाहनों वाली सड़क पर संचालन करना और अनाड़ी चालक होने के कारण इनके खूब एक्सीडेंट हो रहे हैं।

बीते कुछ सालों में विद्यालयों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ा है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड, शौचालय, बिजली, पुस्तकालय जैसे मसलों से लोगों के सरोकार बढ़े हैं, लेकिन जो सबसे गंभीर मसला है कि बच्चे स्कूल तक सुरक्षित कैसे पहुंचें? इस पर न तो सरकारी और न ही सामाजिक स्तर पर कोई विचार हो पा रहा है। इसी की परिणति है कि आए रोज देशभर से स्कूल आ-जा रहे बच्चों की जान जोखिम में पड़ने के दर्दनाक वाकिये सुनाई देते रहते हैं। परिवहन को प्रायः पुलिस की ही तरह खाकी वर्दी पहनने वाले परिवहन विभाग का मसला मान कर उससे मुंह मोड़ लिया जाता है। दरअसल बढ़ते पंजीकरण को देखते हुए बच्चों के सुरक्षित, सहज और सस्ते आवागमन पर जिस तरह की नीति की जरूरत है, वह नदारद है।

निजी स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों की अपनी बसों की संख्या सीमित हैं, औसतन 1000-1500 बच्चे इनसे स्कूल आते हैं। शेष का क्या होता है? यह देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला होता हैं। पांच लोगों के बैठने के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस पाए वैन में 12 से 15 बच्चे ठुंसे होते हैं। बैटरी रिक्शे में दस बच्चे ह्यआरामह्न से घुसते हैं। दुपहिया पर बगैर हैलमेट लगाए अभिभावक तीन-तीन बच्चों को बैठाए रफ्तार से सरपट होते दिख जाते हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यही समय कालोनी के लोगों का अपने काम पर जाने का होता है।

ऐसा नहीं है कि स्कूल की बसें निरापद हैं, वे भी 52 सीटर बसों में 80 तक बच्चे बैठा लेते हैं। यहां यह भी गौर करना जरूरी है कि अधिकांश स्कूलों के लिए निजी बसों को किराए पर लेकर बच्चों की ढुलाई करवाना एक अच्छा मुनाफे का सौदा है। ऐसी बसें स्कूल करने के बाद किसी रूट पर चार्टेड की तरह चलती हैं। तभी बच्चों को उतारना और फिर जल्दी-जल्दी अपनी अगली ट्रिप करने की फिराक में ये बस वाले यह ध्यान रखते ही नहीं है कि बच्चों का परिवहन कितना संवेदनशील मसला होता है।

इस दिशा में सबसे पहले तो विद्यालय से बच्चे के घर की दूरी अधिकतम तीन से पांच किमी का फामूर्ला लागू करना चाहिए। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से करना, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना, प्रयुक्त वाहनों में ओवरलोडिंग या अधिक रफ्तार से चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान करना, असुरक्षित साधनों के लिए कड़े मानदंड तय करना समय की मांग है।

नक्सलवादः आखिर कब थमेगी अपने ही युवाओं से खून की होली

योगेंद्र योगी

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षाबलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जवान नक्सलियों के अड्डे तक पहुंचने के लिए 20 घंटे तक पैदल चले हैं। नक्सलियों के समूह को देखने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की थी। जब बंदूकें शांत हुईं, तो जंगल के फर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। इनमें ललिता, शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़े के शवों की पहचान सबसे पहले की गई। मृतकों में पंद्रह महिलाएं भी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता को केन्द्र और राज्य में भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कम समय में देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस अभियान को गति मिली है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बल कैंप लगाए जा रहे हैं। 19 के बाद इनकी संख्या 250 हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी मदद मिल रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन महीने में 80 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 125 गिरफ्तार हुए हैं और 150 ने आत्मसमर्पण किया है। देश के 10 राज्यों में 70 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखंड जहां 16 जिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित 14 जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नक्सलियों को आशंका थी कि सरकार उनके खिलाफ अभियान तेज करेगी और हुआ भी ऐसा ही। राज्य की नई सरकार ने शान्ति का प्रस्ताव भी सामने रखा था लेकिन नक्सल नेताओं की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षाबलों को बस्तर में फ्री हैण्ड कर दिया गया हैं। ऐसे में पिछले तीन महीनों में नक्सलियों को कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। अब तक जहां माओवादियों के बटालियन स्तर के नेता ही ढेर हुए थे तो इस बार शंकर राव जैसे डिवीजन लेवल का नेता पुलिस के गोली का शिकार हुआ हैं। ऐसे में नक्सली प्रदेश में पूरी तरफ से बैकफुट में हैं। अब लगातार सवाल किये जा रहे हैं कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ को इस नक्सल दंश से छुटकारा मिल पायेगा और बस्तर में खून की होली थमेगी। सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है कि पिछले एक दशक में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं, मौतों और उनके भौगोलिक प्रसार में काफी कमी आई है। जहाँ वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी वहीं वर्ष 2018 में प्रभावित जिलों की संख्या 60 रह गई है। वर्ष 2009 में जहाँ नक्सलवाद की घटनाओं और इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्रमश 2258 व 1005 थी वहीं वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर क्रमश 833 एवं 240 रह गई। देश के जिन 8 राज्यों के लगभग 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई है उनमें ओडिशा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 तथा बंगाल के 8 जिले शामिल हैं। वर्ष 2015 के बाद से नक्सलियों के 90 प्रतिशत हमले लगभग चार राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हुए हैं।

माओवादियों के थिंक-टैंक और प्रथम पंक्ति के नेता या तो मारे जा चुके हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरूआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड? पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यत कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया है। नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है। सरकार नक्सली चरमपंथ से निबटने के लिये बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय शामिल हैं। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है।

सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप नक्सलियों के हौसले कमजोर हुए हैं तथा उनके आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ रही है। विमुद्रीकरण ने भी नक्सलियों को पहुँचने वाली वित्तीय सहायता पर लगाम लगाई है और इसके बाद से अब तक 700 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48877 किमी. सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। इसके तहत कुल 4072 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर पुलिस की दवाब बनाने की सक्रिय कार्रवाई और विकास बहुआयामी योजनाओं से नक्सली समस्या जड़मूल से समाप्त हो सकेगी।

https://t.me/AllNewsPaper

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 22 अप्रैल 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

रांची से 'इंडिया' का बड़ा संदेश

बीते शुक्रवार 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान और आने वाले शुक्रवार 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के बीच इंडिया गठबंधन की एक और महारैली ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी अब तक एनडीए की 4 सौ पार सीटों की जीत का दावा ही कर रहे थे, लेकिन अब वे राहुल गांधी की वायनाड से हार का दावा भी करने लगे है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से नरेन्द्र मोदी चुनिंदा पत्रकारों और मीडिया घरानों को साक्षात्कार दे रहे हैं, और उन्हीं घिसे-पिटे सवालों के रटे-रटाए जवाब दिए जा रहे हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि वे भाजपा की मजबूती को लेकर आश्वस्त हैं। बल्कि अब कर्नाटक में श्री मोदी ने यह दावा भी कर दिया कि देश के बड़े और ताकतवर लोग विदेशियों से हाथ मिलाकर उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इस तरह का दावा जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जनता अब नरेन्द्र मोदी के निरंतर विलाप को कितना सुनेगी, ये कहा नहीं जा सकता।

बहरहाल, चिलचिलाती धूप में रांची के ऐतिहासिक प्रभाततारा मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली रविवार को हुई। भले ही यह रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा की विशाल रैली चाहे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाले जाने के खिलाफ आयोजित की गई हो, परन्तु जिस प्रकार से विपक्षी दलों के तमाम नेता जुटे और जैसी उन्होंने हुंकारें भरीं, उसने न केवल विपक्षी एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन किया बल्कि देश भर में साफ संदेश गया है कि संयुक्त प्रतिपक्षी गठबन्धन यानी 'इंडिया' डरेगा तो नहीं। छह चरणों का मतदान शेष रहते 'झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रूकेगा नहीं' के नारे के साथ हुई इस रैली को 'उलगुलान' कहा गया जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है क्रांति। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता- पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस विशाल रैली ने यह भी संदेश दे दिया कि तोड़ने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिये तंग कर रही है और उन्हें जेल भेज रही है, उसका अब कोई असर नहीं होने जा रहा। इसके विपरीत इंडिया न सिर्फ अटूट है वरन पूरी शक्ति के साथ भाजपा प्रणीत केन्द्र सरकार के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है।

इस रैली में गठबन्धन में शामिल लगभग सभी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। जिन नेताओं का आना सम्भव नहीं हुआ, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे और सभी ने न केवल एकजुटता दिखलाई वरन मोदी सरकार को इस चुनाव में हराने का संकल्प भी जतलाया। इस मंच के जरिये इंडिया गठबन्धन के सभी नेताओं ने देश की राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उन मुद्दों को उठाया जो इंडिया गठबन्धन के भागीदार दल देश भर में उठा रहे हैं। लगभग सभी नेताओं ने अपने भाषणों में मोदी सरकार की इस बात के लिये कड़ी आलोचना की कि वह पिछले 10 वर्षों से विपक्षी दलों को तोड़ने के लिये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अलग-अलग नेताओं ने विभिन्न सन्दर्भों के जरिये बतलाया कि लोकसभा का यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस बार मोदी सरकार आई तो कुछ भी नहीं बचेगा। विभिन्न वक्ताओं द्वारा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशासन और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें बेनकाब की गईं उसने इंडिया की वही बात आगे बढ़ाई जो वह अब तक विभिन्न मंचों से कह रहा है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने केवल महंगाई व गरीबी बढ़ाने का काम किया है और जुमलेबाजी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड में 134 सीटें हैं। इंडिया के घटक दल यदि मिलकर लड़ें तो भाजपा पराजित हो जायेगी। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संविधान व लोकतंत्र को बचाने की रैली है। उन्होंने कहा कि 'हेमंत सोरेन व जेल में ही बन्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम से मंच पर रखी खाली कुर्सियां भाजपा की कुर्सियां खाली करा देंगी।' उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले दौर में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें 80 से 90 सीटें इंडिया को मिलने जा रही हैं। इसके कारण भाजपा डरी हुई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि भाजपा घबराई हुई है और वह हार चुकी है तभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है इसलिये वह बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अगली बार आई तो लोगों का वोट डालने का अधिकार भी चला जायेगा।

रैली के जरिये नेताओं ने लोगों को बतलाया कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आई तो दलितों-वंचितों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे क्योंकि भाजपा के कई नेता साफ कर चुके हैं कि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो संविधान को बदल दिया जायेगा। भाजपा के अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अरूण गोविल आदि इसे जाहिर कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के मसले पर भी सभी वक्ताओं ने भाजपा तथा उसकी केन्द्र सरकार की पूरी तरह से पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार का शोर मचाकर झूठे आरोपों में विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा सरकार जेलों में डाल रही तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कर रही है और उन्हें ऊंचे पदों पर बैठा रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने भरपूर चंदा वसूला। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात बाहर आने से भाजपा और घबराई हुई है। माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद भाजपा का बस चलता तो इसका नाम झारखंड नहीं वनांचल होता। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वालों को मार डाला गया। कई लोगों को मानवाधिकारों की बातें करने वालों को जेल में ठूंसा गया है।

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने आप व इंडिया के जरिये जनसामान्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने और उन्हें गुणवत्तायुक्त नागरिक सुविधाएं देने का वादा किया। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन का जेल से भेजा गया पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड के संसाधनों पर कब्जा करने के लिये उन्हें जेल में डाला गया है। उन्होंने यह भी लिखा कि आदिवासियों के अधिकारों को मोदी सरकार छीन रही है। उन्होंने भाजपा सरकार की सोच आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि के खिलाफ बतलाई। झारखंड और केन्द्र से भाजपा को खदेड़ने की बात भी हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन आदि ने लोगों का सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। चलते चुनाव के बीच हुई इस विशाल व सफल रैली भाजपा को और बैकफुट पर ले जायेगी।

शिक्षा ही मुसलमानों का भविष्य बनाएगी

51 मुस्लिम स्टूडेंट का यूपीएससी में चयन कई तरीके से देखा जा रहा है। मुसलमान इस समय सबके निशाने पर हैं और समस्या यह है कि उसे संभालने वाला दिशा देने वाला कोई नहीं है।

राजनीतिक नेतृत्व है नहीं। सामाजिक कभी रहा नहीं। और धार्मिक उसे पीछे की तरफ खींचने वाला है। ऐसे में यही इन छात्रों का अपनी व्यक्तिगत मेहनत, परिवार के सपोर्ट से आगे निकलना दिशा दिखलाता है।

हर समाज की अपनी समस्याएं हैं अंदरूनी। और उनसे लड़ना उसका अपना काम है। भारत में बाकी लोगों ने काफी हद तक सफलता पाई है। खासतौर से दलित ओबीसी ने। मगर मुसलमान की खुद अपनी कमियों से लड़ाई शुरु हो ही नहीं पाई है।

शिक्षा, आधुनिक शिक्षा ही वह एक मात्र तरीका है जिससे वह आगे बढ़ सकता है। आज हालत क्या है शिक्षा की? बहुत ही खराब। प्राथमिक स्कूल जो एजुकेशन की पहली सीढ़ी है। वहां 10 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। मतलब कभी गए ही नहीं। यह आयु वर्ग 6 से 14 साल के बच्चों का है। इसमें जो स्कूल गए उनमें से 15 प्रतिशत की प्राथमिक स्कूल से ही शिक्षा छूट जाती है। कुल आंकड़ा ऐसे आता है कि 25 प्रतिशत 6 से 14 साल की उम्र वाले मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल गए नहीं हैं या 14 साल की उम्र तक स्कूल से बाहर हो गए हैं। समझने के लिए बता दें कि एससी एसटी समुदाय में यह आंकड़ा केवल 6 प्रतिशत है।

2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का यही अंश सबसे ज्यादा प्रचारित हुआ था कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। दरअसल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी थी मुस्लिम समुदाय के लिए मगर वह अनसुनी रह गई। बात आगे ले जाने से पहले यहां यह और बता दें कि उपर दिए आंकड़े सच्चर कमेटी के बाद के हैं। यह रिपोर्ट 2023 के अंत में आई है। यह नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है। जिसे शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग के प्रो अरुण मेहता ने तैयार और विश्लेषित किया है।

बहुत ही चिंताजनक है यह रिपोर्ट। आकंड़ों के द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर वही सही तस्वीर बताते हैं। रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 6 से 8 तक देश भर में 6. 67 करोड़ छात्र होते हैं। यहां मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत 14.42 होता है।

अब देखिए इसके बाद गिरावट आना शुरू होती है। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9-10 में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत कम होता है। और यह 12. 62 रह जाता है। कक्षा 11-12 जिसे उच्च माध्यमिक स्तर कहते हैं यह और गिरकर 10.76 प्रतिशत रह जाता है। मतलब कुल पढ़ने वालों में मुस्लिम बच्चे 10. 76 प्रतिशत ही होते हैं। और विश्वविध्यालयों में केवल 4.9 प्रतिशत ही पहुंचते हैं।

आबादी मुसलमानों की देश में 15 प्रतिशत के करीब है। और उच्च शिक्षा में पहुंच रहे हैं केवल 4.9 प्रतिशत। और नौकरियों में जाते-जाते तो प्रतिशत बहुत ही कम रह जाता है। बात यूपीएससी से शुरू की थी तो उसी का आंकड़ा बताते हैं कि आईएएस केवल तीन प्रतिशत हैं। आईपीएस चार फीसदी और विदेश सेवा में केवल 1.8 प्रतिशत।

शकील अख्तर

> निराशा मुसलमान के स्वभाव में नहीं है। मगर उसे अब अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। समस्या यही है कि उसका धार्मिक नेतृत्व उसे इस बारे में बिल्कुल ही जागृत नहीं करता है। मदरसा तालीम मार्डन एजुकेशन का विकल्प नहीं है। और उन्हें याद रखना चाहिए कि सर सैयद ने एएमयू बनाते समय केवल एजुकेशन की बात नहीं की थी।

तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस साल सफल यूपीएससी उम्मीदवारों में जब 51 मुस्लिम लड़के और लड़कियों के नाम आए तो यह बड़ी खबर क्यों बनी। यूपीएससी में लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन कम होता जा रहा था। और जब थोड़ी सी इसमें वृद्धि हुई तो बहुत ही शत्रुतापूर्ण मानसिकता के साथ इसे आईएएस जिहाद कहा गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। एक टीवी चैनल ने गलत आंकड़ों पर आंकड़े देकर बताया था कि सरकार ने मुसलमानों को फायदा पहुंचाया। यहां तक झूठ कहा गया कि मुसलमानों को आयु में छूट है। उन्हें ज्यादा बार परीक्षा देने दी जा रही है। उनके कट आफ मार्क्स कम हैं। और यहां तक कि मुसलमानों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर है। यह सारे आरोप झूठे थे। और झूठे साबित हुए। मगर उद्देश्य तो माहौल बनाना था। हिन्दु-मुसलमान करना था। और यह किया गया। 2020 में 42 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए थे। यह संख्या कोई ज्यादा नहीं थी। कुल चयनित लोगों में से 5 प्रतिशत से कम। मगर 2018 में केवल 28 ही चुनकर आए थे। तो इसे अचानक बढ़ी हुई बता दिया गया। जबकि इस बीच 2017 में 52 और 2016 में 55 थी। मगर वह आंकड़े न बताकर सीधे 2018 के 28 और 2020 में 42 क्यों कैसे के टीवी पर प्रोग्राम पर प्रोग्राम दिखाना शुरू कर दिए। सारे कारण गलत बताए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। आईपीएस एसोसिएशन ने इसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना पत्रकारिता कहा।

खैर वह तो सारे आरोप कहानियां झूठे थे। मगर यहां एक बात फ्री कोचिंग की। इस फ्री कोचिंग ने इस बार भी 31 उम्मीदवारों को यूपीएससी क्लियर करवाया है। मगर इसमें हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं। हर साल यही होता है। यह है जामिया मीलिया इस्लामिया में। रेजिडेंशल कोचिंग अकादमी (आरसीए)। अभी तक 300 से ज्यादा स्टूडेंट यहां रहकर तैयारी करके यूपीएससी क्लीयर कर चुके हैं। हर धर्म के, हर जाति के।

मुसलमान की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। कुछ अपने कारणों से कुछ सांप्रदायिक राजनीति के कारण से। 2014 के बाद से उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अब तो उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं। इतनी लंबी लिस्ट होगी कि किताब बन जाए। प्रमुख में यही कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री श्मशान और कब्रिस्तान की तुलना करें। होली, दीवाली और रमजान में फर्क बताएं। मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएं। और मोदी योगी का नाम लेकर ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला मुसलमानों की हत्या करे और दूसरी तरफ लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी महेश शर्मा भी मोदी योगी का नाम लेकर सबको बाप की गाली दे तो समझ सकते हैं कि हालत कितनी खराब कर दी गई है।

लेकिन उसका फैसला चुनाव करेगा जो चल रहा है कि जनता क्या चाहती है। जनता जाहिर है कि जिसमें बहुसंख्यक हिन्दू हैं ज्यादा परेशान हैं। उनके युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। मिल तो मुसलमान युवा को भी नहीं रही। मगर नौकरी में उसका प्रतिशत पहले से ही बहुत कम था।

लेकिन अपनी तरक्की की जिम्मेदारी खुद मुस्लिम समुदाय पर भी है। जैसा की शुरू में लिखा कि यूपीएससी में 51 मुस्लिम स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन से आए हैं। साथ में परिवार का सपोर्ट था। उसी को आगे बढ़ना होगा।

शिक्षा, शिक्षा और आधुनिक शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। अभी जामिया का जिक्र किया। उससे बहुत पहले 1875 में 150 साल पहले सर सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कालेज की स्थापना की थी। वही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अब उस पर भी सवाल है। और खुद केन्द्र सरकार द्वारा।

उसका माइनरटी दर्जा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जबकि अल्पसंख्यकों के लिए माइनरटी शिक्षा संस्थान की व्यवस्था संवैधानिक है। तो यह समय मुसलमानों के लिए बहुत निराशाजनक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे खुद ऐसा नहीं मानते। इस बारे में जब भी किसी आम मुसलमान से बात होती है वह कहता है नहीं बुरा समय तो हमारे हिन्दू भाईयों के लिए ज्यादा है। उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। ओवर एज हो रहे हैं। अस्पताल, स्कूल जो सरकारी थे वह खतम हो गए। महंगाई तो देखो आसमान छू रही है। हम तो कर रहे हैं मेहनत मजदूरी। हो रही गुजर। मगर हिन्दू भाई की परेशानी देखकर दु:ख होता है।

अच्छी सोच है। निराशा मुसलमान के स्वभाव में नहीं है। मगर उसे अब अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। समस्या यही है कि उसका धार्मिक नेतृत्व उसे इस बारे में बिल्कुल ही जागृत नहीं करता है। मदरसा तालीम मार्डन एजुकेशन का विकल्प नहीं है। और उन्हें याद रखना चाहिए कि सर सैयद ने एएमयू बनाते समय केवल एजुकेशन की बात नहीं की थी। मार्डन एजुकेशन की बात कही थी। आज एएमयू, जामिया अगर निशाने पर हैं तो इसीलिए कि इन्होंने मुसलमानों की शिक्षा में अहम रोल निभाया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

'डब्ल्यूटीओ' का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन : खेती की वैश्विक फजीहत

■ जिल-कार हैरिस

अबूधाबी के 'नेशनल एग्जिबिशन सेंटर' में आयोजित तेरहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'विश्व व्यापार संगठन' (डब्ल्यूटीओ) की वार्ता मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। सदस्य देश कृषि और मत्स्य पालन नियमों पर सहमत नहीं हो पाए। वार्ता में अड़चन हो सकती है, लेकिन इसकी गंभीरता से इन्कार नहीं किया जा सकता। जैसा कि वार्ता समाप्ति के एक दिन पूर्व, प्रेस मीटिंग में नाम न बताने की शर्त पर, एक यूरोपियन कमिश्नर ने बताया कि -'बहुपक्षीय व्यापार की भावना खत्म हो चुकी है।' उन्होंने कहा कि सरकारें सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही हैं, एक-दूसरे के लिए समझौता करने में किसी की रुचि अब नहीं रही।' ये वार्ताएं हर दो वर्ष में आयोजित होती हैं, जिनमें 166 देश भाग लेते हैं।

अपने जन्म से ही 'डब्ल्यूटीओ' मुसीबतों की जड़ रहा है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के अत्यधिक दबाव में, लेकिन फिर भी इसका मूल-मंत्र यही रहा है कि 'व्यापार विकास को बढ़ावा देता है।' 'डब्ल्यूटीओ' द्वारा सबसे कम विकसित देशों तथा अन्य विकासशील देशों को विशिष्ट तथा अलग तरह से तरजीह देना सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन इस सम्मेलन में एक नई सुधार प्रक्रिया प्रस्तावित की गई जो बेशक आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में भी जारी रहेगी। इसमें विकासशील देशों को दी जा रही खास तरजीह को 'गैर-वाजिब लाभ' देना माना गया है। इस नए शब्दकोष में 'सुधार' को 'समावेशी' बताया जा रहा है, परंतु हकीकत में यह कमज़ोर देशों की कीमत पर आर्थिक रूप से ताकतवर शक्तियों को भारी लाभ पहुंचाने का जरिया है।

> भारत सरकार के लिए यह बड़े असमंजस की स्थिति है। एक तरफ तो वह कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात के जटिल संबंधों पर किसानों से खुलकर समझौता नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा कायम रखने के लिए अनाज व अन्य उत्पादों की सरकारी खरीद नहीं कर पा रही है। खुशकिस्मती से 'डब्ल्यूटीओ' की कृषि संबंधी चर्चाएं (समझौते) किसानों के पक्ष में ही रहीं।

'डब्ल्यूटीओ' में 'एकता परिषद' की भागीदारी 'ओडब्ल्यूआईएनएफएस' (अवर वर्ल्ड इज नॉट फॉर सेल'/ 'हमारी दुनिया बिकने के लिए नहीं है') की विस्तृत नीति के तहत थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में 'कॉर्पोरेट वैश्वीकरण' का वर्तमान मॉडल एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी मॉडल से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर संगठनों और सामाजिक आंदोलनों का एक समूह 'ओडब्ल्यूआईएनएफएस' है। इसका लक्ष्य एक ऐसी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का विकास करना है, जो 'टिकाऊ, लोकतांत्रिक, उत्तरदायी तथा सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो।'

'डब्ल्यूटीओ' को 'प्रभावित' लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए किसान संगठनों, मछुआरों तथा प्रकृति पर निर्भर अन्य समुदायों को एक साथ लाना ही 'ओडब्ल्यूआईएनएफएस' की भूमिका है। भारत से 'संयुक्त किसान मोर्चा' (एसकेएम) के तीन सदस्य भी सम्मेलन में शामिल हुए थे। 'एसकेएम' एक गैर-राजनीतिक किसान संगठन है, जो दिल्ली की सीमाओं पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) के मुद्दे पर अपना संघर्ष जारी रखे था।

'डब्ल्यूटीओ' के महानिदेशक एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला ने दो स्वतंत्र सलाहकार निकाय नियुक्त किए थे - पहले में दस सिविल सोसाइटी संगठन शामिल थे, जबकि दूसरा एक व्यापार मंच था। 'डब्ल्यूटीओ' से विभिन्न मुद्दों पर सलाह मशविरा करने के लिए जून, 2023 में सलाहकार समूह स्थापित किया गया था। इसके प्रतिनिधि मुख्यत: उपभोक्ता संगठनों, पर्यावरण समूहों एवं ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता थे।

जाहिर है, प्रभावित समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 'ओडब्ल्यूआईएनएफएस' के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक था। अंतिम दिन 'डब्ल्यूटीओ' के महानिदेशक ने गैर-सरकारी संगठनों से मुलाकात की। लघु कृषि भूमि मालिकों तथा भूमिहीन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक संगठन की हैसियत से 'एकता परिषद' भी इस मुलाकात में शामिल हुई।

अबूधाबी सम्मेलन के दौरान 'डब्ल्यूटीओ' के महानिदेशक ने सिविल सोसाइटी संगठनों की मीडिया अथवा सदस्य राष्ट्रों से संवाद को प्राथमिकता नहीं दी। पूर्व के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में ऐसा नहीं होता था। महानिदेशक की ओर से सहयोग न मिलने का नतीजा यह हुआ कि सिविल सोसाइटी संगठन अपने पर्चे नहीं बांट पाए, उनके घोषणा-पत्र जब्त कर लिए गए और उन्हें अपनी सामग्री बांटने व फोटो लेने से रोक दिया गया। कुछ सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखने पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकियां तक दीं, जबकि पूर्व के सभी सम्मेलनों में यह आम बात थी। अंतिम दिन महानिदेशक ने सिविल सोसाइटी संगठनों को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने खुलकर अपने विचार सामने रखे।

'डब्ल्यूटीओ' के इस सम्मेलन में सबसे उग्र बहस कृषि मुद्दों पर हुई। कई देश, विशेषकर खाद्य उत्पादों के आयातक ब्राजील जैसे देश इस बात के पक्ष में थे कि खाद्य उत्पादों के व्यापार में अधिक उदारता लाई जाए। खाद्य सामग्री की कमी से जूझ रहे कई देशों के लिए यह बेहद कठिन है क्योंकि वे सस्ती खाद्य सामग्री, खासकर अनाज के आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहते। यह कई सालों से तीखी बहस का मुद्दा रहा है, यहां तक कि इससे एक बहुपक्षीय निकाय के रूप में 'डब्ल्यूटीओ' के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छा गए थे। वर्ष 2008 में वार्ताओं में आया यह व्यवधान बाद में एक अंतरिम समझौते च्पीस क्लॉजज से सुलझा, जिसे 2013 के 'बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' में पारित किया गया था।

कृषि उत्पादों का व्यापार हमेशा से ही विवादास्पद रहा है क्योंकि यह खाद्य सामग्री के निर्यात पर दिए गए प्रोत्साहन को, विशेषकर विकासशील देशों के वंचित समुदायों, खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के विरुद्ध खड़ा कर देता है। हालांकि, पहले 'दोहा विकास कार्य सूची' (2001) और फिर 2013 के च्पीस क्लॉजज के जरिए भारत जैसे देशों की खाद्य सुरक्षा पर बात करने के प्रयास किए गए, किंतु कोई हल नहीं निकल पाया। 'पीस क्लॉज ङ्क2013' में कुछ छूट दी गई है, लेकिन यह इतना अस्पष्ट है और इसमें दी गई शर्तें इतनी ज्यादा है कि जुर्माने के डर से कोई इसका प्रयोग नहीं करता।

नए समझौते न हो पाने से यथास्थिति बरकरार रहना एक तरह से भारत और अन्य देशों की जीत ही माना जा सकता है। यथास्थिति कायम रहने का अर्थ यह है कि अंतरिम 'पीस क्लॉज' बना रहेगा तथा भारत में सब्सिडी के लिए जरूरी सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग भी जारी रहेगी। अब 'डब्ल्यूटीओ' के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह आगे की चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए। इस समस्या को देर तक अधर में लटकाना ठीक नहीं होगा। हालांकि, फिर भी यह साफ नहीं हो पाया कि आगामी चर्चाओं में इस खाई को कैसे पाटा जा सकेगा। अपने विशाल आकार के कारण भारत की यह मजबूरी रही है कि वह उदारीकरण की नीतियों के विरुद्ध खड़ा हो।

कृषि तथा विस्तृत सुधारों पर कोई सहमति न बन पाने पर यूरोपियन व्यापार आयुक्त व्लॉडिस डोम्ब्रोवस्की ने निराशा जताई। उन्होंने भारत को इसमें अड़चन डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने दावा किया कि भारत ने नीति सुधारों में रोड़ा अटकाने का काम किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से वाकिफ था। घरेलू परिस्थितियों और अबूधाबी के दबाव में उनका पूरा जोर इस बात पर था कि 'डब्ल्यूटीओ' की कार्रवाई अमीर देशों के पक्ष में न होने पाए। भारत के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भी कि 'हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अबूधाबी आए थे, उन्हें हमने काफी हद तक हासिल कर लिया है और हम पूर्ण संतुष्ट होकर घर जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी फिक्र अपने किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करना है। हम यह काम शिद्दत से कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे लिए अहम मुद्दा है।'

'डब्ल्यूटीओ' के अबूधाबी सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोप में किसान आंदोलन चल रहे थे, अत: यह माना गया कि सम्मेलन के निर्णय इन आंदोलनों के प्रकाश में लिए गए। भारत में किसान आंदोलनकारियों ने 'डब्ल्यूटीओ' छोड़ने के भी नारे लगाए। किसान संगठनों के नेता बीजू के. ने बताया कि 'सबसे बड़ी समस्या यह है कि खाद्य श्रृंखला का निगमीकरण (कॉरपोरेटाइजेशन) हो गया है। बड़ी-बड़ी निजी कॉरपोरेट कंपनियों ने उत्पादन और वितरण के हर कदम पर कब्जा कर लिया है।'

जिस समय भारत के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और ग्रीस के किसान भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सामान्यत: भौगोलिक परिस्थितियों, सरकारी नीतियों और प्राथमिकताओं में अंतर की वजह से सभी देशों में विरोध प्रदर्शन होते हैं और उनका कोई अंतर्संबंध नहीं होता है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है आमदनी में घटती सहायता, बढ़ती खाद्य असुरक्षा, दिनों-दिन बढ़ते कर्ज और गरीबी ने सारी दुनिया के छोटे और मध्यम किसानों को एक ही मुकाम पर ला दिया है।

ये निर्णय भारत में कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर दुष्परिणाम ला सकते हैं। 'एमएसपी' के लिए किसान संगठनों की मांग को 'डब्ल्यूटीओ' एक गैरवाजिब सब्सिडी के रूप में देख सकता था। भारत सरकार के लिए यह बड़े असमंजस की स्थिति है। एक तरफ तो वह कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात के जटिल संबंधों पर किसानों से खुलकर समझौता नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा कायम रखने के लिए अनाज व अन्य उत्पादों की सरकारी खरीद नहीं कर पा रही है। खुशकिस्मती से 'डब्ल्यूटीओ' की कृषि संबंधी चर्चाएं (समझौते) किसानों के पक्ष में ही रहीं, परंतु फिर भी कहीं-न-कहीं इन मसलों को हल करना जरूरी होगा।

(लेखिका एकता परिषद' से जुड़ी शांति एवं अहिंसा पर मैदानी काम कर रही हैं।)

https://t.me/AINewsPaperPaid

पावन प्रसंग

काम को बोझ न समझें

मनुष्य की आंतरिक अभिव्यक्ति उसके काम करने की लगन और भावना से ही परखी जा सकती है। यह जानने के लिए कि यह कार्य उसे पसंद है कि नहीं, उसकी गतिविधियों पर एक निरीक्षण दृष्टि डालिए। उत्साहपूर्वक किया हुआ कर्म यह व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की अइभरुचि उस काम करने में है कि नहीं। अनुत्साह और शिथिलता, कर्म के प्रति अरुचि का भाव परिलक्षित करते हैं। जिस कार्य से हमें प्यार होता है, उसका परिणाम शीघ्र पाने के लिए वैसी ही तत्परता भी होती है। उतनी ही फुर्ती और उत्साह भी होता है। जी करता है कि कितनी जल्दी इसे समाप्त करें और इसका सुखद परिणाम प्राप्त करें। कर्म का सुख वस्तुत: उसकी लगन भावना और निष्ठा में ही है। उत्साहपूर्वक सम्पन्न किए गए कर्म प्रफुल्लता दे जाते हैं, किंतु अनुत्साहपूर्वक काम करने से निष्कर्ष. क्षोभ और असफलता ही हाथ लगती है।

जिस काम को बोझ समझकर करेंगे, उसमें मन लगेगा ही नहीं। शारीरिक शक्ति भी जिस अनुपात से लगनी चाहिए थी वह न लगेगी तब फिर कार्य के शुभ परिणाम की आशा भी धूमिल ही बनी रहेगी। प्रसिद्ध विचारक स्वेट मार्डेन ने लिखा है- 'मनुष्य की असफलताएं परमात्मा की देन नहीं, उसकी निजी पैदाइश होती है।' यह बात अक्षरश: सत्य प्रतीत होती है। संभव है कि किन्हीं कार्यों के अनुरूप अपनी शक्ति व योग्यता न हो तो उनकी असफलता की तो एक संयोग कह सकते हैं, किंतु जो कार्य हम कर सकते हैं, जो हमारे शक्ति और सामर्थ्य की सीमा में ही हैं, वे कार्य भी यदि अपूर्ण रहते हैं तो यह मानना पड़ता है कि इस काम की लगन और उत्साहपूर्वक नहीं किया गया।

काम करने की एक भावना होनी चाहिए- उत्कृष्ट और विशाल भावना। आपका आत्मविश्वास यह कहता हो कि हम इस कार्य को करके ही छोड़ेंगे, इसमें आत्महित है और पुरुषार्थ है तो आप सच मानिए उस कार्य में आपको असीम आनंद आएगा। कमाई करते हुए जब यह भावना होती है कि इस धन से हमारे बच्चे विकसित होंगे, परिवार, राज्य और राष्ट्र समृद्ध बनेगा तो अंत:करण से अपूर्व शक्ति जाग्रत होती है, स्वाभिमान उठता है और प्रसन्नता से अंत:करण भर जाता है। जब तक हम यह अनुभव नहीं करें कि इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य का श्रेय भी है, तब तक कर्म का सात्विक आनंद नहीं मिल सकता। मनुष्य का जीवन एक आदर्श कर्म विद्यालय है। इसमें नैष्ठिक स्नातक वे समझे जाते हैं, जो कर्म को जीवन ध्येय मानकर उसे कुशलतापूर्वक निभाते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का लाभ तब पाता है, जब वह लगनपूर्वक, भावनापूर्वक अध्ययन कार्यों में लगा रहता है। जिस तरह स्वाध्याय की चमक यह व्यक्त करती है कि विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल है उसी प्रकार कर्म की उत्कट भावना यह बताती है कि इस मनुष्य का हृदय उत्कृष्ट और विशाल है। इन गुणों के कारण ही उसका व्यक्तित्व निखरता, समुन्नत होता और श्रेय प्राप्त करता है।

आलस्यपूर्वक कार्य करने से तो यही अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहें। शरीर को शिथिल और निराश बनाने की अपेक्षा उसे कुछ देर विश्राम दे लेना अच्छा है। अनुत्साह मनुष्य की अयोग्यता का चिन्ह है, इससे मनुष्य को जो नैसर्गिक दिव्यता है, उसका लोप होता है। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष द्वारा अपनी शक्तियों को व्यक्त करना ही मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ है। जिसने जीवन में संघर्ष न किया, परिस्थितियों से टकराकर मानव जीवन की दिव्यता न हासिल की, भला वह भी कोई आदमी है? मनुष्य वह है जो कठिनाइयों को हँस-हँसकर गले लगाता है। परेशानियों के तूफान को उज्जवल भविष्य का प्रतीक मानकर उनसे जूझ पड़ता है। इन वीर पुत्रों के लिए धरती माता का, आंचल सदैव खुला है। वे हर क्षेत्र में सफलता ही प्राप्त करते हैं।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

पानी का संरक्षण, पृथ्वी में जीवन का संरक्षण

मानव सभ्यता के इतिहास को खंगाले तो यह तथ्य सामने आता है कि बड़ी-बड़ी सभ्यता एवं संस्कृतियां नदी, घाटियों में विकसित और फलित हुई है। जल अपने स्वरूप में निर्मलता धारण किए हुए पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन इसकी क्रमिक रूप से घटती मात्रा में जल संकट अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर दिया है। जल अब राज्यों तथा विभिन्न देशों के मध्य बड़े विवाद का कारण बनता जा रहा है। जल मनुष्य के जीवन का अत्यंत आवश्यक स्वरूप है जल के बिना कल नहीं है और जल ही जीवन कहलाता है। ऐसे में जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जल का विवाद सिर्फ गांव तहसील के जिलों में नहीं बल्कि राज्य और देशों के बीच भी गहराता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण कावेरी, मांडवी जैसे अंतरराष्ट्रीय नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र में नील, सतलज जैसी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। वैश्विक जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीकी देशों में एक बड़ी आबादी जलाभाव के कारण काल कब रीत हो रही है। जल संकट की यह समस्या और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुकी है एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी मांग उठाई जा रही है। पृथ्वी पर पीने की योग्य जल की उपलब्धता घटती जा रही है वहीं विकास एवं औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में जल का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। मानव के जल दोहन का बेतरतीब उपयोग जल चक्र के संतुलन को नष्ट कर रहा है। प्रकृति में मानव के हस्तक्षेप के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई से ताजे जल के संकट को कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। शहरों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का स्तर निरंतर कम होते जा रहा है। आवश्यकता से अधिक जल प्रयोग करने से धरती का जलस्तर कृषकों की पहुंच से परे होता जा रहा है।

वैश्वीकरण व उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रेरित अंधाधुंध विकास की दौड़ में जल स्त्रोतों को प्रदूषित कर मानव समाज ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बढ़ती जनसंख्या भी वैश्विक जल संकट का एक बड़ा कारण है। यदि जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार से होती रही तो अगले दशक में जनसंख्या में वृद्धि की दर से 25फीसदी जनसंख्या को प्रयोग जितना ही पानी उपलब्ध हो पाएगा। यह भयानक जल संकट तथा वैश्विक खतरे की ओर इंगित करता है। वैश्विक स्तर पर जल विवाद लगातार होते रहते हैं मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के जल बंटवारे संबंधी विवाद का समाधान तटवर्ती देशों द्वारा संधि के माध्यम से किया गया है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो स्थिति और भी जटिल होती जा रही है देश की जनसंख्या तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5फीसदी है, लेकिन ताजे जल की उपलब्धता 1 फीसदी से भी कम है। राजस्थान में स्थिति जल संकट की बड़ी भयावह है वहां जल की उपलब्धता 1 फीसदी से भी बहुत नीचे जल संकट वहां की नियति बन गई है। 2040 तक भारत के तीन चौथाई शहरों को जल संकट से जूझना होगा। अब हमारा दायित्व तथा कर्तव्य होगा कि समाज को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें एवं जल संरक्षण से संबंधित विधि तथा तकनीक से परिचित कराएं एवं उसका समुचित उपयोग करें।

संजीव ठाकुर

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

• बेस्ट सेलर से सबक | डारियस फोरो

सीधे सोचें तो जीवन में डगमगाएंगे नहीं

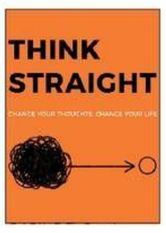

हमारे विचार हमारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन हममें से कितने लोग उन्हें गहराई से समझते हैं या उन पर नियंत्रण रख पाते हैं? इस किताब में लेखक विचारों में गहराई से उतरकर हमें बताते हैं कि अगर आप सीधे सोचना सीख लेते हैं तो सफलता दूर नहीं।

दिमाग को व्यवस्थित करना

आज की हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में हमारा दिमाग सूचनाओं से भरा होता है। क्या आपको याद है पिछली बार आप कब अपने आसपास बिना किसी गैजेट के बैठे थे? सूचनाओं का यह निरंतर प्रवाह एक मानसिक अराजकता पैदा करता है, जिससे प्राथमिकताएं तय करना और किसी बात पर फोकस करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसे ठीक करने का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना है। अपने मन की एक दराज के रूप में कल्पना करें। इसे खाली नहीं करना है, बल्कि इसे व्यवस्थित करना है। ताकि जब आपको किसी विचार की आवश्यकता हो तो आप ठीक-ठीक जानते हों कि उसे कहां खोजना है।

मानसिक शॉर्टकट...

क्या आपने कभी बिना सोचे-समझे खरीदारी की है और बाद में उसका औचित्य सिद्ध किया है? ये कॉग्निटिव बायस है। इस मानसिक शॉर्टकट को पहचानना और उसे चुनौती देना यह तय करने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों के शिकार नहीं हैं।

भावनाएं और तर्क

क्या आपने आवेश में आकर कोई निर्णय लिया है और बाद में उस पर पछतावा हुआ है? बिलकुल, हम सभी ने जीवन में कई बार ऐसा किया है। कारण, भावनाएं आसानी से तर्क पर हावी हो जाती हैं। लेकिन सीधे सोचने के लिए हमें दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना होगा। यह पहचानना कि कब भावनाएं हावी हो रही हैं और कब पीछे हटना है, महत्वपूर्ण है।

एक फिल्टर लगाएं

हम जो मीडिया देखते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, और हम जिन जगहों पर जाते हैं- वे सब हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। तब आप दूसरों के विचारों को दोहराने लगते हैं। इसे एक्सटर्नल स्टिमुली कहते हैं, जो बिना हमारे जाने हमारे नजरिए को बदलते हैं। हमें सचेत होने और यह समझने की आवश्यकता है कि हम वही ग्रहण करें जो हमारे लिए ठीक हो।

विचारों को लिख डालना

क्या आप कभी अपने दिमाग में मक्खियों की तरह भिनभिनाते विचारों से तंग आए हैं और उन्हें डायरी में लिख डालने से ही राहत मिली है? यही जर्नलिंग है। यह स्पष्टता के लिए एक उपकरण है। विचारों को लिखने से अमूर्त भावनाएं मूर्त शब्दों में बदल जाती हैं। जर्नलिंग अराजक विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, जिससे आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।

एक समय में एक काम

अपनी कल्पना किसी बाजीगर की तरह करें। हर अतिरिक्त गेंद के साथ यह कठिन होता जाता है, और जल्द ही आप एक गेंद गिरा देते हैं। यही मल्टीटास्किंग है। हमारा मस्तिष्क एक साथ कई कार्यों को करने के लिए नहीं बना। ऐसा करके हम अपनी दक्षता से समझौता ही करते हैं। एक समय में एक ही कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, उसे पूरा करें और फिर आगे बढ़ जाएं।

• अनंत ऊर्जा | बीके शिवानी, आध्यात्मिक वक्ता और लेखिका

छोटी-छोटी बातों पर गौर करना सीखें

सामान्य परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया या छोटी-छोटी बातों में आपका रिएक्शन ही आगे चलकर आदत का रूप ले लेता है। आदतें कोई भारी-भरकम परिस्थितियों में नहीं बनती। अपने रोजमर्रा के जीवन पर गौर करिए, आप किस तरह प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब आदतें बदलनी हैं तो इन एक्शन को भी ठीक करना होगा।

चौबीस घंटे शांत और स्टेबल रहने के लिए हमें जागरूकता चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारा चुनाव हैं।

आदतें कैसे बदलेंगी? कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। कोई आदत बदलना हो तो जरा अपने 'एक्शंस' पर गौर करिए। कई बार लोगों को लगता है कि सारा दिन इतना ध्यान कौन रखेगा? पर अगर आपने थोड़े दिन भी ध्यान रख लिया तो आदतें बदल भी जाएंगी और नई आदतें पड़ भी जाएंगी। कल्पना करिए कि हमें चाय-कॉफी पीने की आदत है। अचानक ख्याल आया कि यह मेरे लिए सेहतमंद नहीं है और हमने इसे पीना बंद कर दिया। फिर सोचा कि नींबू पानी या नारियल पानी पिएंगे। इस बदलाव में दो से तीन लगते हैं। उन दो-तीन दिन में वह आदत बदलनी होती है।

अटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है

जैसे ही मन में सोचा कि कल से चाय बंद। तो तुरंत दिमाग कहेगा कि नहीं पिएंगे तो सिर दर्द होगा। दरअसल हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं पिएंगे तो सिरदर्द होगा। क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं। अब देखते हैं कि मैं कितना सहन कर पाऊंगी, कोशिश करके देखती हूं। ऐसा सोचना हमारी कमजोरी है। इसे बदलें। अगर हमें चाय-कॉफी कल से छोड़नी हो तो कौन-से विचार पैदा करने होंगे या हम क्या बोलें? खुद से कहें कि कुछ नहीं होगा। अगर इस बीच कुछ होगा तो दो-तीन दिन चल जाएगा। मुझे तो बदलाव करना ही है। हो सकता है कि आसपास के लोग आपसे कहें कि एक ही तो कप पीते थे, इसमें क्या नुकसान होता है? दरअसल यह सब वही लोग बोलते हैं, जो खुद अभी तक चाय या कोई और आदत नहीं छोड़ पाए हैं। वो हमें ऐसा कहते हैं और ऐसे देखते हैं क्योंकि उन्हें ताज्जुब होता है कि ऐसे कैसे इन्होंने छोड़ दी। चाय तो कुछ नहीं है, जो दूसरी चीजें छोड़ते हैं उनके तो बड़े शुभ चिंतक होते हैं। उस टाइम दोस्त तक बदल जाते हैं। हमें भी डर होता है कि अगर हम वो चीजें छोड़ दें तो कहीं दोस्त न खो दें, इसलिए अपने जीवन के अंदर चीजें जारी रखते हैं। जरा शराबियों से पूछकर देखिए। उन्हें भी दोस्त खोने का डर सताता रहता है। अगर किसी आदत को बदलने के लिए हम दृढ़ निश्चय कर लें और उस पर अडिग बने रहें तो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।

कोई भी आदत छोटी या बड़ी नहीं

आदत चाहे चाय की हो या गुस्सा करने की। बदलने की शुरुआत एक कदम से ही होती है। हमारा दिमाग कहेगा कि गुस्से के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। दिमाग में इसके कई सारे जवाब हैं। किसी बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई तयशुदा परिस्थितियां नहीं होतीं। आदतें बड़ी-बड़ी स्थितियों में नहीं बनतीं। आदतें छोटी-छोटी हालात में बनती हैं। क्योंकि छोटी-छोटी परिस्थितियों से आप ज्यादा बार जूझते हैं और बहुत बार की प्रतिक्रियाएं आपकी आदत बन जाती हैं।

कल्पना करिए- आपके गृहकार्य के लिए जो सहायक आती है, हो सकता है कि वो भी अपना संडे मना ले। तो क्या हम शांत रह सकते हैं? अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा भी संडे अच्छा बीतेगा। वहां उसके घर पर बैठे उसका भी संडे अच्छा बीतेगा। ये ऊर्जा...ये स्पंदन...ये वायब्रेशन यात्रा करती हैं। हमारी प्रतिक्रिया से सिर्फ हमारा ही संडे खराब नहीं होता है, हमारी वायब्रेशन उधर तक भी पहुंच जाती है। फिर वही वायब्रेशन लौटकर हमारे पास आएंगी। इस बात पर गौर करिएगा, अगर व्यक्तिगत ऊर्जा सही तरीके से चली तो शक्ति बन जाएगी। अगर गलत दिशा में चली तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। चौबीस घंटे शांत और स्टेबल रहने के लिए हमें जागरूकता चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया हमारा चुनाव है। अगर हमने प्रतिक्रिया कर भी दी तो ये नहीं कहना कि ये इनकी वजह से था। जब हम कहते हैं ना कि इनकी वजह से था। माना हमने दूसरों को पावर दे दी। एक सेकंड रुककर अपने दिमाग को देखिए। उसी समय रुककर शांति से बैठकर उस दृश्य को फिर से देखकर एक नई प्रतिक्रिया दें, इसकी मन में कोडिंग हो जाएगी। फिर सारा दिन एक के बाद एक दृश्य बदलेंगे, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सोचिए आप अपनी कितनी ऊर्जा संरक्षित कर लेंगे। वही ऊर्जा हमारे बच्चों को मिलेगी।

• प्रेरक पत्र

अन्याय का विरोध करना एक नैतिक जिम्मेदारी है...

मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह प्रसिद्ध खत आज भी पढ़ा जाता है।

प्रिय साथी,

एक समय आता है, जब सहनशक्ति का प्याला भर जाता है, और लोग निराशा की खाई में गिरने को तैयार नहीं रह जाते। मुझे आशा है, आप हमारी अधीरता समझ सकते हैं। आप कानून तोड़ने की हमारी इच्छा पर चिंता जताते हैं। यह यकीनन जायज चिंता है। चूंकि हम सार्वजनिक स्कूलों में अलगाव को गैरकानूनी घोषित करने वाले 1954 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए लोगों से बहुत आग्रह करते हैं, इसलिए पहली नजर में यह विरोधाभासी लग सकता है। कोई पूछ सकता है कि आप कुछ कानूनों को तोड़ने और दूसरों का पालन करने की वकालत कैसे कर सकते हैं?

कानून दो प्रकार के होते हैं : उचित और अन्यायपूर्ण। मैं न्यायसंगत कानूनों का पालन करने की वकालत करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। न्यायसंगत कानूनों का पालन करना हमारी न केवल कानूनी बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करना भी उतनी ही बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं सेंट ऑगस्टीन की इस बात से सहमत हूं कि अन्यायपूर्ण कानून, कानून तक नहीं कहलाए जा सकते।

लेकिन दोनों में क्या अंतर है? कोई यह कैसे तय करता है कि कोई कानून उचित है या अन्यायपूर्ण? न्यायसंगत कानून एक ऐसी मानव-निर्मित संहिता होती है, जो नैतिक नियमों के अनुरूप होती है। जबकि अन्यायपूर्ण कानून अनैतिक होते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास के शब्दों में कहें तो अन्यायपूर्ण कानून एक ऐसा मानवीय कानून है, जो प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं होता। मनुष्यता का उत्थान करने वाला हर कानून न्यायसंगत होता है। वहीं हर वो कानून जो मनुष्य को नीचा दिखाता हो, अन्यायपूर्ण है।

बर्मिंघम जेल, अप्रैल 1963

• देश-दुनिया की सकारात्मक परंपराएं

मिनिएचर कला का गढ़ अज़रबैजान, अब भी विख्यात ये परंपरा

• अज़रबैजान की मिनिएचर कला विश्वप्रसिद्ध है। 1920 में जब इस देश को सोवियत संघ में शामिल किया गया तो लोगों को ये कला छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पर इसकी जड़ें मजबूत थीं। 1991 में आजादी के बाद से इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं।

• मध्ययुग में जब इस्लाम अज़रबैजान में जड़ें जमा रहा था, तब से मिनिएचर कला के सुबूत मिलते हैं। मुस्लिम और अज़रबैजानी चित्रकार खुद को अभिव्यक्त करने के लिए यूरोपीय प्रभावों से दूर कला के वैकिल्पक रूपों की तलाश कर रहे थे और इस तरह मिनिएचर कला जन्मी।

अज़रबैजान स्थित सेंटर ऑफ मिनिएचर आर्ट में ऐसी कई कलाकृतियों का संग्रह है।

• अज़रबैजान गलीचों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति इसी से मिली। नाम से स्पष्ट है मिनिएचर आर्ट में छोटे आकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। शुरुआत में यह मुख्य रूप से पुस्तक चित्रण की कला के रूप में उभरी थी।

• आधुनिक कलाओं के दबाव के बावजूद भी यह कला फल-फूल रही है। हालांकि प्राचीन तरीकों में अब बदलाव आ गया है। अज़रबैजान समेत तुर्किये आदि में भी मिनिएचर आर्ट फॉर्म के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

© The New York Times

दैनिक भास्कर

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

ओवरटूरिज्म से जूझ रहे यूरोपीय शहर; अब एम्स्टर्डम में नए होटल पर रोक, वेनिस की कुछ सड़कों पर चलने का भी चार्ज

वेनिस में घूमने के लिए पर्यटक 5 यूरो तक खर्च करते हैं

इटली का वेनिस शहर भी ओवरटूरिज्म से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए वेनिस ने शहर की मशहूर सड़कों पर घूमने के लिए 5 यूरो तक की फीस लगाई है। जो पर्यटक सिर्फ एक दिन के लिए वेनिस घूमने आएंगे, उन्हें 5 यूरो की फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा त्योहारों और व्यस्त दिनों में भी पर्यटकों पर यह फीस लागू होगी। हालांकि जो लोग वेनिस में काम के सिलसिले से या किसी रिश्तेदार से मिलने आएंगे, उन्हें यह फीस नहीं देनी होगी। फैसले पर मेयर लुइगी ब्रुगनारो कहते हैं, 'हमने यह फैसला पैसा बनाने के लिए नहीं लिया है, जितना पैसा हम कमाएंगे उससे अधिक तो शहर की ऑपरेशन या संचालन राशि ही है।'

ग्रीस और फिलीपींस जैसे देश भी ओवरटूरिज्म से परेशान

2023 में क्रोएशिया का शहर डबरोवनिक भी ओवरटूरिज्म के चलते सुर्खियों में था। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' टीवी सीरियल में भी इस शहर को दिखाया गया था। पर्यटक यहां उत्साह से घूमने आते हैं। साल दर साल पर्यटकों का आकलन करें तो 2023 के पहले पांच महीने के दौरान शहर में 46 प्रतिशत ज्यादा पर्यटक आए थे। यह शहर वेनिस को पछाड़ यूरोप का सबसे ज्यादा व्यस्त शहर भी बना था। यूरोप के अन्य देश भी इस मुहिम में शामिल हैं। पिछले साल ग्रीस ने अपने ऐतिहासिक शहर एथेंस में पर्यटकों की संख्या सीमित की थी। दिन में 20 हजार पर्यटकों को आने की अनुमति दी थी। पेरिस के लूव्र म्यूजियम में पिछले साल लगभग 80 लाख पर्यटक आए थे। एक किस्सा तो यह भी है कि वहां आए पर्यटक मोना लिसा की एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे। इसी वजह से विजिटर्स की संख्या को दिन में 30 हजार तक सीमित कर दिया गया है। © The New York Times

बिजनेस

वेटलॉस दवाएं बनाकर 'नोवो' यूरोप की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी

एश्ले नेल्सन

डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क अमेरिका और यूरोप में बेहद लोकप्रिय है। इसकी वजह दो प्रमुख दवाएं हैं ओजेम्पिक और वेगोवी। यह दवाएं डायबिटीज और वजन कम करने के लिए उपयोगी है। इन दो दवाओं के चलते ही नोवो नॉर्डिस्क यूरोप की सबसे मूल्यवान पब्लिक फर्म बन गई है। पिछले साल जब कंपनी के 100 वर्ष पूरे हुए तो नोवो नॉर्डिस्क का रेवेन्यू एक तिहाई बढ़कर 33 अरब डॉलर हो गया था। आज भी कंपनी आधी दुनिया में बिकने वाली डायबिटीज की इंसुलिन बनाती है। लेकिन ओजेम्पिक और वेगोवी ने कंपनी को अलग श्रेणी का लीडर बनाया है। इसमें मोटापे का इलाज शामिल है। क्योंकि अमेरिका में ही 4 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं। ओजेम्पिक लगभग छह साल से मार्केट में है। इलॉन मस्क तक इसका इस्तेमाल करते हैं। ओजेम्पिक टैग किए गए टिकटॉक वीडियो को एक अरब से अधिक बार देखा जा चुका है।

वर्कफोर्स बढ़ा रही है कंपनी, ग्लोबल लीडर बनने की ओर

जैसे ही ओजेम्पिक लोकप्रिय हुई, नोवो नॉर्डिस्क ने वेगोवी को लॉन्च किया, जो विशेष रूप से वजन घटाने की दवाई है। यह डेनमार्क की कंपनी अमेरिका में खूब सफलता पा रही। पिछले वर्ष ओजेम्पिक की दो तिहाई और वेगोवी की लगभग सभी बिक्री अमेरिका में ही हुई थी। कंपनी के ग्लोबल विस्तार की वजह से पिछले वर्ष डेनमार्क की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई थी। नोवो नॉर्डिस्क अब कंपनी की वर्कफोर्स भी बढ़ा रही है। पिछले साल ही 10 हजार नए वर्कर्स को नौकरी पर रखा था। नोवो नॉर्डिस्क डायबिटीज और वजन घटाने की दवाओं से 4 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस दे रही है। बार्कलेज के अनुसार मोटापे की दवाओं का बाजार अगले दशक में 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। नोवो इसका लीडर बनने की दौड़ में सबसे आगे है।

© The New York Times

पर्यटन

पर्यटकों की संख्या कम करने के लिए नीदरलैंड्स से लेकर इटली तक में नए नियम पर जोर

वलेयर मूसा

पिछले साल मार्च में नीदरलैंड्स ने ब्रिटिश पर्यटकों के खिलाफ एक वीडियो कैंपेन शुरू किया था। कैंपेन का नाम 'स्टे अवे' था और इसका उद्देश्य 18 से 35 वर्षीय ब्रिटिश पुरुषों को एम्स्टर्डम आने से रोकना था। इसके तीन महीने बाद जुलाई में एम्स्टर्डम ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यटकों की बड़ी संख्या को कम करने के लिए क्रूज को शहर के केंद्र में चलाने से रोका था। शायद यह प्रयास शहर की समस्याएं कम करने के लिए काफी नहीं थे। इसी वजह से अब एम्स्टर्डम ने नए होटल्स के निर्माण पर रोक लगा दी है। एम्स्टर्डम सिटी काउंसिल ने बयान में कहा, 'अब शहर में नए होटल नहीं बनाए जाएंगे ताकि यहां के रहवासी और पर्यटकों के लिए शहर रहने योग्य बना रहे।' एम्स्टर्डम का लक्ष्य है शहर में सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक ना आएं। हालांकि कोरोना महामारी के पहले एम्स्टर्डम में 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे। नए नियमों के तहत, कोई नया होटल तभी खुल सकता है जब कोई दूसरा बंद हो। इसके अलावा उपलब्ध से अधिक कमरे जोड़ने की भी अनुमति नहीं है।

हालांकि इस अकेले प्रतिबंध से शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी नहीं आएगी। इनहॉलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को. कोएन्स कहते हैं, 'इस कदम से ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि यह नियम एम्स्टर्डम को घूमने के लिए कम आकर्षक जगह बना सकता है। फिलहाल, पर्यटकों को कोई आपत्ति नहीं है'। स्टैटिस्टिक्स नीदरलैंड्स के अनुसार एम्स्टर्डम में लगभग 42 हजार होटल कमरे हैं, जिनमें 92 हजार से अधिक लोग रह सकते हैं। कुल मिलाकर, नीदरलैंड्स में डेढ़ लाख से अधिक होटल कमरे हैं। होटल पर रोक लगाना इकलौता कदम नहीं है। एम्स्टर्डम ने इस सप्ताह घोषणा की है कि वह अपने रिवर क्रूज की संख्या में कटौती करेगा। 2023 में 2125 क्रूज पानी में चल रहे थे। शहर की योजना है कि 2028 तक इसे आधा कर दिया जाए, और संख्या 1150 से अधिक न हो। अनुमान है कि इस प्रयास से शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 लाख 71 हजार तक कम हो सकती है।

ओवरटूरिज्म की समस्या से अकेला एम्स्टर्डम परेशान नहीं है। यूरोप के अन्य आकर्षक पर्यटन स्थल भी इसकी चपेट में हैं। यह एक वैश्विक समस्या बन गया है। पिछले साल दुनिया के सबसे अच्छे द्वीपों में से एक फिलीपींस के बोराके द्वीप को सरकार ने छह महीने के लिए बंद कर दिया था और पर्यटकों पर एक सीमा के बाद ही वापस इसे खोला था।

अमेरिका के 80% बुजुर्गों के पास खुद का घर लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी लोन का तनाव

पर्सनल फाइनेंस

ज्यादातर बुजुर्ग महीने की 30% आय लोन चुकाने पर खर्च कर रहे

पाउला स्पैन

न्यू हैम्पशायर के रहने वाले 71 वर्षीय सुसान अपेल और कीथ इरविन ने 24 साल पहले अपने रिटायरमेंट के लिए एक घर बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने 2 एकड़ जमीन में चार बेडरूम वाला दो मंजिला घर बनाया था। इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद इस घर को अच्छे दाम पर बेचकर किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास पर्याप्त पैसे घरेलू खर्चों के लिए हों। अब सुसान और कीथ दोनों रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने घर पर चल रहे लोन को भी चुका दिया है। आज उनके घर की कीमत 7 लाख डॉलर है। वे घर बेचकर किसी छोटे घर में जाना चाहते हैं, जहां उन्हें सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। लेकिन कोरोना के बाद घरों की कीमत ऐसी बढ़ी है कि सुसान दंपति को एक मंजिला घर भी 9.5 लाख डॉलर तक का मिल रहा है। हालांकि सुसान दंपति पर कोई लोन नहीं है इसलिए वे कुछ मायनों में निश्चिंत हैं। ऐसे ही अमेरिका के 80 प्रतिशत बुजुर्ग अपने घरों में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के ज्यादातर बुजुर्गों पर मॉर्टगेज लोन है। 43 प्रतिशत बुजुर्गों पर घर के लोन का बोझ चल रहा है। इसी वजह से वह अपनी आय का 30 प्रतिशत घरों के लोन और अन्य सेवाओं में खर्च करने पर मजबूर हैं।

अमेरिका के 41% बुजुर्ग लोन की चपेट में फंसे हुए हैं

कैलिफोर्निया के 73 वर्षीय डेविड टुरॉफ के पास आज भी घर का 1 लाख 80 हजार लोन है। बंधक ऋण वाले बुजुर्गों की संख्या दशकों से बढ़ रही है। हार्वर्ड ज्वाइंट सेंटर फॉर हाउसिंग स्टडीज के अनुसार, 2022 में 65 से 70 आयु वर्ष के 41 फीसदी लोग लोन में फंसे हैं। यह संख्या 1989 में 24 प्रतिशत ही थी। महंगाई दर के चलते बकाया राशि भी 21 हजार डॉलर से बढ़कर 1 लाख 10 हजार डॉलर हो गई है।

अर्बन इंस्टीट्यूट के शोध अर्थशास्त्री लिन्ना झू कहते हैं, 'क्या बुजुर्ग अपने घर में सुकून भरा जीवन बिताने के बजाय लोन के दुष्चक्र में फंस रहे हैं? घरों के बढ़ते दामों की वजह से बुजुर्गों के पास एक ही तरीका बचता है, दोबारा लोन लेने का। वो भी अब इन्हें मुश्किल से मिल पाता है। 65 वर्ष से अधिक आयु के 6 लाख बुजुर्गों को ही 2022 में लोन मिला। यह संख्या 2021 में 9 लाख 41 हजार थी। © The New York Times

आधी अमेरिकी आबादी टिकटॉक पर एप ने कई फिल्मों को हिट कराया

टेक्नोलॉजी

टिकटॉक पर 17 करोड़ अमेरिकी, बैन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं

सपना माहेश्वरी

अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की बात चल रही है। कानून निर्माताओं का कहना है कि यह एप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और चीनी सरकार अमेरिकी यूजर्स का संवेदनशील डेटा प्राप्त करने के लिए टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस का सहारा ले सकती है। अमेरिका में टिकटॉक का भविष्य क्या होगा? इस पर फिलहाल संशय है। लेकिन टिकटॉक अब अमेरिकी कल्चर का हिस्सा बन चुका है। 17 करोड़ अमेरिकी टिकटॉक चलाते हैं, जो देश की आधी आबादी के बराबर है। यह 2020, 2021 और 2022 में देश और दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला एप बना था। टिकटॉक से युवाओं को न्यूज भी मिल रही रही हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने पाया कि 18 से 29 साल के एक तिहाई लोगों को टिकटॉक पर नियमित रूप से समाचार मिलते हैं।

अब एक तिहाई युवा टिकटॉक पर ही समाचार पढ़ते हैं

अमेरिका के कल्चर को टिकटॉक ने कैसे बदला? इसे फिल्म के उदाहरण से समझिए। जब कोरोना महामारी से थिएटर्स बंद हुए, प्रोडक्शन कंपनियों को डर लगा कि युवा दर्शक फिल्म देखने वापस थिएटर लौटेंगे भी या नहीं? इस समस्या का हल उन्हें टिकटॉक पर मिला। पिछले साल क्रिसमस पर 'एनीवन बट यू' नामक फिल्म आई थी। यह फिल्म सोनी ने बनाई थी। वीकेंड में फिल्म की 80 लाख टिकटें बिकीं, कुल कमाई 21.9 करोड़ डॉलर रही। कुल-मिलाकर फिल्म हिट हुई। और इसका बड़ा श्रेय टिकटॉक को गया, क्योंकि सोनी ने बड़े पैमाने पर टिकटॉक यूजर्स से इसका प्रचार करने को कहा था। © The New York Times

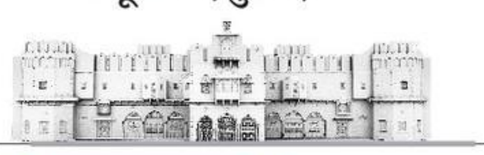

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बुजुर्गों को मिले सम्मान से जिंदगी जीने का अवसर

भारत को युवाओं का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश की 65 फीसदी आबादी की उम्र 35 साल से कम है। फिलहाल तो संतोष की बात यह है कि हमारे देश में कामकाजी उम्र (18 से 59 वर्ष) के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन, घटती प्रजनन दर से भविष्य को लेकर चिंताजनक तस्वीरें उभर रही हैं।

वैसे तो प्रजनन दर का हिसाब-किताब गड़बड़ाने से दुनियाभर में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है पर भारत में यह दर ज्यादा है। सीबीआरई साउथ एशिया नामक संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया में बुजुर्गों की कुल आबादी का 17 फीसदी हिस्सा भारत में होगा। फिलहाल भारत में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। यह संख्या 10-12 साल में 23 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल सितंबर में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी अनुमान जताया गया था कि 2050 तक देश की करीब 20 फीसदी आबादी की उम्र 60 साल से ज्यादा होगी और सदी के आखिर तक यह संख्या 14 साल तक के बच्चों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। भारत में संयुक्त परिवार के विखंडन और बढ़ते एकल परिवारों के बीच बुजुर्ग कितने उपेक्षित हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि भविष्य में जब बुजुर्गों की अच्छी-खासी आबादी होगी, क्या देश में उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं? उनकी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अभी से कदम उठाने की जरूरत है। भारत में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा का ढांचा सीमित है। ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है, जो रिटायरमेंट के बाद उनका मजबूत सहारा बन सके। ज्यादातर बुजुर्ग अपनी बचत के ब्याज पर निर्भर हैं। ब्याज दरों में बदलाव से कई बार उनकी आय घट जाती है। इनकी बचत पर ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए नियामक तंत्र की जरूरत है। बुजुर्गों के लिए उपभोक्ता सामान, उपकरणों पर टैक्स और जीएसटी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। देश में 75 फीसदी बुजुर्ग डिमेंशिया (स्मृति लोप) समेत कई पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए पीपीपी मॉडल के जरिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी विकसित की जानी चाहिए। मेडिकल केयर सेवाओं में वरिष्ठ लोगों को सामान रियायती कीमतों पर मिल सके, इसे भी देखना होगा।

बुजुर्गों को संभालना सरकार से कहीं ज्यादा समाज और परिवार की जिम्मेदारी है। जिन्होंने उम्र का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को समर्थ बनाने के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें ढलती उम्र में हाशिए पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बुजुर्ग हर कदम और हर स्तर पर सम्मान से जिंदगी गुजारने के अधिकारी हैं।

लोकसभा चुनाव 2024

उ.प्र.: दूसरे चरण में 91 प्रत्याशी मैदान में

उत्तरप्रदेश में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 91 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 42 प्रत्याशी करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा 15-15 प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर और मथुरा संसदीय क्षेत्र में हैं।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

बिहार में 57.33 प्रतिशत मतदान हुआ

***लोकसभा** चुनाव 2019 में आंध्र प्रदेश में 80.38 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में 82.11 प्रतिशत और असम में 81.6 प्रतिशत मतदान हुआ था। बिहार में 57.33 प्रतिशत मतदान हुआ था।*

चुनावी चटकारा

कार्यकर्ताओं की हो रही मनुहार

राजस्थान में पहले चरण का मतदान होने के बाद दूसरे चरण के प्रत्याशी पार्टी के प्रभावशाली नेताओं से प्रचार कराने पर जोर देने लगे हैं। मतदान समाप्त होते ही ऐसे नेताओं के पास फोन आने शुरू हो गए। खासतौर से जाति के आधार पर नेताओं को बुलाया जा रहा है, ताकि वे जाति विशेष के क्षेत्रों में जाकर अपील कर सकें। राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं से भी दूसरे चरण के मतदान तक के लिए जुटे रहने की अपील कर रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने थके होने का हवाला दिया तो उन्हें कह दिया कि लग्जरी गाड़ी और रहने की शानदार व्यवस्था रहेगी। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, आ आओ पार्टी का काम है, जीतने के बाद आपका कोई काम नहीं रुकने देंगे। यह बात कई कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड कर ली है। क्योंकि कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि यह मनुहार मतदान के दिन तक के लिए ही है। नेताजी पलट गए तो रिकॉर्डिंग काम आएगी।

राग सियासी

आशा आशंका बढ़ी,
मचा खूब घमसान।
माथापच्ची चल रही,
कम काहे मतदान।।
कम काहे मतदान,
हुई क्या गलती हमसे।
भीतर से हैरान,
कहत आगे हैं सबसे।।
प्रथम चरण कम वोट,
चोट कीन्हों है खासा।
कहीं निकालत खोट,
कहीं जागी है आशा।।

-राम नरेश गौतम

केरल ऐसी कोई गली नहीं दिखी, जहां विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के पोस्टर व होर्डिंग नहीं लगे हों

वामदलों की गहरी नाराजगी ने इस बार वायनाड सीट पर बढ़ाई राहुल गांधी की मुश्किल, भाजपा का भी दबाव

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यहां बांहें फैलाकर स्वागत हुआ था, लेकिन इस बार उनके लिए चुनावी जंग आसान नहीं लग रही। वायनाड से शानदार तरीके से जीतने वाले राहुल गांधी को इस बार भाजपा के के. सुरेंद्रन व सीपीआइ की एनी राजा से चुनौती मिल रही है।

कलपेटा से
पी.एस. विजयराघवन

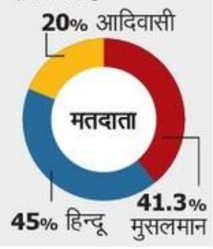

पश्चिम घाटी की खूबसूरत वादियों पर समुद्र तल से 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसा वायनाड पिछले आम चुनाव तक पर्यटन, चाय व कॉफी बागान के लिए मशहूर था। फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम इस जगह से जुड़ गया। अब उसी सीट को बचाने की जद्दोजहद में कांग्रेस है, जो 'इंडिया' गठबंधन के वामदलों के कोपभाजन का शिकार होती हुई प्रतीत हो रही है। बाहरी तौर पर मैदान में वाम नीत एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ ही हैं, लेकिन भाजपा की तुलनात्मक रूप से ठोस मौजूदगी ने इन दोनों ही दलों की उलझन को बढ़ा दिया है।

प्रकृति की गोद में बसा वायनाड कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाओं से जुड़ा है। पहाड़ी और हरियाली भरे मार्ग से गुजरने पर अलग ही अहसास होता है। हालांकि राजमार्ग के नाम पर सिंगल और घुमावदार सड़कें बेहद खतरनाक लगती हैं। मैंने कोझीकोड से वायनाड के जिला मुख्यालय कलपेटा के लिए अलसुबह बस पकड़ी। साथी यात्री अली की बातों में केरल की जमीन की खूशबू और ताजगी थी। उसको केरल और खासकर वायनाड पर गुमान था। अली ने अपनी बातों में चाय, कॉफी और मसालों की सुगंध का अहसास करा दिया। वे 26 अप्रेल को होने वाले मतदान को लेकर उत्सुक दिखाई दिए।

अली, वायनाड के लाखों मतदाताओं में से एक था, जिसको न केवल स्वयं की लोकसभा सीट बल्कि आस-पास की सीटों के प्रत्याशियों के बारे में भी गहन जानकारी थी। होगी भी क्यों नहीं? केरल का मतदाता अपेक्षाकृत शिक्षित और बुद्धिजीवी माना जाता है। उसमें मुझे वही अनुशासन दिखाई दिया जो प्रमुख बस टर्मिनस के बाहर कतारबद्ध ऑटोरिक्शा चालकों का था, जो तभी यात्री को लेकर आगे बढ़ते हैं जब उनकी बारी आती है। मेरा सफर भले ही पेट में बल डालने वाला था, लेकिन यहां का मतदाता सीधे-सीधे अपना मन बना चुका है। मतदाताओं की यह मन स्थिति चुनावों में बहुत मायने रखती है। चुनाव का नाम आते ही उनकी जुबान से सबसे पहले राहुल गांधी का नाम ही निकल रहा है, जबकि अन्य पार्टियां उनको खींचने का प्रयास कर रही हैं।

वायनाड में चुनाव प्रचार परवान पर है। सभी प्रत्याशियों के समर्थक सक्रिय हैं और जोर-शोर से प्रचार में लगे हैं। वायनाड के जिला मुख्यालय पर भले ही मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसी कोई गली नहीं दिखी जहां राहुल गांधी, एनी राजा (भाकपा) और के सुरेंद्रन (भाजपा) के पोस्टर व होर्डिंग नहीं हों। जिला चुनाव अधिकारी के बंगले के सामने भी इन नेताओं की छवियां मतदाताओं को प्रभावित करती नजर आ रही थीं। इस संबंध में भाजपा के कलपेटा कार्यालय के प्रभारी जयचंद्रन का कहना था कि उन्होंने भी अन्य राज्यों में प्रचार किया है। वहां इस तरह की संस्कृति नहीं दिखाई देती। इसका कारण यह है कि हम आपस में एक-दूसरे के होर्डिंग और कट आउट अथवा अन्य प्रचार सामग्री को लेकर सवाल नहीं उठाते। यही परम्परा वर्षों से चली आ रही है।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यहां बांहें फैलाकर स्वागत हुआ था, लेकिन इस बार उनके लिए चुनावी जंग आसान नहीं लग रही। माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड में 5 लाख वोटों से शानदार तरीके से जीतने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस बार केरल भाजपा के के. सुरेंद्रन और सीपीआइ की एनी राजा से चुनौती मिल रही है। ये दोनों ही अपनी पार्टियों के स्टार नेता हैं। के. सुरेंद्रन जहां केरल भाजपा के अध्यक्ष हैं तो एनी राजा सीपीआइ महासचिव डी. राजा की पत्नी हैं और सीपीआइ। की दिग्गज महिला नेताओं में उनकी गिनती होती हैं। इसलिए चुनौती कड़ी है।

राहुल गांधी के मार्ग में बड़ी बाधा वामदल हैं। वाम दलों में उनके प्रति गहरा रोष है। हालत यह है कि भाकपा कार्यालय पर राज्यसभा सांसद संतोष कुमार पी. राहुल गांधी की हार को निश्चित मान रहे हैं। उनके तेवर कांग्रेस को लेकर काफी उग्र नजर आ रहे थे। बातचीत के दौरान वे बोले, गठबंधन की प्रमुख पार्टी के तौर पर कांग्रेस का काम जोड़ने का होना चाहिए था, लेकिन यहां तोड़ने की कोशिश हुई है। जब मुखिया ही उत्तर भारत से चुनाव नहीं लड़ रहा तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? केरल में केवल यूडीएफ बनाम एलडीएफ की ही स्थिति है। जनता केवल उसी को वोट देगी जो भाजपा का कड़ा विरोध कर पाए और वामदल से बेहतर विकल्प कोई दूसरा नहीं है।

राहुल गांधी के खिलाफ किए जा रहे प्रचार में यह भी कहा जा रहा है कि पिछले पांच सालों में वे बमुश्किल नौ बार यहां आए होंगे। सांसद बनने के बाद उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा कोई मसला लोकसभा में नहीं उठाया है। राहुल गांधी का सकारात्मक पहलू यह है कि इस सीट पर अल्पसंख्यकों के वोट अधिक हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इसे सबसे सुरक्षित सीट मानती है।

एनी राजा | राहुल गांधी | के. सुरेंद्रन

प्रमुख मुद्दे

- पर्यटन स्थल होने के बावजूद कनेक्टिविटी का अभाव
- मानव-वन्य जीव संघर्ष, पिछले कुछ सालों में नौ लोगों की मौतें
- जिला मुख्यालय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा और मेडिकल कॉलेज का अभाव

फैक्ट फाइल

- उत्तरी केरल के 3 जिलों के 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं

पत्रिका साक्षात्कार : भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत बोले

'भारतीय किसान यूनियन न्यूट्रल, फिर भी शहादत को कैसे भूलेंगे'

*पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की भूमिका चुनाव में बढ़ गई है। कहने के लिए भाकियू चुनाव में न्यूट्रल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद से ही संगठन केंद्र सरकार से नाराज चल रहा है। **अभिषेक श्रीवास्तव** से विशेष बातचीत के दौरान भाकियू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने खुलकर किसानों का पक्ष रखा। प्रस्तुत है इसी बातचीत के प्रमुख अंश।*

Q लोकसभा चुनाव में भाकियू किसके साथ है?

यह किसानों का खुद का निर्णय होगा। भारतीय किसान यूनियन न्यूट्रल है। किसान जिसे मन करे उसे वोट दें। लेकिन एक बात तो तय है, किसान 2021-22 750 किसानों की शहादत को नहीं भूलेगा। हमारे पास आम आदमी पाटी, कांग्रेस और भाजपा के नेता आ रहे हैं। हमने किसानों पर छोड़ दिया है, वे किसका साथ देते हैं।

Q आरएलडी के जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए?

देखिए यह उनका निर्णय है। केंद्र सरकार कई लोगों के साथ गलत कर चुकी है। केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठी बरसाना भी गलत था। रालोद ने अचानक निर्णय लिया। किसी बड़े बुजुर्ग से चर्चा तक नहीं की।

Q किसान संगठन कोई निर्णय लेंगे?

देखिए पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। अब जो भी निर्णय होंगे, वे किसानों के सामूहिक होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा में छोटे-बड़े सैकड़ों संगठन हैं। हम भी उसका हिस्सा हैं।

Q क्या सरकार और किसानों के बीच की तनातनी खत्म हो गई?

देखिए चुनाव आते और जाते रहेंगे। हम 11 महीने चले किसानों के आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं। एक बात तो तय है सरकार किसान विरोधी है। किसान को सम्मान नहीं मिल रहा है। किसान को खालिस्तानी बोला जाता है। किसान के बच्चे फौज में जाते हैं। इस सरकार में उसे भी अग्निवीर बना दिया गया।

कमल खिलावन | POLI नोक-झोंक | पंजा सिंह

पहला चरण किसके नाम

*(**पहला चरण।** मतदान का महाकुंभ शुरू। दो ठाले, मतदान के ठीक बाद। एक नितांत जरूरी दुकान के बाहर)*

***पंजा सिंह:** मेरी अंगुली पर लगी स्याही गवाही दे रही है, इस बार परिवर्तन होगा।*

***कमल खिलावन:** (अपनी अंगुली आगे करते हुए) और ये क्या मेनिक्योर है ? चुनाव चिह्न पंजा होने का यह मतलब नहीं कि हर उंगली पर लगी स्याही तुम्हारी है।*

***पंजा सिंह:** चुनाव चिह्न कमल होने का मतलब तो लेकिन यह है न कि लक्ष्मी का वास.. इलेक्टोरल बॉन्ड... हें हें हें..।*

***कमल खिलावन:** 2019 में तुम राफेल... राफेल... राफेल.... राफेल रट रहे थे। अब तुम इलेक्टोरल बॉन्ड की माला जप रहे हो। पब्लिक नाम तक नहीं जानती। कम ऑन ग्रो अप माय बॉय।*

***पंजा सिंह:** मुझे कह रहे हो ?*

***कमल खिलावन:** कहना तो तुम्हारे टॉप वाले को चाहता हूं.. पर क्या करूं मेरी रीच तुम्हीं तक है।*

***पंजा सिंह:** ईडी बुला लो.. सीबीआइ बुला लो.. रीच बढ़ जाएगी।*

***कमल खिलावन:** चुनाव की बात करो। टीवी डिबेट नहीं है ये। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग के साथ ही पहला चरण हमारे नाम।*

***पंजा सिंह:** हम क्या मूंगफली खाने उतरे हैं चुनाव में ?*

***कमल खिलावन:** स्टडी की कितनी कमी है.. यह गर्मियों का सीजन है भाई है। सत्तू पी, फलूदा खा, मूंगफली मिलेगी ही नहीं काके। ऊपर से नीचे तक एक ही बीमारी कहां क्या बोलना है, पता नहीं। ठका ठक.. ठका ठक.. ठका ठक।*

***पंजा सिंह:** और तुम.. राम देवरा पीर का जन्म कश्मीर करा दो.. वह क्या है.. टका टक.. टका टक.. टका टक...।*

***कमल खिलावन:** इत्तू सी चूक.. चलती है रे बाबा.. उंडू कश्मीर में उंडू नहीं निकला... हो सकता है बोला हो धीरे से तुम ने सुना नहीं...*

***पंजा सिंह:** बस.. ऐसे ही दस साल निकाल दिए..*

***कमल खिलावन:** तुम्हारे सत्तर से बेहतर थे*

***पंजा सिंह:** सत्तर सिर्फ हमारे नहीं थे.. गठबंधन के भी थे.. तुम्हारे भी थे उसमें।*

***कमल खिलावन:** पत्रकार जब किसी सामान्य अचीवमेंट पर खबर लिखते हैं तो एक लाइन जरूर आती है.. फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लाइन हमारे लिए है। अब पीछे की बात नहीं आगे की करो।*

***पंजा सिंह:** 2047 की करें क्या..*

***कमल खिलावन:** यस.. यही विजन है..*

***पंजा सिंह:** तब तक तुम रहोगे भी क्या..*

***कमल खिलावन:** तुम भी नहीं रहोगे।*

***पंजा सिंह:** तो आज की बात करो न..*

***कमल खिलावन:** ना.. तुम आज में अटके रहो.. हम कल के बारे में तेज रफ्तार में सोच रहे हैं। सब प्लान तैयार है। बड़े फैसले लेने हैं।*

(पास से ही शटर खुलने की आवाज आती है। चुनाव के कारण दो दिन ड्राय डे रहने से भारी भीड़ है। दोनों भी बड़ा फैसला लेते हुए तेजी से उस ओर बढ़ लिए..)

- सुप्रिया शर्मा

बिहार सीमांचल-पूर्वांचल के प्रत्याशी कड़े मुकाबले में फंसे

मोदी की छांव, फिर भी जदयू की राह में बाधाएं विकट

पटना
प्रियरंजन भारती

बिहार के सीमांचल और पूर्वांचल में जदयू को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सीमांचल की मुस्लिम-यादव बहुल आबादी वाले किशनगंज, कटिहार और पूर्णियां में लालू यादव की रणनीति से बदले समीकरणों ने जदयू की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इनमें से किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट है, जिस पर पिछली बार कांग्रेस की जीत हुई और इसी के साथ महागठबंधन का खाता खुल पाया था। पूर्वांचल के भागलपुर और बांका में भी जदयू को अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इन सभी पांच सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रेल को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव की छांव में खड़े जदयू की राहें इन क्षेत्रों में आसान नजर नहीं आ रही हैं।

सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच बढ़ी खटास दूर कर राहुल गांधी इस चुनाव में पहली बार भागलपुर में चुनावी रैली को पहुंचे तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने भी मंच साझा कर एनडीए के खिलाफ हुंकार भरी। भागलपुर सीट से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा 'इंडिया' चैप्टर के उम्मीदवार हैं तो जदयू ने अपने सांसद अजय मंडल को ही रणक्षेत्र में उतारा है।

जहां तक बांका संसदीय क्षेत्र की बात है तो यहां भी जदयू को चुनौती झेलनी पड़ रही है। जदयू ने यादव, राजपूत और अन्य पिछड़ी जाति बहुल सीट पर सांसद गिरिधारी लाल यादव को फिर मैदान में उतारा है। इनका मुकाबला फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की ही तरह आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव से है। आमने-सामने की लड़ाई रोचक हो सकती है। जदयू मोदी मैजिक के भरोसे फिर बेड़ा पार करने की जुगत में हैं।

त्रिकोणीय और दिलचस्प हुआ मुकाबला

बांका संसदीय सीमांचल की यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों की बहुलता वाली पूर्णियां संसदीय सीट पर इस बार त्रिकोणीय और दिलचस्प मुकाबला है। पप्पू यादव निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। पूर्व सांसद उदय सिंह का भी पप्पू यादव ने समर्थन ले लिया है। पप्पू यादव का कोशी क्षेत्र में अपना प्रभाव और बड़ा रुतबा है। चुनावी चौसर पर बीमा भारती पिछड़ गई दिखने लगी हैं। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में बादशाहत की जंग बेहद महत्त्वपूर्ण इबारत लिख सकती है।

कांग्रेस नेतृत्व ने जोर लगाकर कटिहार सीट समझौते में अपने हिस्से ले तो ली पर अब तारिक अनवर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हैं। जदयू के सांसद दुलालचंद गोस्वामी हिंदू वोटों और मोदी मैजिक के सहारे फिर चुनावी जंग में फतह पाने को बेताब हैं। मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे तारिक अनवर जीतने की जद्दोजहद कर रहे हैं। राहुल गांधी की भागलपुर रैली से मुस्लिम समाज को कनेक्ट करने का मौका मिला है। सीमावर्ती बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए चर्चित कटिहार में इस बार भी आर-पार की लड़ाई छिड़ी है। देखना यही खास होगा कि जीत हार में इस बार क्या मायने रखता है।

किशनगंज क्षेत्र में 70 फीसदी मुस्लिम आबादी है। एनडीए की सहयोगी जदयू ने मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से सांसद मोहम्मद जावेद और एआइएमआइएम के विधायक अख्तरूल ईमान के चुनावी मैदान में उतरने से संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है। 2019 में एक यही सीट महागठबंधन के खाते में गई जिसे कांग्रेस के इसरारूल हक ने जीता था। उनके असमय निधन के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के मो.जावेद ने जंग जीती। यहां सांप्रदायिक आधार पर हमेशा ही वोटों की गोलबंदी होती रही है।

आज का सवाल

प्रथम चरण में मतदान कम रहने का क्या कारण है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

गौरवशाली संस्कृति को समझें

संस्कारों को परिवार से ही मजबूत करना होगा। हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को समझना होगा। इंटरनेट पर फैले अपराध और अश्लीलता के मकड़जाल से निकालना भी आवश्यक है।

-पवन गौतम बमूलिया, उदपुरिया, बारां

बच्चों पर रखें निगाह

आजकल लोग कम समय में अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कानून का भय होना बहुत जरूरी है। माता-पिता बच्चों की गतिविधियों पर निगाह रखें और उन्हें गलत संगत से बचाएं।

-सुधा दुबे, भोपाल

आर्थिक विषमता से बढ़ रहे अपराध

अपराध बढ़ने के मुख्य कारण हैं आर्थिक विषमता व रोजगार के अवसरों में कमी। व्यक्ति गरीबी से बाहर निकलने के लिए भी अपराध कर बैठता है। बच्चों को परिवार में संस्कार नहीं मिल रहे हैं।

-प्रियंका महेश्वरी, जोधपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'देश में अपराधों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है ?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें
rb.gy/u7lmid

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 56

आईटी खर्च की दिशा बदलेगी!

देश की तीन दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) और वित्त वर्ष 24 के नतीजे कमजोर रहे हैं। तीनों कंपनियों ने सतर्क अनुमान और सलाह भी जारी किए हैं (हालांकि टीसीएस राजस्व का अनुमान जारी नहीं करती)। तीनों बड़ी कंपनियों के प्रबंधन की यह सोच है कि वैसे तो मांग में कोई स्पष्ट उभार नहीं दिख रहा, लेकिन वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 24 से मार्च 25) संभवतः इसका सबसे निचला दौर हो, जिसके बाद सुधार दिख सकता है। उनको उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर हालात बेहतर होने से वित्त वर्ष 25 के अंतिम महीनों और वित्त वर्ष 26 में आय की गति में धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। आईटी की इन तीन दिग्गज कंपनियों की मौजूदगी सभी भौगोलिक इलाकों और कार्यक्षेत्रों तक है। मार्च 2024 तक इन कंपनियों में कुल मिलाकर करीब 12 लाख कर्मचारी थे और वित्त वर्ष 24 का उनका कुल राजस्व 4.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। उनके महत्त्वपूर्ण आकार और सभी खंडों और भौगोलिक इलाकों में मौजूदगी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वित्त वर्ष 25 के लिए उनके अनुमान और रुझानों का आकलन ज्यादातर आईटी सेवा व्यवसायों के लिए अच्छा रहने की संभावना है, विशेष रूप से उन बड़ी कंपनियों के लिए जो छोटे, विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। तीनों बड़ी कंपनियों का वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में राजस्व कम रहा है। इस अवधि में विप्रो का राजस्व तिमाही आधार पर थोड़ा कम रहा, जबकि एक साल पहले की तुलना में 6.5 फीसदी कम रहा। इसी तरह, इन्फोसिस के राजस्व में तिमाही आधार पर 2.2 फीसदी गिरावट आई, जबकि यह सालाना आधार पर यह सपाट रहा। टीसीएस का राजस्व तिमाही आधार पर 1.1 फीसदी बढ़ा, जबकि सालाना आधार पर इसमें 2.2 फीसदी की बढ़त हुई।

तीनों कंपनियों में वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में भी तिमाही आधार पर गिरावट आई है। एक साल पहले के मुकाबले उनके कर्मचारियों की संख्या में 63,000 से ज्यादा की कमी आई है। इसके बावजूद कार्यबल का उपयोग अभी भी ऐतिहासिक स्तर से नीचे है। तीनों कंपनियों में आट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर भी घटकर 12 फीसदी के आसपास रह गई है जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले आधा है। कर्मचारियों की कम संख्या और कम नौकरी छोड़ने की दर का यह संयोजन पूरे उद्योग में कमजोर मांग का संकेत देता है। तीनों कंपनियां कमजोर विवेकाधीन खर्च को चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बताती हैं। हालांकि सभी कंपनियां लगातार सौदे हासिल कर रही हैं, लेकिन अधिकांश कार्यक्षेत्रों के ग्राहकों ने विवेकाधीन खर्चों में कटौती की है या इसे टाल दिया है। ऐसे में मांग का पूरा माहौल कमजोर बना हुआ है। कंपनियों ने कहा है कि जब तक व्यापक आर्थिक वृद्धि में वैश्विक तेजी नहीं आती है और ग्राहक विवेकाधीन परियोजनाओं को फिर से शुरू नहीं करते हैं, तब तक इसमें बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ये तीनों कंपनियां जेनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों, हाइपरस्केलर्स (क्लाउड सेवा प्रदाता) और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर रही हैं।

कुछ निवेशकों और विश्लेषकों का मानना है कि बाजार का अब सबसे निचला स्तर आ चुका है और वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि तीनों कंपनियां मार्जिन बनाए रखने में सक्षम हैं, भले ही राजस्व वृद्धि कमजोर या नगण्य रही हो। आईटी कंसल्टिंग फर्म गार्टनर का मानना है कि 5 लाख करोड़ डॉलर के वैश्विक आईटी बाजार के खर्च में कैलेंडर वर्ष 2024 (वित्त वर्ष 2025 की पहली तीन तिमाहियों) में 8 फीसदी की महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी। गार्टनर का यह भी मानना है कि आईटी सेवाओं और उत्पादों के लिए 139 अरब डॉलर का भारतीय बाजार 13 फीसदी की बेहतर दर से बढ़ेगा। यदि यह काफी हद तक सही होती है, तो यह मांग बढ़ाने वाला हो सकता है और भारतीय कंपनियों को काफी हद तक इसका लाभ होने की संभावना है। गार्टनर का कहना है कि बढ़ा हुआ खर्च आईटी परामर्श क्षेत्र में केंद्रित हो सकता है। सीआईओ अब एनालिटिक्स और जेनरेटिव एआई में भी निवेश पर विचार कर रहे हैं। भारत में, डिवाइस और उपकरण सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च में तेज वृद्धि देखने की संभावना है। आंतरिक प्रक्रियाओं और वितरण मॉडल को अनुकूलित करने में भी जेनरेटिव एआई ऐप्लिकेशन ढूंढना शुरू कर सकता है। यह पूर्वानुमान मध्यम अवधि में उम्मीद प्रदान करता है, लेकिन निकट अवधि का नजरिया मंद ही दिखाई दे रहा है।

अजय मोहंती

लोक सभा चुनाव में छह राज्यों पर नजर

राजनीतिक परिदृश्य में लोक सभा चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाना संभव नजर आ रहा है लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 2019 की तुलना में कड़ा मुकाबला हो रहा है

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

ये आम चुनाव कितने करीबी हो सकते हैं? अगर आप नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रशंसक हैं तो आप कहेंगे कि इन चुनावों में सबकुछ अनुमान के मुताबिक ही घटित होगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर आप विपक्ष के समर्थक हैं तो आप कह सकते हैं कि ये चुनाव 2004 जैसे होंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले राजग को जीत का दावेदार माना जा रहा था लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। पहले चरण का मतदान हो चुका है। इस बीच टेलीविजन चैनलों पर कई 'ओपिनियन पोल' प्रसारित हुए। इन्हें किस तरह अंजाम दिया जाता है कोई नहीं जानता। इन सभी पोल में यही कहा गया है कि भाजपा 2019 से बड़ी जीत हासिल करेगी। हाल के समय में सबसे सफल चुनाव पूर्वानुमान लगाने वाले प्रदीप गुप्ता (ऐक्सिस माई इंडिया) ने अब तक कुछ नहीं कहा है। एक ट्वीट के मताबिक उन्होंने मनीकंट्रोल से कहा था कि भाजपा को 13 राज्यों में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उस ट्वीट को बाद में हटा दिया गया। उन्होंने ओपिनियन पोल करने का कोई दावा नहीं किया है। जब कोई अग्रणी चुनाव सर्वेक्षक अपने पत्ते नहीं खोल रहा हो तो एक पत्रकार क्या कर सकता है? वह चुनावों का 'पाठ' कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्ष थोड़ा-थोड़ा सही हों और गुप्ता ने अपने मिटा दिए गए ट्वीट में जो कहा था वह भी सही हो?

भारत जैसे विशाल देश के चुनावों में जब मोदी अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हों तब भी नतीजे विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों का ही नतीजा होते हैं। वर्ष 1989 से 2014 तक गठबंधन के 25 वर्षों में मैं यही दलील देता थ कि भारत के आम चुनाव नौ सेट वाले टेनिस मैच की तरह हैं जिनमें पांच सेट जीतने वाला खिलाड़ी यह चुनावी ग्रैंडस्लैम जीतता है। इनमें से नौ राज्य थे: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (विभाजन के पहले), मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और केरल। इन राज्यों में कुल मिलाकर 351 सीट थीं। पांच राज्यों में चुनाव जीतने वाले को करीब 200 सीट मिल जाती थीं। इस प्रकार गठबंधन 272 का आंकड़ा पा लेता था।

वर्ष 2014 में यह सिलसिला खत्म हो गया। इन चुनावों में हम छह राज्यों पर नजर रखेंगे: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा। इन राज्यों में 193 लोक सभा सीट हैं और यहां कड़ा मुकाबला है। इनसे ही तय होगा कि 4 जून को किसके पास कितनी सीट होंगी। अगर उसे 225 से अधिक सीट पर जीत हासिल करनी है तो वे इन्हीं राज्यों से आएंगी।

वर्ष 1977 के बाद जन्मे मतदाताओं के लिए अगर हम पहली गैर कांग्रेस सरकार को प्रस्थान बिंदु मानें तो 2014 तक लोकसभा में बहुमत का ख्याल अजीब था। यही कारण है कि 2014 में मोदी की जीत उन्हें जबरदस्त लगी हालांकि 282 सीट के साथ पार्टी को मामूली बहुमत हासिल था। इंदिरा गांधी ने जब 1969 में कांग्रेस को पुराने नेताओं से मुक्त कराया था तब एक छोटी लोक सभा में भी उनके पास 350 सीट थीं। अगर 2014 की जीत जबरदस्त थी तो 2019 में तो उनकी नजर में सफाया ही हो गया था। पुलवामा-बालाकोट के कारण राष्ट्रवादी उभार ने 2019 में भाजपा को 2014 की तुलना में अधिक वोट दिलाए और उसका मत प्रतिशत 31.34 फीसदी से बढ़कर 37.7 फीसदी हो गया। वहीं सीट में केवल 20 का इजाफा हुआ और पार्टी 303 सीट तक पहुंची।

यह आंकड़ा हमें बताता है कि जब इतना लोकप्रिय नेता सत्ता में हो तब भी देश में चुनाव राज्य दर राज्य ही होते हैं। मोदी को बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे 12 राज्यों में 278 सीट पर जीत मिली थी। बाकी पूरे देश में पार्टी को केवल 25 सीट पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। परंतु 12 राज्यों में स्पष्ट जीत ने यह सफलता तय की।

इतिहास बताता है कि भाजपा को 2019 में 224 से अधिक सीट पर 50 फीसदी से अधिक मत मिले। हम इसे तब अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हम याद करें कि राजीव गांधी 414 सीट जीतने के बावजूद 48.12 फीसदी मत ही हासिल कर पाए थे। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, इन 242 सीट में से अधिकांश भाजपा के अच्छे प्रदर्शन वाले 12 राज्यों में हैं और विपक्षियों के लिए 2024 में कड़ा मुकाबला है। यह तब है विपक्षी गठबंधन है, कुछ जाति समूह नाराज हैं और पुलवामा जैसा कोई कारक भी नहीं है। हरियाणा की बात करें तो वहां कई नकारात्मक कारक हैं। भाजपा की राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष है। वर्ष 2019 में भाजपा को वहां 58.21 फीसदी मत मिले थे। दूसरा, यही आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को जहां इन राज्यों में 224 सीट पर जीत मिली थी जबकि शेष पूरे देश में उसे केवल 79 सीट पर जीत मिली, 319 सीट में से। यह सही है कि पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी लेकिन मैं 224 सीट के अलावा बाकी की बात कर रहा हूं। यानी उसे एक चौथाई से भी कम सीटों पर जीत मिली। अगर आप भाजपा समर्थक हैं तो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं और 224 सीट को हल्के में ले सकते हैं। परंतु 370 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए शेष 319 में से आधी सीट जीतनी होंगी। असली लड़ाई यहीं है। मोदी को अगर अपना दबदबा बरकरार रखना है तो उनके लिए पहला लक्ष्य होगा 303 सीट का आंकड़ा पार करना।

यह बात हमें वापस छह राज्यों के विचार की ओर लाती है। इन राज्यों में कुल 193 सीट हैं। इनमें से चार राज्य- कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड उन 12 राज्यों में शामिल थे जहां 2019 में मोदी को जीत मिली। इन राज्यों में उनके सामने नई राजनीतिक चुनौतियां हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उन्हें पहले ही तरह-तरह की चुनौती मिल चुकी है। लगभग 100 अन्य सीट के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में मुकाबला होगा जहां भाजपा के लिए बहुत अधिक संभावनाएं नहीं हैं। उसे 303 का आंकड़ा पार करने के लिए इन छह राज्यों में 100 सीट पर जीत हासिल करनी होगी।

इन छह राज्यों को चुनने की दो वजह हैं। पहली, भाजपा इनमें से हर राज्य में मजबूत है। दूसरा मोदी को हर राज्य में एक अलग हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में उनके मजबूत साझेदार कमजोर पड़े हैं। शिवसेना का विभाजन हो चुका है और जनता दल यूनाइटेड काफी कमजोर पड़ा है। मोदी के सामने उसके नेता नीतीश कुमार के नाम पर वोट जुटाना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड और कर्नाटक में भाजपा के विरोधी दलों की सरकार है। इससे संतुलन गड़बड़ाया है। ओडिशा में 2019 की तरह फिक्स और दोस्ताना लड़ाई नहीं होगी। उस वक्त विधानसभा चुनाव के बदले लोक सभा चुनाव का सौदा जैसा किया गया था। नवीन पटनायक को चिंता होगी कि अगर वह कमजोर साबित हुए तो उन्हें अपना बुढ़ापा राजनीतिक पराभव में गुजारना होगा और खुद को नहीं तो अपने लोगों को एजेंसियों से बचाना होगा। ये तमाम वजह हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक तौर पर भले ही यह चुनाव अनुमान लगाने लायक लग रहा हो लेकिन कुछ राज्यों में मुकाबला 2019 की तुलना में कहीं अधिक करीबी है। यही वजह है कि हमने जिन छह राज्यों का जिक्र किया है वहां देखना होगा कि मोदी 2019 से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। अगर विपक्ष उन्हें 272 के आंकड़े से नीचे रखना चाहता है तो इन राज्यों में उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

आवास ऋण टॉप-अप पर आरबीआई की नजर

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

अधिकांश बैंक एवं आवास वित्त कंपनियां अक्सर ग्राहकों को आवास ऋण पर टॉप-अप लोन की पेशकश करते हैं। टॉप-अप लोन एक प्रकार का अतिरिक्त ऋण होता है। अगर आपने किसी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से आवास ऋण लिया है तो टॉप-अप लोन के लिए आवेदन कम से कम दस्तावेज के साथ आसानी से कर सकते हैं। टॉप-अप लोन का चलन पिछले दो दशकों से है। मगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसे लेकर पहले चिंतित नहीं था मगर अब वह टॉप-अप लोन को लेकर सहज नहीं दिख रहा है। आरबीआई ने आवास वित्त पर जुलाई 2015 में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था मगर इसमें आवास ऋण पर टॉप-अप लोन का कहीं जिक्र नहीं था। अब बैंकिंग नियामक ऐसे ऋण पर पैनी नजर रख रहा है। आरबीआई हरेक कर्जदाताओं के साथ टॉप-अप लोन पर अलग से बातचीत कर रहा है। यह ऋण मूलतः व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल लोन) है मगर इसे आवास ऋण की आड़ में दिया जा रहा है।

आखिर, आरबीआई इसे लेकर चिंतित क्यों है? आरबीआई सार्वजनिक रूप से यह कह चुका है कि खुदरा ऋण, खासकर असुरक्षित पर्सनल लोन, बांटने को लेकर कर्जदाताओं के अनावश्यक उत्साह से वह खुश नहीं है। आरबीआई को डर है कि वित्तीय संस्थानों के इस उत्साह को देखने के बाद ग्राहक ऋण तो ले लेंगे मगर उनमें कई बाद में इसे चुकाने की हालत में नहीं होंगे। आरबीआई के अनुसार इससे पूरे वित्तीय तंत्र के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसे देखते हुए आरबीआई ने नवंबर 2024 में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी को आवंटित ऋण पर जोखिम भारांश (रिस्क वेटेज) बढ़ा दिया था।

आवास ऋण टॉप-अप किस तरह काम करता है? यह एक प्रकार के सुरक्षित पर्सनल लोन होते हैं। इस ऋण की पेशकश उन ग्राहकों को की जाती है जो अपने ऋण की मासिक किस्तों का भुगतान समय से कर रहे हैं। आम तौर पर आवास ऋण लोन-टू-वैल्यू या एलटीवी की गणना करने के बाद दी जाती है। एलटीवी किसी जायदाद के मूल्य का वह हिस्सा (प्रतिशत) होता है जो कोई बैंक जायदाद खरीदने वाले को उधार देता है। यह जायदाद की कीमतों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने से पहले ग्राहक पहले अपनी तरफ से कुछ रकम का अग्रिम भुगतान करते हैं। ग्राहक जायदाद की कीमत का 10 से 30 प्रतिशत हिस्सा भुगतान करते हैं। ऋण के नियमित भुगतान से वित्तीय संस्थान का मूलधन कम होता जाता है और एलटीवी अनुपात कम होने लगता है। इसके बाद वित्तीय संस्थान अपने अच्छे ग्राहकों को टॉप-अप लोन की पेशकश करते हैं। ग्राहक इस ऋण का इस्तेमाल विवाह, छुट्टियां मनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च या कारोबार विस्तार आदि प्रयोजनों पर कर सकते हैं।

पर्सनल लोन की तुलना में टॉप-अप लोन की अवधि 10-15 वर्षों या बकाया ऋण की शेष बची अवधि के अनुसार हो सकती है। वित्तीय संस्थान टॉप-अप लोन देने से पहले आवास ऋण की रकम, ऋण भुगतान में निरंतरता और कर्जदाताओं की भुगतान क्षमता पर विचार करते हैं और इनसे आश्वस्त होने के बाद ही आवंटन करते हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज दर व्यक्तिगत ऋण की तुलना में काफी कम होता है मगर आवास ऋण से अधिक होता है।

आखिर, टॉप-अप लोन अब आरबीआई को क्यों खटकने लगा है? इस ऋण से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिन पर आरबीआई ध्यान खींचना चाहता है। आवास ऋण पर टॉप-अप लोन का मुख्य मकसद घर की सजावट या इसमें सुधार होना चाहिए। अगर ग्राहक इस ऋण का इस्तेमाल छुट्टियां मनाने के लिए करता है तो इसका मतलब है है कि रकम का इस्तेमाल मूल उद्देश्य के लिए नहीं हो रहा है।

ऐसे ऋण के मामले में कागजात में अक्सर ये बातें स्पष्ट होती हैं कि रकम का इस्तेमाल कयास आधारित गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। मगर कोई ग्राहक टॉप-अप लोन लेकर शेयर बाजार में इसे लगाता है तो क्या इस पर नजर रखी जा सकती है? या फिर ग्राहक दूसरे ऋण चुकाने के लिए टॉप-अप लोन का इस्तेमाल करता है तो क्या बैंक इसका पता लगा सकते हैं?

आरबीआई की मुख्य चिंता यह है कि टॉप-अप होम लोन की आड़ में व्यक्तिगत ऋण का अंबार लगता जा रहा है। वित्तीय संस्थानों को इससे रोकने के लिए आरबीआई ने व्यक्तिगत ऋण के लिए पूंजी की आवश्यकता बढ़ा दी है। पूंजी की आवश्यकता बढ़ने से कर्जदाता संस्थानों के लिए ऋण देना और ग्राहकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऊंची पूंजी की आवश्यकता से बचने के विए वित्तीय संस्थान टॉप-अप होम लोन के जरिये पर्सनल लोन की पेशकश कर रहे हैं।

मार्च 2024 तक भारतीय वित्तीय प्रणाली में आवास ऋण का हिस्सा लगभग 35 लाख करोड़ रुपये था। इनमें बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 28 लाख करोड़ रुपये थी। इनमें आवास ऋण टॉप-अप लोन कितना है? हम इस बारे में नहीं जानते हैं। अलग-अलग ऋणदाता टॉप-अप लोन को अलग-अलग रूप से परिभाषित करते हैं। कुछ वित्तीय संस्थानों के लिए टॉप-अप लोन आवास ऋण से अलग नहीं है और वे दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। कुछ वित्तीय संस्थान टॉप-अप लोन को जायदाद के एवज में दिए ऋण और भविष्य में किराये से होने वाली कमाई के एवज में दिए गए ऋण (मॉर्गेज के तौर पर) के साथ जोड़ देते हैं। मॉर्गेज के लिए पूंजी की आवश्यकता 75 प्रतिशत है जो आवास ऋण के लिए पूंजी की आवश्यकता का लगभग दोगुना है। हालांकि, यह पर्सनल लोन के लिए 125 प्रतिशत पूंजी की आवश्यकता से कम है।

आवास ऋण टॉप-अप लोन पर आरबीआई की पैनी नजर वाजिब है। टॉप-अप लोन पर पाबंदी लगाने के बजाय आरबीआई को उन लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए जो इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं और वित्तीय प्रणाली को जोखिम में डाल रहे हैं।

आपका पक्ष

शिक्षा एवं स्वास्थ्य से मानव विकास

लेख 'मानव विकास को प्राथमिकता जरूरी' समाज की मूलभूत आवश्यकताओं पर गहन चर्चा और चिंतन करता है। वर्तमान में चुनावों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक दलों में कोई गंभीर संवाद नहीं है जो चिंता का विषय है। शिक्षा ही मानव विकास की संजीवनी है लेकिन दिक्कत यह है कि स्कूली और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान सबसे कम है। सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। यह स्वागतयोग्य है कि बहुत नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज खुले हैं लेकिन स्कूली शिक्षा का शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तो इन प्रतिष्ठित और उन्नत संस्थानों में पढ़ने योग्य छात्र कहां से मिलेंगे? नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में बहुत अनावश्यक देरी हुई है और यहां तक कि कुछ राज्यों में इसका विरोध भी है। नई शिक्षा नीति का मुख्य आकर्षण भी रोजगार परक शिक्षा है। स्वरोजगार एवं उद्यम कौशल से प्रशिक्षित युवा शिक्षा के बाद नौकरियां तलाशने के बजाय अपने उद्यम लगा सकेंगे और इस तरह देश की समृद्धि और अपने सुंदर भविष्य के वाहक बन सकेंगे। आज अमेरिका, कनाडा, रूस और यूरोप के युवा विदेश में जाकर नौकरियां नहीं ढूंढते और अपने ही देश की समृद्धि के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं और हमारे युवा अपना देश छोड़कर उन्हीं देशों की समृद्धि बढ़ाने के लिए चले जाते हैं जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हमें इसे ब्रेन गेन में बदलना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत और सशक्त बनाने की जरूरत है जबकि शहरी क्षेत्रों में छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में निवेश करने के बजाय जिला अस्पतालों को उन्नत और सर्वसुविधायुक्त बनाना चाहिए। सभी कॉरपोरेट और बड़े अस्पतालों में गरीब रोगियों के लिए एक-दो डॉक्टर उपलब्ध रहें तो सरकार के बिना खर्च के अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

रांची स्थित एक स्कूल की छात्राओं ने लोक सभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए रविवार को जागरूकता अभियान चलाया

पृथ्वी का संरक्षण जरूरी

अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने 1970 में पृथ्वी संरक्षण के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस को अमेरिका ट्री डे के रूप में मनाता है। अब 1970 से बहुत से देशों में हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आज जिस तरह पूरा विश्व ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे से चिंतत हैं, उसके लिए तो रोजाना ही पृथ्वी दिवस मनाया जाना चाहिए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। सड़कों का विस्तार करने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। जहां कभी हरे भरे खेत होते थे या फिर वृक्षों की ठंडी छांव होती थी वहां अब कई भवन या फिर औद्योगिक इकाइयां बन गई हैं। आज पृथ्वी पर जल और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी को सही सलामत रखने और इसे हर तरह के प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धरती पर लगभग 3,00,000 वनस्पति और जीव-जंतु हैं लेकिन इनमें से बहुत से जीव-जंतु लुप्त हो गए और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2,550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर उनको पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 22 अप्रैल 2024

ज़रूरी हैं बदलाव

देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रस्तावित आमूल बदलाव को उस समय काफी ताकत मिली, जब शनिवार को CJI डी वाय चंद्रचूड़ ने उसे युगांतकारी बताया। इस बदलाव का मुख्य वाहक बन रहे तीन कानून- भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और इस साल एक जुलाई से लागू होने वाले हैं। CJI के बयान की अहमियत इस मायने में है कि प्रस्तावित बदलावों को लेकर समाज के कुछ हिस्सों में कुछ आशंकाओं के भी संकेत मिलते रहे हैं।

क्रिमिनल लॉज का कायापलट

ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल | इन्हीं आशंकाओं का एक रूप साल के शुरू में ट्रक ड्राइवरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में सामने आया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना था कि ड्राइवरों ने अपनी पहल पर काम बंद किया है और इसके पीछे प्रस्तावित नए कानूनों के तहत हिट एंड रन मामलों के लिए किए गए सख्त प्रावधानों के दुरुपयोग का डर है। सरकार उस डर को निराधार बता रही थी। फिर भी उसने आश्वासन दिया कि इससे संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को उनसे विचार-विमर्श के बाद ही लागू किया जाएगा। 1 जुलाई से तीनों कानूनों के बाकी प्रावधान लागू हो जाएंगे, लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधानों के अमल पर रोक लगी रहेगी।

आशंकाओं को परखने की जरूरत | जब भी कोई बड़ा बदलाव लाया जाता है तो उसे लेकर शंकाएं-आशंकाएं होती ही हैं। इन आशंकाओं को सही नजरिए के साथ परखने की जरूरत होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो CJI का ताजा बयान जहां बदलते दौर की जरूरतों के मद्देनजर प्रस्तावित बदलावों की अहमियत को रेखांकित करता है, वहीं यह भी बताता है कि इन बदलावों के पीछे जो मकसद हैं, वे अपने आप हासिल नहीं हो जाएंगे। उसके लिए कई स्तरों पर समानांतर प्रयास चलाए जाने की जरूरत है।

तकनीकी विकास का फायदा | असल जरूरत यह समझने की है कि जब समाज और हमारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो रहा हो तब हम पुराने कानूनों से चिपके रहते हुए काम नहीं चला सकते। प्रस्तावित तीनों कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उस तरह के बदलाव लाने वाले हैं, जिनकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-विजुअल रेकॉर्डिंग की बात हो या क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी की - जांच और न्याय प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित करने वाले इन उपायों का विरोध करने की कोई सुसंगत वजह नहीं दिखती।

संवेदनशीलता की शर्त | मगर ऐसे बदलावों के दुरुपयोग की आशंकाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। जाहिर है, ऐसे में खुले दिल-दिमाग के साथ सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ना ही सबसे सही विकल्प है। हां, नागरिक अधिकारों और डेटा सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता इसकी अनिवार्य शर्त होनी चाहिए।

चक्र-व्यू

बोलती बंद पान

राहुल पाण्डेय

नब्बे के दशक की शुरुआत में देहरादून पहुंचा तो पता चला कि यहां बोलती बंद पान मिलता है। पहले तो मुझे लगा कि इसमें शायद कत्थे में ऐसा किवाम डाला जाता होगा, जिससे जीभ लड़खड़ा जाती होगी। या फिर लौंग का कोई सत डाला जाता होगा। ज्यादा लौंग खाने वाले कभी-कभी तुतलाने लगते हैं। पान का पत्ता एनेस्थीसिया का काम करता है, तो लौंग भी पीछे नहीं। किसी का दांत दर्द करता है तो लौंग का तेल लगाने की सलाह मिलती है, क्योंकि लौंग में भी एनेस्थीसिया वाले गुण होते हैं। कई लोगों को मैंने दांत दर्द में उसी दांत की ओर पान का बीड़ा दबाते भी देखा है। आयुर्वेद में भी दोनों को दर्द-निवारक बताया गया है, लेकिन दोनों दर्द भुलावक हैं, निवारक नहीं। निवारक तो उसे कहेंगे, जिससे परमानेंट निवारण मिल जाए। पान और लौंग, दोनों का असर जाते ही दर्द वापस आ जाता है।

बोलती बंद पान के बड़े बखान के बाद आखिरकार एक रात उससे मुलाकात हो ही गई। पता चला कि उसमें ढेर सारा मेवा भरकर उसकी साइज काफी बड़ी कर दी गई थी। इसके चलते पान मुंह में जाते ही न सांस भरने की जगह रह जाए, ना आवाज निकालने की। दुनिया भर के पान रसियाओं के मुंह से गूं-गूं की आवाज तब निकलनी शुरू होती है, जब गाल में गिलौरी सेट हो जाती है, और मुंह रस से सराबोर हो जाता है। मगर यहां तो गिलौरी सेट होने की कौन कहे, गिलौरी मुंह में जाते ही इंसान गूंगा बन जाए। इसे गिलौरी कहना स्वयं गिलौरी का अपमान होगा। यह गिलौरा था बल्कि गिलौरा से भी बड़ा अगर कुछ होता हो, तो वो था। वहां सब इसकी बड़ी तारीफ करते तो जल-भुनकर मैं कहता कि यह पान नहीं, पान का अपमान है। अब देहरादून जैसे शहर में तो वैसे ही पान खाने वाले कम हैं, और जो हैं, उन्होंने भी कभी गिलौरी का मान रखने के लिए पत्ता तक नहीं टरकाया। हमारे फैजाबाद में क्या मजाल कि कोई ऐसा पान लगा दे। लगा दे तो उसे चूना मिलाकर वो-वो बातें सुनने को मिलेंगी पान और कान, दोनों में खून उतर आए।

गिलौरी तो वो होती है, जो गाल में जाकर यूं सेट हो जाए, जैसे स्त्री के कान में बाली और पैर में पायल। धीमे-धीमे छनछनाती है, हौले-हौले रस बाहर आता है। रस पहले गाल, फिर गला और फिर आत्मा तर कर देता है। जिस तरह से कान में टायर और पैर में घंटाघर नहीं पहना जा सकता, उसी तरह से वह पान भी शास्त्रहीन समझा जाता है, जो मुंह को इतना भर दे कि रस तो दूर, हवा की ही जगह न रहे। जो कहते हैं कि पान खाया करो गुलफाम, जुबान काबू में रहा करेगी, वो ऐसे बोलती बंद अपमान के लिए नहीं कहते। वो उसी गिलौरी के लिए कहते हैं, जो दाहिने से बाएं गाल तक कथक करके इंसान की जुबान को सम्मोहित कर दे। एक दिन मैंने उस बोलती बंद पनवाड़ी से पूछा कि पान का ऐसा अपमान करने की हिम्मत तुममें आती कहां से है? वह बोला, हम क्या करें? यहां के पान रसिया इसी को पान समझते हैं!

एकदा

तुकाराम की करुणा

17वीं शताब्दी में एक महान संत कवि हुए संत तुकाराम। उन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में समानता, श्रद्धा और करुणा का संदेश फैलाया। एक बार संत तुकाराम के घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से कुछ कीमती सामान चुरा ले गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव वालों ने चोर को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। आसपास के गांवों में भी बात फैल गई। कुछ समय बाद चोर को पकड़ लिया गया। गांव वाले चोर को तुकाराम के सामने लाए। तुकाराम ने उसे अपने पास बुलाकर प्यार से पूछा, 'भाई, तुमने यह चोरी क्यों की?' चोर ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया कि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसे चाहिए थे। तुकाराम की आंखें भर आईं। उन्होंने न केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि कुछ पैसे भी दिए और कहा, 'भाई, आगे से चोरी मत करना। मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालो।' इसके बाद चोर तो से वहां से चला गया पर आसपास मौजूद लोगों ने उनसे कहा, 'तुकोबा, उसने चोरी की थी, बिना सजा के उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। आपने उलटे उसे पैसे देकर उसका हौसला बढ़ाया। इससे तो चोरी को बढ़ावा मिल सकता है।' संत तुकाराम ने समझाया, 'अपनी गलती स्वीकार करने में उसने थोड़ा भी समय नहीं लगाया। वह मजबूर था, इसलिए उसने चोरी की थी। हो सकता है, दंड पा लेने के बाद उसे मलाल नहीं होता। पर यह शर्मिंदगी उसके साथ बनी रहेगी। देखना वह कभी चोरी नहीं करेगा।' लोगों को तुकाराम की बात समझ में आ गई। संत तुकाराम का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपने मन से क्रोध, घृणा और बदले की भावना को निकाल देना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए।

Subrata Dhar

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

लोकसभा चुनाव में संविधान में कथित बदलाव को लेकर छिड़ी बहस कितना बड़ा मुद्दा

BJP संविधान नहीं बदलेगी, मान लीजिए

स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर

क्या लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद BJP धर्मनिरपेक्षता को छोड़ने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में बदलाव करेगी? बहुत ज्यादा संभावना है कि नहीं। इस देश का स्वरूप पहले से ऐसा है, जिसे बहुत लोग हिंदू स्टेट कहते हैं। साथ ही, औपचारिक रूप से यह धर्मनिरपेक्षता पर भी कायम है। ऐसे में उस फॉर्म्युले को क्यों छोड़ा जाए, जो व्यावहारिक राजनीति में सफल हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारगर साबित हो सकता है।

अनंत विवाद | जब से BJP सांसद अनंत हेगड़े ने कहा है कि अगर पार्टी 400 सीटें जीतेगी तो संविधान बदल देगी, तब से पार्टी बैकफुट पर है। BJP ने खुद को हेगड़े के बयान से अलग कर लिया है, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि मामला तो अब खुल चुका है। विपक्ष ने आगाह किया है कि BJP न केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकती है, बल्कि नौकरियों में आरक्षण को भी खत्म कर सकती है।

मोदी का बचाव | बिहार के गया में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, 'कांग्रेस ने यह बात फैलाई कि अगर BJP सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी या BJP की तो बात ही क्या करें, संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते। इसलिए उन्हें झूठ फैलाना बंद कर देना चाहिए।'

संविधान दिवस की दुहाई | मोदी ने जनता को याद दिलाया कि BJP ने संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति अपने आदर को दर्शाते हुए संविधान दिवस की स्थापना की थी। वैसे, संविधान को कभी न बदलने का उनका बयान अजीब था क्योंकि BJP दावा करती है कि उसने संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है।

संशोधन ही संशोधन | BJP के नेतृत्व वाले NDA ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कम से कम 22 बार संविधान में संशोधन किया है। 76 बरसों में 106 संशोधनों के साथ भारत का संविधान शायद दुनिया में सबसे अधिक संशोधित संविधान है। संविधान में संशोधन से अधिक सामान्य कुछ भी नहीं। कांग्रेस और BJP ने साल में औसतन एक से अधिक बार ऐसा किया।

संविधान संशोधन आम
- औसतन साल में एक से ज्यादा संशोधन
- कांग्रेस, BJP दोनों के राज में संशोधन
- BJP के संविधान में भी है सेकुलरिज्म

विपक्ष का समर्थन | वाजपेयी के दौर में NDA ने 79 से 92 तक, 14 संवैधानिक संशोधन लागू किए। वहीं, मोदी ने 99 से लेकर 106 तक, 8 संशोधन लागू किए हैं। चूंकि संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई और राज्य सरकारों के बहुमत की मंजूरी चाहिए होती है, इसलिए इन संशोधनों को विपक्षी दलों के बहुमत का समर्थन प्राप्त था। विपक्ष के बहुमत बिना NDA के पास जरूरी संख्याबल नहीं होता। राजनीतिक सर्वसम्मति से संवैधानिक संशोधन नियमित रूप से होते रहते हैं।

अटल बदलाव | वाजपेयी के वक्त जो संशोधन हुए, उनमें 10वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्यों के साथ सभी केंद्रीय करों को एकत्रित करना और साझा करना, दलबदल को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर राष्ट्रीय आयोग को विभाजित करना, वेकेंसी के बैकलॉग को भरने में SC/ST आरक्षण की रक्षा करना, पदोन्नति में SC/ST के उम्मीदवारों के लिए qualifying marks में छूट देना और शिक्षा के अधिकार को 14 वर्ष तक के बच्चों तक बढ़ाना शामिल था। इसके अलावा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया। सबसे रूटीन संशोधन है SC/ST रिजर्वेशन को बढ़ाना। जब भी इसकी मियाद खत्म होने वाली होती है, तो इसे बढ़ा दिया जाता है।

Madhu Kumre

नागपुर में संविधान दिवस के मौके पर संविधान की प्रस्तावना के साथ बच्चे (फाइल फोटो)

मोदी का दौर | नरेंद्र मोदी के समय जो संशोधन हुए उनमें शामिल है- GST की शुरुआत, भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनों का आदान-प्रदान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक पदों में 10% आरक्षण, महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करना।

बात का मतलब | संशोधनों के इतने लंबे इतिहास को देखते हुए आखिरकार मोदी ने गया में क्यों कहा कि संविधान को बदला नहीं जा सकता? शायद उनका आशय यह था कि आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये दोनों संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता।

मन की चाहत | जिस पार्टी के ट्रोल सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं और हिंदू राज्य की वकालत कर रहे हैं, क्या उसके लिए यह स्पष्टीकरण बहुत उदार है? क्या BJP के लिए औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्षता को त्याग देना महज वक्त की बात है? पार्टी के भीतर बहुत से लोग ऐसा चाहते होंगे, लेकिन कई लोग धर्मनिरपेक्षता के चोगे के साथ एक वास्तविक हिंदू स्टेट पाकर खुश हैं।

BJP का संविधान | Amnesty International के पूर्व प्रमुख आकार पटेल BJP के कट्टर विरोधी हैं। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके संगठन को बंद करा दिया था। लेकिन, अपनी किताब 'Our Hindu Rashtra' में उन्होंने खुलासा किया कि BJP के सदस्यता फॉर्म में एक प्रतिज्ञा भरनी होती है। यह प्रतिज्ञा है, 'मैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन करता हूं, जो धर्म पर आधारित नहीं है।' यहां तक कि BJP का अपना पार्टी संविधान 'कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने' का वादा करता है।

फायदे की बात | अगर BJP ने धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करने और हिंदू स्टेट बनाने के लिए अपनी पार्टी के संविधान में संशोधन नहीं किया है, तो क्या वह भारतीय संविधान में संशोधन करेगी? मुझे नहीं लगता।

जीवन को खूबसूरत बना देती है सलून की कुर्सी

Salon

AI Image

जीवन आनंद

छब्बू की जानकारी वाली दुनिया बहुत सरल थी। वह कभी बनारस के पश्चिम में प्रयागराज से आगे और पूरब में बिहार के गया से पीछे नहीं गए। पढ़े वह थे नहीं और इटैलियन रेस्तरां तब बनारस में खुले नहीं थे। ऐसे में उन्होंने कभी इटली का नाम तक नहीं सुना था। इससे जाहिर है कि वह जिस तरह चौराहे पर, सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे लोगों के दाढ़ी-बाल बनाते उसे 'इटैलियन सलून' नाम उन्होंने तो दिया नहीं था। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बैठने वाली जगह को यह नाम मिला हुआ है। वह रोज सुबह टीन का अपना बक्सा लेकर, जिसमें एक नाई के सारे हथियार मौजूद होते, अपनी जगह पहुंच जाते।

धूप कड़ी होती तो दो ईंटों के बीच में फंसाकर काले रंग का बड़ा वाला छाता लगा देते, ताकि ग्राहक को थोड़ी ओट हो जाए। शेविंग करनी होती, तो ग्राहक को ईंट पर बैठाते और अगर बाल काटना होता, तो खुद ईंट पर बैठते। शीशा ग्राहक को खुद पकड़ना होता था। सीटों वाले सलून आम होने के पहले खूब दबदबा था ऐसे 'इटैलियन सलून' का। काशी से लेकर कोलकाता तक, कुछ ऐसे सलून आज भी मिल जाएंगे।

छब्बू अब दुनिया में नहीं रहे। उनका 'इटैलियन सलून' भी अब नहीं है। सड़क चौड़ी होने के बाद वहां फुटपाथ बन चुका है। उसी बाजार में अब कई सारे सलून खुल चुके हैं, एसी वाले। जमाना बदल गया है, लेकिन आनंद जो एक सलून में जाकर मिलता है, वह अब भी पुराना वाला ही है। इनका इतना गहरा असर होता है हम पर कि खाने के लिए भले नए रेस्तरां में चले जाएं, कपड़े किसी भी दुकान से खरीद लें, लेकिन भरसक कोशिश होती है कि सलून पुराना वाला ही हो। यह रिश्ता बनते-बनते बनता है।

आखिर जिस उस्तरे के सामने सिर झुकाना है, उस पर यकीन पहली बार में आएगा कैसे! लेकिन यह भी है कि जब भरोसा जम जाता है, तो कोई शंका नहीं रह जाती। फिर चाहे जितनी लंबी वेटिंग हो, इंतजार करना गवारा होता है, सलून बदलना नहीं। और जब शहर छूटता है, तो नई जगह वीकेंड पर पहली तलाश किसी अच्छे सलून की ही होती है।

वैसे अचरज हो सकता है कि पश्चिम में जब पहले-पहल सलून खुला, तो उसका दाढ़ी-बाल से कोई कनेक्शन नहीं था। ये जगहें समाज के संभ्रांत लोगों के रिलैक्स होने की थीं। जहां लोग पीते-पिलाते, दांव लगाते। रोल बदल चुका है, लेकिन देखा जाए तो रिलैक्स लोगों को सलून आज भी कराते हैं। इनकी कुर्सी पर बैठते ही तनाव गायब हो जाता है कुछ देर के लिए। जब सिर पर पानी की फुहारें पड़ती हैं, तो बाहर मौसम कितना भी गर्म हो, अंदर माहौल सुहाना ही बनता है। फिर शुरू होती है कैंची की धुन। कैंची चलती है और सीट पर बैठे शख्स में यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि इस काट-छांट के बाद वह और निखरकर निकलेगा। तब सलून की वह कुर्सी और आरामदायक लगने लगती है। बंदा खास समझने लगता है खुद को। सलून पर्सनैलिटी में चार चांद ही नहीं लगाते, बल्कि उसे वाकई बदलकर रख देते हैं। इनमें जाना और दाढ़ी-बाल पर खर्च किया हर पैसा एक तरह का निवेश है। इसका रिटर्न मिलता है कॉन्फिडेंस, लुक और खुशियों के रूप में।

सलून सिखाता है भरोसा करना। एक बार सीट पर बैठने के बाद हम अपने को पूरी तरह सामने वाले के हवाले कर देते हैं। अपने को छोड़ देते हैं उस पर, कि वह जो कर रहा है बेहतर ही होगा। एक बार जब यह रिश्ता पुराना हो जाता है, तो फिर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हम चाहते क्या हैं। बालों की हालत देख समझ जाता है सलून वाला और तमाम बातें इशारों में होने लगती हैं। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि जब आप सही हेयरड्रेसर से मिलते हैं, तो दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है। और खूबसूरती का यह काम हमारी उम्मीद से भी पुराना है।

करीब 30 हजार साल पुरानी Venus of Willendorf में मूर्ति के बाल स्टाइलिश ढंग से बंधे नजर आ रहे हैं। यानी जब यूरोप पत्थर युग में था, तब भी खास ख्याल रखा जाता था बालों का। उस वक्त आज जैसे सलून तो होंगे नहीं, 'इटैलियन' वाले भी नहीं, लेकिन तय है कि जैसे भी सलून रहे हों और उनका जो भी नाम रहा हो, उनमें आनंद वही आता होगा जो आज आता है।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

क्या हमारी किस्मत में अमर होना लिखा है

संजय खाती

सदियों से इंसान मौत को जीतने का सपना देखता रहा है। अमरता की यह तलाश आखिरी दौर में पहुंच गई लगती है। मार्क ओ'कॉनेल की किताब **'To be a machine'** (प्रकाशक : डबलडे) इस अजब खोज की दिलचस्प दास्तान है।

'जब मैं 8 साल की थी, मेरी दादी हमारे घर आईं। मुझे याद है मैं उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वह दौड़ ही नहीं सकती थीं। तब मुझे एहसास हुआ उनके शरीर में कुछ है जो टूट चुका है। मैंने सोचा जरूर कोई मेरी दादी की बीमारी को ठीक करने पर काम कर रहा होगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेरी दादी को हुआ है, उसे बीमारी नहीं माना जाता। यहां तक कि उसे गलत भी नहीं समझा जाता।'

AI Image

विचार विंडो

लौरा डेमिंग को फिर यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसकी दादी के साथ जो गड़बड़ थी वह इस बात का आखिरी संकेत थी कि जल्द ही उनका वजूद खत्म हो जाएगा। इस हकीकत को समझते ही वह इस खौफ से घिर गईं कि दादी की तरह एक दिन उसके माता-पिता, उसके दोस्त और वह खुद भी नहीं रहेगी। वह तीन दिन तक रोती रहीं। इस तकलीफ ने एक जिद को जन्म दिया। 11 साल की उम्र तक वह ठान चुकी थी कि बुढ़ापे और मौत की समस्या का कोई जवाब खोजेंगी। आज वह बायो-टेक्नॉलजी के इस फील्ड की जानी-मानी रिसर्चर हैं।

यह तलाश ऐसे ही जिद्दी और जुनूनी लोगों से भरी पड़ी है। ओ'कॉनेल यहां हमारी मुलाकात उन सब से कराते हैं। वे जिस यूटोपिया के पीछे दीवाने हैं, उसे ट्रांस ह्यूमनिज्म कहा जाता है और यह लौरा डेमिंग के बायोलॉजिकल उपाय से भी आगे की अजब और औघड़ दुनिया है।

बेसिक आइडिया कुछ इस तरह है- बुढ़ापा और मौत हमारी किस्मत में हैं, क्योंकि हम एक जैविक शरीर के तौर पर रहते हैं। खून और गोश्त के इस शरीर के साथ दुनिया भर की दिक्कतें हैं। अगर हम इस शरीर से छुटकारा पा जाएं, तो बुढ़ापे और मौत से भी मुक्ति मिल सकती है। यहां 'हम' का मतलब है हमारा दिमाग, जो हमारी चेतना और बुद्धि का घर है। यानी शरीर से मुक्ति का असल मतलब है चेतना और बुद्धि (माइंड) के इस जैविक दिमाग (ब्रेन) से आजादी।

यह काम दो स्तरों पर चल रहा है। एक फौज उन ट्रांस ह्यूमनिस्ट की है, जो साइबोर्ग के आइडिया पर काम कर रहे हैं। यानी इंसान और मशीन को मिलाकर ऐसा कुछ करना कि जैविक शरीर धीरे-धीरे मशीन में बदल जाए। इन लोगों का कहना है कि वैसे भी हम साइबोर्ग बनते जा रहे हैं और मशीनें हमारी जिंदगी में घुस चुकी हैं, जैसे कि मोबाइल फोन।

ओ'कॉनेल यहां ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो खुद ही अपने शरीर में चिप फिट करने का जानलेवा ऑपरेशन कर रहे हैं। ओ'कोनेल हमें उन प्रयोगशालाओं और नाइट्रोजन सिलिंडरों तक भी ले जाते हैं, जहां भविष्य की तैयारी चल रही है। यह ट्रांस ह्यूमनिज्म का दूसरा मोर्चा है, जहां माइंड को सॉफ्टवेयर में बदलने की जुगत की जा रही है।

पूरे शरीर या दिमाग संभाल कर रखे जा रहे हैं, ताकि तकनीक हासिल हो जाने पर भविष्य में उन्हें फिर से जिंदा किया जा सके। या कम से कम इतना हो कि माइंड को पूरा पढ़कर कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए। चेतना और बुद्धि से बने माइंड को किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बदल देने की कल्पना सिर्फ शरीर से आजादी तक सीमित नहीं है। यह आजादी है किसी भी मीडियम से परे चले जाने की। कल्पना कीजिए ऐसी चेतना की, जिसमें शरीर का कोई एहसास ही न हो। ऐसा अशरीरी अस्तित्व कैसा होगा? हवा की तरह? बादल की तरह? या कुछ भी नहीं और सब कुछ की तरह?

जब बात इस स्तर पर चली जाती है, तो अध्यात्म की छाया साफ उतर आती है। यह अमृत की प्यास, देह से परे चले जाने की अलौकिकता- यही तो शाश्वत आत्मा की अवधारणा हमारे भीतर नए रूप में करवट ले रही है। बुढ़ापे और मौत से अगर इंसान जीत गया तो इससे बड़ी जीत और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन इस आइडिया में कुछ है जो असहज करता है। इस पूरे किस्से में ओ'कॉनेल लगातार इस दुविधा से जूझते रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। क्या मशीन में बदलने वाला इंसान इंसान नहीं रह जाएगा?

करियर को नई उड़ान

प्रणव प्रियदर्शी

अमेरिका की मल्टिनैशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनैंशल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली के भारत स्थित ग्लोबल कपैबिलिटी सेंटर से जुड़ी हैं हेमा राधाकृष्ण। वह इंस्टिट्यूशनल सिक्यॉरिटीज टेक की एक्जिक्युटिव डायरेक्टर हैं। उनका करियर इस मायने में खास कहा जाएगा कि उन्होंने शुरू में ही दुनिया की बड़ी कंपनियों में और अलग-अलग देशों में काम कर लिया। जर्मनी में वह सीमेंस में थीं। उसके बाद नीदरलैंड्स, अमेरिका, पोलैंड और ब्रिटेन में भी काम किया। कह सकते हैं कि शुरुआती फेज में ही वह करियर की उस ऊंचाई पर पहुंच गईं जो किसी आम हिंदुस्तानी लड़की का सपना होता है। लेकिन फिर जो बेड़ियां आम हिंदुस्तानी लड़की के पैरों में पड़ी होती हैं, जो उसे एक हद से ज्यादा दूर नहीं जाने देतीं या एक सीमा से अधिक रफ्तार नहीं हासिल करने देतीं, उन भावनात्मक बेड़ियों ने हेमा को भी अपनी मौजूदगी का अहसास कराया। नतीजा यह कि 2012 में हेमा अपने देश लौट आईं। अगले 10 साल उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्ग होते मां-बाप और सास-ससुर के नाम कर दिए। मगर खास बात यह रही कि फॉरेन पोस्टिंग को बाय-बाय करने और एक तरह से करियर संबंधी एंबिशन को प्राथमिकता में नीचे लाने के बाद भी हेमा ने टेक्नॉलजी के अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। यहां वह दो अलग-अलग टेक स्टार्टअप से जुड़कर काम करती रहीं। जब पर्सनल लाइफ में हालात बदले तो उनके सामने इस बात को लेकर कोई दुविधा नहीं थी कि फुलटाइम कॉरपोरेट वर्क की पुरानी स्थिति में वापस जाना है। लेकिन वह जानती थीं कि यह आसान नहीं है। लेटरल हायरिंग में रिक्रूटमेंट प्रॉसेस की जो बाधाएं थीं उन्हें पार करना मुश्किल साबित हो रहा था। उसी समय मॉर्गन स्टैनली का रिटर्न टु वर्क प्रोग्रैम आया और हेमा ने उस अवसर को लपकने में देर नहीं की। इस कार्यक्रम ने हेमा के लिए वर्कफोर्स में वापसी का एक नॉन जजमेंटल रास्ता खोला। इस प्रोग्रैम के पीछे की मेच्योर सोच कह लीजिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रासंगिक जानकारी के मोर्चे पर हेमा की कमजोरियों और करियर के दस साल लंबे ब्रेक को नजरअंदाज करते हुए उनके कौशल, उनकी क्षमता और उनमें निहित संभावनाओं को तवज्जो दी गई। नतीजा यह कि हेमा के करियर को एक नई उड़ान का मौका मिल गया और इंडस्ट्री को उनके एक्सपीरिएंस, विजन तथा लीडरशिप एबिलिटी का फायदा।

हेमा राधाकृष्ण

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

नई भाषा, नई सीख

'जीवन आनंद' कॉलम में 15 अप्रैल को प्रकाशित लेख 'भाषा बदलने से दुनिया बदल जाएगी, क्यों कहते हैं ऐसा' पढ़ा। असल में भाषा विचारों के आदान-प्रदान करने का भी तरीका है। हम दूसरी भाषा को सीखकर दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों से साझा कर सकते है। अपनी भाषा का ज्ञान होना तो जरूरी है ही, दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान हो तो और भी अच्छा। भारत में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी सहित कई भाषाएं हैं। पूरे देश के विचारों को समझने के लिए ये भाषाएं बेहतर माध्यम बन सकती हैं। नई भाषा सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और नई संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है।

पैंथर तोमर, किशन गंज

ऐसी बानी बोलिए

यह पत्र 15 अप्रैल के लेख 'भाषा बदलने से दुनिया बदल जाएगी, क्यों कहते हैं ऐसा' से संबंधित है। संत कबीर ने कहा है- ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, ताकि हमारे कहे का उद्देश्य पूरा हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों के दिल में अपने लिए सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और महापुरुष भी हमें प्यार की भाषा बोलने की शिक्षा देते हैं। यहां तक यह भी कहा जाता है कि एक चुप, सौ सुख। हमें हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे बोलनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

जीवन आनंद

सरसराती हुई हवा

खुशी का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति के लिए खुशी के स्रोत अलग-अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि खुशियां बड़ी उपलब्धि से ही मिलती हों। छोटी-छोटी बातों को अपने जीवन में शामिल करके भी जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। सुबह की सैर तो दिनचर्या का एक हिस्सा है, लेकिन सुबह-सुबह की ताजी हवा जब हमारे तन को सहलाते हुए गुजरती है, तो मन और शरीर ताजगी से भर जाता है। कल्पना कीजिए, गर्मी के दिनों में पसीने से आप सराबोर हों और अचानक हवा का एक झोंका सरसरा कर गुजर जाए, तो वह कितना सुख देता है।

प्रवीण राणा, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

इलॉन मस्क नहीं आ रहे भारत, टल गया दौरा – एक खबर
– लगता है कि टेस्ला को हमारी सड़कें रास नहीं आईं!

गणेश मंडल

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

आकाश के साक्षी हो पाते हैं space scientists?

सुरक्षित गोस्वामी

कभी अमावस्या की रात छत पर जाकर आकाश को देखें तो आपको चारों तरफ टिमटिमाते हुए लाखों तारे दिखाई देंगे, और आकाश की विशालता का अनुभव होगा। दिन में सूरज की रोशनी आकाश के इस विराट स्वरूप का वैसा अनुभव नहीं होने देती। आकाश की इस विशालता को हम जब साक्षी भाव से देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे हम उस विराट का ही हिस्सा हैं और इस विश्व का साक्षी हैं।

केवल आकाश को ही नहीं, बल्कि जब किसी ऊंची पहाड़ी या समुद्र के किनारे खड़े होकर दूर तक का नजारा देखते हैं, तब भी हम अपने आप को साक्षी पाते हैं। उस समय हम अकर्ता और दृष्टा होकर विश्व के साक्षी हो जाते हैं। विश्व साक्षी होना सभी के लिए सहज बात है, क्योंकि साक्षी भाव हमारा वास्तविक स्वरूप है। विशालता के प्रति एक छोटा बच्चा जितना साक्षी होता है, उतना ही एक जवान और एक बुजुर्ग भी होता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ कोई छोटी सी चीज, जिसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाए, उसका साक्षी होना कठिन होता है।

विराट आकाश का साक्षी होना आसान है, इसलिए हम अपने घर-परिवार और संबंधों में साक्षी नहीं हो पाते। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम अपनी housing society में walk करें तो society के सभी 300 flat के एक साथ साक्षी हो जाते हैं। लेकिन अपने flat के अंदर जाते ही flat से साक्षी भाव छूट जाता है। इसका अर्थ है कि जहां कर्तापन है वहां साक्षी भाव छूट जाता है। अष्टावक्र ने गीता में विश्व साक्षी की जो बात कही है वह यही है कि आप क्षुद्र से लेकर विराट तक समान रूप से सभी के साक्षी हो जाएं। यानी साक्षी होने का भाव।

छोटा बच्चा जब अपने शरीर को देखता है तब वह उसका साक्षी होता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसमें अपने शरीर के प्रति लगाव आ जाता है, जिससे उसका साक्षी भाव छूट जाता है। आसक्ति और कर्तापन साक्षी भाव को समाप्त कर देते हैं। आकाश के प्रति हमारा कर्तापन नहीं रहता, इसलिए हम आकाश को साक्षी हो कर देख पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अकर्तापन ही साक्षी भाव प्रकट करता है।

जब एक space scientist आकाश में rocket ले जाता है, तब वह आकाश में कुछ करने लगता है। rocket के प्रति लगाव के कारण उसका आकाश के प्रति अकर्ता भाव छूट जाता है। अब वह विश्व साक्षी नहीं रह पाता। ऐसे ही जब हम बादलों में cloud seeding करते हैं, तब भी हम बादलों में जाकर कुछ करते हैं और कर्ता बन जाते हैं, तब हम उसके साक्षी नहीं रह पाते। यह बात नहीं कि हमें cloud seeding नहीं करनी है या space में rocket नहीं लेकर जाना है।

बात बस इतनी ही है कि हम आकाश के प्रति अपने साक्षी भाव को न छोड़ें, तब अपने भीतर की विशालता को अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा कर्तापन हमें हमारी विशालता से हटा देगा। यदि हम साक्षी भाव से space के लिए कार्य करें तो और बेहतर तरीके से हम space में काम कर सकेंगे। लेकिन यदि कर्ताभाव से space में कार्य करेंगे तो उस विशाल, विराट और अनंत के रहस्य को नहीं जान पाएंगे।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

बेहतर दुनिया

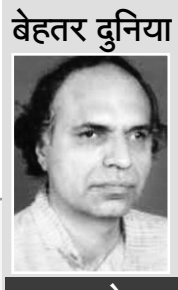

भारत डोगरा

अमन- शांति की बुनियाद मजबूत करें

गाजा में, यूक्रेन में, सुडान में और कितने ही स्थानों पर आज विश्व बुरी तरह हिंसा से त्रस्त है। महाविनाशक हथियारों की ऐसी बहुत खतरनाक होड़ पहले से और तेज हो रही है जो दुनिया को किसी बड़े संकट की ओर ले जाएगी। जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, वे कभी असहाय नजर आते हैं तो कभी केवल चिंता प्रकट करने या बयानबाजी तक ही अपनी जिम्मेदारी को समेट लेते हैं।

इस बिगड़ती स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। उम्मीद की एक किरण हम सब जनसाधारण अपने प्रयासों से भी ला सकते हैं। बेशक, हम जनसाधारण प्रत्यक्ष रूप से बड़े युद्ध समाप्त नहीं कर सकते पर अपने आसपास की हिंसा को समाप्त कर या न्यूनतम कर एक अमन-शांति पर आधारित दुनिया बनाने के लिए अच्छी शुरुआत जरूर कर सकते हैं। दुनिया आखिर करोड़ों परिवारों के मिलने से ही तो बनती है, लाखों समुदायों के मिलने से ही तो बनती है। यदि परिवार और समुदाय स्तर से ही अहिंसक विश्व बनाने की बड़ी पहल हो तो इसका असर दूर तक भी जा सकता है। यदि परिवार और समुदाय के स्तर पर हम अहिंसा की जो सीख प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग आगे, अधिक व्यापक स्तरों पर अमन-शांति के प्रयासों के लिए करते रहें। इस सोच के मूल में यह समझ है कि हिंसा मनुष्य के दुख-दर्द का एक प्रमुख कारण है। हर मनुष्य दुख-दर्द कम करना चाहता है और इसके लिए एक प्रमुख मार्ग यह है कि वह अपने भीतर की हिंसा और अपने आसपास की हिंसा को कम करे। यह मार्ग हम सबको उपलब्ध है, पर फिर भी यह प्रायः उपेक्षित है। यहां तक कि अपने भीतर की हिंसा को एक समस्या के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति भी कम ही नजर आती है। पर वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य के भीतर की हिंसा और आसपास की हिंसा अधिकांश समाजों में एक बड़ी समस्या है। भारत हो या अमेरिका इसकी एक बड़ी अभिव्यक्ति घरेलू हिंसा के बेहद चिंतित करने वाले आंकड़ों में उपलब्ध होती है।

अमेरिका जैसे 'विकसित' समाज में भी एक वर्ष में 110 से 120 लाख व्यक्ति घरेलू हिंसा अपने नजदीकी साथी (इंटीमेट पार्टनर) की हिंसा का शिकार होते हैं (प्रति मिनट 20) और इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। 19 प्रतिशत घरेलू हिंसा की घटनाओं में किसी न किसी हथियार का उपयोग भी होता है। घरेलू हिंसा की बड़ी वारदात को रहने दें तो भी कितने ही दिन जनसाधारण के ऐसे गुजरते हैं जिसमें छोटी-छोटी बातों में, क्रोध के आ जाने से जो कहा-सुनी हो जाती है उसके कारण दिन खराब हो जाता है, दुख भी होता है। हमारे समाज में परिवार में प्रेम और लगाव बहुत है, पर झगड़े भी कम नहीं हैं-फिर चाहे पति-पत्नी के झगड़े हों, भाई-भाई या सास-बहू के। अंत में अधिक सहना तो महिलाओं और बच्चों को ही पड़ता है, जबकि घरेलू हिंसा के दौर में बच्चे जो सहते हैं उसका अहसास भी कई बार व्यस्क सदस्यों को नहीं होता। बाद में मन में आता है कि ओह, क्रोध में हम क्यों नाहक अपने प्रियजनों को परेशान करते हैं और स्वयं भी होते हैं, पर यह सोचने के बाद भी बार-बार ऐसी वारदात होती ही रहती हैं। इसकी वजह यह है कि अपने भीतर की हिंसा को पहचानने और उसे कम करने के जरूरी प्रयास नहीं होते। इसके साथ कहीं न कहीं आधिपत्य की भावना जुड़ी होती है। यह लिंग आधारित हो सकती है (पुरुष द्वारा महिला पर आधिपत्य समझना), आयु-आधारित या धन-संपत्ति आधारित हो सकती है।

वास्तव में अहंकार, क्रोध, आधिपत्य, हिंसा यह सब आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इन के साथ यदि नशे की प्रवृत्ति जुड़ जाए, विशेषकर शराब के नशे की प्रवृत्ति, तो इन सब की अभिव्यक्ति और भयानक रूप में हो सकती है। यदि इस सब को एक गंभीर समस्या के रूप में समझ कर इसे कम करने का प्रयास होगा तो अधिकांश व्यक्तियों और परिवारों में दुख-दर्द, परेशानी, तनाव, अपमान, आहत होने के अहसास और अवसाद में बहुत कमी आ सकती है, तथा दूसरी ओर खुशहाली, परस्पर प्रेम और सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

इस तरह समाज की सबसे छोटी पर बुनियादी इकाई के स्तर पर अहिंसा के प्रयासों को जो सफलता मिलेगी, उसके आधार पर जनसाधारण को, महिलाओं और पुरुषों को, युवाओं और छात्रों को प्रेरित कर समुदाय के स्तर पर अधिक व्यापक भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है। समुदाय में जो धर्म, जाति, लिंग आदि के स्तर पर भेदभाव हैं, वह भी मन के अंदर की हिंसा की एक अभिव्यक्ति है। हिंसा, आधिपत्य, अहंकार के मिले-जुले असर से किसी अन्य मनुष्य को धर्म, जाति के आधार पर हीन भावना से देखा जाता है। धर्म, जाति उप-जाति के आधार पर किसी को हीन मानना या उससे भेदभाव करना बुनियादी तौर पर अनुचित और अन्यायपूर्ण है पर जब सामुदायिक स्तर पर लोगों के दिलों में हिंसा, आधिपत्य और अहंकार की प्रवृत्ति है तो वह इन अनुचित रूपों में प्रकट होती रहती है जिससे अंत में क्षति पूरे समुदाय की ही होती है। जिनसे भेदभाव या अन्याय होता है वे तो आहत ही होते हैं, किन्तु जो अन्याय और भेदभाव करते हैं, वे भी सही मानवीय विकास की संभावनाओं से दूर हो जाते हैं, उनका सही विकास नहीं होता है और वे संकीर्ण विचारों के जाल में फंसे हुए अपने और अपने निकटस्थों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं।

दूसरी ओर अहिंसा और अमन-शांति का संदेश सही ढंग से पूरे समाज में पहुंचता है तो समुदाय के सभी लोगों की उचित न्यायसंगत प्रगति के अवसर बढ़ते हैं, पूरे समुदाय की एकता और मजबूती बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है। इस तरह के सामुदायिक प्रयास पूरे देश में होते हैं तो पूर्ण राष्ट्र की खुशहाली, समता, एकता और प्रगति मजबूत होती है। यह इस रूप में मजबूत होती है कि अपने सभी लोगों में प्यार और सद्भावना बढ़ते ही हैं, पर देश की यह बढ़ती एकता और मजबूती किसी अन्य देश के लिए खतरा नहीं बनती है क्योंकि यह प्रगति मूलतः अमन-शांति और अहिंसा पर आधारित है। इस तरह यदि राष्ट्र की प्रगति होती है तो राष्ट्र की यह क्षमता भी साथ-साथ बढ़ती है कि वह हिंसा से बुरी तरह आहत दुनिया को अमन-शांति की राह दिखा सके। कल्पना कीजिए कि यदि विभिन्न देश इस तरह समाज की छोटी इकाई से ऊपर तक अमन-शांति और अहिंसा के प्रसार का प्रयास निरंतरता से करें तो क्या पूरे विश्व में अमन-शांति की संभावना नहीं बढ़ सकती है? क्या युद्ध की संभावना को न्यूनतम करते हुए विनाशक और महाविनाशक हथियारों की होड़ और दौड़ को भी नहीं रोका जा सकता? यह सब कोरी कल्पना नहीं है, वास्तविक संभावना है। कहा भी गया है, बहुत सी बड़ी

अहिंसा और अमन-शांति का संदेश सही ढंग से पूरे समाज में पहुंचता है तो समुदाय के लोगों की न्यायसंगत प्रगति के अवसर बढ़ते हैं, समुदाय की खुशहाली बढ़ती है। इस तरह के सामुदायिक प्रयास पूरे देश में होते हैं तो पूर्ण राष्ट्र की खुशहाली, समता, एकता और प्रगति मजबूत होती है। इस रूप में कि अपने सभी लोगों में प्यार और सद्भावना बढ़ती ही हैं, पर देश की यह बढ़ती एकता और मजबूती किसी अन्य देश के लिए खतरा नहीं बनती क्योंकि यह प्रगति मूलतः अमन-शांति और अहिंसा पर आधारित है। इस तरह राष्ट्र की प्रगति होती है तो राष्ट्र की यह क्षमता भी साथ-साथ बढ़ती है कि वह हिंसा से आहत दुनिया को अमन-शांति की राह दिखा सके। विभिन्न देश समाज की छोटी इकाई से ऊपर तक अमन-शांति और अहिंसा के प्रसार का प्रयास करें तो क्या विश्व में अमन-शांति की संभावना नहीं बढ़ सकती है

आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नम्बर दो हो गई हैं। सुनीता जी का स्थान, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी ऊपर है। फिर अन्य सांसदों का नीचे रहना स्वाभाविक है। अरविंद जी पॉलिटिक्स बदलने आए थे!

— रंगनाथ सिंह, लेखक/पत्रकार@rangnathsingh_

ताली का मनोविज्ञान

मीडिया

सुधीश पचौरी

ऐसे सीनों को देख लगता है कि हमारी चुनावी राजनीति भी एक प्रकार की 'स्टैंडअप कामेडी' है, और अपने कई नेता टॉप के 'स्टैंडअप कामेडियंस' हैं। जिस तरह 'स्टैंडअप कामेडियन' हर 'आइटम' में एकाध ऐसी पंच लाइन लगाते हैं कि जिसे सुन दर्शक तुरंत ताली मारें। जो जितना ताली पाता है, उतना ही हिट होता है

इन चुनावी दिनों में हम अपने एक मित्र के घर बैठे थे। उनके ड्राईंग रूम में रखे टीवी में एक पॉपूलर खबर चैनल चालू था जो पीएम की एक रैली को लाइव दिखा रहा था। अपने मित्र की देखादेखी हम भी रैली के लाइव प्रसारण को देखने लगे। अचानक पीएम ने कहा, 'अभी तो ये ट्रेलर है...' कि सामने मौजूद अनगिनत श्रोताओं ने ताली मारी। फिर जब पीएम ने 'राम मन्दिर' का जिक्र किया तो ताली पड़ी, जब 'रामनवमी' की बात की तो ताली पड़ी, जब 'शाहजादे' कह कर कटाक्ष किया तो ताली पड़ी।

कुछ देर बाद वही चैनल 'बेलेंस' करने के लिए, विपक्ष के कुछ नेताओं की रैलियों में बोले गए जब ऐसे ही 'कटाक्ष' दिखाने लगा तो लगा तालियों की भी राजनीति होती हैं। उस चैनल ने दिखाया कि जैसे ही एक विपक्षी नेता ने कहा कि मैं युवकों, महिलाओं को हर साल लाख रुपये 'खटाखट खटाखट' पहुंचाऊंगा तो उनके 'खटाखट' वाली बात पर ताली पड़ती दिखी। ऐसे ही जब एक विपक्षी नेता ने कहा कि हमारा राज आने दो हम इनको अंदर कर देंगे तो कुछ पत्रकारों के चेहरे खिले दिखे। ऐसे सीनों को देख लगता है कि हमारी चुनावी राजनीति भी एक प्रकार की 'स्टैंडअप कामेडी' है, और अपने कई नेता टॉप के 'स्टैंडअप कामेडियंस' हैं। जिस तरह 'स्टैंडअप कामेडियन' हर 'आइटम' में एकाध ऐसी पंच लाइन लगाते हैं कि जिसे सुन दर्शक तुरंत ताली मारें। जो जितनी ताली पाता है, उतना ही हिट होता है। लेकिन हमें 'हेटस्पीच' और तालीपूर्ण 'कटाक्ष' में फर्क करना होगा। 'हेटस्पीच' प्रतिक्रिया में 'हेट' पैदा करती है जबकि 'कटाक्ष' मनोरंजन। यों राजनीतिक नेताओं के भाषणों में 'कटाक्ष' के नाम पर 'हेटस्पीच' भी पेल दी जाती है।

हेटस्पीच भी खूब ताली पड़वाती है। लेकिन बेहतरीन 'स्पीच' होती है जो 'हेटस्पीच', 'गाली-गलौज की जगह, मजाहिया कमेंट से विपक्षी को धराशायी करे। यों इस चुनाव से पहले बहुत सी 'हेटस्पीचें' दी जा चुकी हैं जिनकी शिकायतें अदालतों तक गई हैं लेकिन समकालीन चुनाव प्रचार में उतनी मात्रा में 'हेटस्पीचें' नहीं दिखाई दीं। इसका एक कारण 'चुनाव आयोग' की आचार संहिता है तो दूसरा कुछ नेताओं की 'समझदारी' भी है कि टीवी पर दी जाती 'हेटस्पीच' से 'देने वाले' की कमजोरी ही जाहिर होती है, और शायद यह बात भी कई नेताओं की समझ में आ गई है कि जैसी मार कटाक्ष या व्यंग्य करता है वैसी मार 'हेटस्पीच' नहीं करती।

हमारा मानना है कि टीवी और सोशल मीडिया के जमाने में चुनाव प्रचार परंपरागत प्रचार मात्र नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रकार का 'राजनीतिक कामेडी शो' बन चला है। इसीलिए इस चुनाव में कई नेता अपनी राजनीति के 'स्टैंडअप कामेडियन' अधिक नजर आते हैं। भाषणों में ऐसी पंच लाइनें मारते हैं कि जनता आनंदित होकर ताली पीटने लगती है। जो नेता जितनी बार ताली पड़वाता है। उतना ही हिट होता है। मीडिया भी ऐसे 'शोज' को पसंद करता है। इसीलिए मैं चैनलों पर मीडिया कवरेजों में 'तालियां' ढूंढता रहता हूं ताकि मालूम हो कि कौन नेता कितना पॉपूलर है।

स्पष्ट है 'ताली' का भी 'मनोविज्ञान' और 'समाजशास्त्र' होता है। ताली का होना 'जन स्वीकृति' का होना है। नेता से जनता के दिल के तार का मिलना है। ताली का होना बताता है कि नेता ने जो बोला वह जनता के दिल में उतर गया है। नेता भी तालीप्रिय होते हैं। जानते हैं कि उनको ताली न मिली तो वे गए। इसलिए अक्सर ऐसे 'कटाक्षों' का सहारा लेते हैं कि तुरंत 'ताली' मिले। ताली का मतलब है सुनने वाली जनता का 'अप्रूवल' यानी 'जनता की मुहर'। सुनने वाले भी ताली तभी मारते हैं, जब कोई 'कटाक्ष' और 'कमेंट' से उन्हें मजा देता है, उनके दिल की बात कहता है, उसका मनोरंजन करता है।

इस मानी में आजकल के चुनाव 'परफॉरमेंस' की तरह आते हैं, और नेता 'परफॉर्मर' की तरह काम करते हैं ताकि सुनने वाली जनता उनको सराहे, दिल की बात कहने वाला समझे। तेज गरमी में भी जनता अपने नेता को सुनने आती है तो पैसे से नहीं आती। जो पैसा लेकर आती है वो सही वक्त पर ताली नहीं मार सकती। ताली वही जनता मारती है जो नेता के विचार की 'फोलोअर' होती हुई, उसकी 'फैन' हो जाती है क्योंकि वही उसके 'कटाक्ष कमेंट' के मानी समझ सकती है। हमारा मानना है सबसे अधिक ताली लेने वाले नेता मोदी हैं, दूसरे नंबर पर राहुल, तीसरे पर अखिलेश और चौथे पर ममता नजर आती हैं।

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता को लेकर रखा गया प्रस्ताव अमेरिका के वीटो के कारण पारित नहीं हो सका। प्रस्ताव के पक्ष में बारह मत पड़े और केवल अमेरिका ने इसके विरोध में वोट दिया। ब्रिटेन और स्विटजरलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया। जातीय एकजुटता के कारण ब्रिटेन अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता लेकिन स्विटजरलैंड का रवैया विचारणीय है। स्विटजरलैंड आम तौर पर पूरी तरह तटस्थता का रवैया अपनाता रहा है, लेकिन फिलिस्तीन की सदस्यता पर उसका मौन रहना समझ से परे है। इससे यह पता लगता है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद दुनिया में शांति की बजाय युद्ध की भावना बलवती हो रही है। अमेरिका के दबाव में जापान और स्केंडिनेवियाई देशों स्वीडन और नार्वे जैसे देशों ने भी संघर्ष और युद्ध की मनोवृत्ति को अपनी विदेश नीति का मानो हिस्सा बना लिया है।

करीब पैंतीस हजार लोगों की मौत और लाखों लोगों के घायल होने के बावजूद अमेरिका मानवीय रवैया अपनाने की बजाय इस्राइल के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहा है। दो राज्यों (इस्राइल और फिलिस्तीन) की स्थापना के पक्ष में बयानबाजी करने के बावजूद यह जाहिर है कि अमेरिका का सत्ता प्रतिष्ठान इस्राइल की ही तरह स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौर में मतदाताओं के दबाव में बाइडन प्रशासन फिलिस्तीन में मानवीय संकट को लेकर बयानबाजी अवश्य कर रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखता। अमेरिका में फिलिस्तीन के पक्ष में युवा वर्ग और छात्र समुदाय सड़कों पर उतरा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान इसे लगातार नजरअंदाज करता रहा है।

कुछ विश्लेषक आरोप लगाते हैं कि अमेरिका में 'यहूदी लॉबी' हावी है। कोई भी राष्ट्रपति इस लॉबी का विरोध नहीं कर सकता। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के पूरी तरह खिलाफ हैं। निकट भविष्य में कभी फिलिस्तीन पूर्ण एवं स्वतंत्र राज्य बन सकेगा, इसकी संभावना नहीं है। इस बीच, पश्चिम एशिया में संघर्ष के इस मुख्य मुद्दे का समाधान हो सकेगा, इसकी संभावना अभी नहीं है।

ईरान और इस्राइल के बीच संघर्ष ने पश्चिम एशिया के पूरे परिदृश्य को भयावह कर दिया है। चिंता की बात यह है कि अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व अब ईरान-रूस-चीन के शैतानी त्रिगुट की बात कर रहा है। इसमें उत्तर कोरिया को भी शामिल किया जा सकता है जिसके बाद यह शैतानी क्वाड बन जाएगा। एक क्षेत्रीय मुद्दा विश्व नेताओं की लापरवाही के कारण किस तरह विश्वव्यापी अशांति का कारण बन सकता है, इसका यह सटीक उदाहरण है। फिलहाल, ईरान और इस्राइल के बीच अखाड़े में युद्ध का पहला राउंड खत्म हो गया है और दोनों पहलवान सुस्ताने की मुद्रा में हैं। पूरी संभावना है कि पूरे दम-खम के साथ वे फिर अखाड़े में उतरेंगे। विश्व समुदाय दर्शक गैलरी से तब तक तमाशा देखेगा जब तक कि यह भयावह खेल उनके लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं बनता।

हाल के महीनों में रूस ने इस्राइल के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए हैं। उसने इस्राइल के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने तक की मांग की है। वास्तव में रूस इस्राइल से अधिक उसके पैरोकार अमेरिका को निशाना बना रहा है। भारत ने ईरान और इस्राइल के संघर्ष में अपनी संतुलन की नीति को कायम रखा है। जिहादी आतंकवाद का सामना करने वाला भारत इस्राइल का एक स्वाभाविक सहयोगी है, लेकिन साथ ही भारत ग्लोबल साउथ के अन्य देशों की तरह फिलिस्तीन का समर्थक भी है। ईरान के बारे में भी भारत इस्राइल का साथ देने की स्थिति में नहीं है।

ईरान में इस्लामी क्रांति के बावजूद भारत और ईरान एक ही सभ्यागत भू-भाग के हिस्से हैं। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से अरब देशों की तुलना में ईरान हमारे अधिक नजदीक है। साथ ही, मध्य एशिया और रूस तक संपर्क सुविधा के लिहाज से भी ईरान का केंद्रीय महत्त्व है। ईरान में चाबहार बंदरगाह का एक हिस्सा भारत संचालित करता है। अंतरराष्ट्रीय दक्षिण-उत्तर परिवहन गलियारा इसी बंदरगाह पर निर्भर है। अमेरिका यदि चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में प्रतिबंध लगाता है, तो यह भारत के लिए बहुत चिंता की बात होगी।

फिलहाल, ईरान और इस्राइल के बीच अखाड़े में युद्ध का पहला राउंड खत्म हो गया है और दोनों पहलवान सुस्ताने की मुद्रा में हैं। पूरी संभावना है कि फिर पूरे दम-खम के साथ वे अखाड़े में उतरेंगे। विश्व समुदाय दर्शक गैलरी से तब तक तमाशा देखेगा जब तक कि यह भयावह खेल उनके लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं बनता

बुजुर्गों को दें सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा

चर्चा

विनोद के. शाह

कभी संयुक्त परिवार में अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित बुजुर्ग; बदलते जीवन मूल्यों एवं आर्थिक उपार्जन में निर्बलता के कारण उपेक्षित, एकाकी एवं वृद्धाश्रम का जीवन गुजारने को मजबूर हैं। यह समस्या देश के अस्सी फीसद बुजुर्गों की बन चुकी है।

नीति आयोग की 'भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल-प्रतिमान परिकल्पना' शीर्षक से प्रकाशित रपट कहती है कि 2050 में भारत का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग की श्रेणी में होगा। वर्तमान में देश की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.40 करोड़ है, जो 2050 में जनसंख्या का 19.5 फीसद यानी 35 करोड़ होगी।

सामाजिक मूल्यों में हो रहे क्षरण की चुनौती के साथ देश में बुजुर्गों के लिए ससम्मान सुरक्षित भविष्य को तलाशना देश एवं सरकार, दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आर्थिक आवश्यकताओं के लिए देश के 48 फीसद बुजुर्ग पूर्णतः संतानों पर निर्भर हैं। उनके पास आय के संसाधन नहीं हैं। मात्र 34 फीसद बुजुर्ग आबादी को सेवानिवृत्त पेंशन मिलती है। एक सामाजिक आकलन यह भी कहता है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त अस्सी फीसद बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि उनकी संतान परिवार खर्चे के लिए छीन लेती हैं। हावी होती उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण 60 फीसद बुजुर्ग पारिवारिक प्रताड़ना सहने को मजबूर हैं। इनमें से मात्र 30 फीसद ही अत्यधिक प्रताड़ना से तंग आकर पारिवारिक हिंसा की शिकायत दर्ज कराने कानून की चौखट तक पहुंचते हैं।

देश के बुजुर्गों को पारिवारिक परिवेश सहित संस्थागत माहौल में भी दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है। मारपीट, चोट पहुंचाना, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक तंगी के हालात; परिवार या निकटतम व्यक्ति द्वारा पहुंचाने वाली सर्वाधिक घरेलू हिंसा में शामिल है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इन अपराधों को सामान्य अपराध के रूप में ही तवज्जो दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75 फीसद बुजुर्ग पारिवारिक हिंसा के शिकार हैं, लेकिन उन्हें कानूनी संरक्षण तक भी नहीं मिल पाता।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की इंडिया एजिंग रपट 2023 कहती है कि 2046 तक भारत की बुजुर्ग आबादी उसके देश के बच्चों की आबादी के बराबर हो जाएगी। देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है जो परिवार में अधिक तनाव, फासला पैदा करने के साथ ही बुजुर्गों के एकाकीपन में वृद्धि करने वाला बड़ा कारक साबित होगी। सामाजिक मूल्यों में गिरावट देश में बुजुर्गों के भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता खड़ी करती है। अर्थशास्त्र इसमें यह कहकर एक बड़े निवेश की संभावनाओं को टटोल कर इसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाओं वाले सेवा उद्योग का दर्जा भी देता है। बुजुर्गों की मदद के बहाने रोजगार स्थापना के लगभग डेढ़ सौ से अधिक स्टार्टअप्स इस सेवा क्षेत्र में आ चुके हैं। देश में 2023 में बुजुर्ग सेवा सेक्टर के नाम पर रोजगार स्थापित करने के लिए लगभग 210 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। निवेशकों पर गौर करें तो भारत में विकसित होती ओल्डएज होम संस्कृति एवं बुजुर्गों का एकाकीपन, युवाओं का रोजगार तलाश में घर छोड़कर चले जाना एंव पारिवारिक क्लेश इस उद्योग को अवसर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन देश में विकसित हो रहा ओल्डएज होम बाजार देश की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर आघात करता है।

झूठ का सच, सच का झूठ

बतंगड़ बेतुक

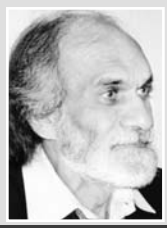

विभांशु दिव्याल

झल्लन बोला, 'ददाजू, जाने क्यों हमें ये बार-बार आभास हो रहा है कि हमारा छोटा सा दिमाग अपना संतुलन बनाए रखने के चक्कर में संतुलन खो रहा है।' हमने कहा, 'झल्लन, ये तो बुरा हो रहा है लेकिन तुझे अपनी इस बीमारी का अहसास क्यों और कब से हो रहा है?' झल्लन बोला, 'दरअसल ददाजू चुनाव के इस मौसम में जो नेता अपने सच होने के जितने बड़े-बड़े दावे करता है वो न जाने क्यों हमें उतना ही बड़ा झूठा लगने लगता है और झूठा-झूठा कह के जिसे जितनी गालियां दी जाती हैं हमें उसमें उतनी ही सच्चाइयां नजर आती हैं। जब हमारे मन में किसी के झूठे होने का भाव उतरता है तो उसका सच सामने उतरने लगता है और जब हमें किसी के सच होने का अहसास होता है तो तुरत ही बगल में झूठ उभरने लगता है। जब झूठ-सच लगने लगे, सच में झूठ दिखने लगे, झूठ और सच का फर्क मिटने लगे, झूठ-सच का यह चक्कर बवंडर बनने लगे, झूठ को सच से अलग करने के चक्कर में दिमाग फटने लगे, तो बताइए हमारे जैसा आदमी क्यों न घबराने लगे। इसीलिए हमें लगता है कि हम झूठ-सच के चक्कर में बीमार हो रहे हैं और इस लोकतंत्र में पैदा होने पर आठ-आठ आंसू रो रहे हैं। आप बताइए, हम अपने दिमाग को बचाएं तो कैसे बचाएं और बचाने के लिए जायें तो कहां जायें?'

हमने कहा, 'झल्लन, यह तेरे अकेले की बीमारी नहीं है, यह बीमारी सबके दिमागों से खेल रही है और चुनावों से पहले तेजी से पूरे देश में फैल रही है। किसी भी बीमारी का वायरस तभी फैलता है जब उसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है, इसी वातावरण के कारण हर व्यक्ति वायरस का शिकार बन जाता है। झूठ के वायरस को राजनीति का भरपूर साथ मिल रहा है इसलिए यह वायरस दिनोंदिन खतरनाक हो रहा है। वैसे बता, किस घटना ने तुझे ऐसा छुआ है कि यह वायरस तुझ पर इस कदर हावी हुआ है?'

झल्लन बोला, 'सच बताएं ददाजू, जब से चुनावी बांड का जिन्न सुप्रीम कोर्ट की फूंक से आरबीआई की बोतल से बाहर आया है तभी से हमारे दिमाग का संतुलन ज्यादा गड़बड़ाया है। अब देखिए, हमारे राहुल बबुआ घूम-घूमकर चुनावी बांड को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं, इसे जबरन वसूली योजना का तमगा पहना रहे हैं और इसका मास्टर माइंड प्रधानमंत्री मोदी को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उन्हें चुनावी बांड का चंदा दे दिया तो मानो उसने अपनी पवित्रता का प्रमाणपत्र ले लिया, उसे या तो कोई मनचाहा ठेका दे दिया गया या फिर उसे सीबीआई के जालिम शिकंजे से सुरक्षित बाहर कर दिया गया। अगर हम राहुल बबुआ को सच मानते हैं तो हमें हमारे जननायक मोदी जी प्रचंड खलनायक जैसे लगने लगते हैं और हमारे विश्वास के पैर हिलने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब मोदी जी बांड पर बात करते हैं, अपनी बात समझाने लगते हैं तो हमारे हिलते विश्वास के पांव फिर से जमने लगते हैं, मोदी जी सही और स्वयं राहुल बबुआ ही गलत लगने लगते हैं।'

हमने कहा, 'मोदी जी की कौन सी बात तुझे भा जाती है जो तेरे विश्वास की हिलती धरती अपनी जमीन पर जम जाती है?' वह बोला, 'मोदी जी कहते हैं कि चुनावी बांड को लेकर विपक्ष कोरा झूठ फैला रहा है, एक अच्छी योजना पर कलंक का टीका लगा रहा है। योजना में खामी हो सकती है जिसे हटाया जा सकता है, चुनाव में काले धन के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी अधिक सक्षम व्यवस्था को लाया जा सकता है। वो यह भी कहते हैं कि एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने चंदा दिया था उसमें से केवल 37 प्रतिशत भाजपा ने पाया जबकि बाकी 63 प्रतिशत भाजपा विरोधी दलों के हिस्से में आया। दूसरे, इस योजना को इसलिए सफल माना जाना चाहिए कि इसी के कारण यह पता लग पाया कि किससे किस पार्टी ने कितना खाया। अब इस योजना पर रोक लगाकर ज्यादा बुरा कर दिया गया है और देश को पूरी तरह चुनावी काले धन के दौर में धकेल दिया गया है। अब आप बताइए ददाजू, हम मोदी जी को सच मानकर भाजपा के पक्ष में झंडा उठाएं, या राहुल बबुआ की बात को सही मानकर उनकी बारात में शामिल हो जायें? आप ही हमें बताइए, ठीक से समझाइए।'

हमने कहा, 'इस दौर की चुनावी राजनीति में न कोई पूरी तरह सच बोलता है, न कोई पूरी तरह झूठ बोलता है। जो सच बोल रहा होता है उसमें भी कुछ झूठ छिपा होता है और जो झूठ बोल रहा होता है उसके पीछे भी थोड़ा सा सच लगा हुआ होता है। तेरा राहुल बबुआ जब मोदी पर आरोप लगाता है तो उसकी अपनी पार्टी के पास पैसा कहां से आया इसका सच छिपा जाता है और जब मोदी पक्ष चुनावी बांड के पक्ष में बात चलाता है तो बड़ी सफाई से आधा सच दबा जाता है। जब तक यह चुनावी लोकतंत्र रहेगा तब तक झूठ-सच का खेल ऐसे ही चलेगा। सो अपने दिमाग को दुरुस्त कर ले, दोनों में से कोई रास नहीं आये तो किसी तीसरे पक्ष का वरण कर ले।'

हमने कहा, 'मोदी जी की कौन सी बात तुझे भा जाती है जो तेरे विश्वास की हिलती धरती अपनी जमीन पर जम जाती है?' वह बोला, 'मोदी जी कहते हैं कि चुनावी बांड को लेकर विपक्ष कोरा झूठ फैला रहा है, एक अच्छी योजना पर कलंक का टीका लगा रहा है। योजना में खामी हो सकती है जिसे हटाया जा सकता है, चुनाव में काले धन के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी अधिक सक्षम व्यवस्था को लाया जा सकता है। वो यह भी कहते हैं कि एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने चंदा दिया था उसमें से केवल 37 प्रतिशत भाजपा ने पाया जबकि बाकी 63 प्रतिशत भाजपा विरोधी दलों के हिस्से में आया। दूसरे, इस योजना को इसलिए सफल माना जाना चाहिए कि इसी के कारण यह पता लग पाया कि किससे किस पार्टी ने कितना खाया। अब इस योजना पर रोक लगाकर ज्यादा बुरा कर दिया गया है और देश को पूरी तरह चुनावी काले धन के दौर में धकेल दिया गया है। अब आप बताइए ददाजू, हम मोदी जी को सच मानकर भाजपा के पक्ष में झंडा...

राष्ट्रीय सहारा ● राष्ट्रीयता ● कर्तव्य ● समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 18, अंक 6279 — आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

अंतरिक्ष में चीन

स्टार वार की कल्पना पुरानी है, पर उस दिशा में नए-नए प्रयासों की खबरें यदा-कदा आती रहती हैं। रूस-अमेरिका के बीच 1960-70 के दशक में अंतरिक्ष विज्ञान के मोर्चे पर गजब होड़ थी और उसी होड़ के चलते इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ। जब वह होड़ खत्म हुई, तो धीरे-धीरे अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट तक सीमित होता गया, पर हकीकत यह है कि अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने की होड़ खत्म नहीं हुई है। इसी दिशा में ताजा चिंताजनक खबर यह है कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम वास्तव में सैन्य योजना का हिस्सा है। अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञान संस्था नासा के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि चीन अपने सामरिक मकसद को छिपाने के लिए नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उपयोग कर रहा है। ऐसे में, वाशिंगटन को सतर्क रहना चाहिए। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कैपिटल हिल में सांसदों को बताया कि चीन ने अंतरिक्ष के मोर्चे पर पिछले 10 वर्षों में असाधारण प्रगति की है, पर प्रगति बहुत गोपनीय है। ऐसा लगता है कि चीन के बारे में कोई नई बड़ी सूचना अमेरिका के हाथ लगी है, तभी नासा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि अंतरिक्ष में होड़ जारी है।

चीन पर अमेरिका के अविश्वास पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चीन अपनी किसी भी योजना को युद्ध स्तर पर ही बनाता और लागू करता है। मामला खेल का हो, उत्पादन का हो या तकनीक का, उसकी कोशिश हमेशा से अपने सामरिक हितों के अनुरूप रही है। वैसे अमेरिका भी लंबे समय तक इसी रणनीति के तहत काम करता रहा है। बड़ा सवाल अब यह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका के पास क्या योजना है? क्या अमेरिका के पास कोई ठोस सूचना है, जिससे पता चल सके कि चीन अंतरिक्ष में सैन्य मोर्चा सजा चुका है? अगर ऐसी कोई ठोस सूचना है, तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, पर अमेरिका की जो योजना दिखती है, वह आश्वस्त नहीं करती। दरअसल, नासा को अपनी सरकार से बड़ा बजट चाहिए, इसलिए उसके प्रमुख ने अमेरिकी संसदीय समिति के सामने चीन के संबंध में चेतावनी दी है।

क्या अमेरिका के पास कोई ठोस सूचना है, जिससे पता चल सके कि चीन अंतरिक्ष में सैन्य मोर्चा सजा चुका है? अगर ऐसी कोई सूचना है, तो दुनिया को पता चलना चाहिए।

क्या अमेरिका इस बात से डर रहा है कि अगर चीन चांद पर पहले पहुंच गया, तो किसी और देश को वहां नहीं पहुंचने देगा? इसका मतलब है कि नासा को ज्यादा बजट चाहिए, ताकि वह चांद पर जल्दी पहुंच जाए। वैसे भी, चांद पर अमेरिका सबसे मजबूत है और चीन को चांद पर अभियान भेजने में अभी समय लगेगा। हां, अमेरिका की पकड़ निश्चित रूप से कमजोर पड़ी है और इसके लिए वह स्वयं दोषी है। अमेरिका ने एक लंबा समय अपने पूरे संसाधनों के साथ दुनिया के तानाशाहों, उग्र संगठनों, इराक, अफगानिस्तान व अरब दुनिया में लगाया, जबकि इसी समय में चीन ने तकनीक और विज्ञान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में ध्यान दिया है। नासा की ताजा बेचैनी को समझा जा सकता है। चीन 2022 में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर चुका है। इस स्टेशन के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है और यही सबसे खतरनाक बात है। अमेरिका या नासा को अगर समझ आ गई है, तो अब वह कहां से शुरुआत करेगा? ध्यान रहे, चीन की तकनीकी तरक्की में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है और अब भी उसकी चीन संबंधी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिका के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे अंतरिक्ष में अपनी वैश्विक बढ़त को बनाए रखना होगा।

पृथ्वी के नाम पर बस एक खास दिन

यहां स्कैन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

पर्यावरण के नाम पर जन-आंदोलन खड़ा करके सरकारों पर दबाव बनाने का जो सपना गेलॉर्ड नेलसन ने देखा था, आज का पृथ्वी दिवस उससे बहुत दूर जा चुका है।

पृथ्वी दिवस के इतिहास को खंगालते हुए हम अगर पीछे की ओर जाएं, तो हमारी मुलाकात रचेल कार्सन से होती है। कार्सन वहां खड़ी हैं, जहां से आधुनिक दौर की पर्यावरण चेतना शुरू होती है। यहां कार्सन को याद करने का एक और कारण यह भी है कि आज से ठीक 60 साल पहले अप्रैल के महीने में ही उनका निधन हुआ था। यह सन् 1962 की बात है, जब कार्सन ने एक किताब लिखी थी- *साइलेंट स्प्रिंग* यानी मौन बसंत। कई बरस से सिंथेटिक कीटनाशकों के खतरों पर काम कर रहीं कार्सन ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी, जब बसंत का मौसम तो आएगा, पर न पक्षी चहचहाएंगे और न भौंरे गुंजार करेंगे। दरअसल, वे होंगे ही नहीं, क्योंकि फसलों को बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरह से डीडीटी जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसके बाद तो इन सबके बचने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है।

कार्सन की इस किताब को लोगों ने हाथों-हाथ लिया, लेकिन उद्योगों ने इसका भारी विरोध भी किया। खुद कार्सन पर निजी हमले भी हुए। मामला अदालत में पहुंच गया और सरकारों को सफाई देनी पड़ी। इसी के साथ ऐसे वैकल्पिक कीटनाशकों को विकसित करने का दबाव भी बना, जो ज्यादा खतरनाक न हों। हालांकि, पुस्तक प्रकाशन के डेढ़ साल बाद ही कार्सन का निधन हो गया, पर पर्यावरण की चेतना का जो सिलसिला उनसे शुरू हुआ, वह फिर रुका नहीं।

अब एक नजर उस दौर पर भी डाल लेते हैं, जिसने इस चेतना को जड़ें जमाने की जमीन दी। कार्सन जिस समय यह किताब लिख रही थीं, उस समय अमेरिका और पश्चिम के कई देशों में हिप्पी आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। दूसरे विश्व-युद्ध के बाद के निर्दयी औद्योगीकरण से उकताए नौजवान ही बगावत पर उतारू थे। वे स्थापित मान्यताओं की बहुत सी जंजीरों को तोड़ देने पर आमादा थे। फिर बेवजह से लग रहे वियतनाम युद्ध से आई कहानियां पूरे अमेरिका को झझकोर रही थीं। पश्चिम से निकलकर यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश कर रहा था। कार्सन की किताब ने नौजवानों को अपनी बगावत को सही ठहराने का एक और तर्क दे दिया था।

हर तरफ चिंताएं बढ़ रही थीं कि इन नौजवानों को कैसे पटरी पर लाया जाए। ठीक इसी समय अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेलसन को एक रास्ता समझ में आया। उन्हें लगा कि इन नौजवानों की ऊर्जा को पर्यावरण से जोड़कर अच्छे भविष्य की एक मुहिम चलाई जा सकती है। उन्होंने कोशिश की, तो दुनिया की कई सरकारें और संगठन उनके साथ आ गए। यहीं से पृथ्वी दिवस की अवधारणा निकली। 22 अप्रैल, 1970 को जब पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो अकेले अमेरिका में इसके कार्यक्रम में दो करोड़ लोग शामिल हुए। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में एक अरब लोगों ने इसमें शिरकत की। इसका श्रेय पूरी तरह से पृथ्वी दिवस को तो नहीं दिया जा सकता, पर इसी के बाद से हिप्पी आंदोलन का उबाल बैठने लग गया।

हालांकि, नेलसन चाहते थे कि पर्यावरण को लेकर नौजवान एक जन-आंदोलन करें, जो सरकारों और स्थापित सत्ताओं पर दबाव बनाए। अमेरिका के नौजवानों ने तो रास्ता बदलना शुरू कर दिया, मगर बाकी दुनिया के नौजवानों में जो उथल-पुथल दिखाई दी, उसे युवा असंतोष का दौर कहा जाता है। यह वही समय था, जब 1974 में गुजरात के एक छात्रावास में छोटा-सा आंदोलन शुरू हुआ था और जल्द ही वह बिहार समेत पूरे देश में फैल गया था। कुछ समय बाद नौजवानों ने इसका नेतृत्व जय प्रकाश नारायण को सौंपा और इसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नाम दिया गया। आज देश में जितने भी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, वे किसी न किसी तरह से उस दौर की राजनीति से ही निकले हुए हैं।

इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों ने सोचा कि पर्यावरण की इस चेतना को एक राजनीतिक आकार दिया जाए। इसी सोच से जन्म हुआ ग्रीन पार्टी का। ऑस्ट्रेलिया से निकलकर यह अवधारणा दुनिया के कई देशों में फैल गई। बहुत से देशों में ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई। एक समय तक तो यूरोप के कई देशों में इसका खासा असर भी दिखाई दिया। इस पार्टी ने स्थानीय स्तर पर कुछ एक चुनाव भी जीते। राजनीतिज्ञों ने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और इसे भविष्य की राजनीतिक ताकत कहा जाने लगा, लेकिन राजनीति का रास्ता कभी इतना सीधा नहीं होता। राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश में ग्रीन पार्टी धीरे-धीरे अपनी पहचान खोती गई और ओझल होने लगी।

यह जरूर है कि इसके बाद से पर्यावरण के मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडे में जगह पाने लगे। भले ही इसका बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतने भर से पर्यावरण को लेकर इन दलों की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लगता। यह दुनिया भर में हुआ। इस समय हमारे देश में आम चुनाव चल रहा है और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि चुनावी जंग में पर्यावरण के मुद्दे कहां खड़े हैं। घोषणापत्र पर्यावरण की चिंता से अछूते नहीं हैं, पर यहां बातें किसी औपचारिकता से आगे का कोई रास्ता नहीं पकड़ती हैं। आप इसे कोरा जुबानी जमाखर्च भी कह सकते हैं। पर्यावरण के नाम पर कोई दल या उम्मीदवार जनता से वोट नहीं मांग रहा है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे उन राज्यों में भी, जहां पर्यावरण में बदलाव का असर लोगों के जीवन पर पड़ता दिखाई भी देने लगा है। अच्छे पर्यावरण का कोई वादा नहीं कर रहा, यह किसी भी गारंटी में शामिल नहीं है।

आज भी हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हमें बीच राह में भटक गए पर्यावरण के संकल्पों की याद दिलाने आ जाता है। इस दिन दुनिया भर के स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, दफ्तरों वगैरह में बड़े और भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, पर इनमें बदलाव की ऊर्जा कम होती है और पर्व मनाने की औपचारिकता ज्यादा। कुछ जगह तो वे कंपनियां ही ऐसे कार्यक्रमों की प्रायोजक होती हैं, जिन पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप चस्पां हैं। पर्यावरण के नाम पर जन-आंदोलन खड़ा करके सरकारों पर दबाव बनाने का जो सपना गेलॉर्ड नेलसन ने देखा था, आज का पृथ्वी दिवस उससे बहुत दूर जा चुका है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारतीय सहकारी समितियों को दुनिया भर में पहुंचाया जाए

यहां स्कैन करें

जॉर्ज स्कारिया | अर्थशास्त्री

पिछले हफ्ते गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (एमएमपीए) के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत ब्रांडेड अमूल दूध अमेरिका में हजारों लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कामयाबी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक, अमूल के उत्पाद पहले से ही करीब 50 देशों में भले निर्यात किए जा रहे हैं, पर यह पहली बार है कि इसका ब्रांडेड ताजा दूध भारत के बाहर लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा, यह कदम अभी अमेरिका तक सीमित है, लेकिन इसमें अन्य देशों में भी अमूल के लिए द्वार खोलने की क्षमता है। तीसरा, यह देश की दूसरी सहकारी समितियों के लिए वैश्विक स्तर पर विस्तार का आधार बनाता है। दरअसल, पिछले दो दशक में कॉरपोरेट भारत में अनेक वैश्विक कंपनियों का उदय हुआ है, पर सहकारी समितियों के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। यह हालात बदलने का समय है।

सहकारी समिति कानून 25 मार्च, 1904 को बना था। 14 दिसंबर, 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, पंजीकृत किया गया था। सन् 1947 में देश की आजादी के बाद सहकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला और यह पंचवर्षीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अक्तूबर 1964 में आणंद, गुजरात की यात्रा पर दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा लाए गए सामाजिक-आर्थिक बदलावों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की कल्पना की थी। पूरे देश में दुग्ध सहकारी समितियों की आणंद शैली को दोहराना था। गौरतलब है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सहकारी समितियां दबाव में आ गईं। अंततः उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए जुलाई 2021 में कृषि मंत्रालय से अलग करके केंद्रीय सहकारी मंत्रालय बनाया गया। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर करीब 30 करोड़ सदस्यों वाली 8,50,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो डेयरी, कृषि, ऋण, मत्स्य पालन, हथकरघा और चीनी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इनमें से दो, जीसीएमएमएफ व इफको दुनिया की अग्रणी सहकारी समितियों में शुमार हैं।

भारतीय सहकारी समितियों की वैश्विक पहुंच की क्या स्थिति है? जीसीएमएमएफ द्वारा अमेरिका में ताजा ब्रांडेड अमूल दूध पेश करने का कदम दूसरी भारतीय सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के करिश्माई नेतृत्व ने अमूल की कामयाबी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को दूध की कमी वाले देश से दूध की अधिकता वाले देश में बदलकर उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत हो चुकी है। वैसे, मलयेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और केन्या जैसे देशों में भी सहकारी समितियां खूब फली-फूली हैं, उनसे भी हमें सीखने की जरूरत है। संयोगवश, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर रखा है, इसलिए भारत के सहकारी आंदोलन के वैश्वीकरण का एक विशेष संदर्भ बन जाता है।

अमूल के उत्पाद पहले से ही करीब 50 देशों में जा रहे हैं, पर यह पहली बार है कि अमूल का ब्रांडेड ताजा दूध भारत के बाहर लॉन्च किया जा रहा है।

न्यूजीलैंड में फोंटेरा (डेयरी के लिए), वॉलनट कोऑपरेटिव व जेस्प्री (कीवी फल के लिए) जैसे मजबूत वैश्विक सहकारी संगठन हैं। ये सभी सहकारी संगठन बिजनेस एनजेड नामक एक व्यापक संगठन का हिस्सा हैं, जो अपने सदस्य संस्थानों को प्रशासन, विपणन, प्रौद्योगिकी सहायता और साझेदारी के लिए कार्यशालाओं व गतिविधियों के जरिये वैश्विक स्तर पर सहायता करता है। यह संगठन एक कार्यक्रम भी संचालित करता है, ताकि सहकारी संस्थाएं दीर्घायु हों। भारत इनसे सीख सकता है व साझेदारी कर सकता है।

वैसे, वैश्विक पहुंच और मान्यता के लिए पूरे सहकारी क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश के बजाय सरकार सर्वश्रेष्ठ सहकारी समितियों का चुनिंदा समूह बना सकती है। सार्वजनिक उद्यमों की नवरत्न अवधारणा की तरह वह वैश्विक भारतीय सहकारी समितियों के रूप में 10-12 राष्ट्रीय व राज्य सहकारी समितियों को चुन सकती है। हमारी सहकारी समितियों के वैश्वीकरण से रोजगार, धन सृजन और समग्र राष्ट्रीय विकास में मदद मिलेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

दिखावे की यह दुनिया

फिलहाल माहौल कुछ ऐसा है कि जब तक कोई घटना तस्वीर के जरिये लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती, तब तक तसल्ली ही नहीं होती। पहले फोटोग्राफर मौजूद होता है और बाद में घटना घटती है, चाहे वह किसी की मृत्यु हो या जन्म। बड़ी हैरानी की बात है। बच्चे के जन्म से पहले ही गर्भावस्था में, मां के पेट का फोटो लेकर दिखाने का फैशन चल पड़ा है। पहले कोई स्त्री ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका पेट प्रदर्शन का विषय होगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ को छिपाती थीं, ताकि किसी की नजर न लगे।

कोई माता-पिता की सेवा कर रहा है, तो उसके फोटो; आईसीयू में दाखिल लोगों के वीभत्स फोटो। आज अगर देश के साधु को भी प्रतिष्ठा पानी है, तो उसे किसी मंत्री से सत्संग साधना पड़ता है! अब साधु मंत्रियों से प्रतिष्ठित होते हैं! पहले साधु एकांत में रहते थे और राजा उनका आशीर्वाद लेने उनके चरणों में जाते थे, लेकिन दिखावा अब जीवन का हिस्सा बन गया है। यह स्थिति स्वस्थ नहीं है, यह रुग्ण मानसिकता है।

ओशो कहते हैं, यह बहिर्मुखी युग है। यहां जो प्रतिष्ठा बाहर से आंकी जा सकती है, उसकी ही कीमत है। भीतर का कोई मूल्य नहीं। कवि भी सम्मानित नहीं होगा, ज्ञानी भी सम्मानित नहीं होगा, जब तक कि उसे कोई पुरस्कार न मिले। कवि बेझिझक मंच से तालियां मागते हैं, मगर तालियां तो दिल से निकलती हैं। यदि मांगनी पड़े, तो वे भी नकली हैं। ऐसा नहीं है कि अंतर्मुखी लोग बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन अंतर्मुखी मूल धारा नहीं है। युग भी रूपांतरित होते हैं। जीवन में सब चीजें बदलती रहती हैं। हर चीज ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। हर अंतर्मुखी युग के बाद बहिर्मुखी युग होता है। बहिर्मुखी के बाद अंतर्मुखी युग होता है।

युग की धारा को पहचानते हुए ओशो ने बहिर्मुखी लोगों के लिए सक्रिय किस्म के ध्यान बनाए हैं, क्योंकि आज मन की शांति और सुकून जितना जरूरी है, शायद ही कभी था। इतने अधिक दिखावे की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि लोग अंदर से बिल्कुल खाली हैं। दरअसल, वे अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जो

यह बहिर्मुखी युग है। यहां जो प्रतिष्ठा बाहर से आंकी जा सकती है, उसकी ही कीमत है। भीतर का कोई मूल्य नहीं। कवि, ज्ञानी भी सम्मानित नहीं होगा, जब तक उसे कोई पुरस्कार न मिले।

खालीपन है, उसे हमें ऐसे लोग प्रशिक्षित करके पूरा करना है, जो बहिर्मुखी ध्यान कर सकें, सिखा सकें। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो भी कृत्य हो, कंप्यूटर पर काम करना, गाड़ी चलाना, दौड़ लगाना, आप उसे ही ध्यान बना सकते हैं। बाजार में, दुकान में, दफ्तर में, हर जगह ध्यान किया जा सकता है। ध्यान यानी रिलेक्स होकर बगैर तनाव के काम करना, जीवन जीना, ताकि अपनी भी याद रहे और दूसरों की भी। इससे एक मानसिक संतुलन पैदा होगा और दिखावे की होड़ खत्म हो जाएगी।

अमृत साधना

कमला हैरिस | अमेरिकी उप-राष्ट्रपति

अमेरिकी बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह कोई बीमारी या कार दुर्घटना नहीं, बल्कि बंदूक हिंसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर इस स्थिति को बदल सकते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 22 अप्रैल, 1949

तपेदिक का खतरा

तपेदिक मानव जाति के भयंकर शत्रुओं में से एक है। भारत में यह रोग बराबर प्रसार पा रहा है। यह बहुधा नौजवानों को अपना शिकार बनाता है जिन्हें देश की असली दौलत कह सकते हैं। यह रोग इसलिए भयंकर है कि यह छूत से फैलता है और जो लोग एक बार इसके शिकार हो जाते हैं, उनमें से बहुत कम पुनः स्वस्थ होते हैं। भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रिणी श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर ने भारत की तपेदिक संस्था की वार्षिक बैठक में भाषण देते हुए बताया है कि तपेदिक इस देश में प्रति मिनट एक व्यक्ति का प्राण हरण कर लेता है। यह रोग चिन्ताजनक तेजी के साथ प्रसार पा रहा है और उसके आक्रमण को रोकने के लिए सभी ओर से प्रयास किया जाना चाहिए।

यह स्वीकार करना होगा कि पश्चिमी देशों की तुलना में इस देश में तपेदिक का सामना करने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध हैं। तपेदिक के रोगी को अपने घर में रहने देकर इस रोग के प्रसार में सहायता ही पहुंचाई जाती है। भोर कमेटी ने राज्य पर यह दायित्व डाला था कि वह प्रत्येक तपेदिक के रोगी को अस्पताल में रखने और उसकी समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध करे। किंतु तपेदिक संस्था की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों को रखने का स्थान बहुत सीमित है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में २५ लाख तपेदिक के रोगी होंगे, किंतु अस्पतालों में केवल आठ हजार रोगियों के लिए ही स्थान है। दूसरे शब्दों में प्रति ३१० अथवा ३१५ रोगियों के पीछे एक के लिए अस्पतालों में स्थान है। यह अवस्था सचमुच असंतोषजनक है। अस्पतालों में तपेदिक के गरीब रोगियों के लिए स्थान पाना बड़ा कष्ट-साध्य होता है। प्रायः वही लोग उनसे लाभ उठा पाते हैं जो काफी धन व्यय कर सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार ने इस बारे में एक काम का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में तपेदिक रोगियों के लिए जो स्थान हैं, उनमें से यथासंभव अधिक से अधिक गरीब रोगियों के लिए सुरक्षित कर दिये जायें; धनवान रोगी तो अपने घरों में ही अलग रह सकते हैं और अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। इस देश में तपेदिक के बढ़ते हुए प्रकोप का कारण यहां की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं।

विकसित देशों को अब बाध्य कीजिए

जब 1970 में पहली बार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था, तब दो करोड़ अमेरिकी लोगों ने इसमें भाग लिया था। उस कार्यक्रम में हरेक समाज, वर्ग और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस तरह वह आंदोलन आधुनिक वक्त का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बन गया। इस वर्ष का पृथ्वी दिवस पर्यावरण के आगे प्लास्टिक से उत्पन्न खतरे पर केंद्रित है, जिसमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को समाप्त करने और उसका विकल्प खोजने का आह्वान किया गया है, ताकि उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके। पृथ्वी पर जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, यहां प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की गति भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते असंतुलन के कारण वह दिन बहुत दूर नहीं, जब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग जाग जाएं, अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझें और पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। महात्मा गांधी ने भारतीयों को आधुनिक तकनीक के प्रति दशकों पहले आगाह किया था। गांधीजी का मानना था कि पृथ्वी, वायु, जल और भूमि हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं हैं, बल्कि वे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की अमानत हैं। हमें अपनी भावी पीढ़ी को वैसा ही साफ-सुथरा पर्यावरण सौंपना होगा, जैसा हमें हमारे पुरखों से मिला है। गांधीजी का यह भी मानना था कि पृथ्वी के पास लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन उनके लोभ की पूर्ति लायक नहीं।

हमारी पारंपरिक मान्यता है कि पृथ्वी एक मां की तरह है, जो मनुष्य, वनस्पति, जीव-जंतु समेत समस्त प्राणियों को अपनी गोद में पालती-पोसती है। दूसरी तरफ, मनुष्य अपने क्षणिक फायदे और भौतिक सुख भोगने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करते जा रहा है। इसलिए आज हमें कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। पृथ्वी की रक्षा के लिए हमें छोटे-छोटे प्रयास करने की जरूरत है, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाएं, औद्योगिकीकरण को कम करने में अपना सहयोग दें, चीजों के बार-बार उपयोग की आदत डालें, वाहनों के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं। ऊर्जा-संरक्षण समेत कई ऐसे प्रयास हम कर सकते हैं, जिनसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और उसमें संतुलन लाया जा सके। दुनिया के तमाम विकासशील देशों को मिलकर विकसित देशों पर दबाव बनाना चाहिए कि वे गरीब देशों की कीमत पर अब अपने लिए सहूलियतें नहीं जुटा सकते। जब तक विकसित और अमीर देशों पर अंकुश नहीं लगेगा, पृथ्वी के लिए बहुत उम्मीद नहीं पाली सकती।

प्रत्यूष शर्मा, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पृथ्वी दिवस

कुदरती संसाधनों का दोहन मजबूरी

पिछले कई वर्षों से हरेक साल पृथ्वी दिवस पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है और इसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री तूफानों की बारंबारता बढ़ गई है, सागर का जल-स्तर ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण कई तटीय इलाकों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विकसित देश खुद तो बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं और गरीब मुल्कों पर तमाम तरह की पाबंदियां थोपने की कोशिश में हैं।

इन सारे विलाप के बरक्स कुछ बड़े सवाल हैं कि यदि ये विकसित देश अपना उत्पादन नहीं बढ़ाते, तो कितने सारे लोग भूख से मरते? कितने सारे बदन कपड़ों के बगैर जीने को विवश होते और कितनी बड़ी मानव आबादी के सिर पर हर मौसम को झेलने लायक छत होती? अपने देश को ही लीजिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो आपको कोसते हुए मिल जाएं कि पंजाब-हरियाणा के खेत बंजर हो चुके, अधिक उर्वरकों के इस्तेमाल ने कई बीमारियों को जन्म दिया है और हजारों लोगों की जिंदगी पर बन आई है। मगर जरा सोचिए, आजादी के बाद हमारी सरकार को 32 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए किस तरह अमेरिका-यूरोप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था और वे देश हमें घटिया अनाजों की आपूर्ति करते थे। धन्यवाद दीजिए लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का कि उन्होंने वर्गीज कूरियन, एमएस स्वामीनाथन जैसे विलक्षण कृषि विज्ञानियों को आगे बढ़ाया और भारत में श्वेत- हरित क्रांति को संभव बनाया। आज हम 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह मुफ्त में अनाज मुहैया करा रहे हैं, तो यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण ही मुमकिन हो रहा है।

अगर आस्थावान बनकर सोचें, तो यह मानना पड़ता है कि ऊपर वाले ने ऐसे कई ग्रह बनाए हैं, जिन तक इंसानों की पहुंच नहीं है। मनुष्य चांद पर बस्तियां बसा पाता है या नहीं, यह तो भविष्य की बात है, मगर सोचिए कि यदि हमारी पिछली पीढ़ियां यूं ही रोती रहतीं कि नहीं, इससे पृथ्वी के वायुमंडल की सेहत प्रभावित होगा, तो क्या आज हमारे कदम चांद पर पड़े होते? धरती के कई कोनों का तो अभी हम पूरी तरह से उद्घाटन भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए इसकी क्षमता को कमतर आंकने के बजाय हमें इसकी दुर्गम जगहों तक पहुंचने और उनको जानने-समझने की कोशिश करनी चाहिए। धरती का दोहन हमारी जरूरत और मजबूरी, दोनों है।

अंबुज राय, टिप्पणीकार

https://www.epaperpdf.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 22 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

यदि बोलना एक कला है तो मौन उससे भी बड़ी कला है

घिसी-पिटी बातें

विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की रांची रैली में एक बार फिर यही अधिक सुनने को मिला कि लोकतंत्र के साथ संविधान खतरे में है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल पिछले एक अर्से से यही बात करने में लगे हुए हैं। आम चुनावों की घोषणा होने के उपरांत इन दलों ने इसे अपना एक मुख्य मुद्दा सा बना लिया है कि यदि नरेन्द्र मोदी की सत्ता में वापसी हुई तो इस बार के आम चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव साबित होंगे और संविधान का बचना भी मुश्किल है। क्या यह विडंबना नहीं कि लोकतंत्र और संविधान के खतरे में होने पर सबसे ज्यादा जोर वह कांग्रेस दे रही है जिसने देश पर न केवल आपातकाल थोपा, बल्कि संविधान में मनमाने परिवर्तन किए। भले ही आपातकाल का दौर गुजरे कई दशक बीत गए हों, लेकिन देश अभी उसे भूला नहीं है। यह विचित्र है कि जिन दलों ने इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें से कुछ अब लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के जुमले को दोहराने में लगे हैं। यह स्थिति यही रेखांकित करती है कि आइएनडीआइए के पास उन मुद्दों का अभाव है जिन्हें आगे कर वह जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। निःसंदेह ऐसा नहीं है कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं और मोदी सरकार ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आइएनडीआइए के घटक दल अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से भी कोई प्रभावी वैकल्पिक एजेंडा जनता के सामने नहीं रख सके। उनके एजेंडे में कई ऐसी बातें हैं जो एक-दूसरे के विपरीत हैं। क्या कांग्रेस अथवा उसके सहयोगी दल यह बता सकते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो किसके घोषणा पत्र पर अमल किया जाएगा।

रांची की रैली में यह भी सुनाई दिया कि मोदी सरकार जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। इस तरह के आरोपों पर इसलिए शायद ही कोई ध्यान दे, क्योंकि दिल्ली की सरकार के नियंत्रण वाला तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को दिए जा रहे भोजन और दवाओं के बारे में कुछ अलग ही रिपोर्ट दे रहा है। यह ठीक है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन यदि वे तार्किक और जनता के गले उतरने वाले न हों, तो फिर वे केवल खबरों का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। रांची की रैली में जहां सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोदी सरकार से खतरा बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने यह कहकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की कि भाजपा अगर फिर सत्ता में आई तो आदिवासी समाज के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा हो कि आइएनडीआइए के घटक दल यह समझें कि इस तरह की घिसी-पिटी और प्रभावहीन बातें करने से या आरोप लगाने से बात बनने वाली नहीं है।

स्कूलों में हो सुधार

झारखंड में अभी भी ऐसे विद्यालय हैं, जहां बहुत ही कम संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या गिनी-चुनी ही है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के परिणाम में यह तथ्य सामने आया है कि रांची जिले में ही कई ऐसे स्कूल हैं जहां से इस परीक्षा में एक से 10 की संख्या में ही विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अन्य जिलों में भी ऐसे स्कूलों के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह चिंताजनक स्थिति है। राज्य सरकार के जिम्मेदार विभागों के पदाधिकारियों के लिए भी मंथन और जांच का विषय है कि आखिर यह स्थिति क्यों है? कुछ वर्ष पूर्व बच्चों की कम संख्या वाले विद्यालयों की पहचान कर उन्हें पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज कराया गया था। इसका उद्देश्य भी था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तथा संसाधन भी बेकार न जाए। निश्चित रूप से किसी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ही कम होने से संसाधनों की बर्बादी ही होती है। कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां बच्चे गिने-चुने होते हैं तथा शिक्षक अधिक होते हैं। ऐसे में शिक्षकों के वेतन पर खर्च होनेवाली राशि बेकार ही जाती है। कई स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जहां शिक्षक के नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो पाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि निरीक्षण के मजबूत तंत्र होने के बाद भी ऐसे स्कूलों की जानकारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तक क्यों नहीं पहुंच पाती। सिर्फ चिह्नित स्कूलों को ही आदर्श या उत्कृष्ट बनाने से काम नहीं चलेगा।

स्कूलों में शिक्षकों तथा छात्रों की संख्या में संतुलन और बेहतर अनुपात होना जरूरी है

संविधान पर व्यर्थ की बयानबाजी

हृदयनारायण दीक्षित

संविधान के प्रति भारतीय जन गण मन की निष्ठा है। संविधान बदलने या पूरा संविधान ही खारिज करने और तानाशाही लाने जैसे आरोप हास्यास्पद हैं

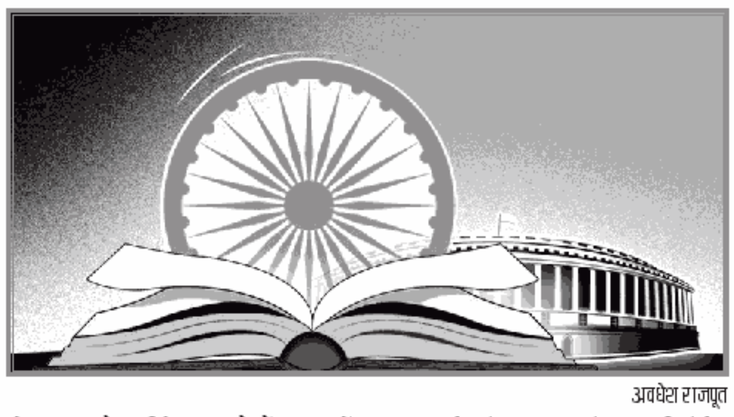

अवधेश राजपूत

भारत में संविधान की सत्ता है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन कुछ समय से बहस चली है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव में भारी बहुमत पाकर संविधान बदल देंगे। बहस व्यर्थ है। संविधान साधारण अभिलेख नहीं है। जड़ नहीं, गतिशील संस्था है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहते हैं। अब तक लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में ही संविधान संशोधन के स्पष्ट प्रविधान हैं। संविधान बदलने और संशोधन करने में मूलभूत अंतर है। संविधान संशोधन विषयक प्रविधान पर संविधान सभा में बहस चली थी। बहस में हिस्सा लेते हुए एचवी कामथ ने कहा था, 'संशोधन आखिरकार क्या है? संशोधन का अर्थ हो सकता है संविधान में कुछ परिवर्तन। उसमें कुछ जोड़ना या उसका निरसन,' लेकिन यहां संशोधन को लेकर तो कोई बहस ही नहीं, बल्कि संविधान बदलने या खत्म करने की हास्यास्पद बयानबाजी है।

संविधान निर्माता संविधान संशोधन की आवश्यकता के प्रति सजग थे। संविधान सभा में पीएस देशमुख ने कहा था कि 'भविष्य में कुछ समय तक संविधान में तमाम परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। इसलिए संविधान संशोधन आसान बनाना जरूरी है।' बृजेश्वर प्रसाद ने कहा कि 'किसी संविधान की अपरिवर्तनशीलता के कारण नई चीजें नहीं आ सकतीं। परिवर्तन रुक जाता है।' सभा में अनेक सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। डा. आंबेडकर ने सभी सदस्यों के उत्तर दिए। भारत में संशोधन की शक्ति विधायिका में निहित है। उन्होंने कहा कि 'हम संविधान संशोधन को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। एक श्रेणी में संसद का साधारण बहुमत पर्याप्त है। दूसरी श्रेणी के संशोधन में दो तिहाई बहुमत आवश्यक है। तीसरी श्रेणी में देश की आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है।' यहां संशोधन की पूरी प्रक्रिया औचित्यपूर्ण है।

संविधान सभा में कई सदस्यों ने संशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। तर्क यह था कि कभी आम जनता राजनीतिक प्रणाली को बदलने की मांग कर सकती है। डा. आंबेडकर ने कहा, 'जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में दो तिहाई बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह मान लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है।' उच्चतम न्यायालय ने स्थापना दी थी कि हमारे संविधान का कोई भाग ऐसा नहीं है, जिसका संशोधन नहीं हो सकता। गोलकनाथ के चर्चित मुकदमे में 11 जजों की न्यायपीठ ने छह न्यायाधीशों के बहुमत से पूर्व विनिश्चय को उलट दिया था और कहा था कि 'यद्यपि अनुच्छेद 368 में कोई अलग अपवाद नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वे अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं हो सकते। यदि ऐसे किसी अधिकार का संशोधन करना है तो नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी।' गोलकनाथ फैसले के बाद केशवानंद वाद का फैसला आया। गोलकनाथ वाद के समय से ही प्रश्न उठाया जा रहा था कि 'क्या मौलिक अधिकारों के बाहर भी संविधान का कोई उपबंध है, जो संशोधन की प्रक्रिया से मुक्त है?' केशवानंद के मुकदमे में बहुमत ने गोलकनाथ के मत को उलट दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं, जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संशोधन संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन के लिए है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित करने का अधिकारी होगा। न्यायालय ने भारत की संप्रभुता, अखंडता, परिसंघीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन, संसदीय प्रणाली आदि अनेक विषयों को संविधान के आधारिक लक्षण बताए। इस तरह संशोधन की प्रक्रिया कठिन हो गई है।

विपक्षी दलों का मोर्चा आइएनडीआइए संविधान बदलने और खत्म करने की निराधार कल्पना बार-बार दोहरा रहा है। संविधान में आपातकाल के लिए देश की आंतरिक अशांति को आधार बताया गया है। इंदिरा गांधी ही आंतरिक अशांति से पीड़ित थीं। देश नहीं। उन्होंने आपातकालीन प्रविधान (अनुच्छेद 352) का दुरुपयोग किया। आइएनडीआइए को आपातकाल (1975-77) के समय पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 का अध्ययन करना चाहिए। संविधान के विद्वान डा. डीडी बसु ने ठीक लिखा है कि '42वां संशोधन एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण ही था। इसके माध्यम से संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन हुए। 53 अनुच्छेद एक साथ बदले गए। सातवीं अनुसूची में भी परिवर्तन किए गए। यह उपबंध किया गया कि कोई उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या जिसमें ऐसे कानून के अंतर्गत अधीनस्थ विधान भी सम्मिलित हैं, संविधान विरुद्ध होने के आधार पर उसे अमान्य नहीं कर सकेगा।' इस प्रकार 42वां संशोधन न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों की शक्ति को घटाने वाला था। कहा गया कि उच्चतम न्यायालय किसी राज्य विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा। संविधान संशोधन अधिनियमों के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का भी संशोधन हुआ। उपबंध किया गया कि जिस विधि को संविधान संशोधन विधि बताया जाएगा, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

स्पष्ट है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान और उसके आत्मा को ही कुचल दिया था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आई। जनसंघ जनता पार्टी का मुख्य घटक था। नई सरकार ने 43वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन के न्यायपालिका के अधिकार की बहाली की। सभी जनविरोधी प्रविधानों को निरस्त कर दिया। संविधान के प्रति भारतीय जन गण मन की निष्ठा है। संविधान बदलने या पूरा संविधान ही खारिज करने और तानाशाही लाने जैसे आरोप हास्यास्पद हैं। भारतीय संविधान के इतिहास में संविधान के साथ छेड़खानी का निंदनीय कृत्य दूसरा नहीं मिलता। विपक्षी संविधान बदलने या हटाने की बात उठाकर आपातकाल की संवैधानिक त्रासदी की याद दिला रहे हैं। इस दृष्टि से उनका यह कृत्य उपयोगी है। संविधान को तहस-नहस करने के कृत्यों का पाठ और पुनर्पाठ जरूरी है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

गहराता जा रहा है धरती का संकट

रमन कांत

यह सोच सही नहीं कि जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी केवल पर्यावरण संगठनों और सरकारों की है

दुबई में भी दिखा पर्यावरण की उपेक्षा का नतीजा। एएफपी

मानव गतिविधियों के चलते हमारी धरती अनेक प्रकार के झंझावत झेल रही है। बेतरतीब विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी का संकट गहरा रहा है। यही कारण है कि आए दिन किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक तबाही होती रहती है। दुबई शहर बेमौसम बरसात के कारण कराह उठा। 16 अप्रैल को हुई घनघोर बारिश ने वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। वहां एक ही दिन में 250 मिलीमीटर से भी अधिक बरसात हुई। दुबई में इतनी बरसात दो वर्षों में होती है। दुबई की सारी चकाचौंध प्रकृति के एक झटके से बेरौनक हो गई। दुबई में बारिश के कहर के तीन दिन बाद पाकिस्तान ने प्रकृति की मार झेली। वहां हुई जोरदार बारिश के कारण 80 से अधिक लोगों की जान गई और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अप्रैल माह में हिमपात देखने को मिल रहा और वह भी उस समय जब देश के कई हिस्सों में समय से पहले गर्म हवाएं चल रही हैं। बीते दिनों हैदराबाद में भी भारी बारिश देखने को मिली। ऐसी घटनाएं विश्व भर में अब कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। प्रकृति का ऐसा व्यवहार जहां चिंतनीय है, वहीं यह सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह तथ्य किसी से छुपा नहीं कि इन सब घटनाओं के मूल में जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम वर्ष भर नए-नए रूप में प्रकट होते ही रहते हैं।

यह सर्वविदित है कि मानव की प्रकृति के प्रतिकूल गतिविधियां धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं। महासागर हों या पहाड़, नदियां हों या खेती की जमीन सब जगह प्रकृति कराह रही है। अनेक देशों में पहाड़ी क्षेत्रों के जलाशय सूख रहे हैं और वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। इसी कारण आए दिन जब जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने बाहर आते हैं तो मानव के साथ उनका संघर्ष होता है। जंगलों की घटती नमी के कम होने और अत्यधिक तापमान के कारण जंगलों में आग लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बरसाती नदियां सूख रही हैं तो बड़ी नदियों में पानी की मात्रा लगातार घट रही है। खेती वाली जमीन में कार्बन तत्व लगातार घट रहा है। इससे अन्न उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। एक ही देश के अलग-अलग हिस्से सूखे और बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ाने के कारणों में बढ़ती आबादी और उसका उपभोक्तावाद भी शामिल है। अधिक आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए तथा अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति के चलते प्रकृति के संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। उपभोक्तावाद के चलते ही कार्बन डाईआक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें अधिक मात्रा में वातावरण में पहुंच रही हैं। उपभोग की वस्तुओं के निर्माण से लेकर दैनिक जरूरत के पानी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि उसका संरक्षण उस अनुपात में नहीं किया जा रहा है।

कई देशों में जगह-जगह कचरे के पहाड़ बन रहे हैं। दुनिया में प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसके वर्ष 2050 तक कई गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत में भी अच्छा-खासा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो विगत पांच वर्षों में दोगुना हुआ है। इसमें करीब 90 प्रतिशत कूड़े के ढेर, नदी और नालों में जाता है। प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी की जैव-विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है। इस कचरे के छोटे-छोटे कण धीरे-धीरे पानी में घुल जाते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। प्लास्टिक का कचरा धरती के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया है, लेकिन उसका उपयोग कम करने की कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। प्लास्टिक के कचरे से महासागर अटे पड़े हैं। वह अन्य तरह से भी धरती की सेहत के लिए खतरा बन रहा है। इसी कारण इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम धरती बनाम प्लास्टिक है। चूंकि प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे।

पृथ्वी की संपूर्ण जैव-विविधता खतरे में पड़ गई है। मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी हांफने लगी है। उसकी ऐसी हालत किसी के भी हित में नहीं है। कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है। अभी समय है चेतने का, सुधरने का और उपभोक्तावाद पर लगाम लगाने का। अगर हम अब भी नहीं चेते तो संकट इतना गंभीर हो सकता है कि उससे निपटना मुश्किल हो जाए। धरती को बचाने के उपाय अमल में लाने में पहले ही देर हो चुकी है। सरकारों के साथ समाज को भी यह समझना होगा कि आधुनिक जीवनशैली में बदलाव लाए बिना बात बनने वाली नहीं है। हमें भौतिकतावादी जीवन छोड़ना होगा। खाने-पीने की चीजों की बर्बादी रोकनी होगी और बिजली-पानी का किफायती उपयोग करना सीखना होगा। हमें यूज एंड थ्रो संस्कृति का परित्याग करना होगा। यह संभव नहीं कि कुछ लोग तो जीवनशैली बदलें और शेष लोग यह मानकर चलते रहें कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। यह सोच भी सही नहीं कि जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी पर्यावरण संगठनों और सरकारों की है। सरकारें और पर्यावरण संगठन तभी कुछ हासिल कर पाएंगे, जब लोग भी उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे। यह तत्परता सभी को दिखानी होगी-उन्हें कुछ अधिक, जो एसी, लक्जरी कारों, विमानों आदि का प्रयोग अधिक करते हैं। धरती की रक्षा में उसके संसाधनों का अधिकाधिक उपभोग करने वालों की जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि भारत सरीखे देशों को गरीबों के जीवनस्तर में भी सुधार करना है।

(लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

महादान

दान का महत्व सभी धर्मों में बताया गया है। दान की महिमा संतों, विद्वानों और महापुरुषों ने खूब गायी है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों से स्नान, तीर्थयात्रा, यज्ञ, हवन या कोई भी अनुष्ठान करते समय दान का अनुकल्प अनिवार्य है। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पूजन, पाठ, प्रार्थना एवं व्रत आदि के पश्चात दान किए बिना वे पूर्ण नहीं माने जाते। हमारे यहां स्वर्ण दान, भूदान या गोदान की महत्ता सर्वविदित है। अन्नदान, जलदान और वस्त्रदान की परंपरा की गाथा में प्राण दान का भी उल्लेख है। विद्या दान और कन्या दान की कथा तो आदिकाल से सुनी गई है।

आज के युग में जब लोकतंत्र ने जगत को समेट लिया है, तब मतदान का विशेष प्रयोजन राज सत्ता के लिए हो रहा है। यह व्यवस्था का अंग है कि जनमत को स्वीकार किया जाएगा। इसलिए मतदान की महिमा विशिष्ट है। लोकतंत्र में जनमत ही निर्णायक है। इस जनमत का प्रयोग मतदान से ही संभव है, यह स्वाभाविक है। तो फिर मतदान ही लोकतंत्र का भाजक है। यह तथ्य देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि नागरिक अधिकार का स्रोत मतदान ही है। अन्य दानों की तरह यह भी आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। मतदान को कतई राजनीति या समाज या व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बजाय इसे आत्मसत्ता का भजनफल माना जाना चाहिए।

मतदान चाहे किसी भी संस्थान का हो, किसी केंद्र का है, किसी विषय का हो-तंत्र का बल है। और तंत्र के बिना मंत्र भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा। राजा हो या प्रजा, दोनों का संपूर्ण प्रभाव मतगणना से ही लगाना सैद्धांतिक है। व्यावहारिक गणित के अनुसार सही मतदान की सही मतगणना ही जनजीवन की राह है। मतदान का दर्शन प्रथम नागरिक को भी ज्ञात हो और अंतिम नागरिक को भी। सो, मतदाता से लोकतंत्र का अस्तित्व है। वर्तमान युग में मतदान ही सबसे बड़ा दान है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

स्वास्थ्य पेय के नाम पर सेहत से खिलवाड़

देवेंद्रराज सुथार

बाजार में बिक रहे कई पेय पदार्थों में शर्करा की मात्रा कहीं अधिक पाई गई है, जो बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है

हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कामर्स पोर्टलों को बोर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक यानी 'स्वास्थ्य पेय' की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक जांच से पता चला है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्वास्थ्य पेय की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। किसी भी बाद के कानून या विनियमन ने न तो इसे परिभाषित किया है और न ही इसके लिए मानक निर्धारित किए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने स्पष्ट किया है कि डेयरी, अनाज या माल्ट पर आधारित पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्य' या 'ऊर्जा' पेय के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। उसने देश में व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले पेय पदार्थों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। इन पदार्थों के मुख्य उपभोक्ता बच्चे और स्वास्थ्य लाभ कर रही माताएं हैं। इन पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा हमेशा चिंता का विषय रही है।

उनमें से कई में शर्करा की मात्रा कहीं अधिक होती है। यह बच्चों में मोटापा, मधुमेह, दंत और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। विवाद के कारण कुछ पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा कम हो गई है, लेकिन इससे 'स्वास्थ्य' या 'ऊर्जा' पेय के रूप में उत्पादों के विपणन की समस्या का समाधान नहीं होता है। स्वादयुक्त जल-आधारित पेय, कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड दोनों को ऊर्जा पेय कहा जाता है। इससे यह आभास होता है कि ये पेय पदार्थ स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं या ऊर्जा देते हैं, लेकिन पोषण विशेषज्ञ ऐसे दावों को भ्रामक और नुकसानदायक बताते हैं। कंपनियों का दावा है कि उत्पादों पर लेबल लगाया जाता है और सामग्री का उल्लेख किया जाता है इसलिए उपभोक्ता निर्णय ले सकते हैं, पर भारत में बहुत कम लोग लेबल पढ़ते हैं और जो कुछ वे पढ़ते हैं उसे समझते भी कम हैं। अधिकांश लोग प्रिंट विज्ञापन या स्क्रीन पर दिखाए गए इनके लाभों पर विश्वास करते हैं, कभी-कभी मशहूर हस्तियों द्वारा भी इसका समर्थन किया जाता है।

इस क्षेत्र में स्पष्ट नियामक मानदंडों और प्रथाओं की आवश्यकता है, क्योंकि मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए योग्य मानदंड लागू करने का दायित्व नियामक अधिकारियों पर है। इसमें न केवल स्वास्थ्य पेय के वर्गीकरण को परिभाषित और मानकीकृत करना शामिल है, बल्कि लेबलिंग और विज्ञापन प्रथाओं पर कड़े दिशानिर्देश भी लागू करना शामिल है। निर्माताओं को उनके दावों की सत्यता के लिए जवाबदेह ठहराकर उपभोक्ताओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सशक्त बना सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सरकार पर निर्भरता बढ़ाने वाला सोच

'वैकल्पिक एजेंडे का अभाव' शीर्षक से युक्त आलेख में संजय गुप्त ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्रों का जो विश्लेषण किया है, वह गौरतलब है। विपक्षी दलों के एजेंडे में भविष्य के विकसित भारत का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है वह देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षा सरकार पर निर्भर रखने वाला अधिक है। जिसमें कर्ज माफी, एमएसपी, सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को धनराशि जैसी लोकलुभावन चुनावी घोषणाएं हैं, जिनका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है। विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इस तरह की सरकारी सहायता के लिए धन कहां से आएगा? जबकि मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकालों में लोकहितैषी योजनाओं को लागू करने से पहले उनके धरातल तक सफल क्रियान्वयन और अर्थव्यवस्था की चिंता की। इसीलिए मोदी सरकार की उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुफ्त कोरोना वैक्सीन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास जैसी जनहितकारी योजनाएं न केवल सफल रहीं, अपितु वास्तविक लाभार्थियों ने उसका लाभ भी उठाया। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार ने देश के विकास में बाधक पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, अलगाववाद और अनुच्छेद-370 के उन्मूलन के साथ वैश्विक स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था को पांचवें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और अपने तीसरे संभावित कार्यकाल में इसे तीसरे स्थान पर लाने की बात कर रहे हैं। अपने चुनावी एजेंडे में प्रधानमंत्री मोदी जहां भविष्य के भारत-निर्माण की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकारी निर्भरता की पुरानी लीक पर चलते हुए देश को पीछे धकेलने की चेष्टा करता दिखाई दे रहा है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

अगर-मगर वाले घोषणा पत्र

आलेख 'वैकल्पिक एजेंडे का अभाव' में संजय गुप्त ने विपक्ष के घोषणा पत्रों के वादों को अगर-मगर के दायरे में रखते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि उनके घोषणा पत्र मूलतः भाजपा की नीतियों के विरोध तक ही सीमित हैं। लोकलुभावन वादे रेवड़ियों की तरह परोसे गए हैं। वित्तीय संसाधनों की अनदेखी करते हुए घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। कांग्रेस, डीएमके, सपा, राजद और वामपंथी दलों के वादे इसी श्रेणी के हैं। विपक्षी दलों ने तो मौजूदा सरकार की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों की अनदेखी कर 'अगर हम सत्ता में आए तो' वाले शब्दों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर इतना ही कहना पर्याप्त है कि विपक्ष के घोषणा पत्रों में कोई दम नहीं है और किसी ठोस एजेंडा के अभाव में प्रभावहीन हैं। मोदी सरकार की दस वर्षों की उपलब्धियों पर मात्र बुलडोजर चलाने की मंशा और मानसिकता विपक्ष के घोषणा पत्रों में है और इसके अलावा कुछ नहीं।

कैलाश मेहरा, गुरुग्राम

वोट प्रतिशत का गिरना

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक त्योहार भारत के लोकसभा चुनाव पर सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, लेकिन आम मतदाताओं में वोटिंग को लेकर थोड़ा उत्साह कम देखने को मिला। लोकसभा के चुनाव में 75 से 80 प्रतिशत तक वोटिंग का अनुमान लेकर चला जाता है। वोटिंग प्रतिशत के गिरने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे भयंकर गर्मी, उम्मीदवारों को लेकर उत्साह की कमी, कई राज्यों में शादियों का सीजन होना। लेकिन वोटिंग के लिए किसी भी बहाने को स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कम वोटिंग लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। दे जितना ज्यादा देश के अंदर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। शासन व्यवस्था के अंदर आम जनता की भागीदारी का स्तर उतना ज्यादा ही ऊपर उठेगा। जिसके कारण लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से एक शासन व्यवस्था के रूप स्थापित होगा।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

घिसी-पिटी बातें

विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की रांची रैली में एक बार फिर यही अधिक सुनने को मिला कि लोकतंत्र के साथ संविधान खतरे में है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल पिछले एक अर्से से यही बात करने में लगे हुए हैं। आम चुनावों की घोषणा होने के उपरांत इन दलों ने इसे अपना एक मुख्य मुद्दा सा बना लिया है कि यदि नरेन्द्र मोदी की सत्ता में वापसी हुई तो इस बार के आम चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव साबित होंगे और संविधान का बचना भी मुश्किल है। क्या यह विडंबना नहीं कि लोकतंत्र और संविधान के खतरे में होने पर सबसे ज्यादा जोर वह कांग्रेस दे रही है जिसने देश पर न केवल आपातकाल थोपा, बल्कि संविधान में मनमाने परिवर्तन किए। भले ही आपातकाल का दौर गुजरे कई दशक बीत गए हों, लेकिन देश अभी उसे भूला नहीं है। यह विचित्र है कि जिन दलों ने इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें से कुछ अब लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के जुमले को दोहराने में लगे हैं। यह स्थिति यही रेखांकित करती है कि आइएनडीआइए के पास उन मुद्दों का अभाव है जिन्हें आगे कर वह जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। निःसंदेह ऐसा नहीं है कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं और मोदी सरकार ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आइएनडीआइए के घटक दल अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से भी कोई प्रभावी वैकल्पिक एजेंडा जनता के सामने नहीं रख सके। उनके एजेंडे में कई ऐसी बातें हैं जो एक-दूसरे के विपरीत हैं। क्या कांग्रेस अथवा उसके सहयोगी दल यह बता सकते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो किसके घोषणा पत्र पर अमल किया जाएगा। रांची की रैली में यह भी सुनाई दिया कि मोदी सरकार जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। इस तरह के आरोपों पर इसलिए शायद ही कोई ध्यान दे, क्योंकि दिल्ली की सरकार के नियंत्रण वाला तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को दिए जा रहे भोजन और दवाओं के बारे में कुछ अलग ही रिपोर्ट दे रहा है। यह ठीक है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन यदि वे तार्किक और जनता के गले उतरने वाले न हों, तो फिर वे केवल खबरों का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। रांची की रैली में जहां सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोदी सरकार से खतरा बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने यह कहकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की कि भाजपा अगर फिर सत्ता में आई तो आदिवासी समाज के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा हो कि आइएनडीआइए के घटक दल यह समझें कि इस तरह की घिसी-पिटी और प्रभावहीन बातें करने से या आरोप लगाने से बात बनने वाली नहीं है।

सावधानी बरतें

प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। विगत एक सप्ताह से मौसम विभाग लू की चेतावनी जारी कर रहा है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। शेखपुरा में सर्वाधिक तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की मानें तो अभी ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न जिलों में स्कूलों का समय घटा दिया गया है। जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क है। गर्मी से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 2019 में औरंगाबाद और गया में एक दिन में 50 से अधिक लोगों की भीषण गर्मी से मौत का मामला सामने आया था। ज्यादातर मौतें दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे के बीच हुई थीं। बिहार में एक दिन में गर्मी के प्रकोप से मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। अभी मौसम में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। खासकर, बच्चों और वृद्धों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। इस मौसम में तरल पेय पदार्थ जैसे पानी, छाछ, लस्सी, मौसमी फल आदि का अधिक सेवन किया जाना चाहिए। पोटैशियम व मिनरल वाले फल-सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। धूप में निकलने पर सिर को ढंककर रखें। बाहर निकलने से पहले पानी पी लें। यदि तेज बुखार, सुस्ती, बेहोशी, चक्कर आ रहे हैं तो इसका कारण लू हो सकता है। ऐसे में पीड़ित को ठंडे स्थान पर रखें, ठंडे पानी की पट्टी दें तथा चिकित्सक से तुरंत परामर्श करें। बच्चों को ऐसे मौसम में स्कूल बस में अधिक पसीना आता है। इसके कारण उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने की आशंका अधिक रहती है। उन्हें मौसमी फल अधिक खाने को दें। दोपहर में भी खाने के लिए पौष्टिक भोजन दें। किसी भी स्थिति में पेट खाली न रहे।

भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बेहतर उपाय है। यदि इसकी चपेट में आ जाते हैं तो घरेलू उपचार की बजाय तुरंत चिकित्सक से सलाह लें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान प्रतिशत संतोषजनक है?

आज का सवाल

क्या कांग्रेस और सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में विरोधाभास उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है?

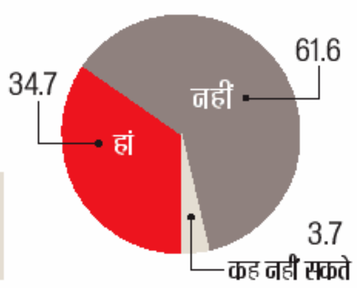

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संविधान पर व्यर्थ की बयानबाजी

हृदयनारायण दीक्षित

संविधान के प्रति भारतीय जन गण मन की निष्ठा है। संविधान बदलने या पूरा संविधान ही खारिज करने और तानाशाही लाने जैसे आरोप हास्यास्पद हैं

भारत में संविधान की सत्ता है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन कुछ समय से बहस चली है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव में भारी बहुमत पाकर संविधान बदल देंगे। बहस व्यर्थ है। संविधान साधारण अभिलेख नहीं है। जड़ नहीं, गतिशील संस्था है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहते हैं। अब तक लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में ही संविधान संशोधन के स्पष्ट प्रविधान हैं। संविधान बदलने और संशोधन करने में मूलभूत अंतर है। संविधान संशोधन विषयक प्रविधान पर संविधान सभा में बहस चली थी। बहस में हिस्सा लेते हुए एचवी कामथ ने कहा था, 'संशोधन आखिरकार क्या है? संशोधन का अर्थ हो सकता है संविधान में कुछ परिवर्तन। उसमें कुछ जोड़ना या उसका निरसन,' लेकिन यहां संशोधन को लेकर तो कोई बहस ही नहीं, बल्कि संविधान बदलने या खत्म करने की हास्यास्पद बयानबाजी है।

संविधान निर्माता संविधान संशोधन की आवश्यकता के प्रति सजग थे। संविधान सभा में पीएस देशमुख ने कहा था कि 'भविष्य में कुछ समय तक संविधान में तमाम परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। इसलिए संविधान संशोधन आसान बनाना जरूरी है।' बृजेश्वर प्रसाद ने कहा कि 'किसी संविधान की अपरिवर्तनशीलता के कारण नई चीजें नहीं आ सकतीं। परिवर्तन रुक जाता है।' सभा में अनेक सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। डा. आंबेडकर ने सभी सदस्यों के उत्तर दिए। भारत में संशोधन की शक्ति विधायिका में निहित है। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि 'हम संविधान संशोधन को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। एक श्रेणी में संसद का साधारण बहुमत पर्याप्त है। दूसरी श्रेणी के संशोधन में दो तिहाई बहुमत आवश्यक है। तीसरी श्रेणी में देश की आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है।' यहां संशोधन की पूरी प्रक्रिया औचित्यपूर्ण है।

संविधान सभा में कई सदस्यों ने संशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। तर्क यह था कि कभी आम जनता राजनीतिक प्रणाली को बदलने की मांग कर सकती है। डा. आंबेडकर ने कहा, 'जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में दो तिहाई बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह मान लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है।' उच्चतम न्यायालय ने स्थापना दी थी कि हमारे संविधान का कोई भाग ऐसा नहीं है, जिसका संशोधन नहीं हो सकता। गोलकनाथ के चर्चित मुकदमे में 11 जजों की न्यायपीठ ने छह न्यायाधीशों के बहुमत से पूर्व विनिश्चय को उलट दिया था

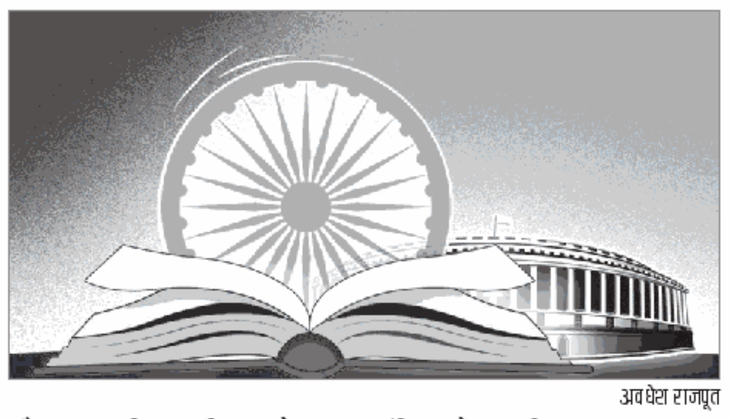

अवधेश राजपूत

और कहा था कि, 'यद्यपि अनुच्छेद 368 में कोई अलग अपवाद नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वे अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं हो सकते। यदि ऐसे किसी अधिकार का संशोधन करना है तो नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी।' गोलकनाथ फैसले के बाद केशवानंद वाद का चर्चित फैसला आया। गोलकनाथ वाद के समय से ही प्रश्न उठाया जा रहा था कि 'क्या मौलिक अधिकारों (भाग-3) के बाहर भी संविधान का कोई उपबंध है, जो संशोधन की प्रक्रिया से मुक्त है?' केशवानंद के मुकदमे में बहुमत ने गोलकनाथ के मत को उलट दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं, जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संशोधन संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन के लिए है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित करने का अधिकारी होगा। न्यायालय ने भारत की संप्रभुता, अखंडता, परिसंघीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन, संसदीय प्रणाली आदि अनेक विषयों को संविधान के आधारिक लक्षण बताए। इस तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी कठिन हो गई है।

विपक्षी दलों का मोर्चा आइएनडीआइए संविधान बदलने और खत्म करने की निराधार कल्पना बार-बार दोहरा रहा है। संविधान में आपातकाल के लिए देश की आंतरिक अशांति को आधार बताया गया है। इंदिरा गांधी ही आंतरिक अशांति से पीड़ित थीं। देश नहीं। उन्होंने आपातकालीन प्रविधान (अनुच्छेद 352) का दुरुपयोग किया। आइएनडीआइए को आपातकाल (1975-77) के समय पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 का अध्ययन करना चाहिए। संविधान के विद्वान डा. डीडी बसु ने ठीक लिखा है कि '42वां संशोधन एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण ही था। इसके माध्यम से संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन हुए। 53 अनुच्छेद एक साथ बदले गए। सातवीं अनुसूची में भी परिवर्तन किए गए। यह उपबंध किया गया कि कोई उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या जिसमें ऐसे कानून के अंतर्गत अधीनस्थ विधान भी सम्मिलित हैं, संविधान विरुद्ध होने के आधार पर उसे अमान्य नहीं कर सकेगा।' इस प्रकार 42वां संशोधन न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों की शक्ति को घटाने वाला था। कहा गया कि उच्चतम न्यायालय किसी राज्य विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा। संविधान संशोधन अधिनियमों के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का भी संशोधन हुआ। उपबंध किया गया कि जिस विधि को संविधान संशोधन विधि बताया जाएगा, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह मूल संविधान के ठीक उल्टा है। देश को संविधान का वह अपमान याद रखना चाहिए।

स्पष्ट है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान और उसके आत्मा को ही कुचल दिया था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आई। जनसंघ जनता पार्टी का मुख्य घटक था। नई सरकार ने 43वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन के न्यायपालिका के अधिकार की बहाली की। सभी जनविरोधी प्रविधानों को निरस्त कर दिया। संविधान के प्रति भारतीय जन गण मन की निष्ठा है। संविधान बदलने या पूरा संविधान ही खारिज करने और तानाशाही लाने जैसे आरोप हास्यास्पद हैं। भारतीय संविधान के इतिहास में संविधान के साथ छेड़खानी का निंदनीय कृत्य दूसरा नहीं मिलता। विपक्षी संविधान बदलने या हटाने की बात उठाकर आपातकाल की संवैधानिक त्रासदी की याद दिला रहे हैं। इस दृष्टि से उनका यह कृत्य उपयोगी है। आपातकाल संवैधानिक त्रासदी था। संविधान को तहस-नहस करने के कृत्यों का पाठ और पुनर्पाठ जरूरी है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

गहराता जा रहा है धरती का संकट

मानव गतिविधियों के चलते हमारी धरती अनेक प्रकार के झंझावत झेल रही है। बेतरतीब विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी का संकट गहरा रहा है। यही कारण है कि आए दिन किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक तबाही होती रहती है। दुबई शहर बेमौसम बरसात के कारण कराह उठा। 16 अप्रैल को हुई घनघोर बारिश ने वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। वहां एक ही दिन में 250 मिलीमीटर से भी अधिक बरसात हुई। दुबई में इतनी बरसात दो वर्षों में होती है। दुबई की सारी चकाचौंध प्रकृति के एक झटके से बेरौनक हो गई। दुबई में बारिश के कहर के तीन दिन बाद पाकिस्तान ने प्रकृति की मार झेली। वहां हुई जोरदार बारिश के कारण 80 से अधिक लोगों की जान गई और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अप्रैल माह में हिमपात देखने को मिल रहा और वह भी उस समय जब देश के कई हिस्सों में समय से पहले गर्म हवाएं चल रही हैं। बीते दिनों हैदराबाद में भी भारी बारिश देखने को मिली। ऐसी घटनाएं विश्व भर में अब कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। प्रकृति का ऐसा व्यवहार जहां चिंतनीय है, वहीं यह सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह तथ्य किसी से छुपा नहीं कि इन सब घटनाओं के मूल में जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम वर्ष भर नए-नए रूप में प्रकट होते ही रहते हैं।

यह सर्वविदित है कि मानव की प्रकृति के प्रतिकूल गतिविधियां धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं। महासागर हों या पहाड़, नदियां हों या खेती की जमीन सब जगह प्रकृति कराह रही है। अनेक देशों में पहाड़ी क्षेत्रों के जलाशय सूख रहे हैं और वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। इसी कारण आए दिन जब जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने बाहर आते हैं तो मानव के साथ उनका संघर्ष होता है। जंगलों की घटती नमी के कम होने और अत्यधिक तापमान के कारण जंगलों में आग लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बरसाती नदियां सूख रही हैं तो बड़ी नदियों में पानी की मात्रा लगातार घट रही है। खेती वाली जमीन में कार्बन तत्व लगातार घट रहा है। इससे अन्न उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। एक ही देश के अलग-अलग हिस्से सूखे और बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ाने के कारणों में बढ़ती आबादी और उसका उपभोक्तावाद भी शामिल है। अधिक आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए तथा अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति के चलते प्रकृति के संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। उपभोक्तावाद के चलते ही कार्बन डाईआक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें अधिक मात्रा में वातावरण में पहुंच रही हैं। उपभोग की वस्तुओं के निर्माण से लेकर दैनिक जरूरत के पानी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि उसका संरक्षण उस अनुपात में नहीं किया जा रहा है।

रमन कांत

यह सोच सही नहीं कि जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी केवल पर्यावरण संगठनों और सरकारों की है

दुबई में भी दिखा पर्यावरण की उपेक्षा का नतीजा ● एएफपी

कई देशों में जगह-जगह कचरे के पहाड़ बन रहे हैं। दुनिया में प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसके वर्ष 2050 तक कई गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत में भी अच्छा-खासा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो विगत पांच वर्षों में दोगुना हुआ है। इसमें करीब 90 प्रतिशत कूड़े के ढेर, नदी और नालों में जाता है। प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी की जैव-विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है। इस कचरे के छोटे-छोटे कण धीरे-धीरे पानी में घुल जाते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। प्लास्टिक का कचरा धरती के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया है, लेकिन उसका उपयोग कम करने की कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। प्लास्टिक के कचरे से महासागर अटे पड़े हैं। वह अन्य तरह से भी धरती की सेहत के लिए खतरा बन रहा है। इसी कारण इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम धरती बनाम प्लास्टिक है। चूंकि प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे।

पृथ्वी की संपूर्ण जैव-विविधता खतरे में पड़ गई है। मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी हांफने लगी है। उसकी ऐसी हालत किसी के भी हित में नहीं है। कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है। अभी समय है चेतने का, सुधरने का और उपभोक्तावाद पर लगाम लगाने का। अगर हम अब भी नहीं चेते तो संकट इतना गंभीर हो सकता है कि उससे निपटना मुश्किल हो जाए। धरती को बचाने के उपाय अमल में लाने में पहले ही देर हो चुकी है। सरकारों के साथ समाज को भी यह समझना होगा कि आधुनिक जीवनशैली में बदलाव लाए बिना बात बनने वाली नहीं है। हमें भौतिकतावादी जीवन छोड़ना होगा। खाने-पीने की चीजों की बर्बादी रोकनी होगी और बिजली-पानी का किफायती उपयोग करना सीखना होगा। हमें यूज एंड थ्रो संस्कृति का परित्याग करना होगा। यह संभव नहीं कि कुछ लोग तो जीवनशैली बदलें और शेष लोग यह मानकर चलते रहें कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। यह सोच भी सही नहीं कि जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी पर्यावरण संगठनों और सरकारों की है। सरकारें और पर्यावरण संगठन तभी कुछ हासिल कर पाएंगे, जब लोग भी उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे। यह तत्परता सभी को दिखानी होगी-उन्हें कुछ अधिक, जो एसी, लक्जरी कारों, विमानों आदि का प्रयोग अधिक करते हैं। धरती की रक्षा में उसके संसाधनों का अधिकाधिक उपभोग करने वालों की जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि भारत सरीखे देशों को गरीबों के जीवनस्तर में भी सुधार करना है।

(लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

महादान

दान का महत्व सभी धर्मों में बताया गया है। दान की महिमा संतों, विद्वानों और महापुरुषों ने खूब गायी है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों से स्नान, तीर्थयात्रा, यज्ञ, हवन या कोई भी अनुष्ठान करते समय दान का अनुकल्प अनिवार्य है। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पूजन, पाठ, प्रार्थना एवं व्रत आदि के पश्चात दान किए बिना वे पूर्ण नहीं माने जाते। हमारे यहां स्वर्ण दान, भूदान या गोदान की महत्ता सर्वविदित है। अन्नदान, जलदान और वस्त्रदान की परंपरा की गाथा में प्राण दान का भी उल्लेख है। विद्या दान और कन्या दान की कथा तो आदिकाल से सुनी गई है। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र, मकरध्वज और कर्ण की दान शृंखला सदैव चलती रहेगी।

आज के युग में जब लोकतंत्र ने जगत को समेट लिया है, तब मतदान का विशेष प्रयोजन राज सत्ता के लिए हो रहा है। यह व्यवस्था का अंग है कि जनमत को स्वीकार किया जाएगा। इसलिए मतदान की महिमा विशिष्ट है। लोकतंत्र में जनमत ही निर्णायक है। इस जनमत का प्रयोग मतदान से ही संभव है, यह स्वाभाविक है। तो फिर मतदान ही लोकतंत्र का भाजक है। यह तथ्य देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि नागरिक अधिकार का स्रोत मतदान ही है। अन्य दानों की तरह यह भी आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। मतदान को कतई राजनीति या समाज या व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बजाय इसे आत्मसत्ता का भजनफल माना जाना चाहिए।

मतदान चाहे किसी भी संस्थान का हो, किसी केंद्र का है, किसी विषय का हो-तंत्र का बल है। और तंत्र के बिना मंत्र भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा। राजा हो या प्रजा, दोनों का संपूर्ण प्रभाव मतगणना से ही लगाना सैद्धांतिक है। व्यावहारिक गणित के अनुसार सही मतदान की सही मतगणना ही जनजीवन की राह है। मतदान का दर्शन प्रथम नागरिक को भी ज्ञात हो और अंतिम नागरिक को भी। सो, मतदाता से लोकतंत्र का अस्तित्व है। इस प्रकार वर्तमान युग में मतदान ही सबसे बड़ा दान है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

सरकार पर निर्भरता बढ़ाने वाला सोच

'वैकल्पिक एजेंडे का अभाव' शीर्षक से युक्त आलेख में संजय गुप्त ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्रों का जो विश्लेषण किया है, वह गौरतलब है। विपक्षी दलों के एजेंडे में भविष्य के विकसित भारत का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है वह देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षा सरकार पर निर्भर रखने वाला अधिक है। जिसमें कर्ज माफी, एमएसपी, सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को धनराशि जैसी लोकलुभावन चुनावी घोषणाएं हैं, जिनका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है। विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इस तरह की सरकारी सहायता के लिए धन कहां से आएगा? जबकि मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकालों में लोकहितैषी योजनाओं को लागू करने से पहले उनके धरातल तक सफल क्रियान्वयन और अर्थव्यवस्था की चिंता की। इसीलिए मोदी सरकार की उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुफ्त कोरोना वैक्सीन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास जैसी जनहितकारी योजनाएं न केवल सफल रहीं, अपितु वास्तविक लाभार्थियों ने उसका लाभ भी उठाया। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार ने देश के विकास में बाधक पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, अलगाववाद और अनुच्छेद-370 के उन्मूलन के साथ वैश्विक स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था को पांचवें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और अपने तीसरे संभावित कार्यकाल में इसे तीसरे स्थान पर लाने की बात कर रहे हैं। अपने चुनावी एजेंडे में प्रधानमंत्री मोदी जहां भविष्य के भारत-निर्माण की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकारी निर्भरता की पुरानी लीक पर चलते हुए देश को पीछे धकेलने की चेष्टा करता दिखाई दे रहा है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

घोषणा पत्र में विरोधाभास

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'वैकल्पिक एजेंडे का अभाव' पढ़ा। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सरकार की नीतियों को गलत ठहराते हैं, लेकिन अभी तक अपनी नीति जनता के समक्ष पेश नहीं किए हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के घोषणा पत्र में विरोधाभास है। एक ओर देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो दूसरी ओर उसकी सहयोगी पार्टी माकपा ने देश के सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने की घोषणा की है। विपक्षी पार्टियां सरकार को बेरोजगारी व महंगाई के लिए जिम्मेदार मानती है, स्वयं सरकारी नौकरी देने की बात करती है, लेकिन रोजगार सृजित करने के तौर तरीके के बारे में मौन रहती है। महंगाई नियंत्रित करने की रूप रेखा भी कोई दल प्रस्तुत नहीं कर सका है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

मतदान प्रतिशत बढ़ाने को कानून बने

19 अप्रैल को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कम मतदान का होना चिंताजनक है। मतदाताओं की उदासीनता एवं लापरवाही से लोकतंत्र की मूल भावना को ठेस पहुंचती है, क्योंकि हो सकता है कि चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र की अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व न करता हो। मतदान बढ़ाने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। मताधिकार को कर्तव्य मानें।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

ममता के बयान के मायने

इस लोकसभा चुनावों में लगता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। वे अभी से ही वर्ष 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर नजर रख रही हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जिसमें उन्होंने एक चुनावी जनसभा में घोषणा की कि वे चुनाव बाद आइएनडीआइए का नेतृत्व करेंगी। 'एकला चलो' की घोषणा करने वाली ममता बनर्जी ने अपना पक्ष सामने रख दिया है कि अगर मैं मंजूर हूं तो आइएनडीआइए का नेतृत्व कर सकती हूं। स्पष्ट है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को कमतर आंक रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार के चुनाव परिणाम के बाद यदि आइएनडीआइए सम्मानजनक सीटें नहीं ला सकी तो क्या इसका अस्तित्व बचा रहेगा? कांग्रेस राहुल गांधी या पार्टी अध्यक्ष खरगे को दरकिनार कर ममता को अपना नेता स्वीकार करेगी? वामपंथी, एनसीपी, आप, सपा, राजद आदि अनेक दल ममता को तीसरे मोर्चे का नेतृत्वकर्ता स्वीकार करेंगे? इधर, विरोधाभास है कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव में स्पष्ट तौर पर मुस्लिम समुदाय से भाजपा, कांग्रेस एवं भाकपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं करने की अपील की है। कांग्रेस व माकपा दोनों दल बंगाल में आइएनडीआइए के घटक नहीं हैं। ममता ने कहा है कि उक्त तीनों पार्टियों की साठगांठ है कि किसी भी कीमत पर तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में धराशाई किया जाए।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

यदि आप नोटा का बटन दबाने का फैसला करते हैं तो यही संदेश देते हैं कि आपको इसकी परवाह नहीं कि देश में शासन तंत्र सुधरे। मकरंद@Makarand_S

कोई समझाएगा कि मतदान प्रतिशत कम रहने के आधार पर यह अनुमान लगाने के पीछे कौन सा विज्ञान है कि भाजपा हार रही है और अधिक रहने पर यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया जाता है कि वह आराम से जीत रही है?

संदीप भटेरा@Sauryasaksham84

देश में विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। उसकी व्यापकता चकित करने वाली है। करीब सौ करोड़ मतदाता होते हुए भी भारत के चुनाव दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी हैं। हमें उन लोकतांत्रिक देशों से उपदेश नहीं चाहिए, जिनकी आबादी हमारे मोहल्लों के बराबर है और जो यह भी नहीं जान पाते कि उसका सही जेंडर क्या है?

सुशांत सरीन@sushantsareen

लोकतंत्र और संविधान के तथाकथित ठेकेदार अपनी बात ग्रामीण भारत के मतदाताओं को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इसलिए कि आज वहां लोगों का सपना विकास और परिवर्तन का है।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

जनपथ

आएंगे अब देश में दिन ऐसे भी यार,
किया करेंगे रैलियां गुंडों के परिवार।
गुंडों के परिवार लगाएंगे वे नारा,
मिले जेल से छूट यही अधिकार हमारा।
हम भारत के लोग फिस इडी रह जाएंगे,
गलत-सलत कुछ लोग अगर चुनकर आएंगे!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 11

****

हम जीवन और एक-दूसरे की देखभाल करने के लिए पृथ्वी पर हैं।
-जिया बास्टिडा, मैक्सिकन जलवायु कार्यकर्ता

आम चुनाव के लिए सियासी पारा तो पहले ही चढ़ गया था, अब 2019 की तुलना में कुछ जगहों पर हुए कम मतदान पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को बूथ तक लाने के प्रयास करें और मतदाता भी अपने वोट की ताकत को समझकर लोकतंत्र को मजबूत करें।

जागरूक हों मतदाता

पहले और सबसे बड़े चरण में 21 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने की सात चरणों वाली मतदान प्रक्रिया का पहला पड़ाव पार हो गया है। आम चुनाव के लिए सियासी पारा तो पहले ही ऊपर चढ़ गया था, मगर 2019 की तुलना में कुछ जगहों पर हुए कम मतदान पर चर्चाओं और दावों का दौर एक बार फिर गर्म है। पिछली बार की तरह बिहार में सबसे कम वोट पड़े, तो नगालैंड के छह जिलों में तो राजनीतिक वजहों से एक वोट तक नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर समेत कई जिलों में मतदान प्रतिशत का गिरना सभी दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी वजह गेहूं की कटाई, सहालग, बेतहाशा गर्मी व मतदाताओं की उदासीनता बताई जा रही है। दरअसल, उम्मीद से ज्यादा मतदान होने पर अमूमन यह माना जाता है कि मतदाता बदलाव के लिए एकजुट हो रहे हैं, दूसरी ओर, वोटिंग अपेक्षा से कम रहने पर मतदाताओं की उदासीनता की वजह पूरे राजनीतिक वर्ग से असंतोष को माना जाता है। वजहें जो भी रही हों, कम वोटिंग उन 75 सीटों पर लड़ाई को जरूर दिलचस्प बना सकती है, जहां 2019 के चुनावों में कांटे की टक्कर यानी हार-जीत का फर्क 20 हजार वोटों से कम रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश भर में कम वोटिंग हुई। इसलिए, एक ही चरण के चुनाव से देश में मतदाताओं के ट्रेंड के बारे में अनुमान लगाना भी सही नहीं होगा। हां, युवाओं की उदासीनता जरूर निराश करती है। पहली बार वोट देने का अधिकार पाए युवाओं में केवल 38 फीसदी ने 2024 के चुनावों के लिए बतौर मतदाता पंजीकरण करवाया है। इस मामले में बिहार (17 फीसदी) तो सबसे पीछे है, राजनीतिक तौर पर जागरूक माने जाने वाले महाराष्ट्र (22 फीसदी) की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कम मतदान से किसे फायदा पहुंचेगा और किसे नुकसान, यह तो बाद की बात है, फिलहाल तो सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे मतदाताओं को बूथ तक लाने और मतदान के प्रति जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाएं, क्योंकि यह तय है कि नजदीकी मुकाबलों में जो दल अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में कामयाब रहेंगे, वे ज्यादा लाभ में रहेंगे। मतदाताओं को भी समझना होगा कि नागरिक के प्रति वह मतदान उनकी एक जिम्मेदारी और वोट उनकी ताकत है, जिसके जरिये वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। पूरे पांच साल बाद मतदाताओं को यह मौका मिलता है, इसलिए अपने वोट का उपयोग करने के साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

ताकि तपती धरती को राहत मिले

आज हमारी पृथ्वी के सामने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का भयावह संकट है। इससे निपटने के लिए प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार को प्रोत्साहन देना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार के बीच तालमेल से हम एक हरित और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

वर्ष 1970 से प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन पृथ्वी को बचाने और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सबसे आवश्यक जिन दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है, वे हैं प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार। जबकि ये दोनों परस्पर जुड़े प्राकृतिक और सामाजिक समाधान जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह पर जीवन को अक्षुण्ण रखने के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

वीर सिंह

प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को जीवन-ऊर्जा में रूपांतरित करने की नैसर्गिक घटना है और शाकाहार प्राकृतिक दोहन को नियंत्रित करने की मानव की मौलिक प्रकृति-प्रदत्त जीवन शैली। इन्हें प्रोत्साहित किए बिना हमारे जीवित ग्रह को बचा पाना संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसके माध्यम से हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। यह नैसर्गिक क्रिया न केवल वनस्पति के साम्राज्य को बनाए रखती है, वरन हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। ग्लूकोज पृथ्वी के समस्त जीव रूपों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। वास्तव में यह सौर ऊर्जा ही है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैव-रसायन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसी से हमारा ग्रह एक जिंदा ग्रह बना है।

वर्तमान में हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के ऐसे कुचक्र में फंसी है, जिससे अगर यह बाहर न निकली, तो इसका भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी को इस दुश्चक्र से मुक्त करने के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति है प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम क्षमता तक अभिवृद्धि। जलवायु परिवर्तन की केंद्रीय संचालक है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण और जीवाश्म ईंधनों के दहन जैसी मानव गतिविधियों ने इस नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया है, जिससे

वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में खतरनाक वृद्धि हुई है तथा ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ा है। इससे निपटने के लिए हमें न केवल बचे हुए वनों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करनी चाहिए, वरन वनीकरण और पुनर्वनीकरण प्रयासों को भी बढ़ावा देना चाहिए। हरित आवरण का विस्तार करके हम प्रकाश संश्लेषण के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखा जा सकता है।

इसके साथ-साथ शाकाहार को अपनाना पृथ्वी की जीवटता में और प्राण फूंकने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पशुधन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है, जो वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 14.5 प्रतिशत है। पशुओं के सघन औद्योगिक पालन से न केवल भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस मीथेन उत्पन्न होती है, बल्कि इसके लिए व्यापक भूमि, पानी और चारा की भी आवश्यकता होती है, जिससे वनों की कटाई और जैव विविधता के क्षरण को बढ़ावा मिलता है।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में मांस उद्योग एक बड़ा स्रोत है। इसके विपरीत पौधों पर आधारित आहार में कार्बन पदचिह्न काफी कम होता है। शाकाहार खान-पान की एक शैली ही नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जिसे अपनाकर हम प्रकाश संश्लेषण के निकटस्थ, अर्थात सूर्य की शक्ति के सबसे निकट, जीवन यापन कर प्रकृति के सिद्धांतों का अनुपालन कर सकते हैं। वैसे भी जीवन विकास के क्रम में अपनी आकृति-प्रकृति, एनाटॉमी, शारीरिक कार्यिकी, अपने स्वभाव और अपनी चेतना से मानव एक शाकाहारी प्राणी है। शाकाहार को अपनाकर हम पृथ्वी की पारिस्थितिकी सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। वैसे भी वनस्पति-आधारित आहार कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिनमें मोटापा और कई तरह के कैंसर के खतरों से बचाव सम्मिलित हैं।

प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार के बीच तालमेल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए पौधों की शक्ति का उपयोग करने के उनके साझा लक्ष्य में स्पष्ट है। संपूर्ण मानवता द्वारा शाकाहार अपनाने और प्रकाश संश्लेषण को चरम तक ले जाने वाली प्राथमिकताओं का समर्थन कर हम प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं और एक हरित और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अपेक्षित नियंत्रण करने के साथ-साथ प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार पर्यावरण के लिए कई सह-लाभ प्रदान करते हैं। शाकाहारी भोजन पैदा करने के लिए मांस-प्रधान आहार की तुलना में काफी कम पानी और भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण के उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं। जैसे, जिस भूमि क्षेत्र में 100 क्विंटल शाकाहारी भोजन पैदा होता है, उतने क्षेत्र में केवल 10 क्विंटल मांस ही पैदा होगा। शाकाहार खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन का अवशोषण होता है, जबकि मांस उत्पादन में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।

इस तरह शाकाहार पर निर्भर रहकर मानव अपने अधिकांश प्राकृतिक वनों को बचाते हुए मिट्टी, जल और जैव विविधता का संरक्षण कर सकता है, लुप्तप्राय जीवों के अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण को त्वरित कर पृथ्वी को उसकी सुंदरता, स्वास्थ्य, जीवटता और वैभव लौटा सकता है तथा अपने लिए आशाओं और प्रसन्नताओं से भरा भविष्य पैदा कर सकता है। शाकाहार के दर्शनशास्त्र को जीवन का मूलभूत तत्व बनाकर हम सभी के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाली एक न्यायसंगत और टिकाऊ खाद्य प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा लोगों को अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य हेतु शाकाहार पर निर्भर बनाने और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर ठोस नीति तैयार होनी चाहिए। पृथ्वी पर जीवन को अक्षुण्ण रखने वाली प्राकृतिक प्रणालियों का पोषण और सुरक्षा हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है।

-प्रोफेसर एमेरिटस, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्वामी रामतीर्थ

काम, लोभ और क्रोध के कारण मनुष्य निराशा का अनुभव करता है और उसका निष्फल अहं काम, लोभ और क्रोध से ही तृप्ति की खोज करता है। इस प्रकार हमारी चेतना निराशा के दुश्चक्र में फंस कर रह जाती है।

पतन का कारण है हमारी स्वार्थपरता

स्वार्थपरता मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जब किन्हीं कारणों से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं, तभी स्वार्थपरता अस्तित्व में आती है। साथ ही, जो मनुष्य मानव-स्वभाव के वास्तविक स्वरूप से अनजान होता है, उसमें भी इस प्रवृत्ति का जन्म होता है। जन्म-जन्मांतर के विकास क्रम में हमारे भीतर नाना प्रकार के जो संस्कार एकत्रित होते जाते हैं, उनसे मानवीय चेतना आच्छादित हो जाती है। ये संस्कार ही इच्छाओं के रूप में प्रकट होते हैं और इन इच्छाओं के द्वारा हमारी चेतना और ज्ञान का दायरा सिमटता चला जाता है। स्वार्थपरता का दायरा इच्छाओं के दायरे के समान ही होता है। तरह-तरह की इच्छाओं के अवरोध के कारण अपने यथार्थ स्वरूप की अभिव्यक्ति आत्मा के लिए असंभव हो जाती है। इससे हमारा जीवन अपने तक ही केंद्रित और सीमित हो जाता है। इसके लिए हम इच्छानुकूल वस्तुओं की खोज करते रहते हैं, जो सब की सब परिवर्तनशील और क्षणभंगुर होती हैं। किंतु ऐसी नाशवान वस्तुओं द्वारा वास्तविक तृप्ति होना असंभव है। इस प्रकार असंतोष का एक सामान्य भाव सदैव बना रहता है और इसी के साथ सभी प्रकार की चिंताएं भी उत्पन्न होती रहती हैं।

मनुष्य का निष्फल अहंकार जितने मुख्य रूपों में व्यक्त होता है, उनमें काम, लोभ और क्रोध मुख्य हैं। काम, लोभ के समान ही है। केवल इसके तृप्त होने की विधि भिन्न है। काम स्थूल शरीर के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। लोभ हृदय की अशांति की एक अवस्था है और वह अधिकार व सत्ता की लिप्सा से पैदा होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिकार और शक्ति की खोज की जाती है। इस प्रयत्न में मनुष्य आंशिक रूप से ही सफल हो पाता है और उसका यह आंशिक संतोष इच्छा की अग्नि को शांत करने के बजाय और बढ़ाता जाता है। इस कारण लोभ के लिए अपने सम्मुख स्थित विशाल क्षेत्र पर विजय पाना असंभव होता है और वह मनुष्य को लगातार असंतुष्ट बनाए रखता है। इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध इच्छाओं के खंडित होने से उत्पन्न होता है। उसका लक्ष्य होता है, इच्छाओं के तृप्त होने के मार्ग की बाधाओं को दूर करना।

इस प्रकार काम, लोभ और क्रोध की प्रवृत्तियों के द्वारा ही मनुष्य निराशा का अनुभव करता है और उसका निष्फल अहं काम, लोभ और क्रोध के द्वारा ही अधिक तृप्ति के साधनों की खोज करता है। इस प्रकार हमारी आत्मा की चेतना असीम निराशा के दुश्चक्र में फंस कर रह जाती है। काम, लोभ या क्रोध की पूर्ति न होने से निराशा उत्पन्न होती है। इन तीनों पतनकारी प्रवृत्तियों का विस्तार स्वार्थपरता के साथ ही होता है। इसलिए स्वार्थपरता ही वास्तव में हमारी समस्त निराशा और चिंताओं का मूल कारण है। पर इस प्रयत्न में वह अपने आपको ही पराजित करती है। वह इच्छाओं के द्वारा अपनी तृप्ति करना चाहती है। लेकिन परिणाम में उसे एक असंतोष ही मिलता है।

इच्छाओं का त्याग ही सुख...

सूत्र

स्वार्थपरता का अनिवार्य परिणाम असंतोष और निराशा ही है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए सुख की समस्या का एकमात्र उपाय इच्छाओं का त्याग है। बाहरी दमन के कारण इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, वे सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही जड़ से मिटाई जा सकती हैं।

दूसरा पहलू

सुबह खाया जानेवाला हल्का खाना शरीर और मस्तिष्क को दिन भर ऊर्जा मुहैया कराता रहता है।

नाश्ता न करने जैसा है अस्वास्थ्यकर नाश्ता

अनेक अभिभावक जानते हैं कि सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चों के लिए नाश्ता करना आवश्यक है। काम पर जाने से पहले अनेक युवा भी नाश्ता करने से कतराते हैं, जबकि सुबह खाया जानेवाला हल्का खाना शरीर और मस्तिष्क को दिन भर ऊर्जा मुहैया कराता रहता है। अपने नए अध्ययन में हमने यह जानने की कोशिश की है कि सुबह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करने, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह चीज खा लेने और सुबह कुछ न खाने का शरीर पर क्या असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की परियोजना के तहत हमने ऑस्ट्रेलिया के पांच हाई स्कूलों के 13-14 वर्षों के कुल 648 छात्रों को अपने अध्ययन में शामिल किया। ये सभी विज्ञान के छात्र थे और निजी स्कूलों में पढ़ते थे।

एंड्र्यू जे मार्टिन

हमने अपने अध्ययन में पाया कि जिन छात्रों ने सुबह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता किया था, कक्षाओं में वे पढ़ाई के प्रति ज्यादा प्रेरित थे और उनकी उपलब्धियां भी अधिक थीं।

हमने उनसे पूछा कि वे सप्ताह में कितने दिन नाश्ते में फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रोटीन, साबुत अनाज आदि लेते हैं। वे सप्ताह में कब-कब चीनी वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रसंस्कृत मांस, फास्ट फूड, नुकसानदेह बेकरी उत्पाद आदि नाश्ते में लेते हैं। हम जानना चाहते थे कि कितने आत्मविश्वास से वे स्कूल का काम करते हैं, विज्ञान विषय को कितना महत्व देते हैं और सीखने के प्रति उनमें कितनी ललक है?

अस्वास्थ्यकर नाश्ता करने वाले और बिना नाश्ता किए स्कूल आने वाले छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगन और एकाग्रता समान रूप से कम पाई गई।

हमने पाया कि जिन छात्रों ने सुबह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता किया था, कक्षाओं में वे पढ़ाई के प्रति ज्यादा प्रेरित थे और उनकी उपलब्धियां भी अधिक थीं। कक्षा की जांच परीक्षा में भी उन्हें ज्यादा नंबर मिले।

जबकि बिना नाश्ता किए स्कूल आने वाले छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगन और एकाग्रता कम पाई गई। पर अध्ययन का सबसे हैरान करने वाली बात थी कि अस्वास्थ्यकर नाश्ता करने वाले छात्रों की एकाग्रता का स्तर भी बिना नाश्ता किए स्कूल आने वाले सहपाठियों की तरह ही था। इसका मतलब यह है कि सुबह अस्वास्थ्यकर नाश्ता करना नाश्ता न करने जैसा ही नुकसानदेह है। हालांकि यह पता लगाना अभी शेष है कि ऐसा क्यों है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अस्वास्थ्यकर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा शरीर और मस्तिष्क को उस तरह चालित नहीं कर पाती, जो पढ़ने और सीखने के लिए जरूरी है। अध्ययन में शामिल सभी छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली गई थी, लेकिन इस पर व्यापक अध्ययन होना अभी बाकी है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बच्चों के स्वास्थ्यकर नाश्ता करने या न करने में क्या संबंध है। *(कन्वर्सेशन से)*

-साथ में एमा बर्न्स, जोएल पीयरसन, केइको सीपी बोस्टविक और रोजर कैनेट।

आंकड़े

मोबाइल फोन निर्यात

पिछले एक दशक में मोबाइल फोन के निर्यात में हमारे देश ने शानदार कामयाबी हासिल की है और अब छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।

2014	23
2018	16
2020	11
2021	10
2022	6

स्रोत: ITC

सुपात्र को ज्ञान देने से वह ज्ञान फलीभूत हो उठता है, जबकि कुपात्र को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता।

सुपात्र को ही ज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

रामकृष्ण परमहंस को संसार का कोई भी सुख और वैभव आकर्षित नहीं कर पाता था। उनके भीतर किसी प्रकार की लालसा नहीं थी। वह कभी किसी वस्तु का अभाव महसूस नहीं करते थे, किंतु अपनी अस्वस्थता के दिनों में अवश्य दुखी हो गए थे। वह उपासना के दौरान अपने कष्टों को देवी मां के समक्ष प्रकट करते थे।

एक बार वह बड़े करुण होकर देवी मां से बोले, मां, तूने संसार में इतनी बुराइयों को बनाया ही क्यों? जीवों में भी तूने ज्ञानी की जगह अज्ञानी ही ज्यादा बनाए। अगर तुमने ज्ञानी लोग ज्यादा बनाए होते, तो इस संसार की यह दशा कदापि नहीं होती।

अपनी शारीरिक अक्षमता और संसार की आत्मिक दुर्बलता उन्हें और विचलित करती थी। वह संसार का कल्याण करना चाहते थे। वह अपने भक्तों में भी सदैव सुपात्रों की तलाश में रहा करते थे।

एक दिन किसी ने पूछा, भक्त तो सभी भक्त हैं, उनमें सुपात्रों की तलाश क्यों? उन्होंने कहा, सुपात्र को ज्ञान देने से वह ज्ञान फलीभूत हो उठता है, जबकि कुपात्र को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। अज्ञानी और कुपात्र तो उस फूटे ढोल के समान हैं, जिसे रात दिन बजाने पर भी ताल नहीं निकल सकती, संगीत नहीं उभर सकता।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 30 नवंबर, 1989

उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग मुख्यमंत्री का इस्तीफा

उ.प्र. विधानसभा भंग मुख्यमंत्री का इस्तीफा
लखनऊ, 29 नवम्बर (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी है, मगर नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को कार्यभार संभालने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफे के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी।

अपराधों के दुश्चक्र में नाबालिग

नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध को कम करने के लिए सही सजा का प्रावधान हो, ताकि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके।

दीपिका शर्मा | समाज

जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और बैट-बॉल जैसी चीजें शोभा देती हैं, उस उम्र के बच्चों के हाथों में चाकू-छुरे जैसी चीजें देखना दिल दहला देने वाली घटना है। हाल के कुछ वर्षों में नाबालिग बच्चों द्वारा अपराध की घटनाओं में तेजी दिख रही है।

हाल ही में तिमारपुर इलाके में महज माचिस देने से मना करने पर एक नाबालिग ने 21 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी। साल भर पहले भी उसी नाबालिग ने महज कंधा टकराने पर 16 साल के एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। उसके बाद कुछ समय तक बाल सुधार गृह में रहने के बाद वह बाहर आ गया। वहीं 2023 के अंत में दक्षिण पूर्वी जिले के बदरपुर इलाके में तीन नाबालिगों ने किशोरी दोस्त के साथ गैंगरेप किया और वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये घटनाएं आपराधिक मामलों में नाबालिगों की संलिप्तता की बानगी हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के

आंकड़ों की मानें, तो वर्ष 2022 में देश में नाबालिगों द्वारा कुल 30,555 अपराध किए गए, जिनमें झपटमारी, लूटपाट, वाहन चोरी, घरों में चोरी, ठगी की वारदातें और यहां तक कि दुष्कर्म के मामले भी शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ किए गए अपराधों में 3,545 नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनमें से 345 मामले जबरन शादी के इरादे से महिलाओं के अपहरण से संबंधित मामले पाए गए। नाबालिगों द्वारा अपराध के मामले में देश की राजधानी 2,340 से अधिक मामलों के साथ छठे स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर महाराष्ट्र(4,406), फिर मध्य प्रदेश (3,795) और राजस्थान (3,063) हैं।

नाबालिगों द्वारा अपराध के मामलों में इजाफे का क्या कारण है? क्या इन सबके पीछे का कारण दोषपूर्ण परवरिश व सामाजिक माहौल में बदलाव है या नई तकनीकी दुनिया। फरवरी 2024 में बिहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें मरने से पहले इंसान को तड़पता हुआ देखने के लिए तीन नाबालिग लड़कों ने कैब ड्राइवर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा कि किसी की भी रुह कांप जाए। एक ने ड्राइवर के गले में फंदा डाला, तो दूसरे ने ड्राइवर के गले में कील घोंप दी। इसके बाद वे रस्सी से ड्राइवर का गला तब तक कसते रहे, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस के सामने उन्होंने कबूला कि उसकी जान निकलते देखने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। उन्होंने यह भी कबूला कि कत्ल करने का यह तरीका उन्होंने यूट्यूब से सीखा और उस ड्राइवर से उनकी न तो जान-पहचान थी और न ही कोई दुश्मनी।

पुलिस के लिए भी ऐसी विकृत मानसिकता चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि ऐसे संगीन अपराधों में भी नाबालिगों को कड़ी सजा देने का प्रावधान नहीं है। उन्हें बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है या उनकी काउंसिलिंग करा कर ही घर भेज दिया जाता है, जिस कारण कई बार बड़े-बड़े अपराधी उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें अपराध के दलदल में फंसा देते हैं। बालमन को पैसों का मोह, मौज-मस्ती तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। अपराध से जुड़ी फिल्मों और वेब सीरीज का भी बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और उनमें आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देता है।

बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं। यदि इनका भविष्य संवर गया, तो देश का विकास मुमकिन है और यदि इसी गति से नाबालिगों के अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी होती रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब देश पर माफिया का राज होगा। इसलिए जरूरी है कि नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध को कम करने के लिए सही सजा का प्रावधान हो और ऐसी नीति बनाई जाए कि बच्चों को जुल्म की दुनिया में कदम रखने से रोका जा सके। नाबालिगों को उसके अपराध की प्रकृति के आधार पर सजा का उचित प्रावधान होना चाहिए, ताकि जघन्य अपराधों की तरफ रुख करने से बालमन बचा रहे व कोई उन्हें बहला-फुसलाकर अपराध की राह पर न धकेल सके।

सरकार, समाज, माता-पिता, अभिभावकों को बच्चों के बेहतर व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। 11 से 16 वर्ष की किशोरावस्था किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए इस उम्र में उन्हें सही-गलत की पहचान कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि स्वस्थ मानसिकता के साथ बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव बन सकें।

कल्पमेधा

जब तक तुम स्वदेश-प्रेम को मानवता से बाहर नहीं खदेड़ देते, तब तक तुम कभी भी एक शांतिमय विश्व का निर्माण नहीं कर सकते।

- बर्नार्ड शा

बेखौफ बंदी

पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष में दो की मौत से एक बार फिर जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार की रात को कुछ कैदियों ने दो कैदियों पर हमला कर उन्हें धारदार हथियार से मार डाला। जेल प्रशासन का कहना है कि जिन कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई, उनका किसी आपराधिक गिरोह से संबंध नहीं था। उनके बीच आपसी रंजिश थी, जो खूनी संघर्ष में परिणत हो गई। यानी इस बात की जानकारी जेल प्रशासन को थी कि कुछ कैदियों में कहासुनी की वजह से तनाव बना हुआ था। विचित्र है कि प्रशासन ने उस विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। खुद पुलिस महानिरीक्षक ने माना है कि अगर समय रहते इस विवाद को सुलझा लिया गया होता, तो दो कैदियों की मौत नहीं होती। इस घटना के बाद भी फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैदियों को धारदार चीजें कैसे हाथ लग गईं, जिससे उन्होंने दो कैदियों की जान ले ली, जबकि जेलों में ऐसी हर चीज को बंदियों से दूर रखा जाता है, जिनसे वे किसी पर हमला या खुदकुशी कर सकते हों।

पंजाब की जेलों में कैदियों के रखरखाव को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई लोग तो यहां तक कह चुके हैं कि वहां की कई जेलें अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुकी हैं। संगरूर जेल पर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। कुछ साल पहले वहां से एक कुख्यात गिरोह के अपराधी के अपने जन्मदिन पर केक काटने और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने के बाद तो खासा विवाद हुआ था। ऐसे ही मामले बठिंडा, कपूरथला और पटियाला की जेलों से भी दर्ज हुए थे, जब अपराधियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय देखा या फोन पर बाहर के लागों से बात करते, किसी साजिश को अंजाम देते पाया गया। पठानकोट सैन्य अड्डे पर हुए आतंकी हमले के बाद तो सेना ने भी अपनी जांच के बाद चिंता जताई थी कि पंजाब की जेलों में बैठे अपराधी बाहरी लोगों से संपर्क में रहते और मादक पदार्थों की तस्करी आदि में संलिप्त हैं। तब सभी जेलों में औंचक निरीक्षण किया और जेलों के प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया था। मगर स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया। आरोप लगते रहे हैं कि जेलों के प्रशासन से जुड़े लोग ही अपराधियों को मोबाइल फोन आदि उपलब्ध कराते हैं।

हालांकि जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प का मामला केवल पंजाब तक सीमित नहीं है। दिल्ली की अति सुरक्षित और चाकचौबंद मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में भी ऐसी कई घटनाएं हाल के कुछ महीनों में देखी जा चुकी हैं। तिहाड़ में तो कुख्यात आपराधिक गिरोहों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया। ऐसी घटनाएं होने की खबरें देश के दूसरे प्रदेशों की जेलों से भी आ जाती हैं। जेलों को एक प्रकार के सुधारगृह के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है, ताकि अपराधियों को गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर लाया जा सके। मगर जेलें अगर यातनागृह और दबंग अपराधियों की सुरक्षित शरणस्थली का रूप लेती जा रही हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। जेल प्रशासन और अपराधियों के बीच अगर किसी तरह का गठजोड़ बनता है, तो यह ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।

खानपान का हिसाब

अजीब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा का मुख्य बिंदु यह हो गया है कि वे अपने भोजन में क्या-क्या और क्यों खा रहे हैं! हालत यह है कि अदालत में मुकदमे के समांतर उनके खानपान को लेकर बहस हो रही है। एक ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कहना है कि केजरीवाल जेल में जानबूझ कर ऐसा खाना खा रहे हैं, जिससे उनके शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाए, और बीमारी के बहाने वे जमानत पर जेल से बाहर निकल आएं। केजरीवाल ने अदालत में ईडी के दावों को खंडन किया कि वे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाने के लिए आम और मिठाई नहीं खा रहे हैं। इस मसले पर खींचतान का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब सफाई के तौर पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल के घर से अड़तालीस बार खाना आया, उसमें केवल तीन बार आम आए थे।

जाहिर है, इस बात का हिसाब रखा, देखा और परखा जा रहा है कि कितनी बार और क्या-क्या खाना आया और उसका शरीर पर क्या असर हो सकता है। कभी जेल की चारदीवारी के भीतर आलू-पूड़ी, तो कभी आम या मिठाई खाना या वजन बढ़ना या फिर चिकित्सक की निर्धारित सूची से अलग भोजन करना मुद्दा बन रहा है। ईडी की यह दलील भी हैरान करती है कि केजरीवाल कुछ खास चीजें खाकर अपने शरीर में किसी ज्यादा बड़ी दिक्कत को न्योता दे रहे हैं, ताकि उन्हें जमानत मिल जाए! गौरतलब है कि केजरीवाल मधुमेह के मरीज हैं और उन्हें रोजाना इंसुलिन लेनी पड़ती है। उनका कहना है कि उन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श करने की इजाजत दी जाए। निश्चित रूप से वे जिस पद और कद के व्यक्ति हैं और यों भी उनकी सेहत के लिहाज से चिकित्सीय परामर्श की सुविधा मिलनी चाहिए। मगर एक पहलू यह भी है कि जेल में रहते हुए उन्हें जैसा भोजन मिल रहा है, वैसा किसी अन्य कैदी को शायद ही मिलता हो। बहरहाल, बेहतर हो कि अरविंद केजरीवाल जिस आरोप में सलाखों के पीछे हैं, सुनवाई और बहस का केंद्र वह हो, न कि उनका खानपान मुख्य मुद्दा बने।

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की तलाश

अभी 'गैलप' द्वारा दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। उसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत में युवा सबसे ज्यादा दुखी हैं।

सुरेश सेठ

भारतीय संस्कृति में गुरुजनों और वरिष्ठ नागरिकों का हमेशा से सम्मान किया जाता रहा है। यह व्यक्ति को बचपन से ही घुट्टी में पिला दिया जाता रहा है। मगर जमाने ने अपने तेवर कुछ यों बदले, आधुनिकता का एक नया सैलाब कुछ यों उमड़ा कि वृद्धजन उसमें कहीं पीछे रह गए। जिस प्रकार की आर्थिक मंदहाली खेती से लेकर उद्योगों तक बार-बार दस्तक देने लगती है, उससे यह भी लगता है कि देश के युवा भी असमय बूढ़े हो जाएंगे। अभी 'गैलप' द्वारा दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। उसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत में युवा सबसे ज्यादा दुखी हैं। खुशहाली और जीवन संतोष के मामले में भारत दुनिया के 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। यहां मध्यम आयुवर्ग के लोग तो फिर भी संतुष्ट हैं, लेकिन न तीस साल से कम उम्र के युवा खुश हैं और न देश के वरिष्ठ नागरिक व्यवस्थित ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। बेशक एलएसआइ (एजिंग स्टडी इन इंडिया) का एक सर्वेक्षण कहता हो कि देश में 96 फीसद बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं होता और 98 फीसद बुजुर्ग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों? शायद इसलिए कि हमारे देश के बुजुर्गों को अध्यात्म, धर्म और संतोष का सहारा मिल जाता है। यह विडंबना जाहिर है कि भारत के 74 फीसद बुजुर्ग आज शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। देश की औसत आयु में भी आठ वर्ष की वृद्धि हो गई है, लेकिन 79 फीसद के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

देश के बुजुर्गों की बात करें तो कोविड महामारी के बाद जब बंदी हटी तो उम्मीद थी कि उत्पादन और निवेश में वृद्धि होगी। बेकार हो गए लोगों को काम मिलेगा। भुखमरी से लेकर बीमारी तक से छुटकारा मिल जाएगा। जो आंकड़े सामने आ रहे थे वे भी आश्वस्त करते थे कि पिछले दशक में भारत विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में दसवें से पांचवें स्थान तक आ गया। दो-तीन वर्षों में तीसरे स्थान तक पहुंचने को है। मगर शिकायत थी कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को वह सब नहीं मिल पा रहा, जो खुशहाल भारत में उन्हें मिलना चाहिए। बीमारियां भी वृद्धों को घेरती हैं। सरकार ने आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन उसमें पांच लाख रुपए वार्षिक आय तक की सीमा रेखा ने बहुत से वृद्धों को इस सुविधा से बाहर कर दिया।

मगर अब भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में वृद्धों की भी यथोचित सुध ली गई है। एक मानवीय फैसले में कहा गया है कि अब देश के सत्तर से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। यानी, जो भी इस उम्र से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिनकी संख्या औसत आयु बढ़ने के कारण बढ़ रही है, बेइलाज नहीं रहेंगे। चाहे बदलते हुए भौतिक मूल्यों के कारण उनके नाते-रिश्तेदार उनकी परवाह करें या न करें। वंचितों के लिए आयुष्मान चिकित्सा योजना तो पहले से शुरू है, लेकिन अब इसमें वृद्धजनों की स्पष्ट परवाह उनके संतोष और उनकी खुशी में वृद्धि कर सकती है और वे आने वाले समय में अपने आप को संरक्षित महसूस कर सकते हैं। मगर ऐसा माहौल भारत में बन जाएगा, इसके बारे में प्राचीन संस्कृति की तलाश में जुटे भारत के लिए एक चिंतनीय बात है।

अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के वृद्धों को देखें तो पाते हैं कि चाहे भारत के तीन-चौथाई बुजुर्ग शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, जैसा कि 'एजिंग स्टडी इन इंडिया' भी बताती है, लेकिन उनके उचित इस्तेमाल के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। विश्व में तो

> **अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के वृद्धों को देखें तो पाते हैं कि चाहे भारत के तीन-चौथाई बुजुर्ग शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, जैसा कि 'एजिंग स्टडी इन इंडिया' भी बताती है, लेकिन उनके उचित इस्तेमाल के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। विश्व में तो बहुत से देशों में जब तक वृद्ध शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से चैतन्य हैं, तो उनका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक मूल्यों की बेहतर स्थापना के लिए किया जाता है। अमेरिका में इस बार भी जो दो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ में हैं, उनकी आयु अस्सी के आसपास हैं।**

बहुत से देशों में जब तक वृद्ध शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से चैतन्य हैं, तो उनका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक मूल्यों की बेहतर स्थापना के लिए किया जाता है। अमेरिका में इस बार भी जो दो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ में हैं, उनकी आयु अस्सी के आसपास हैं। लेकिन भारत में तो अट्ठावन वर्ष की आयु में लोग सेवानिवृत्त किए जाते हैं। देश की बेकारी का समाधान भी इसी में ढूंढ़ा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति की इस आयु को और घटा दिया जाए। इस तरह बहुत सारे सक्रिय लोग, जो देश के विकास कार्यों में अपना बौद्धिक और शरीरिक योगदान देकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें निष्क्रिय बना कर बिठा दिया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी ने केंद्रीय स्तर पर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ वर्ष तक कर दी, लेकिन पंजाब सहित कई राज्यों में यह नियम लागू नहीं होता। न्यायालयों से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तो अनेक जांचों आदि में समाहित कर लिया जाता है, मगर सामान्य नौकरियों से मुक्त हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठने को विवश होते हैं। समाजचेत्ता कहते हैं कि देश के सही निर्देश में उचित योगदान के लिए अगर वृद्धों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ा दी जाए तो शायद उनके योगदान से एक ओर तो समाज को सही दशा-दिशा मिल जाए और दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों द्वारा अलग-अलग राज्यों में 'ओल्ड एज पेंशन' और नई पेंशन में से चयन के विद्रोही स्वरों को भी कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। अब कहा जा सकता है कि मौजूदा संकल्प पत्र में तो युवा, महिला, किसान, गरीब के साथ वरिष्ठ नागरिकों की यथोचित परवाह करने का वादा किया गया है। बेशक यह वादा पूरा होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिले, अनुदान या अनुकंपा का आसरा नहीं। महिलाओं को आरक्षण के वादे स्थगित या लंबित न हों, किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य मिले और गरीब या वंचित अमीरों के साथ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की दौड़ में इतना न पिछड़ जाए कि देश के दस फीसद समर्थ वर्ग के पास तो नब्बे फीसद संपदा हो जाए और नब्बे फीसद वंचित वर्ग के पास केवल दस फीसद संपदा का सहारा।

पचास फीसद महिलाएं ऐसी हैं, जो भुगतान के बिना अपनी सेवाएं देती हैं, चाहे घर में दें या बाहर। किसानों का एक वर्ग भरपूर मेहनत के बावजूद कृषि की निवल आय में वृद्धि नहीं कर पाता, क्योंकि वे छिपे हुए बेरोजगार हैं, उन्हें कृषि फसलों के विनिर्माण की ओर मोड़ देना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग उनकी आय में योगदान का सहारा दें। इसी प्रकार अगर वृद्धजनों की योग्यता का भी पूरा इस्तेमाल किया जाए तो देश को एक सार्थक रास्ता मिल सकता है। उसका सत्य की पहचान से विचलित होने का डर कम हो जाएगा।

जिस नैतिकता या सामाजिक मूल्यों की स्थापना की घोषणाएं आजकल फिर होने लगी हैं, अगर उसके ध्वजवाहक वे बुजुर्ग रहें, जिन्हें भारतीय आदर्शों का भली-भांति पता है, तो कोई कारण नहीं कि वृद्धों को एक उपेक्षित वर्ग की तरह भारत में जीने का दुर्भाग्य मिले कि उन्हें अपने नाते-रिश्तेदार तो संभालने के लिए तैयार नहीं और वृद्धाश्रमों की स्थापना का भी रिवाज नहीं होगा। अगर यह संकल्प उभरता है, तो युवा वर्ग, महिलाओं, किसानों और वंचितों के साथ उपेक्षित पर योग्य वृद्धों को भी फालतू सामान की तरह निष्कासित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें भी उचित उपचार के साथ उनकी सेहत की संभाल करते हुए देश के लिए सक्रिय नागरिक बना दिया जाएगा।

छिनते पल

महेश परिमल

समय के मोल की अहमियत पर हर दौर में विचार होता रहा है। इसकी चिंता हर वक्त गहरी रही है और सभी इसे समझते हैं। मगर जमीन पर होता कुछ और है। समय मूल्यवान है, कीमती है, अनमोल है, अमोल है। यह कभी वापस लौटकर नहीं आता। सब कुछ जानते-बूझते हुए भी क्या हमने कभी सोचा कि हमारे आसपास समय के लुटेरे भी हैं, जो हमारा समय चुरा लेते हैं, हमें जीवन में पीछे धकेल देते हैं। हमें कामयाबी तक पहुंचने नहीं देते। कई बार जब हम कोई महत्त्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, तब हमारे पास समय का अभाव होता है। जिन्होंने जीवन में विफलता का स्वाद चखा है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका समय कब, कहां, किस तरह और किसने बर्बाद किया है। विफलता के बाद ही हमें याद आता है कि हमारा कितना समय बर्बाद हुआ। सफल वही, जिसने समय को बर्बाद नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी इसे बेहतर समझती है। पर समय को चुरा लेने वालों ने न जाने कितने युवाओं को भ्रष्ट भी कर दिया है।

आशय यही है कि हम सबके जीवन में कभी समय को चुराने वाले तो कहीं समय को बचाने वाले काम करते हैं। समय को बचाने वाले जीवन संवारते हैं। अपने अनुभवों से ही हम इन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि कहने को दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं दिखता है। बहुत ही बारीक लकीर इन दोनों को विभाजित करती है। हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कभी-कभी बातचीत में इतने अधिक तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं होता। इस बीच वे अपने कई आवश्यक काम नहीं कर पाते। यहां दोनों ही परस्पर समय को गंवाने या चुराने वाले हैं। दोनों ने एक-दूसरे का समय बर्बाद किया।

एक ओर सार्थक बातचीत हमें कुछ सबक देती है, तो दूसरी तरफ निरर्थक बातचीत भी वह सबक देती है कि इस प्रकार की बातचीत में समय लगाना अच्छी बात नहीं है। जहां हमारा समय किसी काम नहीं आ रहा है, न हमारे और न ही किसी अन्य के लिए, तो समझना चाहिए कि वहां समय चुराने वाले काम कर रहे हैं। एक उदाहरण देखा जा सकता है। सड़क किनारे पानी-पूरी खिलाने वाला कई ग्राहकों को एक साथ पानी-पूरी देता है, उन्हें गिन भी लेता है, साथ-साथ ग्राहकों की पसंद के अनुसार पानी-पूरी तैयार करता है। एक साथ कई काम करने के बाद भी वह खुद को चुस्त-दुरुस्त रखता है। इस दौरान उसके पास समय बचता रहता है। अपने कम समय का वह पूरा उपयोग करता है।

कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो कोई हमसे कहता है कि आगे रास्ता खराब है... आप नहीं जा पाएंगे। उस समय वह हमें समय बर्बाद करने वाले के रूप में दिखाई देता है। अगर आगे जाकर सचमुच ही रास्ता खराब मिलता है, तो वही व्यक्ति हमारे लिए समय बचाने वाला बन जाता है। बस इतना ही फर्क होता है दोनों में।

कभी-कभी किसी काम में हमें आवश्यकता से अधिक समय लगता है। इसका आशय यही है कि वहां समय बर्बाद करने वाला तत्त्व काम कर रहा है। कभी कोई काम आसानी से हो जाता है, तो अनजाने में हमारा समय बचाने वाला पक्ष काम आता है। हम अगर तय कर लें कि इस काम में हमें इससे अधिक समय नहीं देना है, तो हम समय बचाने वाला हो गए। कंप्यूटर पर बैठ कर काम करने वाले अक्सर कई घंटे ईमेल देखने करने और जवाब देने में ही लगा देते हैं। जबकि उससे ज्यादा जरूरी काम उनका इंतजार कर रहे होते हैं। किसी की निंदा कथा, ईर्ष्या कथा आदि समय बर्बाद करने वाले ही हैं। दूसरी ओर अच्छे विचार सुनना, बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलना और वह काम करना जिसमें हमारी रुचि हो, तो ये सब हमारे समय बचाने वाले हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **समय बर्बाद करने के कारक हमारे आसपास ही बिखरे होते हैं। जरा ध्यान से देखा जाए, तो समझ में आ जाएगा कि कौन हमारा जीवन संवारने में मददगार है। हर किसी को अपना समय देने की एक सीमा होती है। जो विफल रहे हैं, उनके जीवन में समय चुराने वाले तत्त्व की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।**

आजकल बच्चों का काफी समय मोबाइल और सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों यानी इंस्टाग्राम, वाट्सएप, फेसबुक वगैरह में जाया होता है। इसे वे अभी नहीं समझ पाएंगे। पर बाद में जब कई काम उनसे नहीं हो पाते, तब समझ में आता है कि उन्होंने कितना समय बर्बाद कर दिया। जो लोग अपना टेबल साफ नहीं रख सकते, समय का चोर उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसे समझने के लिए विद्यार्थी की किताबें-कापियां, कपड़े, थैला आदि देखना ही पर्याप्त है। करीने से रखी हुई हर चीज यह बताती है कि वक्त को बचाने वाला मानस उनके साथ है।

समय बर्बाद करने के कारक हमारे आसपास ही बिखरे होते हैं। जरा ध्यान से देखा जाए, तो समझ में आ जाएगा कि कौन हमारा जीवन संवारने में मददगार है। हर किसी को अपना समय देने की एक सीमा होती है। जो विफल रहे हैं, उनके जीवन में समय चुराने वाले तत्त्व की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। ये हमें समय को खोना सिखाते हैं, जबकि समय बचाने वाले समय को बोना सिखाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम किसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इससे भी आवश्यक यह है कि हमें इसकी भी जांच और पहचान कर लेनी चाहिए कि कहीं हम ही तो किसी के लिए समय बर्बाद करने वाले नहीं हैं!

ओझल होता आकाश

बढ़ रहे शहरीकरण के दौर में आज जब रात में आकाश की ओर देखते हैं तो चांद-सितारों की चमक की जगह केवल धुंधलापन दिखाई पड़ता है। उत्पादन, वाहन और शहरी विकास में प्रयुक्त अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण आकाश की ओर परावर्तित होती अतिरिक्त रोशनी प्राकृतिक दृश्य को बाधित कर इस समस्या को जन्म देती है। जिस बल्ब को समय के सबसे महान मानव आविष्कारों में गिना जाता रहा, आज उसकी रोशनी विनाशकारी सिद्ध हो रही है। कृत्रिम प्रकाश का अनुचित उपयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन, वन्यजीवन की लय और तारामंडलीय दृश्यता को प्रभावित कर रहा है। यह अनेक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और निद्रा संबंधित रोगों का जनक है और पशु जीवन की गतिविधियों, आहार की खोज और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। चमकदार बनावटी रात्रि दृश्यों की लालसा में आज मानव वास्तविक सुंदरता को खोता जा रहा है। कभी महान साहित्यिक रचनाओं, खगोल विज्ञान और संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाला तारों से जड़ित आकाश अब आंखों से ओझल हो रहा है।

- खुशी श्रीवास्तव, शाहदरा, दिल्ली

कूटनीतिक तकाजा

'अस्थिर म्यांमा और भारत की मुश्किलें' (लेख, 11 अप्रैल) भारत के पूर्वोत्तर और पड़ोसी देश म्यांमा की संवेदनशील स्थिति का सारगर्भित विश्लेषण करता है। म्यांमा में अलगाववाद दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए भी चुनौती है। एक अन्य पहलू यह भी है कि म्यांमा की आंतरिक अस्थिरता के कारण भारत और बांग्लादेश में शरणार्थी समस्या बढ़ गई है। म्यांमा में इनकी स्थिति को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का घोर उल्लंघन करार दिया गया है। म्यांमा जैसे ही अन्य सैन्य शासन द्वारा शासित देशों जैसे बुर्किना फासो, नाइजर आदि में भी आखिर विपरीत परिणाम तो निर्दोष जनता को ही भोगने पड़ते हैं। चूंकि म्यांमा से भारत के भी सामरिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत को अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर म्यांमा में लोकतंत्र बहाली के कूटनीतिक प्रयास तत्काल करने चाहिए।

- ज्योत प्रकाश गुलाटी, रोहतक

बढ़ती मुश्किलें

जैसे-जैसे चुनावी मौसम के तापमान में वृद्धि हो रही है और मतदाता वोट देने की तैयारी में सक्रिय हो रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे ज्वलंत रूप धारण करते जा रहे हैं। वास्तव में इस परेशानी के चलते गरीब जनता और निम्न मध्यवर्ग सबसे अधिक व्यथा और आर्थिक तनाव महसूस कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों को बेचैन किया हुआ है और रोजमर्रा के आरामदायक जीवनयापन में ये लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, रोजगार और सर्वव्यापी महंगाई से निपटना आगामी केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा होगा। वैसे भी सरकारों का बुनियादी कर्तव्य यही है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की मूल समस्याओं और अहम मुद्दों की पहचान करें और निष्पक्षता से उनका समाधान करें। बहरहाल, उम्मीद है कि लोगों को अनावश्यक तनाव से मुक्ति या राहत मिलेगी।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

युद्ध की आग

ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन की बौछार से इजराइल पर हमला किया, उससे मध्यपूर्व के हालत बेहद संवेदनशील बन गए हैं। हालांकि इन हमलों में ज्यादतर हमले इजराइली वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिए। इजराइल ने कहा कि वह ईरान के विरुद्ध इस लड़ाई को गहरा करना नहीं चाहता है, पर क्या इजराइल शांत रहेगा और ईरान के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा? यह बड़ा प्रश्न है। ईरान-इजराइल की इस तनातनी के बीच हमास और इजराइल के बीच शांति संधि की रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। अब गाजा में जो जानमाल की क्षति हुई है, उसकी भरपाई और दोबारा जीवन बहाल, कब और कैसे होगा, कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। इजराइल और ईरान को समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना इन देशों के अतिरिक्त और भी कई देश युद्ध की आग में जलेंगे।

- बाल गोविंद, सेक्टर 44, नोएडा

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid
www.readwhere.com

क्लाइमेट चेंज पर विकसित देशों का रवैया चिंताजनक

विश्लेषण

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

जलवायु परिवर्तन के खतरे बेशक आम चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दे न हो, लेकिन यह तेजी से बढ़ता वैश्विक संकट है। धरती पर तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका प्रमाण बढ़ रही प्रचंड गर्मी है। क्लाइमेट चेज पर पेरिस करार के तापमान को डेढ़ डिग्री कम करने के संकल्पों की दिशा में ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। इस बार भारत में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। यूं तो मौसम विभाग ने मानसून के सामान्य रहने का अनुमान जारी किया है, लेकिन वैश्विक रिपोर्टों में अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान है। ऐसे में विश्व बैंक, आईएमएफ बैठकों में जलवायु वित्त पर सुस्त प्रगति चिंता की बात है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वार्षिक बैठकें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जरूरी खरबों डॉलर जुटाने की ठोस योजना के बिना खत्म हो गईं। इस साल अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी29) में सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) या नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर चर्चा होनी है। एनसीक्यूजी वह नई राशि है, जिसे विकसित देशों को 2025 से हर साल विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए जुटाना होगा। अमीर देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे 2020 से हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाएंगे, लेकिन वे बार-बार विफल रहे। हाल ही में हुए एक विश्लेषण से पता चला है कि विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह 2023 में नकारात्मक हो गया। इसका मतलब है कि इन देशों को बाहरी वित्तपोषण से मिलने वाली राशि से अधिक भुगतान कर्ज चुकाने के लिए करना पड़ रहा है। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के मकुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2020 से 3,300 अरब डॉलर खो दिए हैं। सबसे गरीब देश अपने बजट का 14 प्रतिशत से अधिक ऋण भुगतान पर खर्च करते हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यह राशि बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों से तमाम जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में विकासशील देशों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने व वैश्विक तापमान में कमी लाने के लिए सहयोग करने के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर विकसित देशों की ओर से प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर देने पर सहमति बनती है, लेकिन विकसित देश इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं। सबसे अधिक अमेरिका की ओर से हीलहवाली है। अब तो वैश्विक तापमान बढ़ने को लेकर अनेक अध्ययन डराने लगे हैं। पत्रिका 'एडवांसेज इन एटमॉस्फेरिक साइंस' में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, दुनिया के कई क्षेत्रों में एक साथ अत्यधिक गर्मी का अनुभव करना एक गर्म ग्रह का 'उभरता लक्षण' बन सकता है। वर्ष 2023 के मौसम और जलवायु की समीक्षा करने वाले नए अनुसंधान में कहा गया है कि पिछले वर्ष अनुभव की गयी कई घटनाएं गर्म होती दुनिया के बारे में पूर्व में की गयी भविष्यवाणियों के अनुरूप हैं। भविष्य में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने पर साल की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और चक्रवात के कारण अत्यधिक बारिश होने की आशंका है। दक्षिण पश्चिमी यूरोप, ब्राजील, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका में 2023 की वसंत ऋतु में गरम हवा देखी गई। उत्तर अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों में पिछले साल जुलाई में एक साथ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई। पिछले साल हवाई और कनाडा के जंगलों में लगी आग भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही है। गर्मी में उम्मीद से अधिक बढ़ोत्तरी बढ़ते तापमान की दस्तक है,चेतना होगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

> इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब करीब 50 हजार डॉलर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है। खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। इस समय भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख टन से बढ़कर दो सौ लाख टन हो गई है। पिछले नौ वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण निर्यातों में 15 गुना वृद्धि है। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत पांच क्षेत्र हैं। एक डेयरी क्षेत्र, दो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, तीन, अनाज का प्रसंस्करण, चार, मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण तथा पाँच, उपभोक्ता वस्तुएं पैकेट बंद खाद्य और पेय पदार्थ।

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण बाजारों में मांग बढने से निजी खपत में भी तेजी आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और प्रमुख मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि अनुकूल मानसूनी मौसम के कारण इस वर्ष 2024 में भारत में अच्छी वर्षा के स्पष्ट संकेत खेती और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद है जिससे कृषि गतिविधियों में और तेजी आएगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी।

गौरतलब है कि विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांवों में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन गाँवों में फ्रिज, दो पहलिया वाहन और टीवी की खरीदारी में सबसे उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पिछले एक दशक में शहरी परिवारों के मुकाबले ग्रामीण परिवारों का खर्च तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय, ग्रामीणों के रोजगार की मनरेगा योजना तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति और मांग में भारी इजाफा हुआ है। इससे ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत में इजाफा हुआ है। यद्यपि अभी आम चुनाव के बाद जून 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के मूर्तरूप लेने में कोई दो माह बकाया है, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मकसद से जिन क्षेत्रों के लिए आगामी पांच सालों के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाना शुरू की गई है उनमें कृषि भी प्रमुख है।

यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस समय पूरी दुनिया में भारत को खाद्यान्न का नया वैश्विक कटोरा माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। गेहूं तथा फलों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर तथा सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर, भारत केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, भिंडी, चावल, चाय, गन्ना, काजू, नारियल, इलायची और काली मिर्च आदि के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में कृषि एवं ग्रामीण विकास का नया आधार तैयार हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 15 फीसदी है। सरकार के द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए एक के बाद एक रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। कृषि बजट में 10 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। किसानों के

सशक्तिकरण, फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों के जनधन खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 3 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित होने जैसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि रसायन, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण, जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं के अधिक उपयोग से किसानों को लाभ हुआ है और इन सबसे जहाँ एक ओर भारत में कृषि क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी एवं लाभदायक बन रहा है, वहीं दूसरी ओर छोटे किसान अधिक लाभांवित हो रहे हैं।

जहाँ कोविड-19 की आपदाओं से लेकर अब तक भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया के जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं भारत ने दुनियाभर में कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का अवसर भी मुठ्ठियों में लिया है। भारत से कृषि निर्यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत से अनाज, गैर-बासमती चावल, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज के अलावा फलों एवं सब्जियों के निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है। भारत के कृषि उत्पादों के बड़े बाजारों में अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल हैं। कई छोटे देशों के बाजार भी मुठ्ठियों में आए है। उल्लेखनीय है कि विश्व बाजार में भारत के मसालों की खुशबू की धमक बहुत अधिक बढ़ी है। चूँकि मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग बढ़ने के रूप में रेखांकित हो रहा है।

इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब करीब 50 हजार डॉलर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है। खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। इस समय भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख टन से बढ़कर दो सौ लाख टन हो गई है। पिछले नौ वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण निर्यातों में 15 गुना वृद्धि है। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत पांच क्षेत्र हैं। एक डेयरी क्षेत्र, दो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, तीन, अनाज का प्रसंस्करण, चार, मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण तथा पाँच, उपभोक्ता वस्तुएं पैकेट बंद खाद्य और पेय पदार्थ। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के इन प्रमुख पांचों क्षेत्रों की व्यापक संभावनाओं को मुठ्ठियों में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे ग्रामीण भारत लाभांवित हो रहे हैं।

यह बात महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2024 में भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण एवं न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) के स्थाई समाधान के लिए जिस तरह प्रभावी पहल की उसके कारण इस सम्मेलन में इन मुद्दों पर कई विकसित देश भारत के किसानों के हितों के प्रतिकूल कोई प्रस्ताव आगे नहीं बड़ा पाए। ऐसे में अब भी भारत अपने किसानों के उपयुक्त लाभ के लिए नीतियाँ बनाते हुए खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक भंडारण की सुविधा से कृषि और ग्रामीण विकास के अभियान को आगे बढ़ा सकेगा।

24 फरवरी 2024 को सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की जिस सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए प्रायोगिक परियोजना के तहत जिन 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को लक्षित किया गया है, उनके माध्यम से पैक्स की किसानों के हित में बहुआयामी भूमिका होगी। देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे अगले 5 साल में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

मुद्दा

एस.एन. वर्मा

महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए डिजिटल शक्ति

देश की आधी आबादी महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की काफी आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जागरूक न होने के कारण अधिकाशं महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार होती जा रही हैं। हालाकि देश भर में महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार पूरे भारत में इस परियोजना के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में परामर्श और सूझ-बूझ के बारे में अवगत कराया गया है। लेकिन यह संख्या का काफी कम है और यह सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है। बिहार,उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के शहरों की महिलाएं इस पहुंच से दूर है। जबकि उनकी आबादी इन छोटे शहरों में ही अधिक हैं और ये महिलाएं ही दूर दराज बैठे साइबर अपराधियों के शिकार आसानी से हो जाते हैं।

पहले हम यह जान लें कि डिजिटल शक्ति क्या है? डिजिटल शक्ति साइबर स्पेस में महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त तथा कुशल बनाने की एक अखिल भारतीय परियोजना है। डिजिटल शक्ति महिलाओं को किसी भी अनुचित घटना के विरुद्ध खड़ा करने की पहल है, जो वे ऑनलाइन स्पेस में देख सकती हैं पिछले एक दशक में भारत में साइबर क्राइम की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुर्भाग्य से, इन अपराधों का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के खिलाफ होता है। इसका प्रमुख कारण भारत में प्रचलित भारी लैंगिक भेदभाव और डिजिटल ज्ञान की कमी भी हैं। एक और चुनौती यह है कि साइबर क्राइम के शिकार ज्यादातर महिलाएं शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं। इसके पीछे सामान्य कारण या तो परिवार और कानून प्रवर्तन से समर्थन की कमी और उनमें जागरूकता का अभाव है। हालांकि साइबर क्राइम के लिए स्पेशलाइज्ड पोर्टल स्थापित किया गया है, लेकिन कई मामले अनसुलझे रह गए हैं। जिन मामलों से जुड़े और जुड़े मामले हैं, वे औसतन 6-12 महीने की रिपोर्ट में बताए गए हैं।

बताते चलें कि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने नवंबर 22 में डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया था। यह अभियान, साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाने का एक अखिल भारतीय परियोजना है। महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्थान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन माध्यम से किसी भी अवैध व अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से शुरू किया है। डिजिटल शक्ति की शुरुआत जून 2018 में देश भर की महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने, लचीलापन अपनाने और साइबर अपराध से सबसे प्रभावी तरीकों से लड़ने में मदद करने के लिए की गई थी। पूरे भारत में इस परियोजना के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा परामर्शों और सूझ-बूझ, रिपोर्टिंग और निवारण व्यवस्था, डेटा गोपनीयता और उनके लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से अवगत कराया गया है। हालाँकि, अभी भी महिला जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साइबरस्पेस में जाने से समय पर महिलाएं सुरक्षित रहें, और सलाह और इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं के कौशल से लाभ हैं। दूसरे चरण में, अभियान को वी थिंक डिजिटल - डिजिटल शक्ति अभियान के रूप में नया रूप दिया गया और 11 फरवरी 2020 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर एक ऑफ़लाइन कार्यशाला के साथ लॉन्च किया गया, जो लखनऊ में 300 से अधिक महिलाओं के लिए आयोजित की गई थी। 12 महीनों की अवधि में, कुल 167 कार्यशालाएँ और छात्रों, शिक्षकों और केस कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों के 1,05,000 से अधिक नेटीजनों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षित किया गया था। डेटा और डिजिटल फ़ुटप्रिंट को समझना , जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, गलत सूचना से लड़ना, साइबर अपराध और निवारण। अभियान को डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2020 के लिए एक चौंपियन प्रोजेक्ट नामित किया गया था। भारत के 6 राज्यों-दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु और मणिपुर में कुल 62,000 लड़कियों और महिलाओं को जागरूक किया गया ।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार व टिप्पणीकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन में निर्भयता लाती है मां दुर्गा की भक्ति साधना

संकलित

दर्शन

वैसे तो हिंदी वर्षानुसार वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत व ग्रीष्म- छह ऋतुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रधान हैं- सर्दी व गर्मी। इन दोनों प्रधान ऋतुओं की संधि बेला को नवरात्रि की संज्ञा दी गई है। दिन और रात्रि के मिलन को संध्याकाल कहते हैं। इस महत्वपूर्ण समय को ईश्वर की आराधना, भजन, संध्या, वंदन व आध्यात्मिक साधना में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय अत्याधिक लाभदायी और कम श्रम से अधिक फल देने वाला माना गया है। संध्या काल को पुण्य पर्व भी कहा गया है। आरोग्य शास्त्र के विद्वानों को विदित है कि आश्विन व चैत्र मास में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में पड़ता है। यह बदलाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रभाव डालता है। अनेकानेक रोग, ज्वर, चेचक आदि मनुष्य पर हावी होने लगते हैं। वैद्य जानते हैं कि वमन, विरेचन, स्वेदन, वस्ति, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का महीना ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसे समय में ही साधना का महत्वपूर्ण पर्व आता है। हिंदू परंपरा के अनुसार, भारतीय पर्व और त्योहारों में नवरात्रि पर्व का अत्यधिक महत्व है। यह वर्ष में दो बार आता है। दुर्गावतरण की पावन कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। देवत्व के संयोग से असुर निकंदिनी महाशक्ति के उद्भव का महत्व हर युग में रहा है। युग की भयावह समस्याओं से त्राण पाने के लिए युग शक्ति के उद्भव की कामना हर मन में उठती है।

पांच मिनट का जीवन

संकलित

प्रेरणा

एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गये वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी माँगा, बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चूँकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह, वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा वत्स तुम्हारा पांच मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था।

अंतर्मन

आज की पाती

कंगना-विक्रमादित्य की बयानबाजी का औचित्य

कांग्रेस के विक्रमादित्य और भाजपा की कंगना रनौत लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से प्रत्याशी हैं। कंगना की राजनीति में नई-नई एंट्री है और वह शायद पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि विक्रमादित्य राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार मंडी से राजनीति का पुराना खिलाड़ी विक्रमादित्य बाजी मारेगा या फिर कंगना रनौत, यह तो मतदाता ही तय करेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये दोनों विभिन्न तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। विक्रमादित्य कांग्रेस की उपलब्धियों को आमजन के समक्ष रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना मोदी सरकार की उपलब्धियों को।

– महेंद्र तिवारी, रायगढ़

ट्रेंड

लोकसेवकों को शुभकामनाएं

सिविल सेवा दिवस पर सभी लोक सेवकों को शुभकामनाएं। आपने देश की प्रगति के लिए अथक काम करने की महान विरासत को आगे बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश के नागरिकों की सेवा करना जारी रखेंगे।

-द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

महावीर के अहिंसा संदेश

महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश के समस्त परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणापुंज हैं।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भाजपा एक पूजक पंथ बन गई

भाजपा अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा पंथ बन गई है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूजा करती है। मोदी के 10 साल के शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गंभीर रूप से कमजोर हुई है।

-पी. चिदंबरम, कांग्रेस नेता

खरीद क्षमता कम हुई

मोदी सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़ों सहित आंकड़ों के कई स्रोत एक मत से इस तथ्य को दर्शाते हैं कि श्रमिकों की खरीद क्षमता आज 10 साल पहले की तुलना में आज कम है। धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के चलते वास्तविक मजदूरी में अभूतपूर्व गिरावट हुई है।

-जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

करंट अफेयर

तालिबान को आतंकी सूची से हटाने रूस कर रहा विचार

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रूस फिलहाल तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके बढ़ते सौहार्दपूर्ण संबंधों का एक संकेत मई में रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए तालिबान का निमंत्रण है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पहले भी तालिबान के साथ चर्चा शुरू की है, और जब संगठन ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया तो रूस एक राजनयिक को मान्यता देने वाले कुछ देशों में से एक था। अफगानिस्तान के राजनीतिक एवं आर्थिक संकट और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का मतलब है कि दोनों पक्षों को मजबूत रिश्ते से कुछ हासिल करना होगा। वर्ष 1999 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1267 को अपनाया था। कुछ महीने बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने और तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने संबंधी एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। रूस के उच्चतम न्यायालय ने 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए कहा कि इसने चेचन्या में अवैध सशस्त्र बलों के साथ संबंध बनाए रखे और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की।

ऑफ बीट

'तनाव चक्र' को पूरा करने बर्नआउट से बचना होगा

क्या आप ऐसा समय याद कर सकते हैं जब आपने जीवन की एक बड़ी घटना से पहले तनाव महसूस किया हो और फिर बाद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बोझ उतर गया हो? यह प्रक्रिया – तनाव प्रतिक्रिया का तेज होना और फिर इसे वापस शांत महसूस करना – 'तनाव चक्र' के पूरा होने को दर्शाता है। दैनिक जीवन में कुछ तनाव अपरिहार्य है। लेकिन तनावग्रस्त रहना अस्वास्थ्यकर है। लंबे समय तक रहने वाला तनाव हृदय रोग और स्ट्रोक और मधुमेह सहित पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों को बढ़ाता है। इससे उदासी या अवसाद भी हो सकता है। व्यायाम, संज्ञानात्मक, रचनात्मक, सामाजिक और आत्म-सुखदायक गतिविधियाँ हमें तनाव को स्वस्थ तरीके से संसाधित करने और तनाव चक्र को पूरा करने में मदद करती हैं। तनाव चक्र कैसा दिखता है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता 'तनाव प्रतिक्रिया' का उल्लेख करते हैं, अक्सर सामना करने या इससे बच निकलने की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 'तनाव चक्र' वाक्यांश को स्व-सहायता विशेषज्ञों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार है। तनाव चक्र किसी तनावपूर्ण घटना के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, चाहे वह वास्तविक हो या कथित, शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://www.epapr.in